छत्तीसगढ़ विधान सभा

की

अशोधित कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

पंचम विधान सभा **दशम् सत्र**

मंगलवार, दिनांक 02 मार्च, 2021

(फाल्गुन 11, शक सम्वत् 1942)

[अंक 07]

Web Copy

छत्तीसगढ़ विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 02 मार्च, 2021

(फाल्गुन 11, शक् संवत् 1942)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत् हुई.

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए)

<u>तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर.</u>

अध्यक्ष महोदय :- शांत बैठिए। आज मेरे ख्याल से सुखद संयोग है कि पूर्व मुख्यमंत्री जी प्रश्न पूछ रहे हैं। वर्तमान मुख्यमंत्री जी जवाब दे रहे हैं। ये पांचवे विधान सभा में मैं समझता हूँ कि पहला दिन है और आज के दिन का पूरा एंजाए करना चाहिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एंजाए कैसे, किस तरह से करना है, कहां पर करना है यह तो आप बताएंगे।

अध्यक्ष महोदय :- मैं बता रहा हूँ।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- माननीय अध्यक्ष महोदय ,आज पहली बार हम डॉ. साहब को हंसते हुए देख रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- मुझे बलवीर सिंह रंग जी की पंक्ति याद आ रही है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या बात है।

अध्यक्ष महोदय :- इन दोनों को समर्पित करता हूँ :-

"कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो पूछे नहीं जाते।

और कुछ उत्तर ऐसे होते हैं कि बतलाए नहीं जाते।" (हंसी)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका मतलब है कि वह न प्रश्न पूछेंगे और न वह बतायेंगे तो आगे बढ़ा जाए। (हंसी)

श्री अरूण वोरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो ऐसे हो रहा है कि कुछ ऐसे बंधन होते हैं जो बिन बांधे बंध जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए। शुरू हो जाएये। डॉ. रमन सिंह।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बात आकाश की है,लेकिन हकीकत जमीनी गहराईयों का है।

श्री रविन्द्र चौबे :- वाह-वाह। क्या बात है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए। डॉ. रमन सिंह शुरू करिये।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

प्रदेश सरकार द्वारा किराये पर लिये गये हेलिकॉप्टर

1. (*क्र. 837) डॉ. रमन सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश सरकार द्वारा किराये पर हेलिकॉप्टर लिये जाने के लिये क्या नियम एवं प्रावधान है? (ख) दिनांक 1 जनवरी, 2019 से 31 जनवरी, 2021 तक राज्य शासन द्वारा कब-कब, कितनी समयावधि के लिए किन-किन कंपनियों से हेलिकॉप्टर किराये पर लिया गया? (ग) प्रश्नांश "क" के अंतर्गत कितनी कंपनियों को किस-किस दर पर कितना-कितना भुगतान किया गया? कितना-कितना भुगतान किया जाना शेष है? वर्षवार कंपनीवार जानकारी देवें?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) छत्तीसगढ़ शासन, वित्त एवं योजना विभाग के वित्त निर्देश 33/2013 द्वारा हेलीकॉप्टर किराये में लिये जाने हेतु विमानन विभाग को वित्तीय अधिकार प्रत्यायोजित किया गया है. (ख) जानकारी प्रपत्र "अ" में † संलग्न है. (ग) दिनांक 01 जनवरी, 2019 से 31 जनवरी, 2021 तक कुल 06 कंपनियों को हेलीकॉप्टरों के प्रकार के आधार पर प्रति उड़ान घण्टे स्वीकृत दर, जीएसटी तथा हैंडलिंग चार्ज अनुसार भुगतान किया गया है. जानकारी प्रपत्र "ब" में [1]† संलग्न है.

डॉ. रमन सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण विषय में है क्योंकि जमीन के 4 हजार फीट ऊपर लगातार सफर करना और मुख्यमंत्री की सुरक्षा और सुरक्षा की चिंता विभाग को करना चाहिए। उसमें जरा भी असावधानी या चूक उचित नहीं होता और इस प्रश्न का मूल भाव इसी से निहित है और जो मैंने प्रश्न किया और जो जवाब आया है कि "ग" में कहा गया है कि दिनांक 01 जनवरी, 2019 से 31 जरनवरी, 2021 तक कुल 06 कंपनियों को हेलीकॉप्टरों के प्रकार के आधार पर प्रति उड़ान घण्टे स्वीकृत दर, जीएसटी तथा हैंडलिंग चार्ज अनुसार भुगतान किया गया है। इसी से एक प्रश्न उद्भुत होता है कि जो लिस्ट दी गई है। उसमें जो सीजी एविएटर, रायपुर छ.ग. 6 वें नंबर की कंपनी है बाकी एविएशन कंपनी के लिए प्रश्न नहीं है, लेकिन जो 6 वें नंबर पर सीजी एविएटर, रायपुर छ.ग. है यह प्रोपराईटर कंपनी है और यह कंपनी नान एन.एस.ओ.पी. ऑपरेटर है जबकि इसके पहले जब भी हेलीकॉप्टर राज्य सरकार को जरूरत पड़ती है एन.एस.ओ.पी. परमिट होल्डर कंपनी से ही सर्विस ली जाती है। सीजी एविएटर,रायपुर छ.ग. कंपनी न तो प्राईवेट लिमिटेड कंपनी है और न ही एयरप्रॉप ऑपरेटर कंपनी है, परंतु यह प्रोपराईटर कंपनी है। यह विभाग की गंभीर चूक है मुझे लगता है कि क्या इस प्रकार की कंपनी से हेलीकॉप्टर लेकर नॉन सी.एस. जो प्लेयर होते हैं प्रोपराईटर ही कंपनी है क्या इसको आगे जारी रखा जाएगा या इसको रद्द किया जायेगा या इसकी जानकारी ली जाएगी कि क्या इस प्रकार के लोग भी एविएशन में है ?

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

1 परिशिष्ट- "एक"

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सारे एग्रीमेंट वर्ष 2013 से हुए थे।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं। सबसे महत्वपूर्ण् बात यह है कि आपकी सुरक्षा के लिए चिंता जाहिर की गई।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके लिए बहुत धन्यवाद।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने इसके लिए धन्यवाद् नहीं दिया।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद दे देता हूं और आपने याद दिलाया उसके लिए भी धन्यवाद्।

श्री अमरजीत भगत :- आप कहां, आज दाल भात में मूसरचंद मत बनिए, दोनों मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री जी की बात चल रही है।

अध्यक्ष महोदय :- आज दोनों पहलवान को निपटने दीजिए। आप लोग थोड़ा शांत रहिए।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 1 जनवरी, 2019 से लेकर 31 दिसंबर, 2019 तक के जो हेलीकॉप्टर 6 कंपनियों से लिये गये, उसमें एक कंपनी के बारे में माननीय सदस्य ने चिंता जाहिर की है और यह हेलीकॉप्टर कंपनी द्वारा ही नहीं दिया जाता। बल्कि हेलीकॉप्टर डी.जी.सी.ए. का लाईसेंस प्राप्त है। सुरक्षित है और इसमें किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है, जिसके बारे में माननीय सदस्य ने चिंता की।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्री गुरू रूद्र कुमार) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज दोनों ब्लैक जैकेट पहनकर आएं हैं। राज की बात क्या है?

डॉ. रमन सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसे नान एन.एस.ओ.पी. ऑपरेटर, ऐसे ऑपरेटर जो प्रोप्राईटर कंपनी है, एविएशन कंपनी से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों को क्या एविएशन कंपनी में रजिस्टर्ड करना चाहिए, डी.जी.सी.ए. के जो सेफ्टी नार्म्स हैं, यदि माननीय मुख्यमंत्री जी की जानकारी है, यदि इस नार्म्स को फुलफिल कर रहा है और मैं इस प्रोप्राईटर कंपनी को नान सीरियस मानता हूं, क्या ऐसी कंपनी को भविष्य में हटाया जायेगा या इस प्रकार की कंपनियों को अलग किया जायेगा?

अध्यक्ष महोदय :- आपने बताया था, मेरे ख्याल से इसका अनुबंध 2013 में हुआ है।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जी अनुबंध हुआ है और इस कंपनी को एन.एस.ओ.पी. धारी कंपनी से सी.जी. एविएशन से दिलवाया गया है।

अध्यक्ष महोदय :- समाप्त।

डॉ. रमन सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह विषय गंभीर है। मुझे लगता है कि जो जवाब आया है एन.एस.ओ.पी. परमिट होल्डर कंपनी से ही हेलीकॉप्टर लेना चाहिए, ऑपरेट किया जाना चाहिए। बेहतर होगा यदि मुख्यमंत्री जी ले रहे हैं, उसके बाद भी मुझे लगता है कि इसमें एविएशन डिपार्टमेण्ट और जानकारी दे सकता है।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

भी भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो चिंता जाहिर की है, उसका पूरा ध्यान रखा जायेगा और इसको और परीक्षण करा लेते हैं, सुरक्षा में किसी प्रकार की ढिलाई नहीं दी जायेगी।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद । शिवरतन शर्मा जी, आप बृजमोहन अग्रवाल जी के प्रश्न को पूछिये1

<u>वनमंडल कटघोरा अंतर्गत जटगा वन परिक्षेत्र में कैम्पा मद से स्टाप डैम निर्माण</u>

2. (*क्र. 1275) श्री बृजमोहन अग्रवाल : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वनमंडल कटघोरा अंतर्गत जटगा वन परिक्षेत्र में कैम्पा मद अंतर्गत कितने स्टाप डैम का कार्य 2019-20 में कराया गया है? इन निर्माण से संबंधी कितनी शिकायतें कब प्राप्त हुई है? क्या जांच हुई है, और उन पर क्या कार्यवाही की गई है? (ख) कंडिका "क" के स्टॉप डैम निर्माण कार्यों में कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई है? अद्यतन कितनी राशि का भुगतान किया गया है? स्टापडेमवार बतावें? (ग) कुल कितने निर्मित स्टाप डैम का निर्माण पूर्ण किया गया है? निर्मित स्टापडैम में से कितने स्टाप डैम अच्छी स्थिति में है और कितने स्टाप डैम क्षतिग्रस्त हो गये है? इसके लिये कौन जिम्मेदार है? क्या स्टॉप डैम निर्माण में कैम्पा के नियमों का पालन किया गया है?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) वनमण्डल कटघोरा अंतर्गत जटगा वन परिक्षेत्र में कैम्पा मद अंतर्गत वर्ष 2019-20 में कुल 17 स्टॉपडैम का कार्य कराया गया है. कुल 05 शिकायतें प्राप्त हुई है. 01 शिकायत दिनांक 03-09-2019 को एवं शेष 04 शिकायतें दिनांक 05-10-2020 एवं 06-10-2020 को प्राप्त हुई. जांच कराई गई है. जानकारी †† संलग्न[2] परिशिष्ट में दर्शित है. (ख) जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. (ग) कुल 17 स्टापडैम का निर्माण कराया जा रहा है, स्टापडैम निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, सभी स्टापडैम का कार्य प्रगति पर है. 03 स्टापडैम आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हैं, क्षतिग्रस्त स्टापडैम के लिए प्रथम दृष्टया तत्कालिन परिक्षेत्र अधिकारी श्री मोहर सिंह मरकाम एवं श्री अरविंद तिवारी, तत्कालीन उपवनमण्डलाधिकारी जिम्मेदार है. स्टॉपडैम निर्माण कार्य में विभागीय नियमों/प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है.

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय बृजमोहन जी के प्रश्न में माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि कुल 17 स्टापडैम का निर्माण कराया गया और उसमें 3 स्टापडैम क्षतिग्रस्त पाये गये। उसमें मोहर सिंह मरकाम और श्री अरविंद तिवारी यह दो लोगों को जिम्मेदार ठहराया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह जो 17 स्टापडैम बन रहे

[2] परिशिष्ट "दो"

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

थे, इसकी निविदा आमंत्रित की गई थी या डिमार्टमेण्ट बनवा रहा था ? नंबर दो इसका तकनीकी सलाहकार कौन था, पक्ष को कौन देख रहा था ?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह निर्माण कार्य विभागीय तौर पर हुआ था। मटेरियल की निविदा आमंत्रित की गई थी और बाकी का विभागीय कार्य हुआ था।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, स्टापडैम का निर्माण कार्य हो रहा है तो निश्चित रूप से स्टापडैम के निर्माण कार्य के लिए टेक्नीकल हैण्ड की आवश्यकता हुआ है, मैंने इसमें यह पूछा है कि टेक्नीकल हैंड कौन था ?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जी.ओ. मेट्रिक केन्द्र बिलासपुर।

श्री शिवरतन शर्मा :- यह शासकीय है या इसको अशासकीय रूप से किया गया था ?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, शासकीय है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें तत्कालीन परिक्षेत्र अधिकारी श्री मोहर सिंह मरकाम एवं श्री अरविंद तिवारी तत्कालीन उपवनमंडलाधिकारी दो लोगों को जिम्मेदार ठहरा करके प्रारंभिक कार्यवाई की गई है, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह टेक्नीकल लोग थे, जिनके खिलाफ कार्यवाई की गई है ? अगर स्टापडैम के निर्माण में कोई कमी रह गई या निर्माण की कमी के कारण कोई क्षति हुई, उसके लिए टेक्नीकल पक्ष जिम्मेदार होगा या अधिकारी जिम्मेदार होंगे ? इनको किस आधार पर जिम्मेदार ठहराया गया ?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक उपवनमंडलाधिकारी और एक परिक्षेत्र अधिकारी थे, इनकी देखरेख में काम होना था। इनकी लापरवाही की वजह से कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ, इस कारण से इनको जिम्मेदार ठहराया गया है। जहां तक तकनीकी विषय है, उसकी तकनीकी आर.आई.एस. के माध्यम से भी जांच की गई और जो उसका स्ट्रेन्थ है वह सही पाया गया।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आश्चर्य की बात है कोई भी निर्माण कार्य होता है, उस निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मूल्यांकन करने का काम तकनीकी पक्ष करता है। स्टापडैम क्षतिग्रस्त हो गया तो तकनीकी पक्ष के खिलाफ कार्यवाई करने के बजाय आप अपने दो विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाई कर रहे हैं। दोनो तकनीकी अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाई नहीं हुई, इसमें आप कोई तकनीकी अधिकारी के खिलाफ कार्यवाई करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय :- अजय चन्द्राकर जी।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो वन के अधिकारी होते हैं, उनको तकनीकी रूप का प्रशिक्षण होता है, उनके मार्गदर्शन में काम होता है। जहां तक ड्राइंग डिजाईन बाने की बात है तो आर.ई.एस. के द्वारा किया गया है। तो निर्माण कार्य इन्हीं के नियंत्रण में किया गया है, इनकी लापरवाही थी, इसके कारण से इनके खिलाफ कार्यवाई की जा रही है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें माननीय मंत्री जी वास्तव में टेक्नीकल हैंड को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें जो टेक्नीकल लोग हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए। आप उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- श्री अजय चन्द्राकर जी, संभाल लेंगे।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या है कि मैं अपने मुर्शीद से प्रश्न कर रहा हूं यही मेरी खता है । (हंसी) माननीय वन मंत्री महोदय, एक ही वनमंडल के एक परिक्षेत्र में आपने 17 स्टापडेम स्वीकृत किये हैं, यह एक तो बड़ा आश्चर्यजनक है । मैं यह नहीं बोलता कि आपने उधर की भौगोलिक स्थिति का आपने अध्ययन किया है कि नहीं किया है, आपके ऊपर तो मैं कुछ लगा ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता लेकिन यह आश्चर्यजनक है । अब इसकी जांच करायी गई तो इसकी जांच किससे कराई गयी ? किन-किन बिंदुओं पर जांच कराई गयी और उन्होंने जांच में क्या प्रतिवेदन दिया ?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जांच कमेटी का गठन किया गया था । उसमें श्री ए.के.चौबे परिक्षेत्र अधिकारी, केंदई, श्री अविनाश इमानवेल, परिक्षेत्र अधिकारी, जटगा, जांच समिति सदस्य । श्री प्रहलाद यादव, उप वनमंडल अधिकारी कटघोरा, श्री वाय.बी. डड़सेना, उप वनमंडल अधिकारी पाली ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कटघोरा वनमंडल के एक परिक्षेत्र में यह पूरा स्वीकृत हुआ । उसी वनमंडल के अधिकारी यदि जांच करते हैं तो उसकी निष्पक्षता कैसे रहेगी ? यह सबसे महत्वपूर्ण बात है तो मेरा यह कहना है कि इसकी जांच यदि आप विभागीय करना चाहते हैं तो आप किसी दूसरी जगह से करवाईये, एक बात । दूसरी बात कितने कार्यों के कितने भुगतान अभी तक बाकी हैं, एक और दूसरा जो डेम बनने की पूरी शिकायत आपके पास है, मेरे ख्याल से दो बार शिकायत हुई है इसलिए मैं शिकायत पत्रों पर नहीं जाना चाहता कि जो जमीन कटाव में आयी है वह विशेष संरक्षित जनजातियों की जमीन है, जो कटाव हुए हैं तो पहली बात यह है कि अभी तक 17 में से कितने लोगों के भुगतान बाकी हैं और दूसरा जिनकी जमीन कटाव में आ गयी है क्या उनको आप मुआवजा देंगे या दूसरी जगह जमीन देंगे, उसके लिये क्या प्रावधान करेंगे ?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन 17 स्टापडेमों के बारे में बात हो रही है जटगा पी. 263, सेमरा नाला, 19 लाख 46,359, जटगा पी. 267, बजरंग नाला, 21 लाख 80,014, जटगा ओ.ए., बजरंग नाला, 00, जटगा कहुआनाला। 17 पूरे हैं ।

श्री अजय चंद्राकर :- वह तो परिशिष्ट में है । मेरा प्रश्न यह है कि अभी तक कितने लोगों की कितनी मजदूरी भुगतान की राशि रूकी है, वह कौन से स्टापडेम का है ? दूसरा जिनकी जमीन कटाव में

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

आयी, वह सब दत्तक पुत्र लोगों की है तो कटाव में आयी तो क्या आप उनको मुआवजा देंगे या दूसरी जगह कोई व्यवस्थापन देंगे ? या उन लोगों की कितनी जमीन कटाव में डूबी है ?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई मजदूरी भुगतान शेष नहीं है । जमीन कटाव के संबंध में अब तक कोई बात सामने नहीं आयी है ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सेकेण्ड ।

अध्यक्ष महोदय :- देखिये, आप दो पूरक प्रश्न कर चुके हैं ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आखिरी प्रश्न है । आपने परिशिष्ट में कहा है आंशिक रूप से मजदूरी भुगतान शेष है । दूसरा जो आपको मूल शिकायत मिली है उसमें इस बात का उल्लेख है । आप कहें तो मैं पढ़ दूं कि इस नाले में जमीन कटाव हुआ है । शिकायत पत्र में है, आप बोलें तो मैं आपको दे दूंगा लेकिन परिशिष्ट में जिसमें आपने बताया है, उसमें लिखा है कि आंशिक रूप से मजदूरी भुगतान शेष है । आप कह रहे हैं कि मजदूरी भुगतान शेष नहीं है तो दोनों में से कौन सी बात सत्य है ?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर देते समय मजदूरी भुगतान में कुछ-कुछ राशि बची हुई थी, जो पूरा भुगतान कर दिया गया है और जहां तक जो कटाव वाली बात है उसको मैं दिखवा लूंगा ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, शिकायतकर्ता ने शपथपत्र के साथ शिकायत की है और 17 बिंदुओं पर शिकायत की है । मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या सारे बिंदुओं पर उस वनमंडल अधिकार क्षेत्र के बाहर के अधिकारियों से जांच करायेंगे ?

अध्यक्ष महोदय :- शिकायतकर्ता कौन है ?

श्री शिवरतन शर्मा :- कोई गोयल है । श्री नवीन गोयल और श्री अजय गर्ग, इन्होंने शपथपत्र के साथ शिकायत की है ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, श्री मोहन मरकाम जी ।

श्री शिवरतन शर्मा :- क्या आप बाहर के किसी अधिकारी से इन सारे बिंदुओं की जांच करायेंगे ?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे 17 बिंदुओं पर जांच हुई है यदि 17 बिंदुओं के बारे में... ।

श्री अजय चंद्राकर :- लेकिन वहीं के लोगों ने जांच की है न, आपकी निष्पक्षता, आपकी छवि पर प्रश्नचिह्न खड़ा हो जाएगा ।

श्री शिवरतन शर्मा :- आप दूसरे वनमंडल क्षेत्र के बाहर से करा लें न ।

श्री अजय चंद्राकर :- आप दूसरे परिक्षेत्र से करवाईये । यह आपकी छवि का सवाल है ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे 17 बिंदुओं की जानकारी है । कोई श्री गोयल हैं जो पर्यावरण प्रेमी हैं, श्री अजय गर्ग भी पर्यावरण प्रेमी हैं और स्टापडेम कहीं कोई क्षतिग्रस्त नहीं हुआ । एप्रॉन जो होता है, जहां ज्यादा पानी होने के कारण पानी नीचे गिरता है तो वह हिस्सा थोड़ा सा क्षतिग्रस्त हुआ है जो सीमेंटेड होता है । कोई बहुत बड़ी अनियमितता नहीं है लेकिन उसके बाद भी जांच कराई गई और हम कार्यवाही कर रहे हैं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- मंत्री जी, आपने स्वयं अनियमितता स्वीकार करते हुए दो लोगों को जिम्मेदार ठहराया है, आपने उत्तर में स्वीकार किया है । प्रथम दृष्टया जिम्मेदार मानकर दो लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है । दूसरे परिक्षेत्र के अधिकारी से जांच कराने में क्या तकलीफ है ? आपको जांच कराना चाहिए । इसका कुछ उत्तर देंगे ?

श्री अजय चन्द्राकर :- आपकी छवि का सवाल है साहब ।

श्री मोहम्मद अकबर :- जांच हो चुकी है 3 लाख 74 हजार रूपए की वसूली के संबंध में कार्रवाई ..।

श्री शिवरतन शर्मा :- उसी क्षेत्र के अधिकारी ने जांच की है । आप किसी दूसरे क्षेत्र के अधिकारी से जांच करा लीजिए ना । दूसरे क्षेत्र के अधिकारी से जांच कराने में आपको क्या तकलीफ है ?

श्री मोहम्मद अकबर :- निर्माण में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं है । स्टॉप्डेम बनने के बाद जब ज्यादा बारिश के कारण ऊपर से पानी नीचे जिस जगह पर गिरता है वह सीमेंटेड होता है, वह आंशिक क्षतिग्रस्त हुआ है, इसके कारण इनके खिलाफ जांच हो रही है कि आपने ध्यान नहीं दिया ।

<u>कोंडागांव जिले के विकासखंड माकड़ी एवं कोंडागांव अंतर्गत कृषि ट्यूबवेल कनेक्शन हेतु प्राप्त आवेदन</u>

3. (*क्र. 1204) श्री मोहन मरकाम : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विगत 02 वर्षों में कोंडागांव जिले के विकासखण्ड माकड़ी एवं कोंडागांव अंतर्गत कृषकों ने कृषि ट्यूबवेल कनेक्शन हेतु समस्त दस्तावेज सहित विभाग द्वारा जारी डिमांड के अनुसार राशि कार्यालय छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, कोंडागांव में जमा किया गया है? यदि हां, तो उन कृषकों का नाम एवं जमा राशि का दिनांक बतावें? ग्रामवार ब्यौरा देवें? (ख) क्या उक्त कृषकों को 31 जनवरी, 2021 की स्थिति में भी कृषि ट्यूबवेल हेतु कनेक्शन नहीं दिया गया है? यदि हां तो, क्यों नहीं दिया गया है? यदि नहीं, तो अद्यतन स्थिति क्या है?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) जी हां. कोंडागांव जिले के अंतर्गत विगत दो वर्षों में कृषि पम्पों के स्थायी कनेक्शन हेतु विकासखण्ड माकड़ी में 366 एवं विकासखण्ड कोण्डागांव में 791 आवेदकों द्वारा मांगपत्र अनुसार भुगतान कर समस्त दस्तावेजों के साथ छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी

लिमिटेड, कोण्डागांव के कार्यालय में आवेदन जमा किया गया है. कृषि पंप के स्थायी कनेक्शन हेतु कृषकों की विकासखण्डवार, ग्रामवार, भुगतान तिथिवार विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट में दर्शित है. (ख) जी हां. उक्त कृषकों में से 31 जनवरी 2021 तक माकड़ी विकासखण्ड के सभी 366 कृषकों को लक्ष्य के अनुरूप वरिष्ठताक्रम में शामिल नहीं होने के कारण स्थायी कनेक्शन प्रदाय नहीं किया गया है जिसमें से 131 आवेदन विस्तार कार्य एवं 235 कार्य निविदा अंतर्गत प्रक्रियाधीन है. इसी तरह कोण्डागांव विकासखण्ड के 791 आवेदकों में से वरिष्ठताक्रम एवं वर्ष हेतु निर्धारित लक्ष्य के आधार पर 184 आवेदकों को स्थायी कनेक्शन प्रदाय किया गया है तथा शेष 607 आवेदकों को, वरिष्ठताक्रम में नहीं होने के कारण स्थायी कनेक्शन प्रदाय नहीं किया जा सका. उक्त लंबित 607 आवेदन लाईन विस्तार कर विद्युत कनेक्शन दिये जाने हेतु लंबित है. जिसमें से 339 लंबित आवेदन निविदा हेतु प्रक्रियाधीन है.

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न स्थायी ट्यूबवेल कनेक्शन से संबंधित था । माननीय मुख्यमंत्री जी का जवाब आ गया है, मैं संतुष्ट हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि जो 607 में 339 आवेदन प्रक्रियाधीन हैं जल्द से जल्द उनका भी कनेक्शन स्थायी हो जाए । यही मेरा निवेदन है ।

अध्यक्ष महोदय :- श्री अमितेश शुक्ल ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, दो साल में अमितेश जी का पहला तारांकित प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय :- इसीलिए तो उनको चांस दे रहा हूं ।

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, माननीय मरकाम जी ने और जानकारी मांगी है । अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अपने क्षेत्र के माकड़ी के और कोंडागांव विकासखंड के पम्प कनेक्शन के बारे में जानकारी मांगी है । अध्यक्ष महोदय, पूरे सदन में स्थायी पम्प कनेक्शन के बारे में अनेक बार माननीय धर्मजीत जी, धरमलाल कौशिक जी, अजय जी और हमारे दल के भी बहुत से सदस्य प्रश्न करते रहे हैं कि स्थायी कनेक्शन कब तक दिये जाएंगे । हमने समय-समय पर जानकारी भी दी है और अनेक चर्चाएं भी हुई हैं । हमने पिछले साल 10 हजार पम्प कनेक्शन का लक्ष्य रखा था लेकिन इस साल 10504 अभी तक दिये जा चुके हैं उसके बाद भी लगभग 35161 कनेक्शन पूरे प्रदेश में लंबित हैं और कोंडागांव विधान सभा क्षेत्र में 973 आवेदन लंबित हैं और सदस्यों की चिंता को देखते हुए यह 35161 कनेक्शनों के स्वीकृति की घोषणा करता हूं ताकि आने वाले वित्तीय वर्ष के पहले ये सारे कनेक्शन दिये जा सकें (मेजो की थपथपाहट) ।

अध्यक्ष महोदय :- मरकाम जी धन्यवाद् दीजिए ।

श्री मोहन मरकाम :- धन्यवाद् साहब ।

श्री धर्मजीत सिंह :- मुख्यमंत्री जी, धन्यवाद् । बहुत तकलीफ थी, हम लोग बहुत परेशान रहते थे और आपसे पिछली बार आग्रह किया, आपने विचार किया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद् ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

जिला गरियाबंद में जल जीवन मिशन अंतर्गत स्वीकृत कार्य

4. (*क्र. 1236) श्री अमितेश शुक्ल : क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जल जीवन मिशन अंतर्गत गरियाबंद जिले के किन-किन गांवों को नल-जल कनेक्शन हेतु चयनित किया गया है? विकासखण्डवार बतावें? क्या इसकी प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है? यदि हां तो लागत राशि बतावें? (ख) कंडिका "क" कार्य के लिए क्या क्रियान्वयन एजेंसी निर्धारित की गई है? यदि हां, तो किनको और किन शर्तों के तहत? (ग) क्या कंडिका "क" के कार्य के लिए निविदा बुलाई गई है? यदि हां, तो कब, किन-किन फर्मों को कार्य आवंटित किया गया? कार्य की प्रगति का ब्यौरा देवें?

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्री गुरू रूद्र कुमार) : (क) जल जीवन मिशन अंतर्गत गरियाबंद जिले के नल जल कनेक्शन हेतु चयनित गांवों की विकासखण्डवार सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" में दर्शित अनुसार है. अद्यतन में जिले के 126 ग्रामों की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है, जिसकी लागत रुपये 5191.11 लाख है. जो पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" में दर्शित अनुसार है. (ख) कंडिका "क" कार्य के अंतर्गत सोलर पंपों के कार्य के लिए क्रेडा छत्तीसगढ़ क्रियान्वयन एजेन्सी है. योजना के अन्य कार्यों हेतु क्रियान्वयन एजेंसी निर्धारित किया जाना शेष है. (ग) कंडिका "क" के अंतर्गत किसी भी कार्य हेतु निविदा नहीं बुलाई गई है. प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता. प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता. तथापि सोलर पम्पों के 91 कार्य क्रेडा छत्तीसगढ़ को दिया गया है. जनवरी 2021 की स्थिति में सोलर पंपों के 36 कार्य प्रगति पर है.

श्री अमितेश शुक्ल :- माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो यह निवेदन करूंगा कि अत्यधिक तनाव के चलते इनकी याद्दाश्त कमजोर हो रही है । क्योंकि अमरजीत भगत जी से ही मैंने तारांकित प्रश्न पूछा था और लगातार तारांकित प्रश्न लग रहे है । कृपया इनसे आग्रह है कि योगा, प्राणायाम करके अपनी याद्दाश्त को बढाएं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, वे तो बिना प्रश्न पूछे ही पसीना पोंछ रहे हैं । इसमें क्या किया जाए ।

श्री शिवरतन शर्मा :- एक वैद्य ने काढ़ा तैयार किया है उसका नाम है बुद्धिवर्धनी ।

श्री कुलदीप जुनेजा :- मेहनत का पसीना है, अजय जी ।

श्री शिवरतन शर्मा :- एक वैद्य ने काढ़ा तैयार किया है उसका नाम है बुद्धिवर्धनी । आप एक बॉटल खरीदकर भेंट कर दो ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अरूण वोरा :- चंद्राकर जी को कोई अधिकार नहीं है कि वे अजय जी को दुखी करें । आपको दुख देने का अधिकार किसने दिया यह बताइए ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं उनको कैसे दुखी कर सकता हूं, वे तो ज़िंदगी का पूरा मज़ा ले रहे हैं ।

श्री अरूण वोरा :- वे दुखी हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- अमितश जी, आपकी उंगली को संभालिए ज़रा । माईक बार-बार जल-बुझ रहा है ।

श्री अमितेश शुक्ल :- अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछा था, उन्होंने अपने जवाब में बताया कि जल जीवन मिशन में 666 गांव को चयनित किया है । प्रशासनिक स्वीकृति 126 गांवों की जारी की गई है । लागत 5191 लाख बताया है । यह भी बताया कि अभी तक टेंडर जारी नहीं किया गया है।

मैं यह जानना चाहता हूं कि जून से सितम्बर 2020 तक की प्रशासकीय स्वीकृति है, लगभग 7-8 माह हो गए हैं लेकिन टेंडर क्यों जारी नहीं किया गया है ?

श्री गुरू रूद्र कुमार :- अध्यक्ष महोदय, टेंडर अतिशीघ्र जारी हो जाएगा । कई जिलों में टेंडर लगने भी शुरू हो गए हैं । इनके यहां भी हो जाएगा ।

श्री अमितेश शुक्ल :- अतिशीघ्र का समय भी बता दें, क्योंकि 8 महीने तो हो ही गए हैं । कुछ समय निर्धारित कर दें कि इस तारीख तक हो जाएगा तो ठीक रहेगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपको यदि टिकिट मिली तो आपके चुनाव के पहले हो जाएगा ।

अध्यक्ष महोदय :- अतिशीघ्र का बताइए। चलिए, मंत्री जी।

श्री कुलदीप जुनेजा :- चन्द्राकर जी, आप टिकट की चिंता मत करिए।

श्री अमितेश शुक्ल :- अभी हमारे मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं। आप समझ लो कि आप चुनाव हारने वाले हो। (हंसी) अजय जी, आप अपनी चिंता करो।

श्री कवासी लखमा :- लोकसभा जैसे होने वाला है।

श्री गुरू रूद्र कुमार :- माननीय अध्यक्ष जी, इनके जिले में भी टेंडर लगना शुरू हो गया है। अब तक 60 टेंडर लग चुके हैं। तो काम तो शुरू है।

श्री अरूण वोरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये चन्द्राकर जी, भूतपूर्व मुख्यमंत्री के लड़कों को क्यों छेड़ते हैं। (हंसी)

श्री शिवरतन शर्मा :- अमितेश जी, चिंता का विषय है कि उत्तर देने वाले को प्रश्न पूछना पड़ रहा है। क्या यह स्थिति अच्छी है, आप यह बता दो। आपको यहां उत्तर देना था। आपको प्रश्न करना पड़ रहा है। क्या यह उचित है ? आप यह बता दो।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- आप यहां से निकलकर जी. 23 ज्वाइन कर लो। आप जी.23 ज्वाइन कर ही लो।

श्री शिवरतन शर्मा :- नहीं-नहीं, आप एक काम करो कि बी. 23 ग्रुप अलग छत्तीसगढ़ में बनाओ। आप बी. 23 ग्रुप बनाओ। (हंसी)

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अमितेश जी ने बहुत ही अच्छी बात कही है कि आगे आपको चिंता करनी है, लेकिन अभी जब से साउथ से प्रभारी आये हैं न, सबको खबर कर दिया गया है कि किसी को टिकट नहीं मिलने वाला है। कोई नया खोज लो। (हंसी) नया केंडीडेट खोज लो। यह संदेश इन लोगों को हो चुका है।

श्री कवासी लखमा :- जैसे लोकसभा में हुआ है न, वैसे ही होगा। (हंसी)

श्री अजय चन्द्राकर :- गुरू जी के उत्तर में मैंने कहा। यदि आपको टिकट मिली तो आपके चुनाव के पहले तक हो जायेगा। मैंने तो कोई दूसरी बात कही नहीं।

श्री भूपेश बघेल :- सबकी टिकट कटने वाली है। (हंसी)

श्री अमितेश शुक्ल :- आप तो टिकट के बाद नहीं जीत पाओगे। मैं तो यह बोल रहा हूं। आपको टिकट मिलेगी तो भी नहीं जीत पाओगे।

श्री शिवरतन शर्मा :- अमितेश जी, आपको प्रश्न पूछना अच्छा लग रहा है क्या ? उत्तर देने वाला व्यक्ति प्रश्न पूछ रहा है। अच्छा लग रहा है क्या ?

श्री अमितेश शुक्ल :- माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके द्वारा गुरू जी से यह पूछना चाहता हूं कि 26 अक्टूबर, 2020 को केबिनेट की बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगभग 10 करोड़ के टेंडर को निरस्त किये, घोषणा किये। क्या इस टेंडर में गरियाबंद शामिल था ?

श्री गुरू रूद्र कुमार :- माननीय अध्यक्ष जी, सवाल दूसरा था। इन्होंने कार्य के बारे में पूछा है। टेंडर निरस्ती के बारे में इन्होंने नहीं पूछा है, लेकिन फिर भी बताउंगा कि वह जो केबिनट का डिसीजन था, वह तो पूरे प्रदेश के लिए था तो प्रदेश के अंदर गरियाबंद जिला आता ही है, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको जवाब में बोला कि आपके यहां जब 60 टेंडर हो चुके हैं। कार्य जारी है। आपको तो माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहिए।

श्री अमितेश शुक्ल :- माननीय मंत्री जी, मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं और आपको भी धन्यवाद देता हूं। मगर इसकी जानकारी जो अधिकारियों द्वारा 10 करोड़ के टेंडर निरस्त किये गये हैं, उसमें जल जीवन मिशन का मामला है।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- इनको पसीना आ रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये प्रश्न पूछ रहे हैं तो इन्हें पसीना क्यों आ रहा है ? ये डर क्यों रहे हैं ?

श्री शिवरतन शर्मा :- अमितेश जी, पुन्नूलाल जी प्रश्न कर रहे हैं।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अमितेश शुक्ल :- जो गांव के मामले का मामला है, जहां पर आदिवासी लोग रहते हैं..।

श्री अजय चन्द्राकर :- मामले का मामला। (हंसी)

श्री अमितेश शुक्ल :- 10 करोड़ के टेंडर को 4 महीने हो गये निरस्त किये। किन अधिकारियों पर क्या कार्रवाई की गई ? मैं यह जानना चाहता हूं। मंत्री जी निश्चित रूप से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इसमें कोई शक नहीं है। मगर अधिकारी लोग जो है, उन पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं, यह जानना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय अमितेश जी, आपके पूरे प्रश्न का उत्तर बिना कागज देखे वे दे रहे हैं। आप कितना सीरियस प्रश्न कर रहे हैं, यह समझ में आ रहा है।

श्री गुरू रूद्र कुमार :- माननीय अध्यक्ष जी, ई.ओ.आई. निरस्त हुआ है। टेंडर तो हुआ नहीं था। वह प्रक्रिया ही अलग थी।

श्री अमितेश शुक्ल :- मैं यह बोल रहा हूं कि निरस्त कर दिया। मुख्यमंत्री जी ने जो 10 करोड़ का टेंडर निरस्त किया, उसमें अधिकारियों पर क्या कार्रवाई हुई ?

श्री गुरू रूद्र कुमार :- केबिनेट के अंदर की बातें हैं। यह गोपनीय बातें हैं।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, कुलदीप जुनेजा जी। चलिए, आप मेरे कक्ष में आइए मैं आपको बताता हूं।

<u>राजधानी रायपुर के उरला सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र में प्रदूषण उत्सर्जित उद्योगों पर कार्यवाही</u>

5. (*क्र. 6) श्री कुलदीप जुनेजा : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सत्य है कि दि. 1-1-2019 से 31-1-2020 तक की अवधि में रायपुर राजधानी उरला सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र में विभाग द्वारा जांच के दौरान विधि द्वारा विहित सीमा से अधिक उत्सर्जन करने वाले 22 उद्योग पाये गये थे? (ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई? तथा दिनांक 31-1-2020 से 31-01-2021 के दौरान इन 22 उद्योगों में विभाग ने क्या स्थिति पाई? क्या इसमें उक्त अवधि में भी उत्सर्जन सीमा विधि द्वारा विहित सीमा से अधिक थी? (ग) दिनांक 1 फरवरी, 2020 से 23 जनवरी, 2021 की अवधि में ऐसे कितने उद्योग थे जो विधि द्वारा विहित सीमा से अधिक उत्सर्जन कर रहे थे? नाम सहित जानकारी दें?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) जी हां. (ख) की गई कार्यवाही का विवरण प्रपत्र "अ" पर †[3] संलग्न है. दिनांक 31-1-2020 से दिनांक 31-1-2021 की अवधि में किये गये निरीक्षण में इन 22 उद्योगों में पाई गई स्थिति एवं उक्त अवधि में इनमें से 05 उद्योगों में भी निर्धारित मानक से अधिक

---

[3] † परिशिष्ट "तीन"

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

उत्सर्जन पाया गया था, का विवरण प्रपत्र “ब” पर † संलग्न है. (ग) नाम सहित जानकारी प्रपत्र “स” पर † संलग्न है.

श्री कुलदीप जुनेजा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा मंत्री जी से एक प्रश्न है। उद्योगों में 2 वर्षों से लगातार विधि द्वारा विहित सीमा से अधिक प्रदूषण हो रहा है। इसके लिए उद्योगों के ऊपर क्या कार्रवाई हुई है और क्या कार्रवाई करेंगे? मेरा आपके एक प्रश्न है।

श्री मोहम्मद अकबर :- जिस समयावधि के बारे में आपने जानकारी मांगी है, उसमें विस्तारपूर्वक 22 उद्योग की जानकारी दी गई है। यदि स्पेशिफिक कोई उद्योग हो, जिसमें आपकी जानकारी में ऐसी बात आयी हो कि इसमें कार्रवाई होनी चाहिए तो आप बता दें। मैं कार्रवाई करवा दूंगा।

श्री कुलदीप जुनेजा :- जी, मैं आपको बता दूंगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- कहां पर बताओगे?

श्री कुलदीप जुनेजा :- जी, अपने ऑफिस में बता देंगे।

अध्यक्ष महोदय :- पुन्नूलाल मोहले।

<u>बिजली बिल हाफ/माफ करने संबंधी</u>

6. (*क्र. 1298) श्री पुन्नूलाल मोहले : क्या मुख्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2019-20 से दिनांक 03-02-2021 तक राज्य सरकार द्वारा कितने हितग्राहियों का बिजली बिल हाफ किया गया एवं माफ किया गया? जिलेवार जानकारी देवें?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा अद्यतन माह नवंबर 2020 तक का ही राजस्व प्रतिवेदन को अंतिम रूप दिया गया है. अतः वर्ष 2019-20 से माह नवंबर 2020 तक प्रदेश के घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं को कुल राशि रुपये 1,271.84 करोड़ का लाभ दिया गया है. नवंबर 2020 की स्थिति में उक्त योजना के अंतर्गत लाभान्वित उपभोक्ताओं की संख्या 38 लाख 68 हजार 462 उपभोक्ताओं है. जिलेवार जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है.

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया है। मैंने प्रश्न पूछा है कि 03/02/2021 तक का उपभोक्ताओं का बिजली का बिल माफ और हाफ पूछा है। इन्होंने लाभ प्राप्त किये हुये उपभोक्ताओं का नाम बताया है तो मैं जानना चाहता हूं कि कितने उपभोक्ताओं का बिजली बिल माफ हुआ, वह स्पष्ट करें और कितने उपभोक्ताओं का बिजली बिल हाफ हुआ, यह भी स्पष्ट करें । उसके बाद जनवरी से 3.2.2021 तक का उत्तर नहीं आया है । मुझे उत्तर देने का कष्ट करें ।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इनका जो प्रश्न है, उसके लिखित उत्तर में सबकुछ स्पष्ट हो चुका है । अभी 38,68,462 हितग्राहियों को इसका लाभ मिल रहा है । अभी तक राज्य सरकार

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

की ओर से 1271 करोड़, 84 लाख रूपए का लाभ 38,68,462 परिवारों को मिल चुका है । इसके लाभान्वित होने की जो प्रक्रिया है, वह इसके नियम में सबकुछ स्पष्ट उल्लेख है । आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो मैं बता दूंगा ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जो लिखित उत्तर दिया है, उसे मैंने पढ़ लिया है । मेरा प्रश्न यह है कि आपने नवम्बर, 2020 तक ही उत्तर दिया है, उसके बाद दिसम्बर तक उत्तर नहीं दिया है, उसके बाद जनवरी और फरवरी का उत्तर नहीं मिला है । आप यह बताएं कि कितने उपभोक्ता थे, कितने लोगों को लाभ दिया गया है, यह बताने का कष्ट करें, मैं सामान्य प्रश्न कर रहा हूं। उसके बाद उपभोक्ताओं को जो बिजली दी जाती है, उसकी प्रति यूनिट दर क्या है और माफ करने का नियम क्या है ? कितने हितग्राहियों को कितना यूनिट देने का है या पूरे बिल में हाफ राशि देने का नियम है या फ्री यूनिट देने का नियम है, यह बताने का कष्ट करें ।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जनवरी-फरवरी के बिल में अंतिम पत्रक मार्च के अंत में ही बन सकेगा इसलिए दो महीने की जानकारी नहीं दी गई हैं । यह आंकड़े बदलते रहते हैं, यह इसलिए बदलते हैं कि मान लीजिए कि कोई उपभोक्ता लगातार दो महीने का बिजली बिल नहीं पटाया है तो इस योजना के लाभ से वह वंचित हो जाएगा । जब वह फिर पटायेगा तो फिर उसको लाभ मिलेगा और उसमें नाम जुड़ जाएगा । इस प्रकार की प्रक्रिया है ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जो उत्तर नहीं आया है, उसे बाद में दे दीजिए । आप प्रति हितग्राहियों का कितना बिल माफ करते हैं ? आप घोषणा करते हैं कि हमने बिजली बिल हाफ कर दिया, ऐसा आपका फोल्डर टंगा रहता है । आप कितना बिजली बिल माफ करते हैं, प्रति यूनिट कितना है और रेट कितना है, यह बता दीजिए ।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, घरेलू उपभोक्ताओं का बिजली बिल 400 यूनिट तक माफ किया जाता है । बी.पी.एल. कार्डधारियों को 30 यूनिट तक बिजली बिल में छूट मिलती है, उसके बाद भी कोई हितग्राही 30 यूनिट से ज्यादा बिजली का उपभोग कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में भी उनको 400 यूनिट तक छूट दी जाती है । बिजली बिल का स्लैब अलग-अलग है । 100 यूनिट तक अलग रेट है, 200 यूनिट का अलग रेट है, 400 यूनिट का अलग रेट है, हजार यूनिट का अलग रेट है । अलग किलोवाट के हिसाब से उसके रेट तय हैं । वह तो सबकी जानकारी में है, आप चाहें तो उसकी अतिरिक्त जानकारी दे दूंगा ।

(श्री शिवरतन शर्मा द्वारा पूरक प्रश्न पूछने के लिए हाथ उठाने पर)

अध्यक्ष महोदय :- शर्मा जी, हर प्रश्न का पूरक प्रश्न पूछेंगे तो कैसे चलेगा ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि प्रति यूनिट दर क्या है ? हितग्राहियों को कितना छूट देते हैं ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही बताया कि मान लीजिए कि कोई 30 यूनिट तक उपयोग करता है तो उसका बिल माफ रहता है, 100 यूनिट तक अलग रेट है, 200 यूनिट का अलग रेट है, 400 यूनिट का अलग रेट है। आप हजार यूनिट या दो हजार यूनिट तक बिजली का उपयोग करते हैं, उसका अलग-अलग रेट है । उसकी अतिरिक्त जानकारी आपको दे दूंगा । वैसे इस प्रश्न में उद्भूत नहीं होता ।

अध्यक्ष महोदय :- आपको अलग से जानकारी दे देंगे ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप सिर्फ हाफ की बात कीजिए कि बिजली के पूरे बिल में आप हाफ करेंगे क्या ? हाफ करेंगे क्या, यह मेरा प्वाइंटेड प्रश्न है ।

श्री अमितेश शुक्ल :- मुख्यमंत्री जी, मोहले जी समझ ही नहीं पा रहे हैं कि बिजली का बिल हाफ देते हैं ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मोहले जी सियान हो गे हे तो ध्यान नहीं रहाय ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- यह बात आपको समझ में नहीं आएगा डहरिया । मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूश्न पूछ रहा हूं ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- सियान हो गे न, ध्यान नहीं रहाय ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- हर समय किसी के भी प्रश्न में खड़े हो जाते हो ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- तोर ध्यान कहां रहिथे, तेन ला बता ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- तोर घर में ।

श्री अमितेश शुक्ल :- मुख्यमंत्री ला इंगलिश में जवाब देना चाहिए, वह समझ नहीं पात हे । मुख्यमंत्री जी लगातार जवाब देवथे । मुख्यमंत्री जी, आप इंगलिश में जवाब देवव ।

<u>जिला गरियाबंद में कैम्पा योजना अंतर्गत निर्मित तालाब</u>

7. (*क्र. 1292) श्री डमरूधर पुजारी : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कैम्पा योजना के अंतर्गत गरियाबंद जिले में कितनी राशि 01 जनवरी, 2019 से दिनांक 03-02-2021 तक कितने कार्यों के लिए दी गई है? इनमें से कितने कार्य प्रारंभ, अप्रारंभ, पूर्ण व अपूर्ण हैं व कितनी राशि व्यय की गई है, कितनी शेष है? कितने कार्य निर्धारित समय-सीमा पर पूर्ण नहीं हुए हैं? (ख) क्या कैम्पा योजना के अतर्गत जिले में निर्मित तालाब के संबंध में अनियमितता की जानकारी/शिकायत प्राप्त हुई थी? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई व दोषी कौन है?

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) कैम्पा योजना के अंतर्गत गरियाबंद जिले में 01 जनवरी 2019 से दिनांक 03-02-2021 तक स्वीकृत राशि, स्वीकृत कार्य, उक्त कार्यों में प्रारंभ, अप्रारंभ, पूर्ण व अपूर्ण एवं व्यय की गई राशि शेष राशि का विवरण निम्नानुसार है :—

स्वीकृत राशि	-	4937.783 लाख	
स्वीकृत कार्य	-	1. 01 जनवरी 2019 से 31 मार्च 2019 तक	93
		2. वर्ष 2019-20	215
		3. वर्ष 2020-21 (03 फरवरी 2021 तक)	161
		योग	469
प्रारंभ कार्य	-	344 कार्य	
अप्रारंभ कार्य	-	125 कार्य	
पूर्ण कार्य	-	199 कार्य	
अपूर्ण कार्य	-	87 कार्य	
व्यय की गई राशि	-	1357.218 लाख	
शेष राशि	-	3580.565 लाख	

(ख) जी हां. जानकारी †[4] संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है.

श्री डमरूधर पुजारी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न में माननीय मंत्री जी का उत्तर आ चुका है । मैं उससे संतुष्ट हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- बहुत बढ़िया ।

श्री अजय चन्द्राकर :- विपक्ष के सदस्य भी आपके द्वारा दिए गए उत्तर से संतुष्ट है इसलिए मैंने आपसे कहा कि छवि का सवाल है, दूसरे वन मण्डल से जांच करवा लीजिए ।

<u>कोरिया जिले में वृक्षारोपण</u>

8. (*क्र. 45) श्री गुलाब कमरो : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि कोरिया जिले के मनेन्द्रगढ़ वनमंडल अंतर्गत अक्टूबर, 2019 से माह जनवरी, 2021 तक वृक्षारोपण मद, सामान्य मद के विभिन्न मदों में एवं कैम्पा मद से कितनी राशि प्राप्त हुई है, तथा कितनी-कितनी राशि किस-किस कार्य में कहां-कहां व्यय की गई है?

4 परिशिष्ट "पांच"

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : कोरिया जिले में मनेन्द्रगढ़ वनमंडल अंतर्गत अक्टूबर 2019 से माह जनवरी 2021 तक वृक्षारोपण मद में राशि रु. 5155.14 लाख, सामान्य मद के विभिन्न मदों में राशि रु. 11460.55 लाख एवं कैम्पा मद में राशि रु. 3366.45 लाख कुल राशि रु. 19982.15 लाख प्राप्त हुई है. प्रश्नांकित अवधि में कराए गए कार्यों का वर्षवार, मदवार, स्थलवार, कार्यवार आवंटित राशि एवं व्यय राशि का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट में दर्शित है.

श्री गुलाब कमरो :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे जानकारी मिल गई है, मैं जानकारी से संतुष्ट हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- वंडरफूल ।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरम लाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, डमरूधर पुजारी वाले प्रश्न में एक पूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- अब हो गया, आगे निकल गए । उससे आगे निकल चुके हैं ।

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उसमें एक प्रश्न कर लेता हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं हो सकता, नहीं हा सकता प्लीज़ । ममता चन्द्राकर जी, आप अपना प्रश्न पूछिए ।

<u>जिला कबीरधाम के अंतर्गत वनमंडलों में संपादित कार्य</u>

9. (*क्र. 1052) श्रीमती ममता चन्द्राकरः क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2018-19 व 2019-20 से दिनांक 03-2-21 तक जिला कबीरधाम में वनमंडलों में किन-किन परिक्षेत्रों में चैनलिंक फेंसिंग कार्य किये गये हैं? कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया है? परिक्षेत्रवार जानकारी देवें ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : कवर्धा परिक्षेत्र में वर्ष 2020-21 में चैनलिंक फेंसिंग का कार्य कराया गया है, तथा रु. 3.77 लाख का भुगतान किया गया है.

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष जी, अकबर जी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। डमरूधर पुजारी सदस्य का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय :- हो गया, आगे निकल गया। ममता चंद्राकर जी पूछिए। ममता चंद्राकर पर ध्यान दीजिए। उनके प्रश्न का उत्तर दीजिए।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष जी, मैं उसमें एक प्रश्न कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं हो सकता। प्लीज। ममता चंद्राकर जी पूछिए।

श्रीमती ममता चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कबीरधाम जिले की वनमंडलों की परिक्षेत्रवार जानकारी चाही थी, परंतु इसमें माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगी, केवल एक ही लाईन में

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

जवाब है जो कि समझ में नहीं आ रहा है। परिक्षेत्रवार जानकारी में केवल कवर्धा परिक्षेत्र की जानकारी है।

श्री मोहम्मद अकबर :- क्योंकि एक ही स्थान पर काम हुआ है, इसलिए एक जगह की जानकारी है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये। हो गया।

श्रीमती ममता चंद्राकर :- जी, ठीक है।

अध्यक्ष महोदय :- अजय चंद्राकर जी, आप चले जाएं।

<u>भारतनेट परियोजना फेस-2 अंतर्गत ग्राम पंचायतों में ब्रॉड बेंड कनेक्शन</u>

10. (*क्र. 551) श्री अजय चन्द्राकर : क्या मुख्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भारतनेट परियोजना फेस-2 अंतर्गत कितनी-कितनी राशि केन्द्रांश एवं राज्यांश की है इस योजना के तहत् कितने ग्राम पंचायतों में ब्रॉड बेंड कनेक्शन लगाने थे? (ख) इस कार्य को कब कौन सी एजेन्सी को किन-किन अनुबंधों के आधार पर दिया गया है? और अनुबंध में कार्य अवधि कितनी थी? तथा इस अनुबंध अनुसार क्या-क्या माइलस्टोन एवं पेनाल्टी के संबंध में क्या निर्देश दिया गया है? (ग) वर्ष 2018 से 31 जनवरी, 2021 तक कितने ग्राम पंचायतों का कार्य पूर्ण हो गया है? कितना कार्य अपूर्ण है एवं उसको पूर्ण करने के लिये क्या समय-सीमा निर्धारित की गयी है? उक्त समयावधि में जिस इंप्लीमेंटेशन एजेंसी (क्रियान्वयन एजेंसी) को कार्य आवंटित किया गया था उसको कितनी बार, किस आधार पर समय सीमा में वृद्धि दी गयी और समय पर कार्य पूर्ण नहीं करने पर कुल कितनी पेनाल्टी अब तक लगाई गयी? तथा किस-किस वर्ष में पेनाल्टी की राशि काटी गयी? इसमें से कितनी राशि कार्य करने वाली एजेंसी को किनके आदेश पर वापस की गयी?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) भारत नेट परियोजना फेस-2 अंतर्गत केन्द्रांश की राशि रु. 2464.14 करोड़ तथा राज्यांश की राशि रु. 112.82 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है. इस योजना के तहत 5987 ग्राम पंचायतों में ब्रॉड बैंड कनेक्शन लगाना है.(ख) उक्त कार्य दिनांक 18 जुलाई 2018 को मेसर्स टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" में दर्शित मुख्य अनुबंध की शर्तों पर दिया गया था. अनुबंध में कार्यावधि कुल 08 वर्ष है, जिसमें निर्माण हेतु एक वर्ष तथा अनुरक्षण एवं संधारण हेतु सात वर्ष सम्मिलित है. अनुबंध अनुसार माइलस्टोन एवं पेनाल्टी के संबंध में निर्देश पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" में है. (ग) परियोजनांतर्गत 31 जनवरी, 2021 तक 2764 ग्राम पंचायतों में कार्य पूर्ण तथा शेष 3223 ग्राम पंचायतों में कार्य प्रगति पर है. उपरोक्त कार्य को पूर्ण करने हेतु एक वर्ष की अवधि मूलतः निर्धारित है. इसमें एजेन्सी मेसर्स टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड है. एजेंसी की समय-सीमा में तीन बार वृद्धि की गई है. कार्य समय पर पूर्ण नहीं होने के कारण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के विरूद्ध

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

पेनाल्टी लगाने हेतु उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है. कार्यवाही वर्तमान में प्रक्रियाधीन है, अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है.

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे थोड़ा सा समय लूंगा। मैं हिंदी का विद्यार्थी हूं। हिंदी साहित्य में एम.ए. हूं। साहब, ये परिशिष्ट पूरा अंग्रेजी में मिला है और ऐसी व्यवस्था विधानसभा में है कि प्रश्न को स्थगित करके हिंदी में परिशिष्ट को दिलवाया गया। मेरा आपसे आग्रह है कि इस प्रश्न को स्थगित करके मुझे हिंदी में जानकारी दिलवा दीजिए।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- न ऐला अंग्रेजी समझ में आए न हिंदी समझ में आए।

श्री अजय चंद्राकर :- बहुत गंभीर बात है। ये जिंदगी का मजा नहीं है। (व्यवधान)

श्री सत्यनारायण शर्मा :- अध्यक्ष जी, ये हिंदी में भी नकल मारकर पास हुए थे। (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- मुख्यमंत्री जी भी गर्व से कहें कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती करके। (व्यवधान)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- न ऐला हिंदी समझ में आए न छत्तीसगढ़ी समझ में आए।

श्री अजय चंद्राकर :- ऐसा हो चुका है। ऐसा पहली विधानसभा में हो चुका है। (व्यवधान)

श्री अमितेश शुक्ल :- अध्यक्ष महोदय, पहले ये मान लीजिए कि अंग्रेजी नहीं चलती। इन्होंने माना है कि इनको अंग्रेजी नहीं आती है। (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- इस प्रश्न को स्थगित कर दिया जाये। मुझे मंजूर है। (व्यवधान)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष जी, ये दोनों पंचायत मंत्री दोनोंपुर पंचायत मंत्री के थोड़ा से करवा लेवव। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- चलिये ठीक है। आपके प्रश्न को ...।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि यह एग्रीमेंट की कापी है, टेंडर की कापी है और भारत सरकार के द्वारा जो गाईडलाईन है, उसके हिसाब से वह टेंडर और एग्रीमेंट यह अंग्रेजी में ही है इसलिए अंग्रेजी में दिया गया है।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विधानसभा में हो चुका है। यदि परिशिष्ट अंग्रेजी में है तो हिंदी में उपलब्ध कराने तक प्रश्न को स्थगित किया गया है, ये इस विधानसभा में हो चुका है।

श्री भूपेश बघेल :- ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। अध्यक्ष महोदय, केवल इसी प्रदेश में हुआ है ऐसा नहीं है, यह तो पूरा देशभर में हुआ है। भारत सरकार की योजना है। राज्य सरकार के थोड़े से अंश रहते हैं और इसको पूरे देश भर में...।

श्री अजय चंद्राकर :- आप अनुमति...।

श्री भूपेश बघेल :- मैं बोल रहा हूं, थोड़ा सुन लें। भारत सरकार पूरे देश में एक ही प्रकार की

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

प्रक्रिया अपना रही है, उसी के हिसाब से एग्रीमेंट की कापी है और उसी के हिसाब से टेंडर भी प्रक्रिया होती है।

श्री अजय चंद्राकर :- वे तो उत्तर दे रहें हैं। मैं तो दूसरी चीज बोल रहा हूं। आप उत्तर में देखिए जानकारी संलग्न है, जानकारी संलग्न है। दो बार है। मैं उस संलग्न जानकारी को पढ़ ही नहीं सकता। माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद ही कहा है कि मुझे हिंदी आती है, वैसे ही मुझे हिंदी आती है तो इसको हिंदीं में उपलब्ध कराने तक स्थगित कर दिया जाये। मुझे एक भी आरोप है, न संदेह है, न कुछ है। मुझे आपकी क्षमता पर पूरा विश्वास है। मैं तो दूसरी बात कह रहा हूं, मुझे अंग्रेजी आती है। मुख्यमंत्री जी ने भी कहा।

श्री अमितेश शुक्ल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये मान ही नहीं रहे हैं कि अंग्रेजी आती है। (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष जी, होने वाले स्पीकर महोदय (हंसी) they are first time mr. chandrakar is a depressed (हंसी)

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, बताईये, आप जैसा कहें मैं वैसा करूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- पूछ लीजिए। आप तो बड़े विद्वान आदमी हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, मेरे को नहीं आती।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रथम विधानसभा में राजस्व मंत्री ने उत्तर देते हुए, स्वयं माननीय सदस्य कह चुके हैं कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती। जब पूछने वाले को अंग्रेजी नहीं आती, बताने वाले को अंग्रेजी नहीं आती तो प्रश्न कैसे होगा ?

अध्यक्ष महोदय :- जहां तक मैं समझता हूं, चंद्राकर जी को अंग्रेजी आती है, हिंदी आती है, उर्दू आती है, सब आती है।

श्री शिवरतन शर्मा :- मुख्यमंत्री जी विधानसभा में स्वीकार कर चुके हैं। आप रिकार्ड निकाल सकते हैं, राजस्व मंत्री के रूप में आपने जवाब देते हुए कहा है मुझे अंग्रेजी नहीं आती है।

श्री अमरजीत भगत :- शर्मा जी, अगर नहीं आती है तो लखमा जी से सीख लें। (हंसी)

श्री शिवरतन शर्मा :- प्रश्न पूछने वाले को अंग्रेजी नहीं आती, उत्तर देने वाले को अंग्रेजी नहीं आती तो प्रश्न कैसे होगा ?

श्री नारायण चंदेल :- इनको छत्तीसगढ़ी भी आती है।

अध्यक्ष महोदय :- छत्तीसगढ़ी भी आती है।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, आप जो व्यवस्था देंगे, मैं मान लूंगा।

श्री अरूण वोरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे ख्याल से श्री आत्मानंद जी अंग्रेजी स्कूल खोला गया है, मैं चाहता हूं कि चंद्राकर जी उसमें दाखिला ले लें। (हंसी)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो भारत नेट परियोजना चल रही है, उसमें देरी के क्या-क्या कारण हैं, जिसके कारण वह समय सीमा में पूरी नहीं हुई। समय-सीमा में वृद्धि देने के लिए कौन सक्षम है ? समय-सीमा में वृद्धि करने के लिए कौन सक्षम है ?

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, समय पर पूरे नहीं होने के अनेक कारण हैं। जिसमें मुख्य रूप से जो लाईन बिछाना है, उस समय लाईन बिछाने के लिए उसे रेल्वे से परमिशन लेना पड़ता है, फारेस्ट से परमिशन लेना पड़ता है, ब्रिज वालों से परमिशन लेना पड़ता है, पंचायतों से परमिशन लेना पड़ता है। इस तरह विलंब के कारण हुए हैं। जो चिप्स के सी.ई.ओ. हैं, उनको समय बढ़ाने का अधिकार है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सन् 2018 में परियोजना स्वीकृत हुई और यह सन् 2021 है और उसमें भी अभी आधा प्रतिशत काम पूरा नहीं हुआ है। तो क्या आप यह सुनिश्चित करेंगे कि और सयम वृद्धि नहीं दी जायेगी ? क्योंकि जो-जो कारण बताये गये, वे दूर हो चुके हैं।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी भी कुछ आर.ओ.डब्ल्यू. बचे हुए हैं और जून,2021 तक पूरा करने के लिए समय में वृद्धि की गई है। यदि पूरा आर.ओ.डब्ल्यू. मिल जाता है तो निश्चित रूप से इसे पूरा किया जायेगा। अन्य राज्यों में भी इसी प्रकार की स्थिति बनी हुई है। खासकर फारेस्ट में आर.ओ.डब्ल्यू. विलंब से मिल रहा है और उसकी प्रक्रिया थोड़ी सी जटिल है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी मिल जाये। वैसे रेल्वे से भी परमिशन मिलने में विलंब हुआ है। इन विलंबों के कारणों से ही समय में वृद्धि हुई है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें एक प्रश्न है। टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के विरूद्ध पेनाल्टी लगाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है। उसमें पेनाल्टी किन-किन कारणों से लगेगी ? जब आपने समय वृद्धि दी है तो पेनाल्टी लगाने के कारण क्या हैं और किन बिन्दुओं पर पेनाल्टी लगाने के लिए कारण बताओ नोटिस, कब जारी किया गया है ?

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक साल में कार्य पूरा करना था और पूरा नहीं होने पर पेनाल्टी लगाई जाती है और उसके नियम हैं और उन बिन्दुओं पर पेनाल्टी लगाया जा सकता है। कार्य समय सीमा में नहीं किया गया, इसलिए उसको नोटिस दिया गया है। उसका जवाब आयेगा, वह प्रक्रियाधीन है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत स्पेसीफिक है। जब आप तीन बार सीमा वृद्धि दे चुके हैं, जब सीमा वृद्धि दे चुके हैं तो पेनाल्टी लगाने के लिए कारण बताओ नोटिस क्यों दे रहे हैं ? इसमें एक प्रश्न यह है कि कारण बताओ नोटिस देने के पहले किसी भी दिन पर पेनाल्टी काटी गई है क्या ? क्या उसको पेनाल्टी लौटाई गई है ?

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पेनाल्टी नहीं काटी गई है। उसके भुगतान रोके गये हैं। ताकि एक दबाव बने और काम शुरू हो सके। अध्यक्ष महोदय, उसका लाभ भी हुआ है। भुगतान रोका गया और उसके बाद काम आगे बढ़ा और उसके बाद उसको रिलीज कर दिया गया। पेनाल्टी नहीं काटा गया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि रोका गया है और उसके रोके गये पैसे को लौटाया गया

श्री भूपेश बघेल :- जी।

श्री अजय चन्द्राकर :- फिर दबाव कैसे बना ? आप कह रहे है कि दबाव बनाने के लिए रोका गया।

श्री भूपेश बघेल :- काम शुरू हो गया न। काम तेजी से आगे बढ़ा।

<u>जिला रायपुर में 33/11 के.व्ही. लाईन व्यवस्थापन हेतु आमंत्रित निविदा</u>

11. (*क्र. 267) श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि छ.ग. स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि. मर्या. रायपुर विभाग द्वारा रायपुर जिले में 33 के.व्ही. 11 के.व्ही. लाईन विस्थापन (शिफ्ट) तथा निम्नदाब लाईन हेतु वर्ष 2019-20 में कब निविदा आमंत्रित की गयी? किन-किन एजेंसियों ने निविदा में भाग लिया, कार्यादेश कब जारी किये गये? उक्त समस्त जानकारी कार्यवार एजेंसीवार, कार्यादेश दिनांकवार देवें?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : रायपुर जिले में वित्तीय वर्ष 2019-20 में छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी द्वारा 33 के.व्ही. 11 के.व्ही.तथा निम्नदाब लाईनों के विस्थापन हेतु आमंत्रित निविदाओं की कार्यवार, तिथिवार, निविदाओं में भाग लेने वाले एजेंसियों एवं जारी कार्यादेश की दिनांकवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट में दर्शित है.

श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, मेरे द्वारा जो लगाया गया था, उसका उत्तर आ चुका है। मैं संतुष्ट हूं।

<u>नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र में अवैध उत्खनन की प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही</u>

12. (*क्र. 1329) श्री चंदन कश्यप : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला नारायणपुर, कोण्डागांव एवं बस्तर में नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2018-19 से 03-2-21 तक अवैध रूप से खनिज/रेत/मिट्टी-मुरम उत्खनन के कितने प्रकरण जिला प्रशासन द्वारा किन-किन व्यक्तियों के विरूद्ध पंजीबद्ध किये गये पृथक-पृथक वर्षवार जानकारी देवें? (ख) प्रश्नांश "क" से

अशासकीय/प्रकाशन के लिये नहीं

पंजीबद्ध प्रकरणों में जिला प्रशासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई? पृथक-पृथक बतायें? (ग) उक्त प्रकरणों में कितनी राशि बतौर जुर्माना वसूल की गई? कितनी राशि शेष है? शेष राशि कब तक वसूल की जावेगी?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) जिला नारायणपुर, कोण्डागांव एवं बस्तर में नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2018-19 से 03-02-2021 तक खनिज रेत, मिट्टी एवं मुरूम के अवैध उत्खनन के 13 दर्ज प्रकरणों की वर्षवार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है. (ख) प्रश्नांश "क" में पंजीबद्ध प्रकरणों में जिला प्रशासन द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट के कॉलम नंबर (8) पर दर्शित है. (ग) उक्त प्रकरणों में समझौता राशि 02 लाख 89 हजार 950 रुपये वसूल किया गया है. वसूली हेतु कोई राशि शेष नहीं है.

श्री चंदन कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो मुख्यमंत्री जी से जो प्रश्न पूछा था, उसका उत्तर आ गया है। मैं उससे संतुष्ट हूं।

श्री अजय चन्द्राकर :- सब, आपका फ्लोर मैनेजमेंट है।

<u>पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पनगांव, लोहर्सी, मेकरी में पानी टंकी निर्माण</u>

13. (*क्र. 622) श्रीमती इन्दू बंजारे : क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत पनगांव, लोहर्सी, मेकरी में कितने-कितने की लागत से पानी टंकी, पाईप लाईन विस्तार किया गया है? ठेकेदार का नाम कार्य की पूर्ण-अपूर्ण की जानकारी देवें?

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्री गुरू रूद्र कुमार) : पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत, पनगांव, लोहर्सी, मेकरी में क्रमशः रु. 13.41 लाख रु. 19.79 लाख एवं रु. 12.30 लाख की लागत से पानी टंकी निर्माण किया गया है. उपरोक्त ग्रामों में पाईप लाईन विस्तार नहीं किया गया है अपितु योजना के अंतर्गत जल वितरण/पंपिंगमेन का कार्य किया गया है. ठेकेदार का नाम, कार्य पूर्ण-अपूर्ण की जानकारी निम्नानुसार है :—

क्र.	ग्राम का नाम	पानी टंकी निर्माण कार्य		जल वितरण एवं पाईप लाईन कार्य	
		ठेकेदार का नाम	कार्य की स्थिति	ठेकेदार का नाम	कार्य की स्थिति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	पनगांव	मेसर्स भवानी बोरवेल्स, जांजगीर	पूर्ण	पूर्णमेसर्स संतोष कुमार शर्मा, नैला-जांजगीर	पूर्ण
2.	लोहर्सी	मेसर्स गायत्री कन्सट्रक्शन,	पूर्ण	मेसर्स मनोज कुमार शर्मा, नैला-जांजगीर	पूर्ण

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

3.	मेकरी	मेसर्स अनुप बोरवेल्स एवं पूर्ण पंप्स डभरा	मेसर्स अनुप बोरवेल्स एण्ड पंप्स, डभरा	पूर्ण

श्रीमती इन्दू बंजारे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से प्रश्न पूछा था कि क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत पनगांव, लोहर्सी और मेकरी में कितने-कितने की लागत से पानी टंकी, पाईप लाईन का विस्तार किया गया है ? ठेकेदार का नाम एवं कार्य पूर्ण है या अपूर्ण है ? तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि पनगांव, लोहर्सी और मेकरी में क्या पानी सप्लाई प्रारंभ हो चुका है और नहीं तो क्यों ?

अध्यक्ष महोदय :- उत्तर में तो लिखा है कि पूर्ण, पूर्ण, पूर्ण। मतलब आपको भी संतुष्ट हो जाना चाहिए।

श्रीमती इन्दू बंजारे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यही तो प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय :- आप गुरू जी से संतुष्ट नहीं हो रहे हैं।

श्रीमती इन्दू बंजारे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्ण नहीं है। विभाग के द्वारा सदन में गलत जानकारी पेश किया गया है। मैं निरीक्षण के लिए वहां गई थी तो पनगांव, लोहर्सी और मेकरी में पानी टंकी का तो निर्माण हुआ है, लेकिन वह सिर्फ शोभा मात्र है। वहां पर न तो पाईप लाईन का विस्तार किया गया है और न ही वहां पानी का सप्लाई हो रहा है। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि अगर पानी सप्लाई नहीं हो रही है तो इसमें पूर्ण जानकारी क्यों दी गई है?

श्री गुरू रूद्र कुमार :- सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने स्पेशिफिक जो प्रश्न किया है उसमें उन्होंने पानी टंकी के निर्माण की बात की है। नल-जल योजना के डिटेल के बारे में इन्होंने नहीं पूछा है। जितना उन्होंने पूछा है वह पूर्ण है।

श्रीमती इंदू बंजारे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि कार्य पूर्ण है तो पूर्ण स्थिति तब आती है जब पाईप लाईन का विस्तार हो और लोगों को पानी मिले। सालभर हो गये, पनगांव, लोहर्सी और मेकरी तीनों पंचायतों में आज तक लोगों को उसका लाभ नहीं मिल रहा है। इस प्रकार से शासन के लाखों रूपये बर्बाद किए जा रहे हैं और यह सिर्फ जो अधिकारी हैं उनकी लापरवाही के कारण हो रहा है। इसलिए माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि वह कब तक चालू होगा?

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी, मेरी सुन लीजिए। आपने प्रश्न के हिसाब से उत्तर दे दिया मगर पानी कब मिलेगा वह बता दीजिए।

श्री गुरू रूद्र कुमार :- सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, योजना बनकर तैयार है। उसमें से एक गांव में पाईपलाईन क्षतिग्रस्त हो गया है। पी.डब्ल्यू.डी की तरफ से उसमें फंड आना बाकी है, पत्र व्यवहार हो

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

गया है और बिद्युत विभाग को तीनों गांवों के लिए कनेक्शन के लिए तीन बार आवेदन किया गया तो वह बहुत जल्द शुरू हो जायेगा इस बात का मैं आपको यकीन दिलाता हूं।

श्री अजय चंद्राकर :- गर्मी इस बात जल्दी आ रही है।

श्री गुरू रूद्र कुमार :- सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित तौर पर पानी की कमी नहीं होगी।

आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो में पंजीबद्ध शिकायतों की स्थिति

14. (*क्र. 1221) श्री सत्यनारायण शर्मा: क्या मुख्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरों में वर्ष 2020-21 में 31-01-2021 तक कितने अधिकारियों के विरूद्ध शिकायत पंजीबद्ध की गई है? (ख) पंजीबद्ध शिकायतों की वर्तमान स्थिति की जानकारी देवें?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो में वर्ष 2020-21 में 31-01-2021 तक 276 अधिकारियों के विरूद्ध नामजद शिकायत पंजीबद्ध की गई है. (ख) कुल 345 पंजीबद्ध शिकायतों में से 60 शिकायतों को संबंधित विभाग/इकाईयों को जांच/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है. 01 शिकायत पर अपराध एवं 05 शिकायतों पर प्रारंभिक जांच पंजीबद्ध होकर जांच/विवेचना में है. 36 शिकायतों को अप्रमाणित पाये जाने पर नस्तीबद्ध किया गया है. 42 शिकायतों में विभागों से पूर्वानुमोदन अपेक्षित है. शेष 201 शिकायत में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है.

श्री सत्यनारायण शर्मा:- अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के जवाब से संतुष्ट हूं।

अध्यक्ष महोदय :- वैरीगुड ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या हुआ कि संतराम जी के प्रश्न के बाद संसदीय कार्य मंत्री जी ने सबको धमका दिया है कि संतुष्ट है, संतुष्ट है बोलकर बैठना है।

श्री बृहस्पत सिंह :- जैसा चंद्राकर जी धमकाते थे, वैसा हम लोगों को कोई नहीं बोलता है।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- मैं बोल रहा हूं कि माननीय सत्यनारायण शर्मा जी संतुष्ट इस कारण हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जरूर बोला होगा कि [XX][5]

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत गलत बात है, इस प्रकार की बात नहीं है। माननीय सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार है, ध्यानाकर्षण का अधिकार है। इस प्रकार की बात न हो। माननीय पुन्नूलाल मोहले जी बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं और मैं समझता हूं कि इस प्रकार से बातें नहीं करनी चाहिए।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, इसे विलोपित करिए। (हंसी)

[XX][5] अध्यक्षीय पठ के आदेशानुसार निकाला गया।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री अजय चंद्राकर :- ये तो आपके सम्मान के लिए बात कही, उसमें विलोपित करने वाली क्या बात है महाराज।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, उसमें आपको क्या करना है। कोई ऑफिस खाली है क्या?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया):- अध्यक्ष जी, डोकरा होगे हे चल गे हवे।

अध्यक्ष महोदय :- शर्मा जी, मैं आपको सुन रहा हूं, आप संतुष्ट हैं, यह बहुत खुशी की बात है। व्यंगबाण चल रहे हैं, होली आने वाली है, उसके बाद भी आप संतुष्ट नहीं हैं इसलिए मैं इसको विलोपित करता हूं। (हंसी)

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, पुन्नूलाल मोहले जी इस सदन के सबसे वरिष्ठतम सदस्य हैं, हर क्षेत्र में उनकी पारंगता प्रकांड है। (हंसी) हॉ-हॉ, बाबा जी हैं, हम लोग जानते हैं। 12 चुनाव जीते हैं और 12 ...।

श्री अजय चंद्राकर :- पैदा किए हैं। जो 12 हैं वह केवल पुन्नूलाल जी के नहीं हैं। कोई पंच का है, कोई सरपंच का है, कोई जनपद सदस्य का है, कोई विधायक का है, कोई सांसद का है। मंत्री भर का नहीं है, सांसद तक है। समझे।

श्री अरूण वोरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, चौबे जी ने कहा कि 12 बार जीते हैं और 12 ही उनके हैं तो उसका उससे ये क्या संबंध है? (हंसी)

जिला बिलासपुर में स्वीकृत रेत घाट

15. (*क्र. 818) श्री रजनीश कुमार सिंह: क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जनवरी, 2019 से दिनांक 31-1-2021 तक बिलासपुर जिले में कितनी रेत घाट स्वीकृत है? प्रत्येक स्वीकृत घाटों की कार्य अवधि कब से कब तक है? (ख) स्वीकृत रेत घाटों का खसरा नम्बर व रकबा की जानकारी प्रश्नांश "क" अनुसार विधानसभा क्षेत्रवार देने का कष्ट करें? (ग) क्या रेत घाट पर सी.सी.टी.वी. लगाना आवश्यक है? यदि हां, तो प्रदेश में किन-किन रेत घाटों पर लगा है? यदि नहीं, लगा है, तो क्यों?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) जनवरी, 2019 से दिनांक 31-01-2021 तक जिला बिलासपुर अंतर्गत कुल 18 रेत खदान स्वीकृत है. विस्तृत जानकारी † संलग्न परिशिष्ट परिशिष्ट के कॉलम क्र. 8 पर दर्शित है. (ख) प्रश्नांश "क" अनुसार स्वीकृत रेत खदानों के खसरा नम्बर व रकबा की विस्तृत जानकारी † संलग्न परिशिष्ट के कॉलम क्रमांक 6 एवं 7 पर दर्शित है. (ग) छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम, 2019 के तहत् किये गये अनुबंध मे रेत खदानों में सी.सी.टी.वी. लगाने के संबंध में कोई शर्त नहीं है.

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री रजनीश कुमार सिंह:- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बिलासपुर जिले के रेत खदान, उसके रकबा, खसरा के संबंध में पूछा था। इसमें से जो छः रेत घाट है मेरे विधानसभा क्षेत्र बेलतरा में आता है जिसमें लछनपुर/पेंडरवा, सरकंडा, मंगला-3, उरतुम, चोरहादेवरी, अकलतरी है। इसमें मंगला-3 का छोड़कर बाकी सब स्थानों पर जो खसरा बताया गया है, जो रकबा बताया गया है उसको छोड़कर रेत के खनन का काम हो रहा है। एक जगह सिर्फ और बाकी मंगला, पाटबाबा में, कोनी, सेंदरी, लोफंदी, कछार, डंगनिया, परसदा, लगरा ये सभी मेरे विधानसभा का है यहां लगातार दो साल से अवैध उत्खनन हो रहा है। और जो रकबा, खसरा बताया जा रहा है उसे छोड़कर अन्य स्थानों पर वहां से बहुत दूर एक-एक, दो-दो किलोमीटर दूर तक किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि क्या इन सभी की एक बार जांच करायेंगे कि जहां अवैध उत्खनन हो रहा है और जो घोषित है? जो घोषित स्थान है उसको छोड़कर अन्य दूर-दूर स्थानों से उसका अवैध उत्खनन हो रहा है, इसकी जांच करवायेंगे क्या ?

श्री भूपेश बघेल:- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने बताया कि कितने रेत खदान हैं उनके क्षेत्र में कितने हैं और रेत खदान संचालित हैं और यदि वह नियत स्थान से इतर खदान संचालित हो रहे हैं तो उसकी प्रक्रिया है शिकायत करवा दीजिए, वह जांच हो जाएगी और उसमें कार्यवाही हो जाएगी। जहां अवैध उत्खनन, परिवहन हो रहा है पूरी सख्ती के साथ कार्यवाही की जा रही है। किसी को बख्शा नहीं जाएगा। राजनांदगांव जिले में अवैध उत्खनन हुआ था, उसकी शिकायत हुई, हमने तत्काल कार्यवाही की और निरस्त किया तो यदि आपके पास कोई शिकायत है तो उसकी प्रक्रिया है उसका पालन करिये और उसमें कार्यवाही हो जाएगी।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाह रहा हूँ कि शिकायत करने के बाद वहां जाते हैं तो उनको फोन कर दिया जाता है तो वहां पर वह गाड़ी नहीं मिलती है। गाड़ी पकड़ते हैं दो किलोमीटर, ट्रेक्टर हाईवा पकड़ रहें हैं, लेकिन जहां अवैध उत्खनन हो रहा है वहां की मशीन एकाध दो को छोड़कर बिलासपुर में कहीं पर ऐसी कार्यवाही नहीं हुई है। रोड, रास्ते पुल में ट्रेक्टर ट्रक पकड़ते हैं तो मैं आग्रह कर रहा हूँ कि यहां पर है आप यहां से जांच कराने की घोषणा कर दीजिए तो निश्चित रूप से इसमें कार्यवाही होगी। इसलिए मेरा बार-बार निवेदन है कि यह बहुत गंभीर मामला है और यह 7-8 खदानों में अवैध उत्खनन हो रहा है और जो घोषित है वहां से दूर-दूर में अवैध उत्खनन किया जा रहा है। कहीं पर ऐसा नहीं हो रहा है जो घोषित खदान है वहां पर अवैध उत्खनन किया जा रहा हो, इसलिए मेरा आग्रह है कि आप घोषित करेंगे तो निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा और उसमें उचित कार्यवाही होगी।

अध्यक्ष महोदय :- उनका आग्रह स्वीकार कर लीजिए।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री भूपेश बघेल:- माननीय अध्यक्ष महोदय, माइनिंग विभाग में, जिला शाखा में शिकायत करवाईये। निश्चित रूप से उसके ऊपर कार्यवाही होगी। अगर शिकायत होगी, आप जो कह रहे हैं उसको दिखवा लेते हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय मुख्यमंत्री जी विधायक सदन में कह रहे हैं और पूरी गंभीरता से कह रहे हैं। आप सदन के नेता हैं। यदि विधायक की मांग पर जांच की घोषणा करते हैं तो विधान सभा की गरिमा बढ़ेगी। विधायक कोई गैर जिम्मेदारी से विधान सभा में नहीं बोलेगा। उनका बोलना ही अपने आप में पर्याप्त है और इसलिए आप जांच की घोषणा यही कर दीजिए।

श्री भूपेश बघेल:- माननीय अध्यक्ष महोदय, शिकायत होगी, तब तो कार्यवाही होगी। यदि शिकायत ही नहीं होगी तो कैसे कार्यवाही हो जाएगी।

श्री अजय चन्द्राकर :- विधायक जी सदन में कह रहे हैं।

श्री भूपेश बघेल:- आप शिकायत करवा दीजिए। उसकी जांच हो जाएगी।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय मुख्यमंत्री जी का बोलना पर्याप्त नहीं था क्या ?

<u>बंसोड़ों को शासन से बांस का प्रदाय</u>

16. (*क्र. 1243) श्री धनेन्द्र साहू : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 में दिनांक 03-02-2021 तक कितनी-कितनी संख्या में कितने बंसोड़ों को शासन की योजना के तहत बांस प्रदान किया गया? कृपया जिलेवार एवं वर्षवार अलग-अलग जानकारी देवें?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : जानकारी [6]† संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है.

श्री धनेन्द्र साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने सभी जिलों के आंकड़े दिये हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि रायपुर जिले में किस-किस ब्लॉक में या ब्लॉकवार आंकड़े वर्ष 2020-21 का ही बता देंगे।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें वन मण्डलवार जानकारी दी गई है। मैं आपको ब्लाकवार जानकारी उपलब्ध करवा दूंगा।

श्री धनेन्द्र साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा ब्लॉकवार पूछने का आशय यह है कि मेरे अभनपुर ब्लॉक में इन वर्षों में एक भी वर्ष बांस नहीं बंटे हैं। वर्ष 2016-17 में केवल 200-200 बांस बंटे हैं। वर्ष 2017-18 में 165 बांस बंटे हैं वर्ष 2018-19 में सिर्फ 65-65 बांस बंटे हैं। वर्ष 2019-20 और 2020-21 में एक भी बांस यहां पर किसी भी बंसोड़ को नहीं बंटे हैं । मैं केवल सिर्फ एक गांव का

[6] परिशिष्ट "आठ"

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

रिकॉर्ड दिया हूँ। मेरे यहां 12 गांव हैं। कार्डधारी 65 बंसोड़ है। उनको विगत दोनों सालों में एक भी बांस नहीं मिला है तो इसीलिए मैंने ब्लॉकवार आंकड़े पूछे। तो क्या आप यह सुनिश्चित करेंगे कि जितना निर्धारित है प्रति कार्डधारी बंसोड़ को एक वर्ष में जितना बांस देने का लगभग 500-600 बांस देने का होता है यहां तो उसके पहले भी नहीं दिया गया और अब तो शून्य है मैं संतुष्ट नहीं हूँ इसीलिए पूछ रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदय :- वह बांस के साथ कैसे संतुष्ट हो सकते हैं?बांस का सवाल है।

श्री धनेन्द्र साहू :- माननीय मंत्री जी, ये जितना निर्धारित है बांस देने के लिए प्रति बंसोड़ परिवार, उसको सुनिश्चित करवायेंगे क्या? यदि यह नहीं दिया गया है तो किन कारणों से नहीं दिया गया है?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सभी बंसोड़ एवं परम्परागत रूप से बांस का समान बनाकर, अपना जीवन यापन करने वाले परिवारों को प्रतिवर्ष उपलब्धता के आधार पर 1500 बांस देने का प्रावधान है। अब क्यों नहीं मिला, उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। छत्तीसगढ़ राज्य में 30 लाख व्यापारी बांस का औसतन उत्पादन होता है। 50 प्रतिशत बांस बसोड़ों के उपयोग के लिए दिया जाता है प्रति वर्ष औसत रूप से 3250 पंजीकृत बंसोड़ों को प्रतिवर्ष प्रति परिवार 1500 बांस के हिसाब से 48 लाख बांस की आवश्यकता है। हमारा उत्पादन 15 लाख का है। तो बांस उपलब्धता के आधार पर दिया जाना है। जहां तक अभनपुर की बात है, अभी कटाई का कुछ काम प्रारंभ हुआ है, सड़क बन रही हैं, माननीय सदस्य बना देंगे तो जितना भी हो सकेगा, हम लोग उपलब्ध करा देंगे।

श्री धनेन्द्र साहू :- मेरा यह कहना है कि आपने रायपुर जिले के आंकड़ें दिये हैं। आपने रायपुर जिले में 2018-19 में बंसोडों को 68,993 बॉस, 2019-20 में 88,148 बॉस, वर्ष 2020-21 में 60,836 बॉस दिया हैं, लेकिन मेरे अभनपुर ब्लाक में एक भी बांस नहीं पहुंच रहा है। मैं यह पूछ रहा हूं कि जब आप बांस दे रहे हैं तो यहां क्यों पक्षपात हो रहा है ? यहां बांस क्यों नहीं मिल रहा है ?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पक्षपात वाली कोई बात नहीं है।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपके साथ तो हर विषय में पक्षपात हो रहा है, बांस तो बहुत छोटी चीज है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है कि आप दोनों को मार्गदर्शक मंडल में बैठना है।

श्री धनेन्द्र साहू :- आप रायपुर जिले में दे रहे हैं, ऐसा नहीं हैं कि बांस उपलब्ध नहीं है, बांस उपलब्ध है तभी आप रायपुर जिले में दे रहे हैं और पूरे प्रदेश का आंकड़ा है। आपने सभी जगह दिया है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो भी बांस उपलब्ध कराया गया है, जितना उत्पादन होगा, पूर्ति जितनी करनी है, उसमें बहुत अंतर है। लेकिन फिर भी हम लोग प्रयास करेंगे कि लोगों को अधिक से अधिक बांस उपलब्ध हो सके।

श्री धनेन्द्र साहू :- मेरा आपसे निवेदन है कि एकरूपता होनी चाहिए। प्रदेश में जितना बांस का उत्पादन हो रहा है, आप जिलेवार, ब्लाकवार, गांव वार एकरूपता लाईये। जितने कार्डधारी हैं, यदि आप 100 बांस दे सकते हैं तो सबको 100 बांस दीजिए। कहीं आप 500 बांस दे रहे हैं, कहीं आप शून्य दे रहे हैं। इसको आप सुनिश्चित करें।

अध्यक्ष महोदय :- आप विशेष रूप से दिखवा लीजियेगा।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस वर्ष सभी वनमंडलों के लिए कार्य आयोजना मंजूर हो गई है और जो एकरूपता की बात की जा रही है तो उसका भी हम लोग प्रयास करेंगे कि समान रूप से बंट जाये।

<u>बलौदाबाजार वनमंडल अंतर्गत लेंटाना घास में व्यय की गई राशि</u>

17. (*क्र. 1117) श्री प्रमोद कुमार शर्मा : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बलौदाबाजार वनमंडल अंतर्गत वर्ष 2017-18 से जनवरी, 2021 तक लेंटाना घास उखाड़ने पर कितनी-कितनी राशि, किस-किस मद से स्वीकृत की गई? वर्षवार एवं परिक्षेत्रवार व्यय की गई राशि की जानकारी देवें? (ख) उक्त कार्यों की निगरानी किस आधार पर की जाती है?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट में दर्शित है. (ख) लेंटाना उन्मूलन कार्य परिसर रक्षक की निगरानी में किया जाता है. परिसर रक्षक के द्वारा कराये जाने वाले कार्यों का सतत् निरीक्षण परिक्षेत्र सहायक के द्वारा किया जाता है. परिक्षेत्र अधिकारी के द्वारा समय-समय पर मौका निरीक्षण एवं कार्य की गुणवत्ता पर नियंत्रण रखा जाता है. उप वनमण्डलाधिकारियों द्वारा कार्य का सत्यापन किया जाता है.

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी द्वारा मेरे प्रश्न का उत्तर प्राप्त हो गया है। मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि लेंटाना घास उखाड़ने के लिए इतनी-इतनी राशि दी जाती है तो वहां फोटोग्राफी क्यों नहीं कराई जाती है ? वहां देखरेख के लिए ऐसा कोई निर्धारण क्यों नहीं किया जाता? माननीय मंत्री महोदय, लेंटाना घास उखाड़ने के नाम से लाखों रुपये की फर्जी बिलिंग हो रही है, क्या इसकी रोकथाम के लिए आप कुछ करेंगे ?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, लेंटाना उन्मूलन की वीडियोग्राफी का कोई प्रावधान नहीं है। माननीय सदस्य फर्जीवाड़े के बारे में कह रहे हैं, यदि वह इस प्रकार की कोई शिकायत करेंगे तो निश्चित रूप से दिखवा लेंगे।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- माननीय मंत्री महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि एक प्रतिनिधि बना रखें ताकि ऐसा फर्जीवाड़ा न हो।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद। श्री धर्मजीत सिंह।

<u>जल जीवन मिशन के टेण्डर का निरस्तीकरण</u>

18. (*क्र. 1271) श्री धर्मजीत सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जल जीवन मिशन योजना के तहत केन्द्र शासन से दिनांक 3-2-2021 तक कब-कब कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई है? (ख) कंडिका "क" के योजना के तहत टेण्डर कब-कब कितनी लागत के जारी किए गए क्या उक्त टेण्डर निरस्त किए गए? कितने टेण्डर और क्यों?

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्री गुरू रूद्र कुमार) : (क) जल जीवन मिशन योजना के तहत् केन्द्र शासन से दिनांक 03-02-2021 तक प्राप्त राशि का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	भारत सरकार का पत्र दिनांक	प्राप्त राशि (रु. लाख में)
1.	04-10-2019	6581.96
2.	27-07-2020	11137.93
3.	29-10-2020	11137.93

(ख) कंडिका "क" योजना के तहत् कोई टेण्डर जारी नहीं किया गया है.

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी से पूछा था कि जल जीवन मिशन योजना के तहत केन्द्र सरकार से प्राप्त दिनांक 03-02-2021 तक कितनी राशि प्राप्त हुई है ? उन्होंने जवाब दिया है कि तीन किश्तों में 28857.82 लाख रुपये प्राप्त होना बताया है। मैंने पूछा है कि क्या इसमें आपने टेन्डर किया है तो आपने कह दिया है कि कोई टेन्डर नहीं किया है। जबकि आपने प्रश्न क्रमांक-4 में गरियाबंद में अमितेश शुक्ल जी के प्रश्न में प्रशासकीय स्वीकृति भी जारी करने का बताया है। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि जब इतनी बड़ी केन्द्र सरकार से गांव और गरीबों को पानी पीने के लिए उपलब्ध कराई गई है तो आपने इसमें क्या प्रक्रिया की, यह राशि अभी कहां है ? क्या यह सच है कि टेन्डर में गड़बड़ी होने के कारण माननीय मुख्यमंत्री जी ने 26 अक्टूबर 2020 की केबिनेट में इस जल जीवन मिशन के टेन्डर को निरस्त किया है ?

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री गुरू रूद्र कुमार :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने प्रश्न क्रमांक-4 का उल्लेख किया। मैं बताना चाहूंगा, दोबारा दोहरा रहा हूं कि टेन्डर तो हुआ ही नहीं तो फिर निरस्त कैसे होगा। आपने जो एक और प्रश्न किया है, इसमें क्रेडा के द्वारा सोलर आधारित कुछ काम हुए हैं, सोलर बेस पंप लगे हैं, पानी टंकी का निर्माण हुआ है और साथ ही साथ रेट्रोफिटिंग के काम हुए हैं। तो निरंतर प्रक्रिया चालू है, काम चल रहा है। ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा है, पर टेन्डर नहीं हुआ है तो निरस्ती का सवाल ही नही उठता।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप एक-तरफ यह बोलते हैं कि काम चल रहा है, दूसरी तरफ बोलते हैं कि टेंडर नहीं हुआ है तो इतने करोड़ रूपए की राशि का काम क्या टेबल में बैठकर बांटा जाता है ? आप यह बता दीजिए कि क्या कोई टेंडर की प्रक्रिया नहीं है ?

श्री गुरू रूद्र कुमार :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सौलर का जो काम होता है वह क्रेडा के जरिए होता है, पी.एच.ई. विभाग क्रेडा को फण्ड उपलब्ध कराता है । यह जो क्रेडा विभाग है, आगे की प्रक्रिया करता है । वह उस जरिये हुआ है तो पी.एच.ई. से कोई टेण्डर नहीं हुआ है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- आपने 28,857 करोड़ क्रेडा को दे दिया । आप टेंडर क्यों नहीं कर रहे हैं, इतना रूपया पड़ा है तो आखिर आप उसकी प्रक्रिया में क्यों नहीं आ रहे हैं ? गांव के लोगों को पीने के पानी की तकलीफ है, आप यह टेंडर के चक्कर में टेंडर नहीं कर रहे हैं । बाहर के ठेकेदारों को बीच में बहुत हल्ला था कि टेंडर बांट दिया गया । स्थानीय लोगों को छोड़ दिया गया, जो 10 हजार करोड़ का टेंडर हुआ है उसे निरस्त कर दिया गया । यह सारी गलतफहमियां या सही स्थितियां जो भी हैं, उसको माननीय मंत्री जी सदन के इस फ्लोर में आप बताईए कि 28,857.82 लाख रूपये जो जलजीवन मिशन के लिए प्राप्त हुआ है इस राशि को कब, कैसे और किस तरीके से खर्च करेंगे ? अभी तक इसमें कितनी राशि खर्च हुई है ?

श्री गुरू रूद्र कुमार :- मैं आपकी चिंता समझ रहा हूं । सम्माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि वर्ष 2023 के अंत तक पूरे प्रदेश के प्रत्येक गांव में, प्रत्येक घर में मुफ्त में नल कनेक्शन हो जाए तो उसके लिये हम प्रक्रिया कर रहे हैं । मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही जैसा आपको बताया कि क्रेडा के थ्रू काम हुआ है, इलेक्ट्रोफीटिंग का काम हुआ है, साथ ही साथ जो नाबार्ड पोषित योजनाएं चल रही थीं, इसके नियम के तहत् उसका भी पेमेंट हुआ है तो जो व्यय हुआ है, उसकी जो आप बात कर रहे हैं वह इनमें हुआ है और रही बात चूंकि मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया है, मेरे पुराने प्रश्न में जिसका आपने उल्लेख किया था कि अब जिलों में टेंडर लगना शुरू हो गया है तो निश्चित तौर पर आप निश्चिंत रहें, बहुत जल्दी काम तेजी पकड़ेगा ।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय मंत्री जी, उसी को आप जवाब में बोल देते न कि जिलों में टेंडर का काम शुरू हो गया है । आप विधानसभा में लिखते हैं कि कोई टेंडर नहीं हुआ है ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री गुरू रूद्र कुमार :- वह पुराना है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं पुराना-नया नहीं जानता । मैं आज तारीख को पूछ रहा हूं तो मुझे तो आज की तारीख में अपडेट रिप्लॉय चाहिए । आपने लिखा कि कोई टेंडर नहीं हुआ, एक लकीर में जवाब दिया । आप 28,857 लाख रूपए का उपयोग तो करिए । कैसे करना है, क्या तरीका होगा, यह सरकार तय करे लेकिन कम से कम इस पैसे का उपयोग तो करो । गांव में पीने के पानी की समस्या है, वहां तकलीफ है और आप क्रेडा कह रहे हैं । जितना क्रेडा का डिपार्टमेंट होगा, उतना आपने दिया अच्छी बात है । बहुत अच्छा काम होता है । क्रेडा के बारे में मेरा इंप्रेशन बहुत अच्छा है क्योंकि मैंने अपने टाईगर रिजर्व में हर गांव में क्रेडा की लाईट को जलते देखा है लेकिन केवल क्रेडा को नहीं करना है । आप बाकी जगह के टेंडर वगैरह के बारे में मुख्यमंत्री जी और सरकार की तरफ से निर्णय करके इसको करवाईए । अगर इतना-इतना रूपया मिला है और उसका उपयोग नहीं हो रहा है तो यह बहुत ही दुखदायी बात है इसलिये मैं चाहता हूं कि चूंकि एक तरफ आप बोलते हैं कि जिले में टेंडर कर दिये । दूसरी तरफ मुझे रिप्लाय देते हैं कि टेंडर नहीं हुआ है, जवाब में यह कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए ।

श्री गुरू रूद्र कुमार :- निश्चित तौर पर आप वनांचल क्षेत्र से आते हैं तो आप भी समझते हैं कि ऐसी जगहों पर जंगल एरिया में बिजली की थोड़ी समस्या रहती है तो वहां क्रेडा के थ्रू काम होता है, बाकी जो है जैसा कि मैंने आपको बोला कि टेंडर अभी लगना शुरू हुआ है, कुछ जिलों में लग चुका है और बाकी प्रक्रिया शुरू है तो आपका प्रश्न अभी लगा है, तब तक प्रक्रिया चालू थी और निश्चिंत रहें । मैं सदन में सबको यह यकीन दिलाना चाहूंगा ।

श्री धर्मजीत सिंह :- नहीं, तो इसी में तो मुझे तकलीफ हो रही है न । आपने बोला कि प्रश्न अभी लगा है, यह प्रश्न 20 दिन पहले लगा हुआ है और आप बोलते हैं कि पहले से प्रक्रिया जारी है ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये बहुत लंबा हो गया, श्री चंदेल जी को कम से कम एक मिनट दे दीजिए ।

श्री धर्मजीत सिंह :- तो जब प्रक्रिया जारी है तो मुझे यही बोल देते कि प्रक्रिया जारी है । आप एक तरफ बोलते हैं कि टेंडर जारी नहीं है । चलिये बढ़वा लीजिए ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, चंदेल जी । आप घड़ी देखते हुए बात कीजिए ।

<u>जिला जांजगीर चांपा में अवैध रेत उत्खनन, परिवहन एवं संग्रहण के दर्ज प्रकरण</u>

19. (*क्र. 1238) श्री नारायण चंदेल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जांजगीर-चांपा जिले में 01 जनवरी, 2019 से 31 जनवरी, 2021 तक रेत घाटों में अवैध रेत उत्खनन, परिवहन एवं संग्रहण के कितने प्रकरण दर्ज किये गये हैं? स्थानवार जानकारी देवें? (ख) प्रश्न "क" के संबंध में रेत माफियाओं द्वारा जनप्रतिनिधियों/विभागीय अधिकारियों के दुरव्यवहार, मारपीट के

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

मामले कहां-कहां दर्ज किये गये और उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? (ग) प्रश्न "क" के संबंध में कितनी-कितनी मात्रा में रेत की जब्ती बनाई गई? क्या अर्थदण्ड भी वसूला गया है? यदि हां, तो कितना-कितना वसूला गया? स्थानवार जानकारी देवें?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) जिला जांजगीर चांपा में 01 जनवरी 2019 से 31 जनवरी 2021 तक रेत के अवैध उत्खनन के 11 प्रकरण, अवैध परिवहन के 848 प्रकरण एवं अवैध भण्डारण के 10 प्रकरण दर्ज किये गये है. स्थानवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर दर्शित है. (ख) प्रश्नांश "क" के संबंध में जिला जांजगीर चांपा में रेत माफियाओं द्वारा जनप्रतिनिधियों/विभागीय अधिकारियों से दुर्व्यवहार, मारपीट का कोई मामला दर्ज नहीं है. अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है. (ग) प्रश्नांश "क" के संबंध में जप्त रेत की मात्रा एवं वसूल की गई समझौता राशि की स्थानवार विस्तृत विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर दर्शित है.

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न अवैध रेत उत्खनन से संबंधित है । मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि चूंकि अवैध भण्डारण के 10 प्रकरण दर्ज किये गये हैं, उस पर क्या कार्यवाही हुई और अवैध उत्खनन के 11 प्रकरण दर्ज किये गये हैं उस पर क्या कार्यवाही हुई ? कृपया माननीय मुख्यमंत्री जी बता देंगे ।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अवैध भण्डारण के और परिवहन के इन दोनों प्रकरणों में जो फाईन किया गया है और उसकी राशि वसूल की गई है ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न क्रमांक-20 । श्री केशव प्रसाद चंद्रा जी । आधा मिनट।

<u>जिला जांजगीर-चाम्पा में पेयजल विहीन गौठान में नलकूप खनन</u>

20. (*क्र. 894) श्री केशव प्रसाद चंद्रा : क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला जांजगीर चाम्पा में शासन की महत्वाकांक्षी योजना नरवा, गरवा, घुरवा एवं बारी के अंतर्गत पेयजल विहीन गौठान में कितने नलकूप खनन का लक्ष्य रखा गया है? एवं लक्ष्य के विरूद्ध क्या उपलब्धि है? (ख) प्रश्नांक "क" अनुसार शेष पेयजल विहीन गौठान में नलकूप खनन का कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा?

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्री गुरू रूद्र कुमार) : (क) जिला जांजगीर-चाम्पा में शासन की महत्वाकांक्षी योजना नरवा, गरवा, घुरवा एवं बारी के अंतर्गत पेयजल विहीन गौठान में 70 नलकूप खनन का लक्ष्य रखा गया है एवं लक्ष्य के विरूद्ध 20 नलकूप खनन कार्य पूर्ण कर लिया गया है. (ख) प्रश्नांश "क" अनुसार शेष 50 पेयजल विहीन गोठानों में नलकूप खनन का कार्य मार्च, 2021 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है.

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह जो नरवा, गरूवा, घुरवा में गौठान बना है जिसमें पानी की व्यवस्था नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्नकाल समाप्त ।

(प्रश्नकाल समाप्त)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

समय :

12:00 बजे

पत्रों का पटल पर रखा जाना

छत्तीसगढ़ भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-20

आवास एवं पर्यावरण मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (क्रमांक 16 सन् 2016) की धारा 78 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-20 पटल पर रखता हूं।

अधिसूचना क्रमांक एफ 1-44/2014/32, दिनांक 27 नवम्बर, 2020

आवास एवं पर्यावरण मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम, 2011 (क्रमांक 19, 2021) की धारा 13 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 1-44/2014/32, दिनांक 27 नवम्बर, 2020 पटल पर रखता हूं ।

छत्तीसगढ नगर तथा ग्राम निवेश नियम, 2020

आवास एवं पर्यावरण मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 85 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 7-24/2018/32, दिनांक 24 दिसम्बर, 2020 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश नियम, 2020 पटल पर रखता हूं ।

विश्वविद्यालयों का वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2019-20)

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) :- अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 47 की अपेक्षानुसार -

1 पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर का छप्पनवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-20

2 अटल बिहारी वाजपेयी, विश्वविद्यालय, बिलासपुर का आठवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-20

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

3 संत गहिरा गुरू विश्वविद्यालय, सरगुजा का वार्षिक प्रतिवेदन (1जुलाई, 2019 से 30 जून 2020)

4 बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-20, तथा

5 हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग का पंचम वार्षिक प्रतिवेदन (1जुलाई, 2019 से 30 जून 2020) पटल पर रखता हूं ।

समय :

12:03 बजे **(सभापति महोदय (श्री देवव्रत सिंह) पीठासीन हुए)**

श्री शिवरतन शर्मा (भाटापारा) :- माननीय सभापति महोदय, ग्राम गुडसा, जिला दंतेवाड़ा की पांडे कवासी नामक महिला की हत्या पुलिस अभिरक्षा में हुई है । ग्राम गुडसा के 6-7 लोगों को पुलिस ने नक्सली बताकर, गांव से उठाकर ले कर आए, जबकि वे नक्सली नहीं थे । पांडे कवासी के घर वालों को पता चला कि उसकी बेटी को उठाकर लेजाकर सरेंडर कराने का नाटक कराया गया है तो पूरे परिवार के लोग थाने मिलने आए और बार-बार निवेदन किया कि उनसे उनकी बेटी की मुलाकात कराई जाए । दिन भर उनको इंतजार कराया गया । और शाम को पांडे कवासी के माता-पिता को कह दिया गया कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली । वास्तव में वह आत्महत्या नहीं, हत्या का प्रकरण है । वह नक्सली नहीं थे, उनको जबरदस्ती उठाकर सरेंडर कराने का नाटक कराया गया है । पूरे क्षेत्र में लोग उद्वेलित हैं । शासन और प्रशासन के प्रति आक्रोश व्याप्त है । हमने इस पर स्थगन प्रस्ताव दिया है आपसे निवेदन करते हैं कि सदन की कार्यवाही रोककर स्थगन पर चर्चा कराई जाए।

श्री नारायण चंदेल (जांजगीर-चांपा) :- माननीय सभापति महोदय, लगातार पूरे बस्तर क्षेत्र में इस प्रकार की अनेक घटनाएं आश्चर्यजनक रूप से घटित हो रही हैं । आदिवासियों को, वनवासियों को इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है और वे लोग आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं । हम लोगों ने इस महत्वपूर्ण मसले पर स्थगन प्रस्ताव दिया है, सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराएं, यह हमारा आग्रह है ।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- माननीय सभापति महोदय, आप देख लें कि जब भी विधान सभा सत्र चलता है, पुलिस अभिरक्षा में कोई न कोई मृत्यु होती है । बार-बार ऐसे विषय को उठाने के बावजूद पुलिस इसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है और न ही किसी मामले की जांच कराने को तैयार है । एक छोटी सी बात होती और मामला खत्म हो जाता है । यह सरकार अपने को आदिवासियों, शोषितों, वंचितों की सरकार कहती है तो आप देखिए कि जो नक्सली नहीं है । मैं फिर से कह देता हूं कि यदि आप नक्सली के बारे में ईमानदारी से कदम उठाएंगे तो हम उसका समर्थन करेंगे । लेकिन जो नक्सली नहीं है, उसके पिताजी कह रहे हैं कि नक्सली नहीं है उसको जबरदस्ती सरेंडर कराया गया ताकि पदोन्नति मिल जाए, मेरा वहां से ट्रांसफर हो जाए या मुझे नगद ईनाम मिल जाए । इस तरह की

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

प्रक्रिया में हो जाए । जिसको आत्महतया बताया जा रहा है, सुबह से शाम तक उसके पिताजी को मिलने नहीं दिया जाता और चुपचाप बता दिया जाता है कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली । न कोई जांच होती है, न पड़ताल होती है, न दंडाधिकारी जांच होती है । एक बेबस लाचार लड़की कह हत्या पुलिस के संरक्षण में कर दी जाती है । पुलिस के संरक्षण में हो रही लगातार हत्याओं के लिए हमने स्थगन प्रस्ताव दिया है । आपसे आग्रह है कि इसको तत्काल ग्राहय करके चर्चा कराई जाए ।

सभापति महोदय :- सौरभ सिंह जी।

श्री सौरभ सिंह (अकलतरा) :- माननीय सभापति महोदय, पूरे बस्तर में नक्सलियों का सरेंडर करना, वे वास्तविक नक्सली हैं या नहीं हैं, उनके सरेंडर का यह पूरे फर्जीवाड़ा का खेल चल रहा है। किसी भी निर्दोष व्यक्ति को लाकर यह कह दिया जा रहा है कि ये नक्सली हैं और इन्हें सरेंडर करवाया जा रहा है और अगर वे पुलिस के मापदण्डों में नहीं मान रहे हैं, उनकी बातों को नहीं मान रहे हैं तो इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। माननीय सभापति महोदय, ये बस्तर में उनके मानव अधिकार का, उनके मूल अधिकार का बहुत बड़ा हनन हो रहा है और हमने इसमें स्थगन का आपसे निवेदन किया है। आपसे प्रार्थना है कि स्थगन को ग्राहय करके इस पर चर्चा करायी जाये।

सभापति महोदय :- रजनीश सिंह जी।

श्री रजनीश कुमार सिंह (बेलतरा) :- माननीय सभापति महोदय, लगातार प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती है और जब भी इसमें सदन में स्थगन के माध्यम से व अन्य माध्यमों से चर्चा होती है, प्रयास किया जाता है तो हम पुराने चीजों को लेकर ऐसे कार्यों को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण प्रदेश में हर प्रकार के अपराधियों की मनोविज्ञान बढ़ोत्तरी हुई है, उनका मनोबल बढ़ा हुआ है और जो ताजा घटना दंतेवाड़ा में हुई है, इसका जीता जागता उदाहरण है कि यदि हम यहां उसे गंभीरता से नहीं लेते तो अपराधी को लगता है कि हमारे प्रदेश में अपराध की कमी है, इसलिए हमेशा ऐसे नये-नये काम हो रहे हैं। इसलिए हमने इसमें स्थगन प्रस्ताव दिया है। विषय की गंभीरता को देखते हुए इस स्थगन को तत्काल स्वीकार कर इस पर चर्चा करायी जाये।

सभापति महोदय :- माननीय नेता प्रतिपक्ष ।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय सभापति महोदय, हम पिछले दो साल की घटना को देखे तो नक्सलियों की हत्या कम हुई है और सुरक्षा में लगे हुए जवानों की हत्या ज्यादा हुई है और उसके साथ में आज नक्सलियों का मनोबल इतना बड़ा हुआ है कि वहां रेंजर पेमेंट करने जाते हैं तो उन्हें काट दिया जाता है। पंचायत कर्मियों को मौत के घाट उतार दिये जाते हैं। उपकरण को जला दिये जाते हैं। सड़क कार्य बंद हो गये हैं। स्कूल कार्य बंद हो गये हैं। पुलिस के इस रवैये को देखकर नक्सलियों को मनोबल बड़ा हुआ है और ऐसे समय में पुलिस के द्वारा कि किसी भी गांव के बच्चे को उठाकर के ले जाना और ले जाकर यह प्रस्तुत करना कि नक्सलियों ने यहां पर सरेंडर किया है और

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

उसके बाद में जब वे मानने से इंकार करें तो उनकी हत्या करना और हत्या करके उन्हें यह बताना कि इन्होंने आत्महत्या किया है, वास्तव में जिस प्रकार की परिस्थितियां वहां पर है, आज सारे लोग आक्रोशित हैं। गांव के और लोगों को भी ले गये हैं। पूरे क्षेत्र में इस बात का आक्रोश है कि पुलिस की जो कार्रवाई है, उसकी भर्त्सना की जा रही है कि उन्हें जबर्दस्ती मौत के घाट उतारा जा रहा है, इसलिए उनके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए। हम लोगों ने स्थगन प्रस्ताव दिया है। इसे स्वीकार करें और इस पर तत्काल चर्चा करायी जाये। हम सारे तथ्य आपके सामने रखेंगे ताकि उस पर कार्रवाई हो सके और उनके जो मां-बाप हैं, उन्हें न्याय मिल सके। इसलिए सभापति महोदय, इस पर तत्काल चर्चा होनी चाहिए।

सभापति महोदय :- स्थगन की सूचना आज ही प्राप्त हुई है, जो विचाराधीन है। अब मैं 138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण की सूचनाएं लूंगा।

श्री शिवरतन शर्मा (भाटापारा) :- माननीय सभापति महोदय, पिछले दो वर्षों से लगातार पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु की घटनाएं हो रही हैं। एक प्रकार से सुनियोजित ढंग से लगातार हत्या की घटनाएं घटित हो रही हैं। इसमें सदन की कार्रवाई रोककर चर्चा करायी जाये। एक आदिवासी बच्ची की हत्या का मामला है और लगातार इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। दो साल से लगातार इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं और आदिवासी लड़की की हत्या हुई है।

श्री धरमलाल कौशिक :- यह महत्वपूर्ण मामला है। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- 9 बजे के बाद सूचनाएं प्राप्त हुई हैं और अध्यक्ष महेादय के समक्ष विचाराधीन है।

श्री शिवरतन शर्मा :- 9 बजे के पहले मेरा स्थगन जमा हुआ है।

श्री नारायण चंदेल :- सभापति महोदय, बहुत गंभीर विषय है। बहुत गंभीर विषय है।

श्री शिवरतन शर्मा :- 9 बजे के पहले मेरा स्थगन जमा हुआ है। (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- गंभीर विषय है। सभापति जी, गंभीर विषय है, इसलिए हम सभापति जी से आग्रह कर रहे हैं कि सदन की कार्यवाही को रोककर इस पर चर्चा करायें। (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- बहुत गंभीर विषय है। (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा करायें। (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- ऐसे मामले पर तत्काल चर्चा करायी जाये। (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- लगातार हत्या हो रही है। (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- रोज आदिवासी मारे जा रहे हैं। निर्दोष आदिवासी मारे जा रहे हैं (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- पुलिस अभिरक्षा में मारे जा रहे हैं। (व्यवधान)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

समय :

12.09 बजे

ध्यानाकर्षण सूचना

सभापति महोदय :- सदस्यों की ओर से अभी तक प्राप्त ध्यानाकर्षण की सूचनाओं में दर्शाये गये विषयों की अविलंबीनयता तथा महत्व के साथ ही माननीय सदस्यों के विशेष आग्रह को देखते हुए सदन की अनुमति की प्रत्याशा में नियम 138 (3) को शिथिल करके मैंने आज की कार्यसूची में 3 ध्यानाकर्षण सूचनाएं शामिल किये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है। मैं समझता हूं कि सदन इससे सहमत है।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।)

(व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति जी, लगातार आदिवासी मारे जा रहे हैं । पुलिस अभिरक्षा में लगातार मौंतें हो रही हैं, लगातार मृत्यु हो रही है । बहुत गंभीर विषय है । (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, निर्दोष आदिवासी मारे जा रहे हैं और सरकार चुप है । हमने स्थगन दिया है, इसमें सदन की कार्यवाही रोककर इसमें चर्चा कराई जाए । आदिवासियों को मारा जा रहा है । (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- सभापति महोदय, इसमें कम से कम शासन का जवाब आ जाये । (व्यवधान)

श्री धरम लाल कौशिक :- उनके विरूद्ध कोई जानकारी आनी चाहिए, गृहमंत्री जी की ओर से कोई वक्तव्य आना चाहिए । यह घटना विधान सभा के चलते हुए हैं। (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- यह बहुत ही गंभीर विषय है, इसमें शासन की ओर से वक्तव्य आना चाहिए । (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- यह घटना विधान सभा के चलते हुए हैं, इसमें सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराई जाए । (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- बहुत गंभीर विषय है । (व्यवधान)

सभापति महोदय :- माननीय डॉ. लक्ष्मी ध्रुव अपने ध्यानाकर्षण की सूचना पढ़ेंगे । (व्यवधान)

खाद्यमंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- सभापति जी, विपक्ष दो मुंहा सांप है । (व्यवधान)

श्री धरम लाल कौशिक :- यह बहस का विषय है, इसमें चर्चा होनी चाहिए (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति जी, यह बहुत ही गंभीर विषय है इसमें तत्कल चर्चा कराई जानी चाहिए । (व्यवधान)

सभापति महोदय :- सदन की कार्यवाही पांच मिनट के लिए स्थगित की जाती है ।

(12.11 से 12.18 बजे तक कार्यवाही स्थगित रही)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

समय :

12:18 बजे **(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए)**

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति जी, हम लोगों ने स्थगन दिया है।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति जी, प्रणाम।

सभापति महोदय :- प्रणाम-प्रणाम।

श्री शिवरतन शर्मा :- प्रभु हमने एक स्थगन दिया है।

सभापति महोदय :- वह तो रिकार्ड में आ गया है।

श्री शिवरतन शर्मा :- रिकार्ड में आ गयी है तो उस पर कोई व्यवस्था आ जाये। एक आदिवासी की हत्या हुई है, उसमें किसी न किसी पर चर्चा करें।

श्री अजय चंद्राकर :- सभापति जी, विचाराधीन की जगह कोई व्यवस्था आ जाये।

श्री शिवरतन शर्मा :- एक आदिवासी बालिका की हत्या हुई है, कोई व्यवस्था आ जाये।

सभापति महोदय :- चूंकि विचाराधीन है, आपको धैर्य रखना चाहिए। अभी विचाराधीन है। डॉ. लक्ष्मी ध्रुव।

(1) नगरी ब्लॉक के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में मोबाईल कनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं होने के कारण ऑनलाईन शिक्षा में असुविधा होना।

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव (सिहावा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है :-

नगरी ब्लॉक के अधिकांश आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र वनों से घिरा हुआ है, जहां मोबाईल नेटवर्क की सुविधा नहीं है। ऐसे में शिक्षा की निरंतरता को बनाए रखने हेतु लागू आनलाईन शिक्षा क्षेत्र में पूरी तरह से प्रभावित है। कोरोना वायरस के संक्रमण से विद्यार्थियों को सुरक्षा देने के उद्देश्य से शासन की महत्वपूर्ण योजना पढ़ई तुंहर दुआर और आनलाईन शिक्षा नगरी ब्लॉक में पूरी तरह से बाधित है। एक ओर छात्र-छात्राओं को आनलाईन पढ़ाई कराने के साथ सुविधा मुहैया कराने का दावा किया जाता है, वहीं वनांचल क्षेत्र में योजना लोगों तक नहीं पहुंच पाती। क्षेत्र में मोबाईल नेटवर्क नहीं होने से छात्र-छात्राओं के भविष्य पर खतरा मंडराने लगा है। नगरी क्षेत्र में सही नेटवर्क नहीं होने से आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के छात्र-छात्राओं को आनलाईन शिक्षा से वंचित होना पड़ रहा है। कुछ जगहों पर निजी कंपनी का टावर लगा हुआ है, लेकिन आज तक कोई कनेक्टिविटी नहीं है। इसका खामियाजा छात्र-छात्राओं को भुगतना पड़ रहा

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

है। इससे छात्र-छात्राओं के पालक एवं क्षेत्र की आम जनता में शासन-प्रशासन के प्रति रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- माननीय सभापति महोदय, यह सही है कि नगरी ब्लाक आदिवासी बाहुल्य है और वनांचल से घिरा हुआ है, परन्तु यह सत्य नहीं है कि शासन की महत्वपूर्ण योजना "पढ़ई तुंहर दुआर" और ऑनलाईन शिक्षा नगरी ब्लाक में पूरी तरह से बाधित है।

सत्य यह है कि नगरी ब्लाक में "पढ़ई तुंहर दुआर" के अन्तर्गत 25,595 विद्यार्थी पंजीकृत हैं और 10,345 ऑनलाईन कक्षाएं संचालित हुई हैं। जिन स्थलों पर नेटवर्क कनेक्टीविटी की समस्या है, वहां पर ऑफलाईन मोहल्ला कक्षाएं संचालित हैं, जिनमें कुल 5,519 विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं।

कोरोना महामारी के दौरान उत्पन्न हुई कठिन परिस्थितियों में भी छात्र-छात्राओं की पढ़ाई जारी रखने में शासन की महत्वपूर्ण योजना "पढ़ई तुंहर दुआर" की मुख्य भूमिका रही है। छात्र-छात्राओं के पालक एवं क्षेत्र के आम जनता में आक्रोश नहीं है।

डॉ.(श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है। मोहल्ला कक्षाएं संचालित हैं, यह सही है। लेकिन फिर भी आज की आवश्यकता है और बाकी क्षेत्रों में भी कनेक्टिविटी की सख्त जरूरत है। इसलिए वहां तुरन्त नेटवर्क प्रारंभ कराया जाये, चालू कराया जाये। जियो कम्पनी का भी टावर लगा हुआ है, उसको भी प्रारंभ करवा देंगे, तो बहुत अच्छा रहेगा। क्षेत्र के लिए भी अच्छा रहेगा। हम लोगों को भी राजनीतिक कार्य करने में असुविधा होती है, कई बार सूचना नहीं मिलती है और अन्य सभी लोगों को असुविधा होती है। तो जैसे बाकी क्षेत्रों में सुविधाएं हैं, वैसे ही नगरी सिंहावा क्षेत्र में सुविधा दी जाये तो क्षेत्र की जनता का भला होगा।

श्री रविन्द्र चौबे :- सभापति जी, मूल प्रश्न में माननीय सदस्या का ऐसा कहना लगता है कि नेटवर्क कनेक्टिविटी पर ही ध्यानाकर्षण है। माननीय सभापति महोदय, "पढ़ई तुंहर दुआर" यह बहुत महत्वपूर्ण योजना है। छत्तीसगढ़ में लगभग 25 लाख पंजीकृत छात्र रहे हैं और 2 लाख शिक्षकों ने आनलाईन कक्षाएं लगाईं। 9 लाख 75 हजार कक्षाएं लगीं। सौभाग्य यह है कि यहां की आनलाईन एजुकेशन है, उसको बंगलादेश, पाकिस्तान, नेपाल तक में लॉगिन करके बच्चों ने पढ़ाई की है। माननीय सभापति जी, दूसरा सौभाग्य की बात यह है कि हमारे देश के बहुत ही सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने "मन की बात" में छत्तीसगढ़ की ऑनलाईन कक्षाओं की प्रशंसा की है। नीति आयोग ने भी इसकी प्रशंसा की है। आखिरी बात, आपने नेटवर्क कनेक्टिविटी के बारे में प्रश्न किया है। नगरी ब्लाक में लगभग 43 मोबाइल टावर लगे हुए हैं। जिसमें अभी लगभग 19 टावर पर कनेक्टिविटी बंद है। आपने कहा कि जियो, रिलायंस, एयरटेल, आइडिया, ये सब अलग-अलग टावरों की जानकारी है। लेकिन आपकी चिंता स्वाभाविक है। चूंकि टावर, नेटवर्क और कनेक्टिविटी यह तो केन्द्र सरकार का मसला है। हम उनसे पत्र लिखकर आग्रह करेंगे, यह एक बात। स्थानीय स्तर पर जिला कलेक्टर को निर्देश जारी कर देंगे कि जो-

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

जो टावर कम्पनियां हैं, उनसे पत्र व्यवहार करें, उन्हें बुलाकर मीटिंग करें। आपके नगरी में जो नेटवर्क कनेक्टिविटी का प्रश्न है, वे इसकी समस्या को दूर करें।

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहती हूं कि जब हम धमतरी से जाते हैं तो नगरी तक तो सड़क है ही नहीं। बस नगरी के आसपास है फिर उसके आगे थोड़ा सिहावा तक यानी सड़क के किनारे-किनारे है बाकी अंदर के क्षेत्र में जाओ तो कहीं नेटवर्क नहीं मिलता। तो मेरी सबसे बड़ी समस्या यह है कि आपने आश्वासन दिया है, वह हो जायेगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद देती हूं। धन्यवाद।

श्री शिवरतन शर्मा :- मंत्री जी, डॉ. रमन सिंह जी ने कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए ही स्काई योजना शुरू की थी, जिसे इस सरकार ने बंद कर दिया। आप तो यह पूछो कि उस योजना को फिर से शुरू करेंगे क्या? उसमें सब जगह टॉवर लगने की बात थी, जिसको रोका गया है। वह पैसा वापस किया जा चुका था, उसके बाद जगह-जगह टॉवर लग रहे थे, मोबाईल बांटे जा रहे थे। इस योजना को चालू करेंगे क्या यह पूछना चाहिए।

श्री रविन्द्र चौबे :- उसमें क्या था, पंचायतों की राशि का दुरूपयोग करने का षड़यंत्र था, इसलिए उसको निरस्त किया गया था। उसको निरस्त करने का कारण भी आ जानते हैं।

सभापति महोदय :- श्री सौरभ सिंह जी अपनी ध्यानाकर्षण की सूचना पढ़ेंगे।

श्री सौरभ सिंह :- ध्यानाकर्षण की सूचना पढ़ूं उसके पहले माननीय रविंद्र चौबे जी। माननीय चौबे जी, प्रधानमंत्री जी की तारीफ किए, अच्छा लगा।

सभापति महोदय :- आप केवल ध्यानाकर्षण की सूचना पढ़ें।

श्री रविंद्र चौबे :- हमने कहा ना माननीय प्रधानमंत्री जी ने छत्तीसगढ़ सरकार की योजना पढ़ई तुम्हर दुआर की प्रशंसा की, मैं पढ़कर सुना देता हूं। दूसरा- नीति आयोग ने भी प्रशंसा की। वह क्या बोले वह भी पढ़कर बता देता हूं।

श्री सौरभ सिंह :- (दाढ़ी की ओर ईशारा) कभी-कभी आप ऐसे-ऐसे भी कर देते हैं ना।

श्री रविंद्र चौबे :- अब ये रविंद्र नाथ टैगोर से लंबी हो गई, ये इशारा उस दिन मैंने किया था। मैं उनके संबंध में सम्मान से ही नाम लेता हूं।

(2) प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में सीजीएमएससी द्वारा अमानक दवा की सप्लाई की जाना।

श्री सौरभ सिंह (अकलतरा) :- माननीय सभापति महोदय, मेरे ध्यानाकर्षण की सूचना इस प्रकार है :- प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में बीमार बच्चों के ईलाज में सीजीएमएससी से भेजी गई अमानक अमोक्सिलीन ओरल सस्पेंशन दवा का इस्तेमाल किया जाता रहा है और किसी को पता नहीं चला। छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कार्पोरेशन से इस सीरप की सप्लाई जून से पहले सभी अस्पतालों में की

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

गई थी। अब चार दिन पहले सीजीएमएससी ने इस दवा के बैच नंबर एमपी 9014 वाले पीस सभी अस्पतालों व सीएमएचओ से वापस मांगने का पत्र लिखा है। अस्पतालों में इस दवा की ज्यादातर मात्रा का उपयोग बीमार बच्चों के इलाज में हो गया है। इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि सिर्फ अंबिकापुर मेडिकल अस्पताल में ही इस बैच की 70 फीसदी से ज्यादा दवा बीमार बच्चों को दी जा चुकी है। यह दवा एंटीबायोटिक है और सर्दी, बुखार, खांसी में इस्तेमाल करने की सलाह डॉक्टरों द्वारा दी जाती है। अधिकारी इस दवा की कुला मात्रा और क्वालिटी टेस्ट से पहले अस्पतालों में इस्तेमाल हेतु सप्लाई कर दिये जाने के सवाल के जवाब देने से बच रहे हैं। सीजीएमएससी द्वारा सरकारी अस्पतालों में दवा की सप्लाई से पहले क्वालिटी टेस्ट किया जाता है, जो दवा एन.एस.क्यू. (नान स्टेण्डर्ड क्वालिटी) श्रेणी में आती है, उस बैच की दवा रोक दी जाती है। इन सारी प्रक्रिया के बावजूद भी अमानक दवा अस्पतालों तक पहुंच गयी। इन अस्पतालों के माध्यम से प्रदेश और विशेषकर अंबिकापुर के कितने मरीजों ने उपरोक्त दवा का सेवन किया और इस अमानक दवा के उपयोग से उनके स्वास्थ्य पर परोक्ष और अपरोक्ष प्रभाव का कोई मूल्यांकन नहीं किया जा रहा है। दोषी कर्मचारियों के ऊपर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य के साथ इस प्रकार हो रहे खिलवाड़ से जनता में भारी रोष और आक्रोश व्याप्त है।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री टी.एस.सिंहदेव) :- माननीय सभापति महोदय, यह कहना सही नहीं है कि प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में बीमार बच्चों के ईलाज में सीजीएमएससी से भेजी गई अमानक अमोक्सीसिलीन ओरल सस्पेंशन दवा का इस्तेमाल किया जाता रहा और किसी को पता नहीं चला। वास्तविकता यह है कि यह दवा मूलत: दिनांक 06.11.2019 के क्रय आदेश के आधार पर आपूर्ति की जाकर दिनांक 13.02.2020 को मानक पाये जाने के उपरांत ही, दिनांक 18.02.2020 से दिनांक 13.06.2020 तक स्वास्थ्य इकाईयों को वितरित की जाकर उपयोग में लाई गयी थी। कुछ समय बीतने के बाद दिनांक 31.08.2020 को शिकायत आने पर इसके वितरण पर तत्काल दिनांक 01.09.2020 को रोक (Hold) लगाते हुए, पुन: गुणवत्ता परीक्षण पूर्व में भेजे गये प्रयोगशाला से भिन्न, एक अन्य अधिकृत प्रयोगशाला से कराया जाकर आगे की कार्यवाही की गई। यह कहना सही नहीं है कि अब चार दिन पहले सीजीएमएससी ने इस दवा के बैच नंबर एमपी 9014 वाले पीस सभी अस्पतालों व सीएमएचओ से वापस मंगाने का पत्र लिखा है। वास्तविकता यह है कि दिनांक 22.10.2020 को उक्त बेच को अमानक घोषित करते हुए, संबंधित फर्म को अमानक पाये गये औषधि के उपलब्ध स्टाक को वापस उठाव किये जाने हेतु निर्देशित किया गया एवं साथ ही भुगतान राशि की वसूली किये जाने की कार्यवाही की गई।

यह कहना सही नहीं है कि सिर्फ अंबिकापुर मेडिकल अस्पताल में ही इस बैच की 70 फीसदी से ज्यादा दवा बीमार बच्चों को दी जा चुकी है। वास्तविकता यह है कि उक्त बेच की कुल 19800 दवा में

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

से केवल 600 अंबिकापुर मेडिकल अस्पताल को उपलब्ध कराया गया था, जिसमें से कुल 458 दवा अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज द्वारा सीजीएमएससी को वापस कर दिया गया है। इस प्रकार उक्त बैंच का मात्र 0.72 प्रतिशत (संख्या 142) का उपयोग अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में किया गया है।

यह कथन सही है कि अमोक्सीसिलीन ओरल सस्पेंशन एक एंटीबायोटिक दवा है और सर्दी, बुखार, खांसी में इस्तेमाल करने की सलाह डॉक्टरों द्वारा दी जाती है। किन्तु यह कहना सही नहीं है कि इस दवा की कुल मात्रा और क्वालिटी टेस्ट से पहले अस्पतालों में इस्तेमाल हेतु सप्लाई कर दिया जाता है, जबकि वास्तविकता यह है कि दवा की आपूर्ति के पूर्व प्रत्येक बैच में से रैण्डम सैम्पलिंग के आधार पर दवा के नमूनों की गुणवत्ता की जांच हेतु सीजीएमएससी के अधिकृत प्रयोगशालाओं से कराई जाती है एवं मानक गुणवत्ता प्रतिवेदन प्राप्त होने पर ही स्वास्थ्य इकाइयों को वितरित की जाती है। दवा के अमानक पाये जाने पर दवाओं की आपूर्ति तत्काल रोक दी जाती है एवं संबंधित फर्म के विरूद्ध निविदा में उल्लेखित प्रावधानों/शर्तों के अनुरूप कार्यवाही की जाती है।

अमोक्सीसिलीन ओरल सस्पेंशन दवा की द्वितीय बार किये गये गुणवत्ता परीक्षण में, अमानक पाये जाने का कारण एएसएसएवाई पैरामीटर में औषधि के स्ट्रेन्थ/एफिकेसी में कमी होना पाया गया। आज दिनांक तक उक्त औषधि के उपयोग से किसी भी प्रकार के जनहानि/स्वास्थ्य हानि/दुष्प्रभाव होने की सूचना/शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। आपूर्तिकर्ता फर्म के विरूद्ध अनुबंध अनुसार वित्तीय हानि की वसूली की कार्यवाही की जा चुकी है एवं उक्त बैच को दवा वितरण प्रणाली साफ्टवेयर में स्वास्थ्य इकाई स्तर तक रोक (Block) दिया गया है एवं भविष्य में ऐसे प्रकरणों की पुनरावृत्ति न हो इसके लिए साफ्टवेयर में केन्द्रीयकृत रोक किये जाने का प्रावधान लागू कर दिया गया है।

अत: यह कथन सत्य नहीं है कि जनता में भारी रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि इसके डिस्ट्रीब्यूशन को 4 महीने के पहले इस अमानक दवाई को रोका गया, दवाई कंपनी कौन सी थी, इसने कितनी दवाई सप्लाई की थी? और इससे इस 4 महीने में कितना पैसा वसूला गया?

श्री टी.एस. सिंहदेव :- माननीय सभापति महोदय, वसूली के पैसे की राशि 2, 29,501 रूपये है यह 9 रूपये का टेण्डर और जीएसटी लगाकर 10 रूपये 8 पैसे की यह दवाई पड़ी थी और 19 हजार 800 वाइल्स की कीमत और एनएचक्यू के जो चार्ज 20 प्रतिशत लगे हैं, उसको लेकर 2, 29,501 रूपये की राशि वसूली की गई है।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय सभापति महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी से पूछा कि कुल यह दवाई कितनी सप्लाई हुई थी? किस कंपनी से सप्लाई हुई थी ? और मेरे दोनों प्रश्नों का जवाब दे दीजिए?

श्री टी.एस. सिंहदेव :- माननीय सभापति महोदय, 19 बैचेस में 3 लाख 81 हजार वायल्स का ऑर्डर मान फार्मास्यूटिकल्स गुजरात की कंपनी है उनको यह सप्लाई की गई थी इसमें शिकायत केवल

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अंबिकापुर से है। एमएबी9014 की जो 19 हजार 800 वाइल्स का बैच था, उसकी आई है और शिकायत आते साथ उसकी सप्लाई, उपयोग को भी रोका गया और परीक्षण उपरांत पूरे को विथड्रा कर लिया गया।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय सभापति महोदय, इस गुजरात की कंपनी ने अमानक दवाई सप्लाई की और माननीय मंत्री जी मान रहे हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि इस कंपनी ने एक अमोक्सीसिलीन एक दवाई सप्लाई की। एक दवाई कंपनी कई कैमिकल फार्मूला की दवाईयां बनाती हैं तो क्या इस दवाई कंपनी का पूरा रजिस्ट्रेशन कैंसल करेंगे?

सभापति महोदय :- गुजरात की कंपनी है भई, जरा देख लीजिए।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- माननीय सभापति महोदय, इसकी भी एक प्रक्रिया है, जो टेस्टिंग होती है, तीन बार सेंपल आने के बाद और 5 बार अमानक पाये जाने के बाद अलग-अलग श्रेणी की कार्यवाहियां होती हैं। अगर किसी का 5 बार सेंपल फेल होता है ब्लैकलिस्टिंग की कार्यवाही होती है।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय सभापति जी, माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में दिया है कि अधिकृत प्रयोगशाला से कराया जाकर आगे की कार्यवाही की गई तो यह कौन सी अधिकृत प्रयोगशाला थी जिसने प्रथम बार जांच की और जांच में उसको मानक बनाकर सप्लाई हो गया? जब आपने द्वितीय बार शिकायत पर कार्यवाही की तो आपने दूसरी एजेंसी से करवाया, उसमें शिकायत के बाद अमानक पाया। आपने प्रथम एजेंसी जिस प्रयोगशाला से जांच कराई, जिसने इसको मानक पाकर सप्लाई कराने के लिए OK किया, क्या उस पर कार्यवाही करेंगे ?

श्री टी.एस. सिंहदेव :- माननीय सभापति महोदय, जिस समय जांच कराई गई, अगर उस समय दवाई की गुण्वत्ता सही थी तो कार्यवाही करने का कोई आधार नहीं होता। ये देश के एन.ए.बी.एल. के मानकों के आधार पर अधिकृत कंपनियां हैं, जो हमारे देश की National accreditation board for testing and calibration laboratories मान्यता प्राप्त होती हैं, उनसे ही ये टेस्ट कराये जाते हैं। जिस laboratories से टेस्ट वर्क कराया गया था, qualicom laboratories थीं, पहली बार जिनसे 6 फरवरी को टेस्ट कराया गया था। और उसमें ब्यूरो ऑफ स्टैण्डर्ड, फर्टिलाईजर, मिनरल, कामर्स नार्थ बाजार रोड, गोकुलपुरा मार्केट, नागपुर है। कोई भी जो laboratories हैं, जो गवर्नमेण्ट पहले थीं, उनने भी जिनको किया था, लगभग वही laboratories चल रही हैं और एस.ई.पी.एल. बहुत मान्यता प्राप्त संस्था है और उनका जो accreditation है, उस पर हम लोग संदेह नहीं करते।

श्री शिवरतन शर्मा (भाटापारा) :- माननीय सभापति जी, माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है 0.72 प्रतिशत दवाई का उपयोग हुआ है। आपके अंबिकापुर में ही 600 दवा गई है और उसमें आप स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि 142 दवा का उपयोग हो चुका है। लगभग-लगभग जो अंबिकापुर गया, उसका लगभग-लगभग 23 प्रतिशत का उपयोग हो गया। आप पहले तो यह बता दीजिए कि 19,800 दवा में से कुल कितने का उपयोग हुआ ? दूसरा एक प्रश्न जो सौरभ सिंह जी ने पूछा था कि पहली बार

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

गुण्वत्ता ठीक पाई गई और दूसरी बार टेस्ट कराने पर वह अमानक पाया गया। एक ही दवाई दो स्थानों पर टेस्ट हो, एक में गुणवत्तायुक्त पाई जाये और दूसरे में गुणवत्ताविहीन पाई जाये, यह कैसे हो सकता है ?

श्री टी.एस. सिंहदेव :- माननीय सभापति महोदय, ये केमिकल्स हैं और जिन स्थितियों में वह रहती हैं, उसमें परिवर्तन उन कारणों से आ सकता है, आपने स्टोरेज कहां किया, जिस फेसिलिटी में गया था। यह जो जानकारी है, यह किसी की शिकायत के आधार पर नहीं आई, यह स्वास्थ्य विभाग के ही कर्मियों ने दवाई देने के पहले जब एक दो वायल में पाया कि सस्पेंशन में कुछ कलर का अंतर आ रहा है तो विभाग ने ही सूचित किया और विभाग के ही सूचित करने पर इस पर रोक लगाई गई थी। समय और परिस्थिति के हिसाब से यह अंतर आता है।

श्री शिवरतन शर्मा :- हम दवाई लेते हैं तो दवाई को किस टेम्प्रेचर पर रखना है, किन परिस्थितियों में रखना है, वह क्लीयर रहता है। एक बार मानक पाई जा रही है, दूसरी बार अमानक पाई जा रही है। क्या हमने जो दवाई ख्रीदी, उसको जिन परिस्थितियों में रखना था, क्या वैसे रखने की व्यवस्था नहीं की थी ? दोनों में एक एक न एक बात बड़बड़ हुई है न।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- माननीय सभापति महोदय, व्यवस्था अवश्य रहती है। लेकिन कहीं न कहीं कोई कारण हुआ होगा कि केमिकल कन्टेंट में अंतर आया है। क्योंकि यह प्रामाणिक है कि अंतर आया।

श्री सौरभ सिंह :- क्या लैब के ऊपर कार्यवाही करेंगे ? प्रथम दृष्टि में जिस लैब से पास कर दिया, क्या उस पर कार्यवाही करेंगे ?

श्री टी.एस. सिंहदेव :- अगर कार्यवाही करने की आवश्यकता होती तो जरूर कार्यवाही करेंगे।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय सभापति जी, मेरा निवेदन है कि यह प्रदेश के स्वास्थ्य का मामला है। प्रथम दृष्टि में जो लैब था, जो लैब ने पास कर दिया और बाद में अमानक पाया गया, उस लैब के ऊपर कार्यवाही करेंगे ?

श्री टी.एस. सिंहदेव :- माननीय सभापति जी, लैब का दोष नहीं है। फरवरी में पहला टेस्ट हुआ, सितंबर में दूसरा टेस्ट हुआ, उतने अंतराल के बाद, उनके कारगरता या उनकी ईमानदारी पर कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। तो बैच बाद में गया, उसमें वह जो अंतर आया है और वह भी कोई ऐसा दुष्परिणाम नहीं था, उसकी एफिसी कम थी, तब माना गया।

सभापति महोदय :- पर्याप्त चर्चा हो चुकी है। माननीय देवव्रत सिंह जी ।

अशोधित/प्रकाशन हेतु नहीं

(3) जिला राजनांदगांव के विकासखण्ड छुईखदान अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों में गुणवत्ताहीन रेडी-टू-ईट खाद्य सामग्री का वितरण किया जाना ।

श्री देवव्रत सिंह (खैरागढ़) :- माननीय सभापति महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है :- राज्य शासन द्वारा जिला राजनांदगांव के विकासखंड-छुईखदान के अंतर्गत छुईखदान, साल्हेवारा, पैलीमेटा एवं गंडई परिक्षेत्र के आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के लिए पौष्टिक पोषक आहार सामग्री रेडी-टू-ईट का वितरण किया जा रहा है, किंतु प्रभारी परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास, छुईखदान के चलते उक्त परिक्षेत्रों में गुणवत्ताहीन रेडी-टू-ईट खाद्य सामग्री का वितरण किया जा रहा है, इसकी शिकायत स्थानीय ग्रामीण जनप्रतिनिधियों ने जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत में की है, जिस पर कोई समुचित कार्यवाही नहीं की गई है । विकासखंड-छुईखदान के अंतर्गत छुईखदान, साल्हेवारा, पैलीमेटा एवं गंडई परिक्षेत्र के आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के लिए पौष्टिक पोषक आहार के स्तरहीन व गुणवत्ताहीन खाद्य सामग्री के वितरण से बच्चों में अपचन एवं उल्टी की शिकायतें हुई है, इस स्तरहीन व गुणवत्ताहीन रेडी-टू-ईट खाद्य सामग्री के वितरण की शिकायतों पर बिना जांच कराए रेडी-टू-ईट खाद्य सामग्री की आपूर्ति कराई जा रही है जिससे स्थानीय ग्रामीण जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणजनों में काफी रोष व्याप्त है ।

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती अनिला भेंडिया) :- माननीय सभापति महोदय, यह कथन सही नहीं है कि जिला राजनांदगांव के विकासखंड-छुईखदान के अंतर्गत छुईखदान, साल्हेवारा, पैलीमेटा एवं गंडई परिक्षेत्र के आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के लिए पौष्टिक पोषक आहार सामग्री रेडी टू ईट का वितरण किया जा रहा है किंतु यह कहना सही नहीं है कि उक्त परिक्षेत्रों में गुणवत्ताहीन सामग्री का वितरण किया जा रहा है । इस वित्तीय वर्ष में प्रेषित नमूनों में से कोई भी नमूना अमानक नहीं पाया गया । रेडी टू ईट की गुणवत्ता के संबंध में स्थानीय ग्रामीण जनप्रतिनिधियों द्वारा जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत में किसी प्रकार की शिकायत नहीं की गई है । यह सही नहीं है कि विकासखंड छुईखदान के अंतर्गत छुईखदान, साल्हेवारा, पैलीमेटा एवं गंडई परिक्षेत्र के आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के लिए पौष्टिक पोषक आहार स्तरहीन व गुणवत्ताहीन खाद्य सामग्री के वितरण से बच्चों में अपचन एवं उल्टी की शिकायतें हुई है । यह कहना भी सही नहीं है कि स्तरहीन व गुणवत्ताहीन रेडी टू ईट खाद्य सामग्री के वितरण की शिकायतों पर बिना जांच कराए रेडी टू ईट खाद्य सामग्री की आपूर्ति करायी जा रही है । स्तरहीन व गुणवत्ताहीन रेडी टू ईट वितरण की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है । प्रभारी परियोजना अधिकारी के द्वारा नियमित रूप से रेडी टू ईट का नमूना विश्लेषण हेतु प्रेषित किया जा रहा है । अत: जिले में कहीं भी स्थानीय ग्रामीण जनप्रतिनिधियों व ग्रामीणजनों में रोष व्याप्त होने की स्थिति नहीं है ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री देवव्रत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को पहले तो यह बताना चाहूंगा कि छुईखदान में महिला बाल विकास विभाग में परियोजना अधिकारी का पद तो विगत् लगभग ढ़ाई साल से रिक्त पड़ा हुआ है और अभी वर्तमान में जो प्रभारी हैं, वह राजनांदगांव से आना-जाना करते हैं । तत्कालीन में वहां पर एक प्रभारी पर्यवेक्षक को जिम्मेदारी दी गई है, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि प्रभारी पर्यवेक्षक जो कि पूरा ब्लॉक और विकासखण्ड के प्रभार पर है, वे कितनी बार साल्हेवारा या पैलीमेटा जो कि वनांचल नक्सलाईट प्रभावित क्षेत्र है । जो प्रभारी पर्यवेक्षक हैं उन्होंने कितनी बार वहां जाकर नमूनों का संकलन किया ? क्योंकि विभागीय रूप से जनपद पंचायत और जिला पंचायत दोनों में यह मामला उठा और दोनों में ही यही जवाब दिया गया कि भविष्य में हम नमूना का संकलन करेंगे तो मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि चूंकि वहां पर परियोजना अधिकारी तो है नहीं तो जो सरस्वती बघेल जी प्रभारी पर्यवेक्षक हैं उन्होंने कितनी बार इस पूरे वनांचल क्षेत्र में जाकर नमूनों का संकलन किया क्योंकि यही जवाब जनपद पंचायत और जिला पंचायत की बैठकों में भी दिया गया कि नमूना संकलन करेंगे ।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- माननीय सभापति महोदय, हर महीने सामग्री के विश्लेषण के लिये भेजा जाता है लेकिन बाहर भेजना रहता है करके एक-साथ एकत्रित करके ही भेजा जाता है और रिपोर्ट भी जल्दी नहीं आ पाती है इसलिए इस तरह की समस्याएं होती हैं, वैसे हर महीने विश्लेषण के लिये जाता है, भले ही रिपोर्ट लेट आती है ।

श्री देवव्रत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से केवल एक आग्रह करना चाहूंगा कि चूंकि वनांचल नक्सलाईट प्रभावित क्षेत्र है । जिला पंचायत के, जनपद पंचायत या महिला बाल विकास के जो जिले के अधिकारी हैं, उनकी एक 3 लोगों की टीम बनाकर क्या रेडी टू ईट का जो भी वितरण किया जा रहा है जो खाने के लिये दिया जाता है क्या उसके स्थल पर जाकर जहां निर्माण होता है, क्या उसकी एक-बार जांच करायेंगे ?

श्रीमती अनिला भेंडिया :- अगर ऐसी आपकी कोई समूह की या कोई जगह की रेडी टू ईट की शिकायत है तो जरूर हम अपनी समिति बनाकर जांच करा देंगे ।

समय :

12:45 बजे

<u>नियम 267-क के अधीन विषय</u>

सभापति महोदय :- निम्नलिखित सदस्यों की शून्यकाल की सूचना सदन में पढ़ी हुई मानी जाएंगी तथा इन्हें उत्तर के लिए संबंधित विभाग को भेजा जाएगा -

1 श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू

2 श्री धनेन्द्र साहू

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

3 डॉ. लक्ष्मी ध्रुव

4 श्री संतराम नेताम

5 श्री अरूण वोरा

अनुपस्थिति की अनुज्ञा

श्रीमती देवती कर्मा, निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-88 दंतेवाड़ा की सदस्य

सभापति महोदय :- निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-88 दंतेवाड़ा की सदस्य श्रीमती देवती कर्मा, द्वारा फरवरी-मार्च 2021 सत्र में दिनांक 24 फरवरी से दिनांक 4 मार्च 2021 तक सभा की बैठकों में अनुपस्थित रहने की सूचना दी गई है । उनका आवेदन इस प्रकार है -

मुझे दिनांक 24 फरवरी, 2021 से दिनांक 4 मार्च, 2021 तक मेरे निजी अत्यावश्यक कार्यों से अपने गृह ग्राम फरसपाल जिला दंतेवाड़ा में उपस्थित रहना आवश्यक है ।

अत: मैं उपरोक्त अवधि में विधान सभा सत्र की कार्यवाही में सम्मिलित होने में असमर्थ रहूंगी ।

उनके आवेदन के परिप्रेक्ष्य में क्या सदन की इच्छा है कि निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-88, दंतेवाड़ा की सदस्या, श्रीमती देवती कर्मा को दिनांक 24 फरवरी, 2021 से दिनांक 4 मार्च, 2021 तक सभा की बैठकों में अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा दी जाय।

अनुज्ञा प्रदान की गई ।

समय :

12:47 बजे **लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति तथा स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखा समिति के लिये नौ-नौ सदस्यों का निर्वाचन**

संसदीय कार्यमंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि - सभा के सदस्यगण, विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 221 के उप नियम (3), नियम 223 के उप नियम (2), नियम 223-ख के उपनियम (1) तथा नियम 223-ग के उप नियम (2) की अपेक्षानुसार लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति तथा स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखा समिति के लिए वित्तीय वर्ष 2021-2022 की अवधि के लिए अपने में से क्रमश: नौ-नौ सदस्यों के निर्वाचन के लिए अग्रसर हों ।

सभापति महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

प्रश्न यह है कि सभा के सदस्यगण, विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 221 के उप नियम (3), नियम 223 के उप नियम (2), नियम 223-ख के उपनियम (1) तथा नियम 223-ग के उप नियम (2) की अपेक्षानुसार लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति तथा स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखा समिति के लिए वित्तीय वर्ष 2021-2022 की अवधि के लिए अपने में से क्रमश: नौ-नौ सदस्यों के निर्वाचन के लिए अग्रसर हों ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

<u>अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिए 09 माननीय सदस्यों का निर्वाचन.</u>

संसदीय कार्यमंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि - सभा के सदस्यगण विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 234-ख के उप नियम (1) की अपेक्षानुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिए वर्ष 2021-2022 की अवधि के लिये अपने में से नौ सदस्य, जिनमें से क्रमश: तीन-तीन सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा शासन द्वारा अधिसूचित पिछड़े वर्ग के होंगे, निर्वाचन के लिए अग्रसर हों ।

सभापति महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

प्रश्न यह है कि - सभा के सदस्यगण विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 234-ख के उप नियम (1) की अपेक्षानुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिए वर्ष 2021-2022 की अवधि के लिये अपने में से नौ सदस्य, जिनमें से क्रमश: तीन-तीन सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा शासन द्वारा अधिसूचित पिछड़े वर्ग के होंगे, निर्वाचन के लिए अग्रसर हों ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, क्या है वे 9-9 सदस्य में चुनकर आ जाते हैं, लेकिन जो दल चुन नहीं पाते वे पूरे वंचित 5 साल के लिए हो जायेंगे, उसमें कोई मार्ग प्रशस्त होना चाहिए कि उनमें से भी एकाक कोई सदस्य उसमें रहना चाहिए। ऐसा कोई मार्ग प्रशस्त हो तो अच्छा रहेगा।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सभापति महोदय :- चलिए, देखेंगे। लोक लेखा, प्राक्कलन, सरकार उपक्रमों संबंधी, स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखा एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति में वर्ष 2021-22 की अवधि हेतु क्रमश: नौ-नौ सदस्यों के निर्वाचन का कार्यक्रम इस प्रकार निर्धारित किया जाता है :-

1. नाम निर्देशन प्रपत्र विधानसभा सचिवालय में सोमवार, दिनांक 8 मार्च, 2021 को अपरान्ह 4:00 बजे तक दिये जा सकते हैं।
2. नाम निर्देशन प्रपत्रों की संवीक्षा मंगलवार, दिनांक 9 मार्च, 2021 को अपरान्ह 1:30 बजे से विधानसभा भवन स्थित समिति कक्ष क्रमांक-दो में होगी।
3. उम्मीदवारी से नाम वापस लेने की सूचना शुक्रवार दिनांक 12 मार्च, 2021 को अपरान्ह 1:30 बजे तक विधानसभा सचिवालय में दी जा सकती है।
4. निर्वाचन यदि आवश्यक हुआ तो मतदान सोमवार, दिनांक 15 मार्च, 2021 को प्रात: 11:00 बजे से अपरान्ह 4:00 बजे तक विधानसभा भवन स्थित समिति कक्ष क्रमांक-2 में होगा।

निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाएगा।

उपर्युक्त निर्वाचनों में अभ्यर्थियों के नाम प्रस्तावित करने के प्रपत्र एवं नाम वापस लेने की सूचना देने के प्रपत्र विधानसभा सचिवालय स्थित सूचना कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं।

समय :
12.52 बजे **(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए)**

सदन को सूचना

अध्यक्ष महोदय :- वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा प्रारंभ होनी है। उसके पहले मैं बता दूं कि आज भोजनावकाश नहीं होगा। मैं समझता हूं कि सदन सहमत है।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई)

अध्यक्ष महोदय :- भोजन की व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से माननीय सदस्यों के लिए लॉबी स्थित कक्ष में एवं पत्रकारों के लिए प्रथम तल पर की गई है। कृपया सुविधानुसार भोजन ग्रहण करें।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

समय :

12.53 बजे **वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा**

अध्यक्ष महोदय :- अब वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा होगी। डॉ. रमन सिंह जी चर्चा प्रारंभ करेंगे। (मेजों की थपथपाहट)

डॉ. रमन सिंह (राजनांदगांव) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के..।

श्रम मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- डॉ. साहब बटन दबा दे न।

डॉ. रमन सिंह :- मुख्य बजट पर अनुमान पर सामान्य चर्चा के लिए खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री ने कल अपने बजट में जिस ऊंचाई (HEIGHT) का उल्लेख किया, दरअसल में उनके सलाहकार, उनके अधिकारियों द्वारा भ्रम में रखने वाली ऊंचाई (HEIGHT) है। जबकि राज्य की जनता ने उस ऊंचाई (HEIGHT) को असली अर्थ में समझा है। HEIGHT का छत्तीसगढ़ की जनता ने असली मतलब क्या निकाला कि HEIGHT के H से होता है hollow जो पूरी तरह खोखला बजट है। जनता के कल्याण राज्य के आर्थिक विकास से पूरी तरीके से मौन है। E से exclusionary इसका मतलब है प्रदेश के बड़े वर्ग को यह बजट गरीब, युवा, बेरोजगार, महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए सारे प्रावधान से यह अछूता है। तीसरा I HEIGHT का impact, यह बजट भाषण मुख्यमंत्री ने न केवल पिछले बजट के आंकड़ों को बदलकर पेश किया है, सरकार की नीति कार्य योजना का अभाव इस बजट में दिखाई दे रहा है। यह बजट शरीर से सुंदर, लेकिन मन आत्मा जिसमें नदारद है। G से governance guilt यह बजट सरकार के प्रशासनिक व्यय के बढ़ते भार का पोल खोलता है, जो वित्तीय अनुशासन प्रदेश में पहले वित्त मंत्री स्व. रामचन्द्र सिंहदेव साहब ने बनाया था, उसकी पार्टी की ही सरकार उसे पूरे तरीके से भंग कर रही है। प्रशासनिक खर्च बढ़ रहा है और उसके साथ ही साथ भ्रष्टाचार से आम जनता परेशान है। H HEIGHT का जो महत्वपूर्ण हिस्सा है horror, यह प्रस्तुत बजट अब डराने वाला है । सरकार की राजकोषीय स्थिति बेकाबू होती दिख रही है । ऐसे में जल्दी ऐसी स्थिति आएगी कि सरकार के पास अपने कर्मचारियों-अधिकारियों के वेतन देने के पैसे भी उपलब्ध नहीं रहेंगे । जनकल्याण विकास की योजनाओं पर इसका असर पड़ेगा । टी-टैरेबल, वेरी अनप्लीजेंट । यह बजट किसी वर्ग को संतुष्ट करने वाला नहीं है । किसानों को चुनावी घोषणा-पत्र के वादे का लाभ नहीं मिला, बेरोजगार युवकों के साथ धोखा हो रहा है, शराब बंदी के वादे को भूलकर शराब की आमदनी से यह सरकार चल रही है। यह है-हाईट, जो इस बजट में जनता ने समझा है । अधिकारियों ने जिस हाइट को प्रस्तुत किया और जनता ने जिस हाईट को जाना है, उसमें बहुत फर्क है । मुख्यमंत्री जी द्वारा कल सदन में जो 2021-22 का बजट भाषण में **गढ़बो नवा छत्तीसगढ़** के दावे के साथ यह बजट प्रस्तुत

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

किया । सरकार कैसे नया छत्तीसगढ़ बना रही है । इसकी बानकी यह है कि सरकार के पहले के तीन बजट के वित्तीय घाटे में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है । पहले बजट में वित्तीय घाटा 10,881 करोड़ था, दूसरे बजट में वित्तीय घाटा 11,518 करोड़ और तीसरे बजट में रिकार्ड तोड़ 17,461 करोड़ का वित्तीय घाटा अनुमानित किया गया है । बीते दो साल के बजट में अनुमानित या वित्तीय घाटा महज अनुमान नहीं है, बल्कि वास्तव में ऐसे हुआ है कि 2019-20 में वास्तविक घाटा बहुत अधिक है । यह आंकड़े प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है । 2019-20 का वास्तविक घाटा 17,970 करोड़, 2020-21 का पुनरीक्षित वित्तीय घाटा 22,838 करोड़ है। इसका मतलब यह है कि बजट में वित्तीय घाटे के अनुमान से ज्यादा घाटा साल दर साल वास्तव में हो रहा है, यह अत्यंत चिंताजनक है । इसका मतलब एक ही है कि सरकार की आमदनी अठन्नी, खर्च रूपैया से ज्यादा होता जा रहा है । अध्यक्ष महोदय, इसकी तुलना जब पिछली सरकार से करते हैं तो यह दो साल की स्थिति है और उसके पहले 15 सालों में हम लोगों ने वित्तीय प्रबंधन को बेहतर बनाकर कैसे रखा । 15 वर्ष में एक वर्ष भी बता दीजिए, जब हमारे बजट में अनुमानित वित्तीय घाटा उस वर्ष के वास्तविक आय-व्ययक के आंकड़ों के अनुमान से ज्यादा हो । इसका मतलब यह है कि हमने 15 साल बजट के आंकड़ों की विश्वसनीयता को सार्थक बनाया । जब हमने सदन में बजट प्रस्तुत किया तो उसे उस पूरे वर्ष पूरी ईमानदारी के साथ साकार किया । इसका मतलब यह भी है कि हमने कड़े अनुशासन वित्तीय अनुशासन, राजस्व में लगातार बढ़ोत्तरी कर बजट में अनुमानित घाटे को एफ.ओ.आर.बी.एम. एक्ट की निर्धारित सीमा के भीतर रखा । इस सरकार को न तो सदन की चिन्ता है, न सदन में पारित एक्ट की चिन्ता है, न ही अपने बजट के आंकड़ों की विश्वसनीयता बना रख पायी है । इसका एक प्रमाण यह है कि इस साल अभी पिछले सत्र में एफ.ओ.आर.बी.एम. एक्ट में संशोधन करके 19-20 और 20-21 के लिए वित्तीय घाटे की सीमा 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत की थी । यह ठीक है कि 3 से 5 प्रतिशत हुआ, लेकिन 2019-20 के वास्तविक आंकड़े जो बजट में दिए गए हैं, उसके हिसाब से 2019-20 में वित्तीय घाटा 5 प्रतिशत से भी बढ़कर 5.21 प्रतिशत हो गया । एफ.ओ.आर.बी.एम. एक्ट की उस सीमा को, अंतिम सीमा को भी लांघ गए । इसका मतलब यह है कि सरकार एक्ट के संशोधन के बाद भी सदन में दिए गए वादों को नहीं निभा पाई है । यही हालत चालू वित्त वर्ष 20 और 21 में हो रहा है । 20-21 के पुनरीक्षित अनुमानों में जो वित्तीय घाटा जी.एस.डी.पी. के 6.52 प्रतिशत के बराबर रखा गया है । यह नया छत्तीसगढ़ बनने वाला है । यदि यह वित्तीय स्थिति छत्तीसगढ़ की बनी है, एफ.ओ.आर.बी.एम. एक्ट 3 से 5 प्रतिशत तक तो ठीक है, 6.52 प्रतिशत तक जी.एस.डी.पी. का वित्तीय घाटा होता है तो उस राज्य के बारे में कल्पना हो सकती है ।

अध्यक्ष महोदय, अब राजस्व घाटे की बात करूं । पिछले दो वर्षों में बजट में सरकार ने राजस्व आधिक्य का अनुमान रखा, ठीक है । 2019-20 में 1151 करोड़, 2021-21 में 2431 करोड़ का राजस्व

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

आधिक्य अनुमानित रखा गया और हुआ क्या ? वर्ष 2019-20 में 9609 करोड़ का राजस्व घाटा। क्या अनुमान रखते हैं ? क्या बजट में यह परिलक्षित होता है ? 9609 करोड़ का राजस्व घाटा और चालू वित्त वर्ष में 12 हजार का राजस्व घाटा होने की संभावना है। ये हमारी वित्तीय स्थिति है, जिसके बारे में बड़ी-बड़ी बातें होती हैं और यह वित्त घाटा है, जिस प्रकार सरकार खर्च बढ़ा रही है। आमदनी हर साल कम हो रही है, छत्तीसगढ़ नये आर्थिक संकट की ओर बढ़ रहा है। सरकार घाटे बढ़ाने की कीर्तिमान बना रही है। राज्य की विकास की प्रक्रिया करीब-करीब ठप्प हो चुकी है। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात सरकार के बजट में पूंजीगत व्यय की अनुमान की बात बताना चाहता हूं। किसी भी राज्य के बजट में यह व्यय सरकार की अधोसंरचना विकास में पूंजीगत व्यय के निर्माण राज्य की राजस्व आय में बढ़ोत्तरी के साथ-साथ बेरोजगारों के बड़े पैमानों पर कामों का सृजन करते हैं। इस सरकार ने पहले बजट वर्ष 2019-20 में पूंजीगत व्यय का अनुमान 12110 करोड़ था जो हमारी सरकार के समय प्रस्तुत वर्ष 2018-19 के बजट के अनुमान 14454 करोड़ से 16 प्रतिशत कम अनुमानित किया गया था। ये जब वर्ष 2018-19 का 2019-20 से तुलना करते हैं, यही 16 प्रतिशत कम है, वर्ष 2019-20 के वास्तविक व्यय के आंकड़े जो इस बजट में दिखाया गया है, उसके अनुसार 12110 करोड़ में से सरकार पूंजीगत व्यय पर केवल 8 हजार ही खर्च कर पाई। ये चिंता का विषय है। चिंता का विषय यह है कि आज जो खर्च करना था, वह खर्च भी नहीं कर पाई और इसमें 12 हजार करोड़ से पूंजीगत व्यय में केवल 8566 करोड़ ही खर्च कर पाई। वर्ष 2020-21 में पूंजीगत व्यय का अनुमान 13818 करोड़ को पुनरीक्षित अनुमान घटाकार 10680 करोड़ कर दिया गया है और जनवरी तक व्यय के आंकड़े के अनुमान में महज 6158 करोड़ है, यह छत्तीसगढ़ में पूंजीगत व्यय की स्थिति है। इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। अभी फरवरी मार्च के दो महीने को जोड़ दिया जाये, अधिकतम 1500 करोड़ रूपये की राशि और जोड़ दिया जाये तो इस वर्ष मात्र 7 हजार करोड़ के आंकड़े भी नहीं छू पायेंगे। 1 लाख करोड़ के बजट में 7 हजार करोड़ ही पूंजीगत व्यय में खर्च होगा। यानी जीरो बजटीग की स्थिति जो मध्यप्रदेश सरकार में थी, तनख्वाह देने के लिये, पेंशन देने के लिए बाकी कामों के लिये तो पैसा है, निर्माण और विकास कार्य के लिये पूरे काम ठप्प हो जायेंगे। पी.डब्ल्यू.डी डिपार्टमेंट की जो स्थिति थी, एरिगेशन की स्थिति थी, वही जीरो बजट की स्थिति छत्तीसगढ़ में सामने दिख रहा है। जब इतने बड़े बजट में सिर्फ और सिर्फ पूंजीगत व्यय 7 हजार करोड़ को नहीं छू पायेगा। पूंजीगत व्यय लगातार कम हो रहा है। इसलिए सरकार की आय और प्रति व्यक्ति आय भी कम होगी। जब पूंजीगत व्यय में investment कम होगा, जब infrastructure का काम कम होगा तो छत्तीसगढ़ के सरकार के विकास की संभावनाओं पर अंकुश लग जायेगा। जब बजट में प्रति व्यक्ति आमदनी कम दिखाई देने लगता है, इसका बड़ा साफ-साफ इंडीकेटर है कि पूंजीगत व्यय में इतना खर्चा राजस्व मद मे हो गया कि पूरा का पूरा बजट एक दिशा में जा रही है। जहां पर निर्माण और विकास कार्य होना चाहिए वह शून्य होता जा रहा है। इस स्थिति की वजह से सरकार की प्रति

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

व्यक्ति आय में कमी हो रही है। हमारे कार्यकाल के आखिरी पूर्ण वित्तीय वर्ष 2017-18 में यह व्यय 10 हजार करोड़ तक पहुंच गया था। वर्ष 2018-19 में भी अप्रैल-मई में लोकसभा चुनाव आचार संहिता और फिर अक्टूबर-नंवबर में राज्य विधानसभा के चुनाव आचार संहिता के बाद 17 दिसंबर तक 5500 करोड़ तक पहुंच गया था। उस वर्ष भी इस सरकार के आते ही निर्माण कार्य में रोक नहीं लगाई होती तो यह 10 हजार करोड़ पार कर जाता। लेकिन इस सरकार ने वित्तीय प्रबंधन, पूंजी निर्माण, राजस्व आय में वृद्धि और रोजगार बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण विकासात्मक कार्यों पर रूचि नहीं दिखाई। अध्यक्ष महोदय, 15 वर्ष के कार्यकाल में अधोसंरचना निर्माण हेतु पूंजीगत व्यय पर राज्य सरकार राज्य की आय से लगभग 70 हजार करोड़ का वास्तविक व्यय हुआ था और इसमें हमने 40 हजार करोड़ राज्य के राजस्व से किये थे। यह महत्वपूर्ण विषय है कि 70 हजार करोड़ जो खर्च हुआ, उसमें 40 हजार करोड़ राज्य के राजस्व से व्यय हुए, जबकि अगर हम पूंजीगत खर्चों के लिए ज्यादा कर्ज भी लेते तो राज्य के इतने बड़े राजस्व और वित्तीय घाटे का सामना नहीं करता, जो इस कार्यकाल में इस प्रकार से हो रहा है। इसी सत्र के दौरान सदन में पूछे गये एक प्रश्न के उत्तर में सरकार से जानकारी मिली है कि 16 दिसम्बर, 2018 की स्थिति में राज्य सरकार पर 41,695 करोड़ का कर्ज था। यह सन् 2018 की स्थिति में है। जब राज्य सरकार के पास 16 दिसम्बर की स्थिति में 41 हजार का कर्ज है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 7 दिसम्बर 2003 की स्थिति में राज्य में पहली बार हमारी सरकार बनी थी, तब राज्य पर 8,660 करोड़ कर्ज हमें विरासत में मिला था। जो हमें विरासत में कर्ज मिला था, उसमें 8,660 करोड़ का कर्ज था। हमने 15 वर्ष के कार्यकाल में केवल 33 हजार करोड़ का ही कर्ज लिया था। यह तुलनात्मक अध्ययन है। जब 15 साल और 2 साल की तुलना होती है तो पूरी दुनिया आश्चर्यचकित हो जाती है कि हमने 15 साल में 33 हजार करोड़ कर्ज लिया, जो कि पूर्णत: छत्तीसगढ़ के सड़क, सिंचाई, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के बड़े पैमाने पर अधोसरंचना निर्माण और विकास के लिए खर्च किया।

अध्यक्ष महोदय, जब हमने राज्य की बागडोर संभाली थी, राज्य का बजट का आकार 9,270 करोड़ का था, वित्तीय घाटा 1,923 करोड़ का था, जो कि राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 5.4 प्रतिशत था। हमने वर्ष 2005 से ही बेहतर वित्तीय प्रबंधन और अनुशासन के लिए राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम बनाया है, FRBM एक्ट बनाया। जिसमें राजस्व घाटा शून्य, वित्तीय घाटा जी.एस.डी.पी. के 3 प्रतिशत तक सीमित रखने का प्रावधान किया। हमने 15 वर्ष के कार्यकाल में इसका कड़ाई से पालन किया। इन दोनों चीजों का राज्य सरकार ने पालन किया था। वह चाहे जी.एस.डी.पी. के 3 प्रतिशत के राजस्व घाटा का हो या वित्तीय घाटा का हो, 15 वर्ष के कार्यकाल में पालन करने के साथ छत्तीसगढ़ ने बेहतर वित्तीय व्यवस्था के लिए देश में अग्रणी स्थान बनाया। छत्तीसगढ़ की पहचान बनी थी।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय, अब इस सरकार की बात है। जब हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो इसके लिए मैंने थोड़ी सी भूमिका रखी। उस भूमिका के आधार पर मैं यह बताना चाहता हूं कि आज यहां राज्य सरकार की जो स्थिति दिख रही है, उसमें 26 महीने के कार्यकाल में राज्य पर कर्ज बढ़कर 71 हजार करोड़ से ज्यादा हो गया है। सरकार केवल 26 महीनों में 30 हजार करोड़ से अधिक का कर्ज ले चुकी है। 26 महीने में 30 हजार करोड़ का कर्ज, हर महीने एक हजार करोड़ के एवरेज कर्ज से ऊपर चल रहे हैं। अर्थात् सरकार औसतन महीने में हजार करोड़ रूपये के कर्ज ले रही है और कर्ज केवल राजस्व व्यय को बढ़ा रही है। इसमें न तो पूंजी का निर्माण हो रहा है, न रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं, न प्रति व्यक्ति आमदनी बढ़ रही है, बल्कि कम हो रही है। अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार पर आरोप लगाया जाता है, लेकिन हर वर्ष अधिक से अधिक राशि केन्द्र सरकार से छत्तीसगढ़ को प्राप्त हो रहा है। नीतिगत फैसले लिए गए। केन्द्र सरकार ने निर्णय लिया और न केवल छत्तीसगढ़, बल्कि हिन्दुस्तान के सभी राज्यों के लिए निर्णय हुआ। उसका असर यह हुआ कि वर्ष 2019-20 में भी छत्तीसगढ़ को 40 हजार करोड़ और वर्ष 2020-21 में अभी तक 25 हजार करोड़ की राशि मिल गई है, जो राज्य के कुल आय का 61 प्रतिशत से अधिक है। केन्द्र से मिलने वाली राशि 61 प्रतिशत है, यानि राज्य का कुल राजस्व 39 प्रतिशत है। इसका मतलब केन्द्र सरकार से मिलने वाला 61 प्रतिशत भाग एक बड़ा योगदान छत्तीसगढ़ के विकास के लिए है। इससे यह साबित होता है कि राज्य अपना आय बढ़ाने में विफल रहा है। सालों से वित्तीय कुप्रबंधन का मिसाल कायम रखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ को ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया है कि राज्य अपनी आय से कमिटेड व्यय ज्यादा कर रही है। आज हमारे राज्य की स्थिति यह बन रही है। बड़े-बड़े पेपरों में छपवा देने से बजट अच्छा नहीं हो जाता है। बड़े-बड़े पेपरों में दे देने से यह देखा जाता है, विशेषज्ञ यह देखते हैं कि राज्य की आय से कमीटेड व्यय क्या है ? कितना वेतन, कितना पेंशन, कितना कर्ज, कितना ब्याज भुगतान आदि ही हो पा रहा है। यानि राजस्व राज्य की अपनी आय से अलग रख दें और उसका हिसाब लगायें तो क्या राज्य की अपनी आय से वेतन, पेंशन, कर्ज, ब्याज भुगतान हो पायेगा? नहीं हो पाएगा। यह स्थिति है। राज्य की राजस्व स्थिति ऐसी है कि वह अपने राजस्व से नहीं कर सकता। जो भी होगा केंद्र सरकार से होगा। अगर वेतन, पेंशन, ब्याज, मूलधन के खर्चों की बात करें तो सरकार अपनी आय से यह खर्च पूरा नहीं कर पा रही है। राज्य के गैर विकासात्मक खर्च लगातार बढ़ रहे हैं। विकासमूलक कार्यों के खर्च पर लगातार कमी हो रही है। अध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने कर्ज लेने का एक और तरीका अपनाया है। छत्तीसगढ़ में कर्ज लेने के नए-नए तरीके ईजाद किए जा रहे हैं और छत्तीसगढ़ ही ऐसा राज्य है जिसने बजट पर सीधे तौर पर वह कर्ज बताने की जरूरत न पड़े, वह है सरकार की गारंटी देकर धान खरीदी से लेकर केंद्रीय योजनाओं के राज्यांश तक की व्यवस्था के लिए बैंकों से कर्ज लिया जाता है। बीते दो साल में सरकार की गारंटी में बहुत तेजी से बढ़ोत्तरी हुई है। वर्ष 2018-19 में 5535 करोड़ थी, अब बढ़कर 33 हजार करोड़ से ज्यादा

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

हो गई है। अब तक ये सरकार जब हम सरकार में थे तो धान खरीदी के लिए हमने मार्कफेड को एक रूपये की गारंटी नहीं दी। अध्यक्ष महोदय, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी सरकार से जब तुलना होगी तो इस बात की भी चर्चा होगी कि क्या उस समय हमने मार्कफेड को गारंटी दी थी तो हमने एक रूपये की भी गारंटी नहीं दी थी और रिजर्व बैंक से कैश क्रेडिट लिमिट पर धान खरीदी की पूरी व्यवस्था 15 साल तक की थी, लेकिन इनका दो साल में सांस फूल रही है। 15 साल तक हमने बिना किसी प्रकार के मार्कफेड से एक रूपये की गारंटी लिये रिजर्व बैंक से ही जो कैश क्रेडिट लिमिट है उस पर धान खरीदी की व्यवस्था की। अगर सरकार द्वारा बीते दो साल में दी गई गारंटी पर नजर डालें तो पता चलता है कि मार्कफेड, नॉन, विद्युत कंपनी से लेकर सड़क विकास निगम तक सबके माध्यम से कर्ज लिया जा रहा है। इनके सबके माध्यम से कर्ज लिया जा रहा है। इसमें मार्कफेड हो, नॉन हो, विद्युत कंपनी हो, सड़क निर्माण विकास निगम हो, सरकार इसके ब्याज और मूलधन का भुगतान कर रही है। इतनी बड़ी मात्रा में गारंटी पर कर्ज लेने से सरकार की देनदारियां तेजी से बढ़ रही हैं और छत्तीसगढ़ कर्ज में डूबता जा रहा है। पहले केंद्र सरकार में इनके यू.पी.ए. की सरकार के 10 वर्षों में इन्होंने रोजगार क्या दिया था? गड्ढे खोदने का रोजगार दिया। अब छत्तीसगढ़ के लोगों को गोबर बेचने का रोजगार दे रहे हैं। गोबर बेचकर मोटरसाईकिल खरीद लिया, गोबर बेचकर रोजगार हो गया। एक समय था जब गड्ढे खोदकर रोजगार दिया जाता था और अब छत्तीसगढ़ में गोबर बेचकर रोजगार दिया जा रहा है। इन लोगों की कभी मंशा नहीं रही कि इस देश और प्रदेश का विकास हो, अच्छी सड़कें बनें, नई रेल लाईन बने, बिजली की प्रचुर मात्रा में आपूर्ति हो, सिंचाई के संसाधनों का विकास हो, गांव की पक्की सड़क बने, रसोई गैस से अच्छे स्वास्थ्य की सुविधा मिले, रोजगार के अवसर हों। इस तरीके के काम पूरी तरह से रूक गये हैं। ये लोग झुनझुना पकड़ाने का काम करते हैं। गरीबी हटाओ से लेकर गड्ढे खोदने और गोबर बेचने को ही रोजगार समझा जा रहा है। ये चाहते हैं कि गांव के लोगों को गरीब ही रखा जाए। आदिवासी लोगों को भावनात्मक रूप से पारंपरिक कला और संस्कृति के नाम से अजायबघर में सजाने वाला बनाकर रखा जाए। अच्छी शिक्षा रोजगार के जरिये विकास की मूल धारा में न आने दिया जाए।

श्री कवासी लखमा :- अध्यक्ष जी, हम लोग गोबर बेचकर गरीब लोगों को रोजगार दे रहे हैं, हमारे मोदी साहब क्या बोलते हैं कि पकौड़ा बेचो। ये कौन सा अच्छा है।

डॉ. रमन सिंह :- अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रयास विद्यालयों, गुरूकुल उन्नयन योजना, आवासीय आश्रम शालाओं से लेकर दिल्ली के द्वारका में आदिवासी बालक हॉस्टल तक सही मायने में विकास और कल्याण के लिए काम किया था, जिसे सरकार ने पीछे ढकेल दिया है। ये जो बजट का कुल प्रस्तुत किया गया है इसमें से कुछ बातें मैं अलग से प्रस्तुत करना चाहता हूं कि बजट का जो इम्पैक्ट मुख्यमंत्री जी के भाषण में आया और बजट की साईज जो है कि किसी साईज को बोनसाई बना देना। बोनसाई का मतलब है कि पूरे के पूरे वृक्ष को छोटे से वृक्ष में बदल देना। यह पिछले बजट का बोनसाई

बन गया है। जो अलग-अलग विभागों के लिए राशि का प्रावधान रखा जाता था कि पी.डब्ल्यू.डी. में हम सड़कों के निर्माण के लिए इतनी राशि करेंगे, खर्च करेंगे, इतना ब्रीज का निर्माण करेंगे, एरिगेशन के लिए हम इतने प्रोजेक्ट करेंगे, अलग-अलग विभागों के लिए अलग-अलग खर्च करेंगे। एक-एक लाईन में बजट में समाप्त कर दिया है।

श्री शिवरतन शर्मा :- क्या है डॉ. साहब। हमारे मुख्यमंत्री जी में बौना बनाने की क्षमता तो अद्भुत है। तो बजट बौना हो गया तो कौन सी बड़ी बात है। उनने तो कई लोगों को बौना बना दिया।

श्री भूपेश बघेल :- आपने बिल्कुल सही कहा। पिछले सत्र में जब रमन सिंह जी यहां थे तो अध्यक्ष महोदय, आखिरी भाषण निकालकर, सुन लीजिएगा। वह बोले थे कि यह चुनाव में जा रहे हैं अब यहां तक के हो, वह यहां और आप एक लाईन में सिमट जाओगे। तो आपने बोनसाई तो बना दिया। 15 सालों में 15 सीट पर आ गये और अब तो 14 सीटों में रह गये हैं। आप बोनसाई तो हुए।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय मुख्यमंत्री जी, उधर भी बहुत लोगों को बौना बना दिये, वे लोग कुछ बोल नहीं पा रहे हैं।

श्री भूपेश बघेल :- अब माननीय शिवरतन जी, आप अपने दर्द को क्यों कुरेदना चाहते हो ? आपकी तो चलती नहीं थी। उनको छोड़ दीजिए। आप और जो लोग हैं सदन में बहुत लोग तो आए ही नहीं। जो सदन में आ गये हैं उनकी कितनी चलती थी ? मंत्री को तो छोड़िए, केवल अधिकारी की चलती थी। यहां तो सारे मंत्रियों की चलती है, विधायकों की चलती है आप तो एक ट्रांसफर नहीं करा पाते थे, मंत्री ट्रासंफर नहीं करा पाते थे। यहां सारे लोग मिलकर, हम 70 लोग हैं हम सब मिलकर, सरकार चला रहे हैं।

डॉ. रमन सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब का भी समय आएगा। पर्याप्त समय रहता है। सारी बातें आ सकती हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बोनसाई को बोल रहा हूँ तो उसमें साईंस को देखकर कह रहा हूँ। हाईट को देखकर नहीं बोल रहा हूँ। हाईट की बात तो बहुत हो गई। मगर जब खोदा पहाड़ तो निकला क्या ? उसको देखने की बात नहीं है। कितना जा रहा है ? कितने काम के लिए कितना स्वीकृत हो रहा है ? बजट का साईज देखने से ही काम नहीं चलेगा। डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या खर्च हो रहा है ? यह बातें बजट में परिलक्षित होती हैं जिसको छुपाया नहीं जा सकता। यह छुपाने का प्रयास कैसे होता है उसके कुछ उदाहरण दूंगा। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में वर्ष 2020-21 में 1500 करोड़ का प्रावधान रखा है। योजना के क्रियान्वयन और कार्य निष्पादन मूल्यांकन में राष्ट्रीय सूचकांक तालिका में छत्तीसगढ़ को द्वितीय स्थान रखा गया है। यह देखिए। यह कमाल की बात है। हिन्दुस्तान में द्वितीय स्थान पाने वाले छत्तीसगढ़ की वास्तविक कहानी क्या है ? क्यों द्वितीय स्थान पाया ? छत्तीसगढ़ का टारगेट था कि वर्ष 2022 तक 19 लाख प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास बनाना था। वर्ष

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

2018-19 में अपने अंशदान में, जब छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार थी। मैचिंग ग्राण्ड के लिए 750 करोड़ से नाबार्ड में कर्ज लिया। यह वर्ष 2018-19 की बात है। उससे 1 लाख, 51 हजार की पहली किश्त प्राप्त हुई। राज्य सरकार का अंशदान आज तक जब वर्ष 2020-21 का टारगेट 6 लाख, 48 हजार आवास देने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार ने मंजूर कर लिया था। 1 लाख, 51 हजार के बाद प्रदेश सरकार का अंशदान गायब हो गया। जो बड़ा लक्ष्य 6 लाख, 48 हजार आवास देने का प्रस्ताव होने वाला था। आवास के पहले किश्त और दूसरे किश्त के बाद सारे काम बंद हो गये। कहीं भी आवास का एक भी काम नहीं हो रहा, दूसरा, तीसरा किश्त नया स्वीकृत लिस्ट जो वर्ष 2022 तक 19 लाख आवास बनाने का लक्ष्य था, वह लक्ष्य अलग हो गया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में वर्ष 2022 तक 11 लाख छत्तीसगढ़ में आवास बनाने थे। यह जो पुरस्कार की बात कर रहे हैं। यह वर्ष 2018-19 के अंशदान से किये गये कामों के लिए है। इनके कार्यकाल में तो जीरो काम है एक भी आवास को स्वीकृत नहीं किया गया। गरीबों के 19 लाख आवास बनने थे। एक बार उसमें 15 हजार स्वीकृत हो गए तो हो गए, उसके बाद क्या इस बजट में इतनी लाईन लिखने की अपेक्षा, यह लिख दिया जाता कि आने वाले समय में जो छत्तीसगढ़ में 11 लाख प्रधानमंत्री आवास बनना है उसके लिए हम मैचिंग ग्राण्ट की राशि उपलब्ध करवा देंगे, हम पैसा दे देंगे। यदि यह हो जाता तो छत्तीसगढ़ के जो गरीब लोग हैं, इधर के लोग जितने बैठे हैं सबके पास गांवों में आवेदन आता है हम लोग गांव जाते हैं हमारे साथी जाते हैं प्रधानमंत्री आवास में पहली किश्त, दूसरी किश्त के बाद तीसरी किश्त मांग रहे हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में जिनकी वेटिंग लिस्ट जारी हो गई थी, यह छोटा मोटा काम नहीं है। छत्तीसगढ़ के लोगों को 11 लाख छत देना है। सरकार बनने और बिगड़ने से मुझे और आपको फर्क नहीं पड़ता, मगर उस गरीब को क्या फर्क पड़ा है? उस गरीब को फर्क यह पड़ा है कि उसको छांव, आवास नहीं मिल रहा है और आने वाले 3 साल में नहीं मिलेगा। यह कितनी बड़ी-बड़ी फोटो खिचा लें, height बढ़ा लें, मगर जनता की निगाह में height कहां जा रही है, वह गरीब आदमी कितनी height देख रहा है, कितनी ऊंचाई तक पहुंचाने का काम हो रहा है। उस गरीब के झोपड़े में यदि आपने मकान बनाने की योजना टाल दी और 11 लाख, 22 लाख परिवारों को आवास के लिए पैसा नहीं दिया, यह ब्लंडर है। इतनी बड़ी गलती है, इस गलती को स्वीकार करना चाहिए। इसके लिए यदि कर्ज लेते हैं, नाबार्ड से लें, कहीं से ले लें, किसी बैंक से ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ता।

श्री अजय चन्द्राकर :- हम लोग समर्थन कर देते।

डॉ. रमन सिंह :- हम सबमें समर्थन करते, गरीबों के आवास का कौन विरोध कर सकता है। हम सब चाहते हैं कि इस योजना का लाभ गरीबों को मिले और बेहतर तरीके से काम हो। मगर इस बजट में उसको छुआ नहीं गया है। सिर्फ ये वाहवाही लूट ली गई कि आपको राष्ट्रीय स्तर में पदक मिला है। ऐसे बहुत पदक मिले हैं, इनके ऊपर बहुत सारे तमगे कंधे में लटक रहे हैं जिस पर ये काम हो रहा है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

माननीय अध्यक्ष महोदय, सड़क के लिए बड़ी-बड़ी बातें हुईं। मैं बजट भाषण में बड़ी उम्मीद के साथ पढ़ रहा था, 5 हजार 225 करोड़ की लागत से 3 हजार 900 किलोमीटर लंबी सड़कों एवं पुल पुलिया का निर्माण कार्य किया जायेगा। उसके आगे की लाईन पढ़ेगे। इन कार्यों के लिये निगम को सहायता देने हेतु बजट में 150 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है। 5,225 करोड़ के खर्चे के लिए 150 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। यदि इसी को हम आगे बढ़ाते रहे तो क्या 5 साल, 10 साल में उन रोड़ो के लिए पैसा मिलेगा ? 5,225 करोड़ रुपये को ही आने वाले समय में यदि आप सड़क निर्माण के लिए जोड़ेंगे तो इस प्रकार के बजट प्रावधान से यह सड़कें कैसे बन पायेंगी ? बोनसाई कहने का मतलब यही होता है कि आपने बड़े-बड़े काम के लक्ष्य रख लिये, लक्ष्य को पूर्ति करने के लिए बजट में जो प्रावधान होना चाहिए, यदि वह समुचित नहीं है तो बजट को टारगेट कैसे करेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, उसी प्रकार मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना के लिए बजट में 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। एशियन डेवलपमेंट की सहायता से फेज-3 परियोजना का कार्य प्रगति पर है। फेस-1 और फेस-2 हमने शुरू किया, फेस-3 की स्वीकृति भी हम लोगों के समय हो चुकी थी, यह फेस-3 उसी समय का काम है। जो थोड़ा-बहुत सड़क का निर्माण दिखेगा, यह फेस-3 का दिखेगा। उसी काम को हो सकता है कि आगे करें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सिंचाई के लिए मैं पिछले 3-4 बजट 2017-18, 2018-19, 2019-20 के पन्ने पलटा रहा था। कल खाली बैठा था, बजट देख रहा था। मैं यह देख रहा था कि पिछले बजट में किस-किस योजना में कितना-कितना पैसा दिया गया था। फिर याद आया केला परियोजना, अरपा-भैंसाझार, राजीव समोदा, निसदा व्यपवर्तन, सोढ़ूर जलाशय अन गोइंग प्रोजेक्ट कितने साल से चल रहे हैं, अरे एक बार इनको पूरा तो करो। जितने 70 प्रतिशत इनमें परियोजनाओं में काम हो चुका है, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए उन योजनाओं को टॉप प्रायरटी में लो। यह तो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट हैं, केनाल का चौड़ीकरण हो रहा है, केनाल का निर्माण हो रहा है, स्ट्रक्चर बन चुका है। सिंचाई की योजना को बढ़ाना है। आप बजट ला रहे हैं। यह विधायकों को बड़ी उम्मीद रहती है कि उनके गांव में सिंचाई की कोई योजना आ जायेगी, छोटे-मोटे प्रोजेक्ट हो जायेंगे। वही योजना हैं जो 5-8 साल से हमारे समय से चल रही हैं, उसी को पढ़कर बता दिया कि 203 करोड़ दे रहे हैं। अब यह 203 करोड़ में भी यह योजनायें आने वाले 10 साल में पूरी नही होंगी। कम से कम इसको तो पूरा करें। यह चार बृहद परियोजना के बारे में बड़ी-बड़ी बात है। 2021-22 के बजट में 203 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। अधूरी नाली का भी काम नहीं हो पायेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं ढूंढता रहा। यह सरकार का तीसरा बजट है, बस दो बजट और आयेगा। वापसी की तैयार हो जाती है। मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री के मुख्य सचिव महोदय जिनको हम घोषणा पत्र की कापी हाथ में देते हैं, सरकार बनते ही सबसे पहले काम मुख्यमंत्री जी करते हैं कि मुख्य सचिव को घोषणा पत्र की कापी दे देते हैं। राजा साहब उपस्थित नहीं हैं। जनघोषणा पत्र में बड़े-बड़े नारे

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

लगाकर उन्होंने दिया, क्या उसको कोई पलटाकर देखने वाला है? क्या उसको कोई पढ़ने वाला है ? क्या नवयुवकों के लिये जो रोजगार के अवसर 2500 रूपये देने की बात हुई थी, 2 साल का बोनस देने की बात हुई थी, गरीबों की बेहतरी के लिये वृद्धावस्था, विकलांग पेंशन, निराश्रित पेंशन की बात हुई थी इन सारी बातों को हम बजट में ढूंढ रहे थे । वह तो नहीं मिला, चूंकि इस बार बजट इतना बड़ा नहीं हो सकता था लेकिन इन सारी बातों को जो घोषणा पत्र में सम्मिलित है उन पूरे के पूरे मुद्दों को जो 36 मुद्दे तय किये हैं, आज मैं उन पूरे मुद्दों पर अलग-अलग से बात नहीं करूंगा । यह बात होती है कि छत्तीसगढ़ के सभी ब्लॉक लेवल में फूड पार्क स्थापित किये जायेंगे, 3 साल हो रहे हैं, तीसरा बजट है । मैं आज भाषण में पढ़ रहा था कि फूड पार्क के लिये तीसरे साल के बजट में जमीन चिन्हांकित किया जायेगा । अगले साल बाउंड्रीवाल होगा और उसके अगले साल फूड पार्क तक सड़क का निर्माण होगा, 5 साल तो निकल गये, उसके बाद फूड पार्क बनेगा । हर ब्लॉक में फूड पार्क, बहुत बड़ी-बड़ी घोषणा कि फूड पार्क हर ब्लॉक में बन जायेगा । अभी दो-ढ़ाई साल, 26-30 महीने हो गये । क्या फूड पार्क में एक पत्थर भी लगा है ? क्या एक फूड पार्क में ऐसे बाउंड्रीवाल का काम चालू हुआ है ? लेकिन घोषणा में आ जाता है कि हम फूड पार्क बनायेंगे और यह 5 साल चलते रहेगा ।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- डॉ. साहब आप 15 सालों तक जो कर नहीं पाये, उसकी शुरूआत करने की बात हो रही है तो आपको इतनी आपत्ति क्यों है?

डॉ. रमन सिंह :- महाराज, मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री रविन्द्र चौबे :- आपने दो-ढ़ाई साल कहा । दूसरा बजट और यह तीसरे साल का बजट और किन परिस्थितियों में आप ही उसको स्वीकार कर रहे हैं ?

डॉ. रमन सिंह :- मैं चाहता हूं कि करो । करिए, करना चाहिए ।

श्री रविन्द्र चौबे :- लेकिन जवाब भी देना चाहिए न कि हम 15 साल कुछ नहीं कर पाये ।

डॉ. रमन सिंह :- नहीं हो रहा है उसकी पीड़ा है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- आपने तो 5 साल में करने की बात की थी न ।

श्री रविन्द्र चौबे :- हां, हम करेंगे न । अभी शुरूआत की है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- 5 साल में करने वाले थे, 3 साल में जमीन चिन्हांकित नहीं कर पाये हो ।

श्री नारायण चंदेल :- डॉ. साहब का यह कहना है कि फूड पार्क नहीं तो फूटपाथ तो बना दो । (हंसी)

श्री अजय चंद्राकर :- हर बात में आपके 15 साल के उदाहरण रहते हैं, अच्छी बात है । आपने एक-बार महात्मा गांधी जी के लिये विशेष सत्र बुलाया था । 15 साल की चर्चा के लिये भी आप एक बार तो सत्र बुलवा ही दीजिए ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- 15 साल की बात की शुरूआत तो डॉ. साहब ने ही की है ।

श्री अजय चंद्राकर :- उसके बाद उदाहरण बंद कर देना । जितने दिन तक चाहो उतने दिन तक चर्चा करवा लेना, कोई एक चर्चा कर लीजिए कि इरीगेशन में कर लेंगे, एग्रीकल्चर में कर लेंगे, किसी भी विषय में जिसमें आप बोलें उसमें कर लेंगे ।

श्री शिवरतन शर्मा :- अच्छा, सबसे बुरी स्थिति तो आपके विभाग के बजट की है । आप सिंचाई का रकबा दुगूना करने वाले हो और बजट प्रावधान 300 करोड़ का है, क्या इसमें सिंचाई का रकबा दुगूना हो जायेगा ।

श्री अजय चंद्राकर :- क्या है कि आपको मैंने बोला था कि आप सी.एम. मटेरियल हैं लेकिन अब आप केप्टिल लॉयन बन गये ।

श्री रविन्द्र चौबे :- आप पूरा बजट पढ़ेंगे तब तो, आप पढ़ लीजिए । 300 करोड़ केवल नई योजनाओं के लिये और बाकी योजनाओं के लिये अभी डॉ. साहब पढ़ रहे हैं । आप पूरा बजट पढ़ लीजिये और उसके बाद अपनी बात कहिएगा ।

श्री अरूण वोरा :- मैं माननीय अजय चंद्राकर जी से यह जानना चाहता हूं कि अगर 15 साल में काम किये होते, जितने काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 वर्षों में करके बताया तो 15 सीटों पर आप कैसे सिमट गये, यह बताईए । मेरा पहला प्रश्न तो आपसे यही है ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- बोले रहेओ कर्जा माफी होही कहि, ओकरो बारे में बताओ ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय मंत्री जी, चर्चा के बीच में पूर्व मुख्यमंत्रियों के लड़कों का खड़ा होना प्रतिबंधित है । वे आपत्ति करते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री के लड़कों को क्यों बोलते हो करके, अब कुछ बोल दूंगा तो वे फिर इस बात को कहेंगे ।

श्री अरूण वोरा :- मैं छेड़ने के लिये नहीं बोल रहा हूं, जवाब देने के लिये बोल रहा हूं । छेड़ तो आप सकते नहीं हो मेरे से क्योंकि आप पहले ही छेड़वा चुके हो । (हंसी)

श्री रजनीश कुमार सिंह :- वोरा जी, वर्ष 1984 में 415 थे, 1979 आते-आते 110 हो गए थे ।

डॉ. रमन सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस विषय की चर्चा हम कर रहे थे । इरीगेशन में यह ठीक है, अरपा, भैंसाझार तो पिछले 8 साल से लिखा जाता है । दो लाईन सब लिख देते हैं लेकिन सवाल इस बात का है । मेरा कुछ ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसके लिये मैं बहुत ताकत से, हर जगह, हर सभा में, हर भाषण में बोलता हूं । मैं बस्तर, दंतेवाड़ा जाउंगा या रायपुर आउंगा या दिल्ली में जाउंगा तो सबसे बड़े ड्रीम प्रोजेक्ट को जो 26-28 महीने निकलने के बाद भी बजट में स्थान नहीं मिल पाया, वह ड्रीम प्रोजेक्ट बोधघाट परियोजना 22 हजार करोड़ की योजना उसके लिए सांकेतिक रूप से ही 100 रूपए का प्रावधान कर दिया गया होता । एक बार बजट में बोधघाट प्रिंट हो जाता तो चुनाव में दिखाने के

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

काम आएगा । बोधघाट बनना-वनना नहीं है । बोधघाट का डीपीआर बना नहीं है, डीटेल सर्वे हुआ नहीं है, वहां के लोग विरोध में खड़े हैं । इस बात को बस्तर में रोज बोलते हो, हमें खुशी होती, बस्तर वाले मेज थपथपाते हैं । उनको भी खुशी हो जाती कि बोधघाट में 100 रूपए का प्रावधान रख दिया गया है । तीसरे बजट में भी नहीं रखा गया है । क्या पांचवें और आखिरी बजट में बोधघाट को याद किया जाएगा और बोधघाट के लिए 100 रूपए का टोकन प्रावधान रखा जाएगा । सिंचाई विभाग के अधूरे कामों की सूची बनाई गई थी, चौबे जी को मालूम है । जो काम 60 प्रतिशत हो गया है, जो 70 प्रतिशत हो गया है, जो 80 प्रतिशत हो गया है, जो 50 प्रतिशत हो गया है उन कामों को क्रमवार नीचे से ऊपर सेंक्शन देने के लिए कार्ययोजना भी बनी थी और ऐसी ही योजनाओं को जो एक साल, डेढ़ साल, ढाई साल में पूरी हो सकती हैं उनको प्राथमिकता से करने के लिए बजट में प्रावधान रखना चाहिए था । आज मैं उन पूरी परियोजनाओं के बारे में विस्तार से चर्चा नहीं करूंगा । उसके लिए विभाग की चर्चा होगी तो ये सारी बातें आएंगी ।

अध्यक्ष महोदय, जब मैं ऊर्जा की चर्चा करता हूं तो बस्तर से सरगुजा तक लाईन विस्तार की चर्चा करता हूं । मुझे एक बात याद आती है बस्तर में 7 दिनों तक ब्लैक आउट था । बस्तर के विधायक बैठे हैं, वहां 7 दिनों तक ब्लैक आउट था। 7 दिनों तक पूरे बस्तर संभाग में अंधेरा था । क्यों अंधेरा था । बस्तर को जाने वाली जो मुख्य लाईन थी केवल 131 की ही थी । उसको अबूझमाड़ के पास नक्सलियों ने तोड़ दिया । 7 दिनों तक पूरा बस्तर अंधेरे में डूबा था । मैं अपने जीवन में पहली बार अबूझमाड़ के अंदर इंद्रावती को क्रॉस करके जीप में बैठकर 12-13 किलोमीटर अंदर जहां टावर को गिराया गया था, वहां गया । वहां हमारे 60/70 मजदूर काम कर रहे थे, बारिश हो रही थी । उस टावर को मुश्किल से 6-7 दिनों में खड़ा किया और बस्तर में बिजली की आपूर्ति हुई । उस दिन मुझे लगा कि बस्तर और सरगुजा के विद्युत का संकट कितना बड़ा होता है और उसी दिन हमने तय किया कि बस्तर और सरगुजा को 220 और 440 मेगावाट से कनेक्टिविटी दी जाए और हमने करके दिखाया । आज बस्तर में 3 कनेक्टिविटी 131, 220 और 440 की है, गांव-गांव तक विद्युत का जाल बिछा दिया । 94 परसेंट, 96 परसेंट विलेज पारे टोले मजरों को चिह्नांकित करके कार्ययोजना बनी । आज मैं बजट में देख रहा था कि किसी चीज को प्रस्तावित करते हैं, जब नदियों के तट से खेत को सिंचाई देने की सुविधा, नदियों के किनारे-किनारे विद्युत लाईन का विस्तार, छत्तीसगढ़ में करीब-करीब 509 बैराज हैं और करीब-करीब 440 अच्छे एनीकट हैं, जिसमें 8 से 12 महीने पानी रहता है । उसकी कार्ययोजना बनी है, यदि आप उसमें इंगित करते कि आने वाले समय में 200 करोड़, 100 करोड़, 50 करोड़ खर्च करके दोनों तरफ विस्तारित करेंगे तो लगता कि कुछ हो रहा है । केवल और केवल घोषणा करने से इसका असर क्या होगा कि आप उसमें लाईन विस्तार की बात कर रहे हैं । दूसरा टारगेट, छत्तीसगढ़ की गरीब जनता को केवल धान की फसल के लिए 2500 रूपए दे रहे है, देना अच्छी बात है । लेकिन होना यह

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

चाहिए कि उसका लागत मूल्य कम करने के लिए, सिंचाई का संसाधन जुटाने के लिए जो उनके 38 से लेकर 40 हजार औपचारिकतापूर्ण किये हुए पम्प के लिए आवेदन हैं उनको समयबद्ध कनेक्शन नहीं देंगे तो कैसे होगा ? इस बजट में जो प्रावधान है मैं उसे पढ़ रहा था । 150 करोड़ का प्रावधान है । उस पूरे प्रावधान को मिलाकर मैंने देखा उस 38 हजार करोड़ में से मुश्किल से 16-17 हजार पम्प लगेंगे और बाकी के पम्प 38 हजार ये हैं । करीब-करीब छत्तीसगढ़ में आज की तारीख में 70 हजार से ज्यादा पम्प कनेक्शन बिना औपचारिकता के या औपचारिकता के हैं, इनको पूरा करने में हमें 8 साल लगेगा । 8 साल लगेगा हमको । 8 साल लगेगा। यदि इसके लिए किसानों का काम है, अनुसूचित जाति, जनजाति के किसानों का मुद्दा है। पिछड़े वर्ग के किसानों का मुद्दा है। इसके लिए यदि एकमुश्त राशि रख देते। थोड़ा बहुत कर्ज दो रूपया और बढ़ा लेते तो निश्चित रूप से यह होता कि हां, सरकार ने किसानों के लिए, उनके पंप कनेक्शन के लिए कुछ बेहतरी का काम किया है। मगर इसके लिए भी कोई राशि का प्रावधान नहीं रखा गया है। मुझे लगता है कि यह प्रावधान होना चाहिए। एक महत्वपूर्ण विषय पर मैं चर्चा करना चाहता हूं जो विषय स्टेट के आर्थिक स्थिति के बारे में है और आर्थिक स्थिति के बाद जो हमारी स्थिति बनी है, जोकि गंभीर मुद्दा है। चंदूलाल चन्द्राकर मेडिकल कॉलेज, दुर्ग का शासकीयकरण किया जायेगा। चंदूलाल चन्द्राकर मेडिकल कॉलेज ही क्यों, इंजीनियरिंग कॉलेज बंद हो रहे हैं, उनका क्यों नहीं? अन्य मेडिकल कॉलेजों की स्थिति ठीक नहीं है, उनकी स्थिति का क्या? चंदूलाल चन्द्राकर के नाम से ही यदि हम समझते हैं तो चंदूलाल चन्द्राकर जी के परिवार के उनके ग्रैंड सन उन्होंने मुझे एप्लीकेशन देकर मांग की और वह एप्लीकेशन मैं आज साथ में लाया हूं। अमित चन्द्राकर ने मांग की कि This should be highly appreciable if you demand the investigation against all the land property sale belonging to company and respective directors can be stopped till investigation. We should be greatly thankful for to you for this act of kindness. यानी उन्होंने इस बात को कहा है कि इस विषय को लेकर चन्दूलाल चन्द्राकर के लड़के के लड़के नाती उन्होंने मुझे यह पत्र देकर अमित चन्द्राकर ने इस बात की मांग की है और इसके साथ ही साथ में दूसरा डाक्यूमेंट बताता है कि चन्दूलाल चन्द्राकर उस महाविद्यालय की स्थापना कैसे हुई ? 12 हजार मीटर का आबंटन का चन्दूलाल चन्द्राकर मेमोरियल हॉस्पिटल 100 बिस्तर का बना। इसका पंजीयन 1996 में हुआ। 30 वर्ष की लीज अवधि 2025-26 को समाप्त होगी। इंडियन बैंक भिलाई शाखा ने प्रश्नाधीन हॉस्पिटल को लीज डीड को बंधक बनाये रखने के लिए निगम से अनापत्ति प्रमाण पत्र लिये बगैर ऋण प्रदान कर दिया गया और उस प्रक्रिया में विधि के विपरीत मूल डीड क्रमांक 7 में पट्टेदार को उक्त भूमि को विक्रय के आधार पर नामांतरण की अनुमति कैसे मिली?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- डॉ. साहब, माननीय अध्यक्ष महोदय, अब इतने वरिष्ठ है। ये 1990 से एम.एल.ए. हैं। अविभाजित दुर्ग जिले के भी निवासी हैं, लेकिन इस सदन में इतना असत्य कथन पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा चंदूलाल जी के लड़के के लड़के। चंदूलाल जी ने शादी ही नहीं की थी। वे

अविवाहित थे तो उसका लड़का कहां से हो गया? और फिर उसका लड़का कहां से हो गया, जो शादी ही नहीं किये। वे आजीवन कुंवारे थे।

डॉ. रमन सिंह :- उनके भतीजे, भाई के लड़के।

श्री भूपेश बघेल :- अभी तो आपने कहा कि लड़के के लड़के ने। रिकॉर्ड निकालकर देख लीजिए।

डॉ. रमन सिंह :- ग्रैंड सन तो भाई का भी होता है।

श्री भूपेश बघेल :- तो कम से कम ऐसा तो मत कहिए।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- बोलते-बोलते जुबान फिसल जाता है।

डॉ. रमन सिंह :- चलिए, मैं ग्रेंड सन यूज कर लेता हूं।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- डॉ. साहब, हाउ डू पॉसिबल। (हंसी)

डॉ. रमन सिंह :- मैं ग्रेंड सन यूज कर लेता हूं। उनके जो ग्रेंड सन हैं, उन्होंने अपने आपको घोषित किया है और वे ग्रेंड सन होंगे। भतीजे के लड़के होंगे, मगर दूसरा विषय जो उससे और गंभीर है कि भिलाई के सारडा के द्वारा उसे इस विषय में लीज दिया अब उस लीज के आधार पर जमीन सरकार है, वह सरकारी जमीन में कर्ज लेकर मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो गयी। वह मेडिकल कॉलेज बंद हो गया। बंद होने के बाद यह स्थिति बनती है कि वह मेडिकल कॉलेज बिकाऊ हो गया। उसके बाद जी.डी. रूंगटा एज्यूकेशन फाउंडेशन के बीच में एसेट परचेज एग्रीमेंट होता है।

श्री कवासी लखमा :- यह कौन से सन में हुआ था। आपके समय का था क्या?

डॉ. रमन सिंह :- अब जब एसेट परचेज एग्रीमेंट होता है और यह चंदूलाल चन्द्राकर हॉस्पिटल के बीच में होता है, इसका मतलब यह है कि उस मेडिकल कॉलेज को बेचने के लिए एग्रीमेंट प्राइवेट सेक्टर में हो गया। प्राइवेट लोग लेने के लिए तैयार हैं। बहुत लोग तैयार थे। उसके बाद सरकार के ढाई सौ, तीन सौ करोड़ लगाकर, अरे, मेडिकल कॉलेज खोलना ही है दुर्ग भिलाई में और चंदूलाल जी के नाम से ही खोलना है तो दुर्ग का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल छत्तीसगढ़ का सबसे बेहतर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। आप उसका नाम चंदूलाल चन्द्राकर मेडिकल कॉलेज रख दो न। आप भिलाई के सेक्टर 9 हॉस्पिटल का नाम चंदूलाल चन्द्राकर रख दो न, मगर ऐसे एसेट, ऐसी प्रापर्टी जो जीवन भर के लिए लायबिलिटी बन जाएगी । नया मेडिकल कॉलेज का कौन विरोध करता है । जहां बनता है, हम उसका स्वागत करते हैं, मगर ऐसी लायबिलिटी को जबरदस्ती सरकार के मत्थे में डालकर इस मेडिकल कॉलेज को पुनर्जीवित करने का काम हो रहा है और इस के पीछे लोगों को कई प्रकार की शंका है, जिस प्रकार से इन्होंने पत्र जारी किया है, जिस प्रकार से लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं । मुझे लगता है कि हमें पूरी पारदर्शिता के साथ इन सारी बातों की जांच करके सिर्फ घोषणा कर देना या बजट में ला देना ही पर्याप्त नहीं है । सारी तथ्यों की जानकारी भी होनी चाहिए और जानकारी करने के बाद सरकार की जो मंशा है, उसे प्रकट करें और इसकी जानकारी लें ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय, अभी विभागीय चर्चा में मैं बहुत सारे मुद्दे में अपनी बात कहूंगा । आज मुझे लगता है कि जितना विषय और आपने जितना समय दिया, अध्यक्ष महोदय, आप घड़ी को बार-बार देख रहे हैं और मुझे देख रहे हैं । मैं इस मुख्य बजट का विरोध करता हूं । आपने समय दिया, उसके लिए धन्यवाद ।

अध्यक्ष महोदय :- मोहन मरकाम जी ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मोहन जी, एक मिनट । कागज नया मिला है या पुराना ही 10 पेज है, पहले यह बताईए ।

श्री मोहन मरकाम (कोण्डागांव) :- पुराना ही है । (हंसी)

श्री शिवरतन शर्मा :- अनुपूरक में आपने राज्यपाल महोदय का अभिभाषण पढ़ दिया था इसलिए चिन्ता हो रही है । (हंसी)

श्री मोहन मरकाम :- चिन्ता करने की बात नहीं है । माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 97106 करोड़ का बजट प्रस्तुत किया गया है, उसका समर्थन करते हुए मैं अपनी बात कहना चाहता हूं ।

माननीय अध्यक्ष जी, यह बजट जनआकांक्षाओं को पूरा करेगा । इस बजट में सरकार का विजन, सरकार का दृष्टिकोण, समृद्ध छत्तीसगढ़ की परिकल्पना की गई है । गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की परिकल्पना इस बजट में दिखती है । किसान पुत्र छत्तीसगढ़ राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत इस बजट से छत्तीसगढ़ राज्य के विकास में मील का पत्थर साबित होगा । जनता की नब्ज को हमारे मुख्यमंत्री जानते हैं इसलिए सर्वहारा वर्ग के लिए, किसान, मजदूर, आम जनता के हितों की रक्षा के लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है । केन्द्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार द्वारा प्रस्तुत 2021-22 का बजट हम देख रहे थे । केन्द्र सरकार ने अपने बजट में लगभग 23 प्रतिशत कटौती की है । कर्मचारियों के वेतन में 30 प्रतिशत की कटौती की है । सांसद निधि से लेकर अन्य विकास कार्यों में बजट में कटौती की गई है, मगर छत्तीसगढ़ की सरकार ने अपने संसाधनों के दम पर छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, छत्तीसगढ़ को रोल मॉडल देने के लिए अपने बजट में प्रावधान किया है ।

समय :
1:41 बजे **(सभापति महोदय (श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह) पीठासीन हुए)**

माननीय सभापति जी, केन्द्र सरकार से छत्तीसगढ़ को लगभग 18 हजार करोड़ रूपए मिलने हैं । केन्द्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ को राशि नहीं देने के बाद भी हमारी सरकार ने अपने बजट में सभी वर्गों के हितों की रक्षा की है । केन्द्र सरकार ने पहली बार देश का ऐसा बजट प्रस्तुत किया है है, जो 2021 का बजट पेश किया है, उसमें सरकारी उपक्रमों, सरकारी परिसम्पत्तियों को बेचने के लिए व्यवस्था

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

की गई है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने 60-70 वर्षों में क्या किया। 70 वर्षों में क्या किया ? मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि क्या रेल्वे स्टेशन, एयरपोर्ट, बैंक, भारत पेट्रोलियम, एल.आई.सी. क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दादा-परदादाओं ने बनाया था ? हमारी सरकार के देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने 1 सितम्बर, 1956 में एल.आई.सी. का गठन 5 करोड़ रूपए में किया था । आज एल.आई.सी. की परिसंपत्तियां लगभग 55 लाख करोड़ रूपये है। आज एल.आई.सी. का शेयर 49 प्रतिशत से बढ़ाकर एफ.डी.आई...।

श्री अजय चंद्राकर :- भैया, छत्तीसगढ़ में आना, कहां लगे हस।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- मिर्ची लग गयी क्या ?

श्री मोहन मरकाम :- मैं छत्तीसगढ़ में आऊंगा। माननीय सभापति जी, एफ.डी.आई 74 प्रतिशत कर दिया है। आज बैंक को बेच रहे हैं, भारत पेट्रोलियम, नवरत्न कंपनी, उसको बेचने का काम किया है। कहीं न कहीं आज केन्द्र की सरकार जो 60 साल में क्या किया ? आज भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार जो हमारी संपत्ति जो केन्द्र की संपत्ति है, उसको बेचने का काम कर रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहना चाहता हूं, आपने 60 साल में जो शौचालय बनाये, उन शौचालयों को आप बेचने का काम क्यों नहीं करते ? आज जो हमारी सरकार है, जो परिसंपत्तियां बनाई हैं, उन संपत्तियों को केन्द्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बेचने का काम कर रही है। आज छत्तीसगढ़ से कोयला, लोहा, बाक्साईड, पानी, बिजली, सब कुछ चाहिए, मगर छत्तीसगढ़ के अन्नदाताओं का धान, चावल नहीं चाहिए। आज केन्द्र सरकार छत्तीसगढ़ के साथ कैसा सौतेला व्यवहार लगातार कर रही है। आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को छत्तीसगढ़ की चिंता नहीं है, किसानों के नाम से राजनीति करना चाहते हैं। मैं पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह जी से पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, कल तक केन्द्र की डॉ. मनमोहन सिंह जी की सरकार को लगातार पत्र लिखते थे, आज पत्र लिखने में उनके आकार, उनकी बोझ को इतनी तकलीफ होती है। नेता प्रतिपक्ष जी आप कहते थे कि हमारे मुख्यमंत्री जी को पत्रजीवी मुख्यमंत्री कहते हैं। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपने छत्तीसगढ़ के किसानों के हित में केन्द्र सरकार को कितने पत्र लिखे हैं। आज केन्द्र सरकार ने 60 लाख मीट्रिक टन चावल लेने की सैद्धांतिक सहमति दी थी, मगर लगातार छत्तीसगढ़ के साथ अन्याय कर रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए इस बजट में भी 5703 करोड़ रूपये राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए वर्ष 2021-22 के बजट में प्रावधान किया है। यह माननीय मुख्यमंत्री जी की दृष्टिकोण किसानों के प्रति है।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- मोहन जी, आधा मिनट आपको समर्पित करता हूं। आप केन्द्र को पत्र लिखने के लिये बोल रहे हैं, मैं पत्र लिख भी दूं। 28 लाख मीट्रिक टन चावल का आदेश दिया। 3 महीने समय बढ़ाया। उसके बाद भी 28 लाख मीट्रिक टन छत्तीसगढ़ सरकार की कस्टम

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

मिलिंग करने की क्षमता नहीं है, उसके बाद आपके उपर कैसे भरोसा करें कि आपको 60 लाख मीट्रिक टन की अनुमति दें। जो 28 लाख मीट्रिक टन नहीं कर सकते और अमरजीत ने इस बात को स्वीकार किया कि हम कस्टम मिलिंग नहीं कर पाये तो आपकी क्षमता और आपने उसको बता दिया है कि यदि किये होते तो उस बारे में जरूर विचार करते।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- मोहन जी, एक मिनट। माननीय नेता जी, आपने बड़ी चालाकी से तो अपनी बात कही, लेकिन हम लोग छत्तीसगढ़ में राजनीति करते हैं, सबकी नैतिक जवाबदारी है, जिम्मेदारी है।

श्री धरमलाल कौशिक :- हम लोग राजनीति नहीं करते।

श्री अमरजीत भगत :- एक मिनट सुनिये। मोहन जी से सीखिए।

श्री धरमलाल कौशिक :- हम लोग राजनीति नहीं करते, आप लोग छत्तीसगढ़ में राजनीति करते हो। यही अंतर है और यही राजनीति करके केन्द्र सरकार को बदनाम करने के लिए पूरा भ्रम छत्तीसगढ़ में फैला रहे हो। अपनी गलती को अपनी असमर्थता को स्वीकार करना चाहिए, अपनी कमियों को स्वीकार करना चाहिए। उसके बाद में आप बात करेंगे तो आपको सहयोग करेंगे।

श्री अमरजीत भगत :- नेता जी, स्वस्थ राजनीति करना चाहिए। जिस प्रकार आपने मोहन जी को बोला, आपको तुरंत समय दिया। हम जब भी बोलते हैं, पता नहीं आपको क्या तकलीफ रहती है। आप हमारी बात सुनना नहीं चाहते। राजनीति में हम लोग अपनी-अपनी बात कहने आये हैं तो केवल आप वन-वे चलायेंगे तो ठीक बात नहीं है। कम से कम हम आपकी बात सुनते हैं तो हमारी बातें भी सुना करें। तभी तो एक दूसरे की बात समझ में आयेगी। अगर नहीं सुनेंगे तो न आपकी भावना न ...।

सभापति महोदय :- चलिये, मोहन मरकाम जी।

श्री धरमलाल कौशिक :- मोहन भैया, एक मिनट। अमरजीत जी, आप ऐसा क्यों सोचते हो। यदि मोहन जी की बात नहीं सुननी होती तो मैं यहां पर क्यों बैठा रहता। मुझे मालूम है कि सरकार की तरफ से बेचारे स्थाई प्रवक्ता हैं। कोई भी विषय आये, मोहन मरकाम जी को सौंप दिया जाता है और हम लोग पूरी तल्लीनता से सुनते हैं।

श्री अमरजीत भगत :- मैंने यह कहा कि इतना उदार दिल होना चाहिए कि अगर कोई समय मांगता है, तो 2 मिनट उसकी बात सुननी चाहिए। वह क्या बोल रहा है, सुनेंगे तभी तो पता चलेगा। मैं यह बोल रहा था कि अगर छत्तीसगढ़ में राजनीति कर रहे हैं तो जितनी सरकार की जवाबदारी है, आपकी भी उससे कम जवाबदारी नहीं है। न धान खरीदी के बारे में, न बोरा खरीदी के लिए, किसानों के लिए जब भी दिक्कत आई तो आप लोगों ने एक पत्र, एक बयान किसानों के बारे में नहीं देते हैं। तो आप लोगों की यह कैसी राजनीति है ? आप लोग केवल आरोप मढ़ने के लिए, केवल आरोप लगाने के लिए राजनीति करते हैं।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री मोहन मरकाम :- माननीय सभापति महोदय, मैं पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह जी के भाषण को बड़े ध्यान से सुन रहा था। वे अपने 15 साल के कार्यकाल को बार-बार इंगित कर रहे थे कि उनका वित्तीय प्रबंधन बहुत अच्छा था, हमने जो कर्ज लिया था, वह जनता के विकास में खर्च किया। मगर मै एक आकड़ा बताता हूं कि 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डॉ. रमन सिंह जी ने क्या किया था? 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में 71 प्रतिशत परिवार 5 हजार या उससे कम कमाते थे, ये केन्द्र सरकार के आकड़ें हैं। माननीय सभापति जी, प्रदेश में 3 प्रतिशत परिवार ऐसे थे, जिनकी कमाई 10 हजार रूपये या उससे कम थी, ये 15 साल के डॉ. रमन सिंह जी के कार्यकाल के हैं। प्रदेश में मजदूरी करने वालों की संख्या 52 प्रतिशत है। सबसे बड़ा, जो छत्तीसगढ़ के लिए जो कलंक था, पूरे देश में सबसे ज्यादा झोपड़ी, लगभग 18 प्रतिशत छत्तीसगढ़ में है। एन.एस.एस.ओ, केन्द्र सरकार की रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रीय सेंपल सर्वे अनुसार देश का सबसे गंदा राज्य छत्तीसगढ़ है। यह भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के शासनकाल में है। जब से हमारी सरकार है, इन दो वर्षों में स्वच्छतम राज्यों में छत्तीसगढ़ को एवार्ड मिल रहा है। यह हमारी सरकार की नीतियां हैं, योजनाएं है।

माननीय सभापति महोदय, आज स्वास्थ्य की बात हो रही थी। लगातार 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी की डॉ. रमन सिंह की सरकार रही है। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य की स्थिति बद से बदतर रही है। हमारी सरकार ने कोरोना काल में भी छत्तीसगढ़ के जनता के हितों की रक्षा के लिए काम किया है। छत्तीसगढ़ का सेहत, राष्ट्रीय रैंकिंग में 12 वां स्थान, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में रहा है। सालाना इन्क्रीमेंटल रैकिंग के अनुसार उस समय जो तीन राज्य बने, चाहे झारखण्ड हो, उत्तराखण्ड हो या छत्तीसगढ़ हो, उसमें भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में झारखण्ड का 6.87 था, जम्मू कश्मीर का 6.83 था और छत्तीसगढ का 3.69 था। इसका मतलब साफ है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में स्वास्थ्य की स्थिति बद से बदतर थी। इण्डिया टुडे के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 21 राज्यों में 20वां नंबर था। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि जो बजट में प्रावधान किया गया था, आपमें भ्रष्टाचार का आरोप लगा था, आपने वित्तीय प्रबंधन की बात की है, जो हमारे संसाधन हैं, उसमें हमारी सरकार वित्तीय प्रबंधन के साथ काम कर रही है। हमारी सरकार ने इस कोरोना काल में भी संक्रमण के रोकथाम और उपचार के लिए त्वरित निर्णय लिये। स्वास्थ्य विभाग के लिए 670 रूपये का अतिरिक्त राशि का प्रावधान किया गया। संक्रमण जांच हेतु 6 RT-PCR. लैब और 18 true- NAT लैब की तत्काल स्थापना की है। मात्र 2020 शासकीय अस्पतालों में आई.जी.यू. बिस्तर की क्षमता केवल 53 थी और हमारी सरकार के कार्यकाल में बढ़कर अभी 406 बिस्तर हो चुकी है। कोरानो संक्रमितों के उपचार हेतु 30 कोविड समर्पित अस्पताल तथा 178 कोविड केयर सेन्टर की स्थापना की गई है। ये हमारी सरकार की नीयत है। छत्तीसगढ़ की 2 करोड़ 80 लाख

जनता के स्वास्थ्य सुविधाओं का विशेष ध्यान देते हुए हमारी सरकार ने विशेष प्रावधान किया है। आप स्कूल की बात कर रहे हैं। जब हमारे डॉ. मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, तब अधिसूचित क्षेत्रों में जो हमारे 85 ब्लाक हैं, जो ऐसे जिले हैं उन जिलों के जो होनहार बच्चे हैं वह मॉडल स्कूल में पढ़ेंगे, इसलिए ऐसे होनहार बच्चों के लिए 72 मॉडल स्कूल बनाये गये थे और पूरे संसाधन की व्यवस्था हमारी सरकारों ने की थी। 17722 से अधिक बच्चे उसमें थे। उन मॉडल स्कूलों को भी मुख्यमंत्री डी.ए.व्ही. पब्लिक स्कूल के माध्यम से प्रायवेट हाथों में दिया गया।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अकबर जी, आपका टिकट वितरण गलत हो गया। लोकसभा का टिकट दीपक बैज की जगह इनको देना था। यह तो राज्य बजट में दिल्ली से नीचे आ ही नहीं रहे हैं। हम क्या बतायें।

श्री मोहन मरकाम :- सभापति महोदय, आज भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे होनहार बच्चों के अधिकारों को भी मारने का काम किया है। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी रोजगार की बात कर रहे थे। मैं तो इनके कार्यकाल को देखा हूं। युवाओं का कौशल विकास, अजय चंद्राकर जी इस विभाग के मंत्री रहे हैं, तीन वर्षों में 3 लाख 37 हजार युवाओं को प्रशिक्षित करने का इन्होंने लक्ष्य रखा था। विभिन्न प्रयास और संस्थाएं मिलाकर बेरोजगारी मुक्त छत्तीसगढ़ बनाने का इन्होंने घोषणा की थी। उस समय 23 लाख पंजीकृत।

श्री अजय चंद्राकर :- चलो, 3 लाख रोजगार दिये या नहीं दिये, चलो उसको मान लिये। मैं तो 15 साल में सब गड़बड़ हुआ चलो मान लिया। कोई बात नहीं। कोंडागांव का स्टेडियम भी नहीं बना, चलो उसको भी मान लेते हैं। माननीय अकबर साहब आप बैठे हैं, मैं ये बोलना चाहता था कि जब स्किल डेव्हलपमेंट की बात हो रही है तो पहला बजट आप पढ़ेंगे तो 10 लाख युवाओं को गौठान में प्रशिक्षण देंगे, और उनको रोजगार मिलेगा, ऐसा बोले थे। अब आपकी सरकार का है कि 10 लाख का प्रशिक्षण हुआ या नहीं हुआ, यहां का बताओ ना। उसको मैं मान लिया कि सब गड़बड़ हुआ, लेकिन आपने जो कहा था कि 10 लाख गौठान के लिए प्रशिक्षण करेंगे उसका बताओ।

श्री मोहम्मद अकबर :- आप पहले पूरा सुनो तो। अभी बहुत बाकी है।

श्री मोहन मरकाम :- सभापति महोदय, तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने वित्त मंत्री के रूप में युवाओं का बजट पेश किया था एवं उसमें युवाओं के कौशल, विकास के लिए 6151 करोड़ रूपये के बजट का प्रावधान किया था। मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के लिए भी अलग से 200 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान किया था। मैं पिछली सरकार से पूछना चाहता हूं कि आपने कितने लोगों को रोजगार दिया? आज केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार चाय बेचने से लेकर पकौड़ा तलने तक ये लोग रोजगार देने की बात कर रहे हैं। आज दो करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात हो रही है।

श्री अजय चंद्राकर :- दिल्ली जाकर भाषण दो।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री मोहन मरकाम :-आज जो बातें हो रही है। वर्ष 2017-18 के नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस की तरफ से कराये गये श्रम शक्ति सर्वे के अनुसार 6.1 प्रतिशत बेरोजगारी दर है। आज हमारी सरकार लगातार छत्तीसगढ़ के युवाओं को रोजगार देने का काम कर रही है। 15580 शिक्षकों की भर्ती, लगभग 3000 पुलिसकर्मियों की भर्ती, 1300 सहायक प्रोफसरेां की भर्ती लगातार हमारी सरकार कर रही है मगर पिछले 15 सालों की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आऊटसोर्सिंग के माध्यम से दूसरे प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने का काम की थी। हमारी सरकार की छत्तीसगढ़ के युवाओं को रोजगार देने की नीयत साफ है। भारत के छत्तीसगढ़ जैसे बड़े और शोषित और विगत 15 वर्षों तक लूट-खसोट होने वाले राज्य के लिए वित्त पोषण कितनी बड़ी चुनौती है इसमें दुनियाभर के अर्थशास्त्री एक राय होंगे। सरकारें अधिकतम लोक कल्याण के लिए चलनी चाहिए और इसी सिद्धांत पर हमारे कांग्रेस की सरकार काम करती आई है।

समय :

2:00 बजे

जनता ने जब भी प्रदेश की सत्ता भारतीय जनता पार्टी से हटाया, उस समय प्रदेश के किसानों के सिर पर 8,743 करोड़ रूपये का कर्ज चढ़ा हुआ था। कांग्रेस सरकार बनने के बाद 17 लाख, 96 हजार किसानों का 8,743 करोड़, 50 लाख रूपये कर्ज माफ किये, आदरणीय चन्द्राकर जी, जिसमें से 8,135 करोड़ रूपया राज्य सरकार द्वारा भुगतान किया गया। आपने तो घोषणा की थी कि अगर कर्ज माफ होगा तो मैं विधायक के पद से इस्तीफा दूंगा। आदरणीय चन्द्राकर साहब, आप कब इस्तीफा दे रहे हैं? आप अपने वायदे पर कायम है या नहीं ? यह घोषणा कर दीजिए?

माननीय अध्यक्ष महोदय, जब भी आप लोग प्रदेश के विकास नहीं होने का आरोप लगाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह जी कह रहे थे उस समय आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में पूरे देश में कोरोना महामारी के कारण पूरा विश्व नहीं, पूरे देश और अन्य प्रदेशों की भी वित्तीय स्थिति गड़बड़ा गई। उसके बाद भी छत्तीसगढ़ सरकार अपने संसाधनों के माध्यम से यह बजट छत्तीसगढ़ के विकास के लिए काम कर रही है। आर्थिक सर्वेक्षणों को खुले मन से स्वीकार करने लायक परिपक्तवता अभी विपक्ष में बैठे हमारे साथियों के पास नहीं है। इसलिए छत्तीसगढ़ की अच्छी स्थिति को भी स्वीकार कर नहीं पा रहे हैं। आज समाचारपत्रों में मुझे पता चला, माननीय डॉ. रमन सिंह जी पूर्व वित्त मंत्री, जो 15 सालों में 12 सालों तक वित्त मंत्री के रूप में बजट पेश किए। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ आर्थिक रूप से बदहाली की ओर बढ़ रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण में प्रति व्यक्ति आय में 0.14 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। जो 20 वर्षों में ऐसा पहली बार हुआ है। मैं महान अर्थशास्त्री डॉ. रमन सिंह, पूर्व वित्त मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि यह भूल गये कि वर्ष 2020-21 में कोरोना आपदा के कारण पूरे देश की अर्थव्यवस्था विपरित में विपरीत

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

प्रभाव पड़ा है। संभवत: उन्होंने भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु जारी आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़े नहीं देखे हैं। मैं माननीय चन्द्राकर साहब, आपसे भी पूछना चाहता हूँ कि अगर विपक्ष के साथी आर्थिक सर्वेक्षण आंकड़ों का अध्ययन कर लेते तो वह छत्तीसगढ़ के कांग्रेस की सरकार की प्रशंसा करते होते, अभिनंदन करते होते। वित्तीय वर्ष में जहां केन्द्र सरकार के नेतृत्व में देश की जीडीपी वृद्धि -7.7 प्रतिशत रही, वहीं छत्तीसगढ़ में जीडीपी वृद्धि दर सिर्फ -1.77 प्रतिशत रही। यानी कि छत्तीसगढ़ में देश की तुलना में कहीं बेहतर प्रदर्शन किया है।

माननीय सभापति महोदय, प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2020-21 के मूल्य पर देश में जब -5.2 प्रतिशत थी। वहीं छत्तीसगढ़ में -0.14 प्रतिशत रही। देश में कृषि क्षेत्र में 3.4 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। वहीं छत्तीसगढ़ में 4.6 प्रतिशत वृद्धि दर देखी गई। उद्योग के क्षेत्र में केन्द्र सरकार -9.6 प्रतिशत रही, परंतु हम छत्तीसगढ़ में -5.2 प्रतिशत ही रहे। यानी उद्योग में भी हमारी सरकार ने अच्छा प्रदर्शन किया है। सेवा के क्षेत्र में देश में -8.8 प्रतिशत वृद्धि दर देखी गई। वही हम छत्तीसगढ़ में पॉजिटिव रहे। 0.4 प्रतिशत वृद्धि हमने, हमारी सरकार ने सेवा क्षेत्र में वृद्धि दर्ज की। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि हमारी सरकार की नियत, योजनाएं, हमारी सरकार का वित्तीय प्रबंधन बहुत अच्छा है। इसीलिए आज कहीं न कहीं आज जो तुलना हो रही है जो छत्तीसगढ़ सरकार की वित्तीय प्रबंधन का, रिजर्व बैंक से लेकर नीति आयोग, अन्य प्रदेशों, अन्य सूबों की सरकार यह नहीं कर रही है। मैं पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह जी से पूछना चाहता हूँ। भाजपा के विधायकों, सांसदों को तो केन्द्रीय वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री पर चढ़ाई कर देनी चाहिए। यदि सचमुच में छत्तीसगढ़ के हितैषी हैं तो आप लोगों को भी केन्द्र सरकार से निवेदन करना चाहिए कि जो 18,500 करोड़ रुपये छत्तीसगढ़ को मिलने हैं वह दे दें तो हम लोगों को कर्ज लेने की जरूरत भी नहीं पडेगी। वर्ष 2018-19 से आप हमसे पैसे का हिसाब मांगते हैं, दिल्ली जाकर अपने आकाओं से हिसाब क्यों नहीं पूछते? सूट बूट वाले साहब जी, आप जाकर पूछिये, आपकी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2018-19 में सिर्फ एक साल में 8 लाख 48 हजार 338 करोड़ रुपये का कर्ज देश के ऊपर लाद दिया। 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक देश पर फिर से 9 लाख 94 हजार 179 करोड़ रुपये का कर्ज चढ़ा। केन्द्र में भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी सरकार ने देश के ऊपर 18 लाख 42 हजार 517 करोड़ रुपये का कर्ज चढ़ा दिया। आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर वित्तीय वर्ष 2021-22 में केन्द्र सरकार द्वारा लिये जाने वाले कर्ज का अनुमानित आंकड़ा 14 लाख 65 हजार 17 करोड़ रुपये है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति जी, इसके लिए अलग से समय निर्धारित करना चाहिए।

श्री मोहन मरकाम :- मैं छत्तीसगढ़ का ही बता रहा हूं।

श्री शिवरतन शर्मा :- आप कितना भी स्तुतिगान कर लो यहां नहीं आ सकते, उधरी रहोगे।

श्री मोहन मरकाम :- मैं तो इतने बड़े पद में हूं, आपको शायद मेरे पद का आकलन नहीं है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री शिवरतन शर्मा :- या आप मोहम्मद अकबर जी से दीक्षा लो। इधर आना है तो दीक्षा लेने इधर आना पडेगा।

श्री मोहन मरकाम :- हमको दीक्षा लेने की जरूरत नहीं है। दीक्षा तो आप जैसे लोगों को लेने की जरूरत है।

श्री शिवरतन शर्मा :- हम तो दीक्षा लेने को तैयार हैं।

श्री मोहन मरकाम :- मुंह में राम, बगल में छूरी, राम नाम जपना, पराया माल अपना, तो दीक्षा आप लोगों को लेनी पड़ेगी। 100 असत्य का सच बनाने की कला तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से सीखनी चाहिए। माननीय सभापति महोदय, इस अवधि में हमारी सरकार ने 13400 करोड़ रुपये ही कर्ज लिया है। केन्द्र सरकार का 2021-22 का डेप्थ जी.एस.डी.पी. रेशियो 62.22 प्रतिशत है, जबकि छत्तीसगढ़ के लिए अनुमान केवल 22.29 प्रतिशत है। इस प्रकार इंट्रेस्ट पेमेंट और रेवेन्यू रिसीप्ट रेशियो अनुमानित 45 प्रतिशत है, जबकि छत्तीसगढ़ का रेशियो मात्र 8.16 प्रतिशत है। यह आंकडें स्पष्ट कर देते हैं कि देश को कर्ज के रसातल की ओर कौन ले जा रहा है। जबकि हमारी सरकार जो भी कर्ज ले रही है, छत्तीसगढ़ के विकास, छत्तीसगढ की 2 करोड़ 80 लाख जनता के विकास और निर्माण के लिए कर्ज ले रही है। आप लोगों को तो अपने आकाओं से हिसाब मांगने की हिम्मत नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ की स्थिति पर प्रकाश डालकर मैं जरूर आप लोगों का भ्रम दूर करना चाहता हूं।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं बोल रहा हूं यह पूरे फ्लेप को यहां टेबल करवा दीजिए, पहले वह इधर थे तो अच्छा भाषण देते थे।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय सभापति जी, 15 साल पूर्व मुख्यमंत्री सरकार चलाये हैं, वह एक शब्द भी इधर-उधर का नहीं बोले, वह तो पूरा पढ़कर बोले। मैं तो बाहर की भी बात बोल रहा हूं। जो 15 साल सरकार के मुख्यिा रहे हैं, वह एक शब्द अपने पन्ने से उधर-उधर नहीं बोले। मैं तो कुछ अलग भी बोल रहा हूं। माननीय चन्द्राकर जी, आप सुनने की हिम्मत तो रखिये। खैर, आप लोगों को तो अपने आकाओं से हिसाब मांगने की हिम्मत नहीं है।

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- वह आपका भ्रम दूर कर रहे हैं।

श्री मोहन मरकाम :- मगर मैं छत्तीसगढ़ के बारे में प्रकाश डालकर आप लोगों के भ्रम को जरूर दूर करना चाहता हूं ताकि आपके दुष्प्रचार के खेल का पर्दाफास हो सके। यह आंकड़ें हैं। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 2011-12 में 10,686 करोड़ का लोन लिया, 2012-13 में 11,704 करोड़ का लोन लिया, 2013-14 में 14,446 करोड़ का लोन लिया, वर्ष 2014-15 में 20,049 करोड़ का लोन लिया, इस ढंग से जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही तो 41,645 करोड़ रूपए का भारतीय जनता पार्टी के जो वर्ष 2011-12 से लेकर वर्ष 2018 तक इन्होंने 41,695 करोड़ का लोन लिया जबकि हमारी सरकार ने दिनांक 18 दिसंबर से 31 मार्च, 2019 तक 10,571 करोड़, दिनांक 01 अप्रेल से 31 मार्च,

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

2020 तक 10,893 करोड़, 01 अप्रेल 2020 ये 30 जनवरी, 2021 तक 8,864 करोड़ हमारी सरकार ने कर्ज लिया, आज ये कर्ज की बात करते हैं। 15 साल कर्ज लेकर कंबल ढ़ांककर घी पिया और मैंने जो आंकड़े बताये न, जो छत्तीसगढ़ की बदहाल स्थिति जब छत्तीसगढ़ राज्य बना था, 37 प्रतिशत गरीबी थी। जब आपने वर्ष 2018 में छोड़ा तो गरीबी का प्रतिशत 39.9 प्रतिशत आपने पहुंचाया इसका मतलब साफ है कि 15 साल लोन लेकर कंबल ढंककर घी पीने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया है । माननीय सभापति महोदय, आज कहीं न कहीं पिछले 3 सालों में यानी कि वर्ष 2018-19 से लेकर 2020-21 तक जो ।

श्री शिवरतन शर्मा :- मरकाम जी, क्या है कि थोड़ी दीक्षा श्री अकबर भैया के पास से ले लो, जहां से दीक्षा ले रहे हैं वह ठीक जगह नहीं है । अभी जहां से दीक्षा लिये हो तो इधर आ जाओगे, वहां जाना है तो अकबर जी के पास बैठो ।

श्री अजय चंद्राकर :- मैं इनको कुरूद ले जाता हूं ।

श्री मोहन मरकाम :- मैं अभी सबसे ज्यादा कुरूद जा रहा हूं, अब आपको तकलीफ हो रही है न । मेरा अगला टारगेट है कि कुरूद विधानसभा कैसे जीतूं ?

श्री शिवरतन शर्मा :- आपको लड़ना है क्या, आपको लड़ना है तो आप आमंत्रित हैं ।

सभापति महोदय :- चलिये, मरकाम जी अपने बात जारी रखिए ।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय सभापति महोदय, पिछले 3 साल यानी कि वर्ष 2018-19 से लेकर 2020-21 में केंद्र से राज्यों को करों के हिस्से की राशि 14,628 करोड़ रूपए और जी.एस.टी. क्षतिपूर्ति 3100 करोड़ रूपया लगभग साढ़े 18000 करोड़ रूपया, मैंने पहले ही कहा है कि अगर यह राशि हम छत्तीसगढ़ के लोगों को मिलती तो हम लोगों को कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ती । आज 20 प्रतिशत के आसपास छत्तीसगढ़ की सरकार ऋण ले रही है, आज कहीं न कहीं जो बैठे हैं, आज जो बातें असल में भारतीय जनता पार्टी के चारवाक के दर्शन पर चलने वाली पार्टी है - जब तक जीओ, सुख से जीओ, कर्ज लेकर घी पीओ ।

सभापति महोदय :- जल्दी समाप्त करिए ।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय सभापति महोदय, मैं पहला वक्ता हूं । मुझे अपनी और सरकार की बात तो रखने दीजिए । माननीय सभापति महोदय, सुख से जीओ, कर्ज लेकर घी पीओ, भाजपा शासनकाल वाले उत्तरप्रदेश, माननीय डॉ. रमन सिंह जी जो आंकड़े बता रहे थे वही मैं अन्य प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें हैं उसमें भी मैं जाना चाहता हूं । भाजपा शासनकाल वाले उत्तरप्रदेश राज्य में इसका बढ़िया नमूना आपको देखने को मिल जाएगा । सन् 2019-20 में उत्तरपद्रेश सरकार पर 4 लाख 99 हजार 968 करोड़ रूपए का कर्ज था, वहीं वर्ष 2020-21 में उत्तरप्रदेश सरकार पर कर्ज बढ़कर 5 लाख 65 हजार 910 करोड़ रूपया हो गया । दोनों साल में सकल घरेलू उत्पाद का

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

लगभग 30 प्रतिशत से अधिक है इसका मतलब साफ है कि हमारी सरकार ने 30 प्रतिशत के अंदर रहकर कर्जा लिया है । उत्तरप्रदेश 30 प्रतिशत... ।

श्री शिवरतन शर्मा :- आपके भाषण को आपकी पार्टी के लोग इतनी गंभीरता से ले रहे हैं कि पूरा ट्रेजरी बेंच खाली है, केवल एक मंत्री औपचारिकता पूरी करने के लिये बैठे हैं । अपने प्रदेश अध्यक्ष के भाषण को सुनने के लिये लोग इतने गंभीर हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, यह प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के सम्मान के खिलाफ है ।

सभापति महोदय :- कृपया बैठिए, अपनी बारी आने पर आप अपनी बात कहियेगा ।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय सभापति महोदय, मैं भारत की बात कहूं । भारत जी.डी.पी. के 90 प्रतिशत कर्ज पर पहुंचने की स्थिति में है । सरकारी बाण्ड नहीं बिक रहे हैं और चुनावी राज्यों में जब चुनाव होता है तो बिहार में फ्री कोरोना वैक्सीन की घोषणा होती है । अभी पश्चिम बंगाल सहित पांच राज्यों में चुनाव है तो वहां फ्री वैक्सीन और 18 लाख करोड़ की घोषणा भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं ।

श्री सौरभ सिंह :- 60 साल से ऊपर वालों को फ्री वैक्सीन लग रही है, रजिस्ट्रेशन करा लीजिए ।

श्री मोहन मरकाम :- सभापति महोदय, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार पर भी ज्यादा कर्ज चढ़ चुका है । इसी से भाजपा की कार्यप्रणाली का पता चलता है । सभापति जी, हमारा पड़ोसी राज्य मध्यप्रदेश है । मध्यप्रदेश पर 2019 में 1 लाख 81 हजार 80 करोड़ रूपए का कर्ज था, जो कि 2020-21 में 2 लाख, 28 हजार 100 करोड़ का कर्ज है जो कि उनके सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का 24 प्रतिशत है । छत्तीसगढ़ 2019-20 में 63,147 करोड़ का ऋण रहा जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 18.3 प्रतिशत है, जबकि 2020-21 के लिए अब तक 72 हजार, 12 करोड़ ऋण लिया है जो सकल घरेलू उत्पाद का 20.05 प्रतिशत है । मैं आंकड़े के साथ बता रहा हूं । ये फर्जी आंकड़े नहीं हैं जो कि केन्द्र की मोदी जी की सरकार.. ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप गुरूजी थे, लेकिन पढ़ाने में तो गधे थे बोलते हैं लोग । लोग बोलते हैं कि गुरूजी ठीक से नहीं पढ़ाते थे । ये बातें आपको किसने पढ़ा दिया । पूरा उत्तर प्रदेश और जहां-जहां से शराब आती है उन सबका उल्लेख आप कर रहे हो ।

श्री सौरभ सिंह :- राज्य सरकार के बजट पर बोलिए, केन्द्र सरकार के बजट पर क्यों चर्चा कर रहे हैं ।

श्री मोहन मरकाम :- चन्द्राकर जी, मैं इतना इंटेलिजेंट था कि शिक्षा कर्मी वर्ग 1, वर्ग दो, एल.आई.सी. डेवलपमेंट ऑफिसर, सीनियर मैनेजर जैसे चार-चार नौकरियों को छोड़कर कांग्रेस ने टिकिट

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

दिया और आज जीतकर आ रहा हूं । इसका मतलब साफ है कि वित्त के मामले में मुझसे ज्यादा जानकारी तो नहीं होगी । बैंकिंग क्षेत्र में क्या होता है उसके बारे में मुझे पता है ।

श्री सौरभ सिंह :- चिटफंड के बारे में भी आपको काफी जानकारी होगी ।

श्री शिवरतन शर्मा :- आप यह बताओ कि आपका भाषण सुनने के लिए एक भी मंत्री उपस्थित नहीं है । कोई अनुशासन का डंडा चलाओगे ।

श्री मोहन मरकाम :- वे भोजन कर रहे हैं और सब लोग सुन रहे हैं ।

सभापति महोदय :- शर्माजी, प्लीज़ हस्तक्षेप न करें ।

श्री मोहन मरकाम :- इस तरह से हम समझ सकते हैं कि भाजपा की सरकारें कुछ भी कर लें तो उन्हें सात खून माफ है और हम यदि किसानों के भले के लिए, जनता के भले के लिए कदम उठाते हैं तो आपके हल्ले की कोई सीमा नहीं रहती । इसे ही कहते हैं - हम आंह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती । सभापति जी छत्तीसगढ़ की स्थिति भाजपा शासित राज्यों की तुलना में कहीं ज्यादा बेहतर है, हमारा वित्तीय प्रबंधन अच्छा है । छत्तीसगढ़ के विकास के मॉडल की तारीफ केन्द्र सरकार और अन्य सूबों की सरकारें कर रही हैं । रमन सरकार के कार्यकाल में अर्थव्यवस्था बर्बाद करने वाले कार्य होते थे, अब बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, हम बोलेंगे तो बोलोगे कि बोलता है । सभापति जी, आपने चांउर वाले बाबा की सरकार ने अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने में कितना योगदान दिया, सबने जाना होगा । आज हमारी सरकार लगातार काम कर रही है और मेरे पास डॉ. रमन सिंह जी का बजट भाषण चाहे 2004-05 का हो या 2008-09 का हो या 2014-15 के बजट की कॉपी और घोषणा पत्र की कॉपी है । 2003 में सरकार बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2004-05 का जो बजट पेश किया, तत्कालीन मुख्यमंत्री जी का जो बजट भाषण था उसमें उन्होंने कहा था कि विधान सभा चुनाव के समय हमने प्रदेश की गरीब जरूरतमंद बेरोजगार लघु एवं सीमांत कृषक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों से अनेक वादे किये थे। साथ ही प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए नयी योजनाएं प्रारंभ करने का संकल्प लिया था। मुझे यह कहने में हर्ष हो रहा है कि हमने इस बजट में इन वादों का पूरा करने के हर संभव प्रयास किया है। माननीय सभापति जी, ये 15 साल सरकार में रहे। इन्होंने कहा था कि लघु एवं सीमांत किसानों का कर्ज माफ करेंगे। इन्होंने कहा था कि 12वीं पास पढ़े-लिखे युवाओं को रोजगार देंगे। रोजगार नहीं देने से 500 रूपया बेरोजगारी भत्ता देंगे। जरसी गाय देंगे। ये 15 साल सरकार में रहे। 15 साल इन्होंने काम नहीं किया। मगर आज किस मुंह से पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह जी दो सालों की सरकार माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार को जनघोषणों की याद दिलाते हैं। दूसरी बात, वर्ष 2009-10 के तत्कालीन मुख्यमंत्री जी के बजट भाषण में..।

सभापति महोदय :- कृपया, संक्षिप्त करें मोहन मरकाम जी।

श्री मोहन मरकाम :- मैं 10 मिनट में अपनी बात कहूंगा। माननीय सभापति जी, हमारी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट प्रस्तुत करने में मैं जहां गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूं, वहीं जनता द्वारा व्यक्त अपार विश्वास के समक्ष नतमस्तक हूं और आगे ये क्या कहते हैं ? संसदीय लोकतंत्र पर आस्था बनाये रखने की पहली शर्त है कि चुनावों के दौरान जो वायदे किये जाते हैं, उन्हें सरकार बनने पर अमलीजामा पहनाया जाये। हमने विधानसभा के चुनाव के समय प्रदेश के गरीब किसान, कामगार, अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों के विकास के लिए अनेक वादे किये। इस बजट में उन वादों को पूरा करने का सार्थक पहल किया है।

सभापति महोदय :- कृपया समाप्त करें।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- मरकाम जी। मरकाम जी।

श्री मोहन मरकाम :- यह वर्ष 2008 का घोषणा पत्र है। एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात प्वाइंट में इन्होंने छत्तीसगढ़ को पलायन मुक्त छत्तीसगढ़, भयमुक्त छत्तीसगढ़ वर्ष 2008 के घोषणा पत्र में वादा किया था। आज ये वर्ष 2018 तक सरकार में में मगर ये कुछ नहीं कर पाये। हमारी सरकार दो वर्षों में 36 में 24 वादे वादे किये।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- मरकाम जी1

श्री मोहन मरकाम :- जी, बोलिए।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- मरकाम जी, घोषणा वादा करना है करके बता रहे हैं। बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता कब देंगे ? दूसरा, आपकी सरकार बनने के बाद क्या पलायन मुक्त हो गया ? पिछले साल आपके रिकॉर्ड में कितने मजदूर पलायन किये थे और इस साल आपके रिकॉर्ड में कितने मजदूर पलायन किये हैं ?

श्री अजय चन्द्राकर :- अभी उनके पास लिखकर नहीं आया है। लिखकर आयेगा तो जवाब आयेगा।

सभापति महोदय :- कृपया, जल्दी समाप्त करें।

श्री मोहन मरकाम :- वर्ष 2014-15 के तत्कालीन मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के रूप में जो बजट प्रस्तुत किया था, उन्होंने कहा था कि किसानों का एक-एक दाना धान खरीदेंगे। 2100 रूपया जो उनके घोषणा पत्र में था, संलक्प पत्र में था। 2100 रूपया धान का समर्थन मूल्य देंगे। 3 साल तक बोनस देंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि आज ये तत्कालीन मुख्यमंत्री हैं और यह वर्ष 2014-15 का बजट है। मैंने पूरा निकाला है। आज कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का चाल और चरित्र इससे साफ जाहिर हो रहा है कि आज कहीं न कहीं माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार जो आज बात हो रही है, लगातार छत्तीसगढ़ की सरकार हमारे हितों की ही रक्षा के लिए लगातार काम कर रही है। ऊर्जा की बात कर रहे थे।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री शिवरतन शर्मा :- अकबर जी, कुछ और भिजवा दो, बचा हो तो। और कुछ पेपर हो तो भिजवा दो।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय सभापति जी, ऊर्जा की बात हो रही है। मैं ऊर्जा की बात बताना चाहता हूं। पिछले मुख्यमंत्री जी ने जो बात छेड़ी, वर्ष 2004-05 के बजट में कहा था कि वर्ष 2007 तक पूरे गांव में बिजली लगा देंगे। वर्ष 2014-15 के बजट में कहा था कि हम 2016 तक लगायेंगे और आज 15 साल राज करने के बाद जो हमारी सरकार जब केन्द्र में डॉ. मनमोहन सिंह जी की सरकार थी।

सभापति महोदय :- मरकाम जी, 45 मिनट हो गये हैं। कृपया जल्दी समाप्त करें।

श्री मोहन मरकाम :- 10वीं, 11वीं, 12वीं, पंचवर्षीय योजना में 900..।

श्री अमरजीत भगत :- मोहन जी, इतने में शिवरतन जी अभी बेहोश हो गये हैं। देखो उधर। (हंसी)

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- जरूरत से ज्यादा पिलाएंगे तो बेहोश तो होना ही है।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय सभापति जी, वर्ष 2004 से वर्ष 2014 तक केन्द्र में बैठी कांग्रेस की तत्कालीन मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। 10वीं, 11वीं, 12वीं पंचवर्षीय योजना में छत्तीसगढ़ राज्य को राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत 920 करोड़ रूपये छत्तीसगढ़ सरकार को दिये थे, मगर उस समय 2018 तक 3666 और 7 हजार से अधिक मजरो-टोलों में बिजली नहीं लगी थी । हमारी सरकार लगातार योजनाएं बना रही है । आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने 35100 पम्पों के ऊर्जीकरण के लिए ऐतिहासिक घोषणा की है । यह ऐतिहासिक घोषणा है । हमें लगता है कि वित्तमंत्री के रूप में मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ के विकास के लिए लगातार काम कर रहे हैं । तत्कालीन मुख्यमंत्री जी हाईट की बात कर रहे थे । वे 10 वर्ष की यू.पी.ए. सरकार को गड्ढे खोदने का, गोबर बेचने की बात कर रहे थे । आपकी सरकार में तो पकोड़े तलने और चाय बेचने को रोजगार माना जाता है, मगर हमारी सरकार छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए, छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए, छत्तीसगढ़ के मजदूरों के लिए, छत्तीसगढ़ की आम जनता के लिए बजट में जो प्रावधान किया है, कहीं न कहीं हर वर्ग उसकी तारीफ कर रहा है, हर वर्ग खुश है और आने वाले इन तीन वर्षों में छत्तीसगढ़ की परिकल्पना के साथ हमारी सरकार आने बढ़ रही है-गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, उस परिकल्पना को साकार करने में हमारी सरकार सफल होगी । सभापति जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- सभापति जी, भारतीय जनता पार्टी की घोषणा पत्र के बारे में, सरकार की नीति के बारे में माननीय चन्द्राकर जी जो जितनी जानकारी नहीं होगी, उससे ज्यादा जानकारी मोहन मरकाम जी को है । मोदी जी पूरे देश में क्यो सफल हो रहे हैं, यह समझ नहीं पा रहे हैं । मरकाम जी उनको आभाश करा रहे हैं ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- माननीय सभापति महोदय, मैं छत्तीसगढ़ के 2021-21 और 2021-22 के बजट में बोलूंगा और मैं कसम खाकर बोलता हूं कि दिल्ली और उत्तरप्रदेश के बारे में नहीं बोलूंगा । जो भी बोलूंगा, सच बोलने की कोशिश करूंगा और जो प्रिंट है, उसी को बोलूंगा ।

सभापति महोदय, माननीय मोहन मरकाम जी, मैं आपकी बात से ही अपना बात शुरू करता हूं । दिल्ली से ही शुरू करता हूं, लेकिन जो उदाहरण है, मैं दिल्ली के बजट पर चर्चा नहीं करूंगा । विनिवेश होने के लिए भाजपा के नेताओं के बाप-दादाओं की सम्पत्ति है क्या ? मैंने जिस शांति से सुना, मैं अपेक्षा करूंगा कि जिस दिन इसका जवाब दूंगा, जब बाप-दादाओं का उत्तर दूंगा तो उस दिन आप कांग्रेस पक्ष के पूरे 70 लोग शांति से सुनिएगा, धैर्य मत खोईएगा क्योंकि यह बात छत्तीसगढ़ से बाहर भी जा रही है और छत्तीसगढ़ में भी उपयोग की गई है कि डिस-इंवेटमेंट भाजपा के नेताओं के बाप-दादाओं का है क्या ? वह किसका है, मैं उसको जरूर बताऊंगा ।

माननीय सभापति महोदय, थोड़ा सा वित्त की बात कर लें और फिर उसके बाद दूसरी बात कर लें । 2020-21 के बजट में जो 95649.71 करोड़ की प्राप्तियां हुईं, उसका पुनरीक्षित अनुमान 91481.97 के आसपास आया और 4167.74 करोड़ शेष राशि रही और वह खर्च ही नहीं किया गया । वह राशि आई नहीं होगी या खर्च नहीं की गई, उसके कारण बजट का आकार घटा, लेकिन उससे जो गंभीर बात है। राजस्व व्यय में पुनरीक्षित अनुमान में 752 करोड़ की कमी आई । मैं पूरा पढ़ देता हूं । 20-21 का बजट अनुमान 81399.95 करोड़ और पुनरीक्षित अनुमान 80647.36 करोड़ है । 752.59 करोड़ की कमी आई । मोटे तौर पर 88 प्रतिशत समझ लीजिए। पूंजीगत व्यय जो 13841.11 करोड़ रखे थे, उसमें पुनरीक्षित अनुमान 10680.51 आया और 3333.6 मतलब 12 प्रतिशत की कमी आई । अब जिस राज्य में पूंजीगत व्यय कम हो रहा है, पिछले साल भी हुआ, इस साल भी हुआ। इसके कारण जो समस्या आ रही है, वह असली समस्या बेरोजगारी की है। माननीय सभापति महोदय, रमन सिंह जी इस विषय को बोल चुके हैं, इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं कहूंगा। वर्ष 2020-21 में शुद्ध लोक ऋण का जो अनुमान लगाया गया था, वह 10859.99 करोड़ रूपये का अनुमान लगाया गया था। वह 17227.89 करोड़ पहुंचा है। अब हम वर्ष 2020-21 में देखें तो जो जी.एस.डी.पी. है, 6.5 प्रतिशत बताया है।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- अजय चंद्राकर जी, तोर मीटिंग हाबे ना, तै मीटिंग आयोजित करके भाषण दे के शुरू कर दे। जाना मीटिंग में।

श्री अजय चंद्राकर :- का हे, भगवान तोला सद्‌बुद्‌धि दे।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- मोर कर हावय।

श्री अजय चंद्राकर :- तोला सद्‌बुद्‌धि दे गा। महाप्रसाद अस ते हां, लेकिन मैं हा तोर सद्‌बुद्‌धि के कामना करत हंव।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- तोला मीटिंग बुला के ऐती भाषण दे के जरूरत का हे, तेला बता।

श्री अजय चंद्राकर :- मे ओखर सदस्य नई हंव, तैं चिंता मत कर। यदि जाहूं तो तोर तनख्वाह जरूर बढाहूं। सदस्य के बढ़े ते मत बढ़े।

माननीय सभापति महोदय, जो ब्याज भुगतान है, वह 6241 करोड़ है। राजस्व कर का वह लगभग 27 करोड़ होता है। अब राजस्व घाटा 2431.35 करोड़ से बढ़कर 12303.75 करोड़ तक हो गया है। अब इससे यह साबित हो रहा है कि 5 प्रतिशत से ऊपर बजट का जी.एस.डी.पी. का घाटा हुआ तो इस बहस से साबित हो रहा है कि जो ऋण है, वह राजस्व कार्यों के लिये लिया गया है, दैनिक खर्चों के लिये लिया गया है, वेतन, भत्ते इस तरह की चीजों के लिये लिया गया है या उपहार बांटने के लिये लिया गया है। वर्ष 2020-21 में आपने जो बात कही है, 2020-21 में 1.5 प्रतिशत की सामान्य वृद्धि है। अमूमन 10 प्रतिशत की वृद्धि मानी जाती है और विगत वर्षों में यह वृद्धि दर्ज भी हुई है। महंगाई प्रतिवर्ष औसतन 4 प्रतिशत माना जाता है। 4 प्रतिशत में यदि डेड़ प्रतिशत की वृद्धि घटा दें तो भी यह बजट ढाई प्रतिशत घाटे का ही बजट है। इस वर्ष भी 4.56 प्रतिशत घाटे का अनुमान लगाया गया। इसका मतलब यह होता है कि इस साल घाटा जब शुरू से ही 4.56 प्रतिशत का लगाया गया है तो आगे चलकर आखिरी तक जब पुनरीक्षित अनुमान या वस्तुस्थिति आयेगी तो यह अनियंत्रित रहेगी। यह साबित हो गया कि पूंजीगत व्यय घटा और घाटा अनियंत्रित है, उसको कोई अनुमान नहीं लगा पा रहा है, यह लगातार है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है,...।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- भूला गे है, सदस्य मन के चिंता करना, तै अपने चिंता में लगे हस।

श्री अजय चंद्राकर :- ये विषय मन हा तोला समझ में नई आवय।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- समझ में नई आये तो छोड़ झंझट खत्म कर।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, एक विषय, 31 मार्च, 2020 की स्थिति में कुल देयताएं। वर्ष 2019-20 के सकल घरेलू उत्पाद से लगभग 22 प्रतिशत बताया गया है। ये जो वित्त सचिव का पत्र है, वित्त सचिव का जो पत्र होता है, वह बजट से ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें जो जानकारी दी गयी है, क्से छिपाया गया है ? वित्त सचिव के पत्र में पेज नंबर 09 में 31 मार्च, 2020 की स्थिति में है। बाकी चीजें जो बतायी गयी है, 2021 की स्थिति में बतायी गयी हैं। 2020-21 दिसंबर की स्थिति में राज्य सरकार के अवशेष दायित्व सकल घरेलू उत्पाद से 4.9 प्रतिशत रहेंगे। अब इसी का उत्तर देखिये। वित्त सचिव के पत्र में 2020 की स्थिति बताई। यदि मैं बोलूंगा कि यह गलत है, ऐसा नहीं बताना चाहिए, ऐसा नहीं छिपाना चाहिए, तो अब जो दूसरा दस्तावेज है, छत्तीसगढ़ राजाकोषीय उत्तर दायित्व बजट प्रबंधन अधिनियम 2005, इसी साल के बजट का यह पत्र है। उसके पेज नं. 4 में एक तो प्रिंट 2020-22 हुआ है, एक तो यही गलती है। उसमें बताया गया है कि राज्य के सकल घरेलू उत्पाद 2020-21, यदि मैं उसे सुधार कर पढ़ूं तो 2020-21 में सकल देयतायें 28.34 है

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

और उसमें छिपाकर बताया गया है। तो पारदर्शिता नहीं है, मैंने पिछली बार भी कहा था कि घाटे को, वस्तुस्थिति को मोटे तौर पर छिपाने का बजट है। इसके बहुत सारे आंकड़े डॉ. रमन सिंह ने पढ़े, इसलिए मैं उन विषयों पर ज्यादा नहीं बोलूंगा।

माननीय सभापति महोदय, इस सरकार का जो गेयर बॉक्स है, वह फंस गया है। वह आगे नहीं बढ़ रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात विश्वसनीयता नहीं है। वित्त मंत्री या सरकार जिन बातों को बजट में कहती है, वह बातें होती दिखनी चाहिए। जैसे उदाहरण बता दूं कि मैं संस्कृति मंत्री था, सन् 2017 के बजट में होगा। देवभवन को अधिग्रहित करना है। विवेकानंद जी का संग्रहालय बनाने के लिए उसमें 5 करोड़ का बजट था। अभी वर्ष 2020-21 के बजट में देव भवन को संग्रहालय बनाया जायेगा, संस्कृति मंत्री बैठे हैं। उसमें एक रूपया भी नहीं है। संग्रहालय हवा में बनेगा ? सचिव महोदया या वह जायेंगे और बात करेंगे और देव भवन संग्रहालय बन जायेगा। मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना, मैंने एक से पूछा कि कैसे, क्या प्रोत्साहन दोगे, तो वह बताने की स्थिति में नहीं है।

श्री अमरजीत भगत :- चन्द्राकर जी, जो विवेकानंद संग्रहालय की बात कर रहे हैं, ओखर पहले बजट एलोकेशन हो चुके हे, ओखर काम होवत हे, काम चलत हे अउ बहुत जल्दी कम्पलीट होने वाला हे। जोन दिन उद्घाटन होही तो तोला बुलाय जाही।

श्री अजय चन्द्राकर :- यहां पर मुख्य सचिव साहब भी बैठे हैं। मंत्री महोदय भी बैठे हैं। पिछले बजट 2020-21 की तुलनात्मक बात हुई। सभी गोठानों को 10 हजार रूपया प्रति महीने दिया जायेगा। उसके बाद 6 करोड़ रूपया रोलर के लिए रखा गया था। सरकार को मेरी चुनौती है कि आप धमतरी जिले को ले लें, मैं बोलता हूं कि अभी चलें कि कौन से गोठानों को साल भर का 12 किश्त मिला है ? आप एकाध गौठान बता दें। प्रदेश में कितने गौठान चालू हो गया मानते हैं, कितने में कम हुआ, मानते हैं और कितना बन रहे, मानते हैं ? मेरे यहां कितने गौठानों में समिति गठित हो गई ? मैं दो गौठानों का उदाहरण भी दे सकता हूं कि गौठान समिति वाले पैसे का मस्त दारू पीयें और बोकरा खाये। तीन किश्त से अधिक तो किसी को मिला ही नहीं है और अभी 8 दिन बाद सत्र खत्म होने वाला है। दो समिति दारू पीये। जो कहा गया था न कि वाइब्रेंट होगा।

श्री अमरजीत भगत :- सभापति महोदय, क्या इस प्रकार की बात उचित है ? अगर गौठान बन रहा है, उसमें दारू पी रहे हैं, इस प्रकार की बात करना ?

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं तो किसी के बारे में कुछ बोल ही नहीं रहा हूं।

श्री सौरभ सिंह :- आप दारू बेच रहे हैं।

श्री केशव चन्द्रा :- नहीं, जो पीये उसमें भी सरकार का फायदा हुआ है।

श्री अमरजीत भगत :- क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, यह तो देखो। इस प्रकार से हर काम में आरोप लगाना और लोगों का मनोबल गिराना, आप हतोत्साहित करने वाला काम मत करिये।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं तो किसी के ऊपर आरोप लगा ही नहीं रहा हूं।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय मंत्री जी, इस बात का सबूत है कि गौठानों में दारू की होम डिलीवरी हो रही है।

श्री अजय चन्द्राकर :- लॉकडान में होम डिलीवरी हुई है, यह प्रश्न के उत्तर में है। होम डिलीवरी करने की योग्यता क्या है ? यह प्रश्न के उत्तर में है। यह विधानसभा की प्रापर्टी है।

श्री अमरजीत भगत :- यह अजय चन्द्राकर जी को होम डिलिवरी के बारे में ज्यादा मालूम होगा।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- ये थोकन बीमार हे, अभी 10-10, 15-15 मिनट मा उठके जाथे। येखर ईलाज करवा।

श्री अजय चन्द्राकर :- तोला सद्बुद्धि मिलय साहब। माननीय सभापति महोदय, मैं वर्ष 2021 की बजट की बात कर रहा हूं। पशु चिकित्सालय के लिए मोबाइल यूनिट बनायेंगे। कृषि मंत्री जी बतायेंगे कि कितने मोबाइल यूनिट चालू हुए ? बस्तर के लिए बोधघाट परियोजना से सिंचित करने का लक्ष्य रखा गया है। उसमें कितना पैसा है भाई ? आप तो कुछ भी लिख दोगे कि मैं तो यह तोड़कर लाऊंगा या रखकर लाऊंगा। प्रसंस्करण के बारे में डाक्टर साहब बोले। सरकार का गेयर बॉक्स खराब हो गया, डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम जी, मैं इसलिए बोला कि आप सबसे सीनियर मंत्री हैं। एक बार खाता खुल गया ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- कहां का खराब हो गया?

श्री अजय चंद्राकर :- एक बार आपने मांग संख्या खोल दी, आप वैचारिक रूप से शून्य हो चुके हैं, आपके पास कार्यक्रम हैं नहीं। आपने पिछले बार मान लो बजट में जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क के लिए 1 करोड़ रूपये का खाता खोल दिया।

श्री अमरजीत भगत :- (अपने आसन से बाहर की ओर आकर) हम इस साल खोल रहे हैं। हम कैसे बतायें आपको। (श्री अजय चंद्राकर द्वारा अपने आसन से बाहर की ओर आकर वक्तव्य दिया जा रहा है) यदि आप आगे आकर पूछेंगे तो हम तो ऐसे ही आपको बतायेंगे। अंदर आपके लिए जगह कम पड़ती है क्या जो बाहर आकर बोलते हैं। (हंसी)

श्री अजय चंद्राकर :- वह आप अपने स्तर का ही इंटरप्सन करेंगे ना।

श्री अमरजीत भगत :- नहीं भाई ठीक है ना, लेकिन जिस ढ़ंग से बाहर आकर बात करते हैं वह उचित नहीं है।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, एक बार मांग संख्या खुल गई, फिर ये खोल दिये कि इस साल 350 करोड़ रूपये दिया जायेगा। अब ये बताना भूल गये कि जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क के उस जगह की वैधानिक स्थिति क्या है। उसके साथ बताते कि हाईकोर्ट ने स्टे दिया है उसके बावजूद हम 350 करोड़ रूपये इसलिए रख रहे हैं, आप छत्तीसगढ़ की जनता को बेवकूफ मत समझिए। माननीय

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सभापति महोदय, पौनी-पसारी योजना प्रारंभ की गई। मैंने पिछले साल बजट भाषण में कहा कि इस पौनी-पसारी को परिभाषित तो कर दो भाई। बस्तर के आदमी को पूछोगे, सुकमा के आदमी को पूछोगे तो वह क्या समझेगा।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- समझ आही तब तो बताये जाही। पौनी पसारी ल तेहं जानथस कुछू। जानबे त बताहूं।

श्री अजय चंद्राकर :- मैं तो कागज देखकर पढ़ नहीं रहा हूं, पिछले साल बजट में कहा गया कि सारे 166 या 160 में पौनी पसारी मार्केट खोला जायेगा। पौनी पसारी को परिभाषित करना इसलिए जरूरी है कि यदि शहरी क्षेत्र में बनेंगे तो सुकमा, बीजापुर और गीदम भी नगर पंचायत है और सूरजपुर भी नगर पंचायत है। पौनी पसारी को पहले परिभाषित तो कीजिए। ये बजट में आ गया लेकिन नियम तो बनाये कि पौनी पसारी मानते किसको हैं क्योंकि हर जगह पौनी पसारी अलग-अलग चीज होती है। मैदानी क्षेत्र में उसकी परिभाषा और उसके मतलब अलग होते हैं। आप ऐसे शब्द का इस्तेमाल राजनीतिक तौर पर कर रहे हैं और उस राजनीतिक तौर में बिना मापदंड तय किए अपने चहेतों को बांटेंगे। और मैं जितना ये पौनी पसारी जानते हैं उतना ही जानता हूं, मैं एक सामंती शब्द का उपयोग नहीं करना चाहता।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- ये पुराना बता रहे हैं कि अपने अपने लोगों को बांटते थे। अंधा बांटे रेवड़ी चीन्ह चीन्ह के देय। ये पहिली बांटे रहिस तेला बतात हवय।

श्री शिवरतन शर्मा :- तोला कुछ पौनी समझ में आथे। कभू पौनी लगाये हस। जब समझ में नई आवय त खड़े झन होये कर। पहिली पौनी काला कथे तेला बैठके समझ, फेर गोठियाबे।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- मैं सब जानत हौं, मैं तो छत्तीसगढ़िया हौं, इहें के रहईया हों। मैं जानत हों।

श्री अमरजीत भगत :- शिवरतन जी, अगर आप पौनी पसारी के बारे में पूछेंगे तो एक बार समझ में आता है लेकिन ये ह छत्तीसगढ़िया आदमी हे, अगर अजय चंद्राकर पूछें कि पौनी पसारी क्या है तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है।

श्री अजय चंद्राकर :- मैं सामंती शब्द का उपयोग नहीं करना चाहता, मैं पौनी पसारी की जमीन छोड़ा हूं। क्या होती है, मेरे घर में पौनी पसारी फोकट में होती थी। समझ रहे हो, उसको मैं बताना नहीं चाहता। मेरे को आप क्या बताओगे। मैं तो आपके हित में बता रहा हूं कि सीतापुर में पौनी पसारी होती है या नहीं होती है उसे मुझे बताना। छत्तीसगढ़ की जो विविधता है न ये दुर्ग और रायपुर के मैदानी क्षेत्र की संस्कृति छत्तीसगढ़ की संस्कृति नहीं हो सकती।

श्री अमरजीत भगत :- लेकिन तें अतका गुस्सा में कांपत काबर हस भाई। बढ़िया आराम से बोल।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, मैं बोला कि आपके पास कार्यक्रम का अभाव है। बार-बार उस चीज को रिपीट करते हैं कि गेयर बॉक्स फंस गया। अभिलेखागार बनायेंगे। यह पिछले साल के बजट में भी है कि छत्तीसगढ़ का अभिलेखागार बनायेंगे। इस साल भी लिख दिया कि अभिलेखागार बनायेंगे। भाई, एक बार आपने हेड खोल दिया, कार्यक्रम नहीं बनाना आता, घोषणा करनी नहीं आती तो छत्तीसगढ़ के लिए हम बैठे हैं साहब। विपक्ष को बुलाईये, हम बतायेंगे कि छत्तीसगढ़ के लिए क्या-क्या योजना बनाई जा सकती है।

श्री अमरजीत भगत :- आपको 15 साल तक खूब देखा है साहब। आप जमीन को छोड़कर आसमान में सड़क बनाने चले थे।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, क्या है मोहन जी चले गये, कोंडागांव जिला खुदाई से प्राप्त हुआ है, पुरातत्व विभाग लाईसेंस लिया है उससे प्राप्त हुआ है। सूरजपुर जिला खुदाई से प्राप्त हुआ है, हमने 15 साल में नहीं बनाया। वह मोहनजोदड़ो और हड़प्पा काल के हैं।

श्री अमरजीत भगत :- आपने 15 साल में बिलासपुर को कैसे खोदा है, बिलासपुर को कैसे खोदापुर बना दिये, ये पाण्डे जी बतायेंगे।

श्री सौरभ सिंह :- पाण्डे जी उसी चक्कर में जीत गये, नहीं तो पाण्डेय जी भोपाल से सी.वी.रमन यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार हो जाते।

सभापति महोदय :- माननीय सदस्य को अपनी बात रखने दें। माननीय मंत्री जी, कृपया बैठिए।

श्री अमरजीत भगत :- कुछ बोलने से पहले थोड़ा देख-दाख के बोला करिए।

सभापति महोदय :- माननीय मंत्री जी, कृपया बैठिए।

श्री अमितेष शुक्ल :-माननीय सौरभ भईया ने स्वीकार कर लिया, यह हमको अच्छा लगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, रामवन गमन पथ के विषय में कहना चाहता हूँ। रामवन गमन पथ पिछले साल उसका मांग संख्या खुल गई 10 करोड़ है इस साल 30 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। एक मांग संख्या रविशंकर विश्वविद्यालय खुल गई, मान लीजिए यह उदाहरण है तो इस साल फिर रविशंकर विश्वविद्यालय, यदि आप उसी में पैसे देंगे। मैंने 196 ठोक दिया हूँ तो 196 मांग संख्या में सबको एक ही विषय को दुबारा-दुबारा दूं क्या, अब उस 10 करोड़ में क्या बताया गया कि वृक्षारोपण हुआ है। 10 करोड़ में नवाचार में रामवन गमन पथ के 3 जगहों में वृक्षारोपण हुआ है। यह उपलब्धि है। यह विश्वसनीयता है। ये इनके कार्यक्रम हैं। अब इस साल 30 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। माननीय सभापति महोदय, एक बना है कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड, यह पिछले साल था।

श्री अमरजीत भगत :- जिस कर्मचारी चयन बोर्ड का आप बोल रहे हैं, उसमें भर्ती हो रही है।

सभापति महोदय :- माननीय मंत्री जी आप बैठे।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :-माननीय सभापति महोदय, बिलासपुर, सरगुजा या बस्तर में एक ठोक भर्ती नहीं हो रही है। यह बता दें कि एक चपरासी, एक संविदा की भर्ती हुई हो तो ? आप इसमें भी देख लीजिएगा ये दूसरे चरण की जब इनकी नियुक्ति होगी तो पी.एस.सी में जो रखे हैं वह राजनीति प्रतिपूर्ति का साधन बनेगा। जैसे इसमें 4 बोर्ड बना रहे हैं पौनी पसारी तर्ज में घानी बोर्ड और रजकवार बोर्ड यह सब बनेगा तो वह सिर्फ एक कार्यकर्ता को देने के लिए बना रहे हैं। यह प्राधिकरण के लोग उनसे मिले थे। एक प्राधिकरण का आदमी बैठा है। कलेक्टर कमीश्नर को चिट्ठी लिखता है कि गाड़ी दे दो, ऑफिस दे दो, कलेक्टर कमीश्नर को लिखता है अभी दो सालों में उनकी गाड़ी तय नहीं हो पायी है ऑफिस तय नहीं हो पायी है (शेम-शेम की आवाज) वह चार लोगों के नियुक्ति राजनीति नियुक्ति भर होगी, कुछ नहीं होगा। वर्ष 2021 के बजट की समाप्ति, 5 जगहों पर साइबर थाना खोलेंगे एक जगह रायपुर में खुला हुआ है। एक जगह। बजट कुछ नहीं। सब में पिछले अनुपूरक में आया था कि 100 रूपये में पूरा रोड डेवलपमेंट वाली सड़क बनायेंगे जिसके लिए 150 करोड़ रूपये का प्रावधान है अभी ऋण ही नहीं मिला है।

माननीय सभापति महोदय, इस बजट में जो बात बोली गई है। मैं कुछ चीजों में आपका ध्यान आकर्षित कर देता हूँ। पिछले बजट में क्या वस्तुस्थिति है, वह बताने की कोशिश की कि इस सरकार की विश्वसनीयता क्या है? अब मैं बजट की गोपनियता में बोल देता हूँ। जो बात माननीय मुख्यमंत्री जी राजयपाल के अभिभाषण में बोले कि पहले 53 बिस्तर था उसको बढ़ाकर हमने इतना बिस्तर कर दिया। इतना आई.सी.यू. था, उसको इतना कर दिया।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, एक मिनट।

सभापति महोदय :- माननीय बृहस्पत सिंह जी कृपया बैठ जाईये।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, मैं आपका उत्तर भी दे सकता हूँ, लेकिन आप भड़केंगे नहीं, कूदेंगे नहीं, नाचेंगे नहीं और व्यवस्था नहीं देंगे तो।

सभापति महोदय :- माननीय चन्द्राकर जी आप मूल विषय में आएं।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय चन्द्राकर जी, आपके जोड़ का वही व्यक्ति है।

सभापति महोदय :- माननीय मंत्री जी, कृपया हस्तक्षेप न करें।

श्री अजय चन्द्राकर :-माननीय सभापति महोदय, जो आंकड़े बजट में आएं, वह आंकड़े मुख्यमंत्री जी राज्यपाल के अभिभाषण में बोल चुके थे जो ठेकेदारों से पंजीयन की बात कही। शहर में पहले बी पंजीयन, सी पंजीयन उसके पोस्टर लग चुके हैं। क्या इस बजट की गंभीरता है ? मैंने वर्ष 2020 के आंकड़े बताएं। वर्ष 2021-22, वर्ष 2022-22 यह गलत प्रिंट हुआ है। क्या इसकी विश्वसनीयता है ? यह खड़े होकर सुधारते हैं कि 1600 करोड़ नहीं, 16 करोड़ है। यह इसकी गंभीरता है। मैंने आपको वही बोला सी मार्ट। डॉ. रमन सिंह जी ने कहा कि बाउण्ड्री वॉल बनाओगे, 119 की जगह चयन हुआ है बाकी

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

प्रक्रिया में है अब वह सी मार्ट होगा। सी मार्ट में बेचने के लिए प्रसंस्कृत चीजें आपके पास कहां से आएंगीं ?यह ताली बजा दें व्यवहारिक क्या है ? ढेकी कितना खुल गया, जिसका आप चावल लाओगे ? कितने शहद प्रसंस्करण केन्द्र हैं मेरे जिले में एक जबर्रा में है, एक दुबली में है। आप जो-जो चीजें बोल रहे हैं कहां से प्रसंस्कृत आएंगीं और कौन से सी-मार्ट में भेजोगे ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- ढेकी भी खुलही, मूसर भी खुलही। ओमे दिक्कत का हे, तोला बता ?

श्री अजय चन्द्राकर :-माननीय सभापति महोदय,ग्रामीण कृषि मजदूरों, रजक बोर्ड, चर्मशिल्प, विकास बोर्ड यह राजनीतिक पद है इसमें कोई गंभीरता नहीं है। यह ग्रामोउद्योग जब पहले से है तो उरनको तो कुटीर उद्योग के लिए फाईनेंस की नीति बनानी चाहिए, संरक्षण और ट्रेनिंग की नीति बनानी चाहिए। लोहार को कोयला एनएमडीसी देगी कि राज्य सरकार देगी। इसकी नीति बनानी चाहिए। बोर्ड बनाने से पौनी पसारी के उन लोगों का कोई भला नहीं होना चाहिए। आज ही देखे हो कि 45 लाख बांस की जरूरत थी और यहां 15 लाख बांस पैदा होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान है तो 20 लाख नार्थ इस्ट से आमंत्रित करें, आयातित करें। यह छत्तीसगढ़ियों की सरकार है, बंसोड़, कर्रा लोग छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, आपको कौन ने मना किया है, आपको बस कर्ज भर लेना है और कुछ थोड़ी करना है। 30 लाख बांस आयातित करने के लिए कर्ज भर लेना है। माननीय सभापति महोदय, कृषि भूमिहीन श्रमिकों की बात बजट में कही गई है कि ग्रामीण कृषि भूमिहीन श्रमिकों को सहायता हेतु नवीन न्याय योजना प्रारंभ की जायेगी। मैं बजट में नहीं देखा कि 1 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये का प्रावधानरखा गया है।

श्री अमरजीत भगत :- आप अभी से इतनी आवाज करने लगे, बजट के ये असर है। पहले बजट को पूरा पढ़ो।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं जल्दी पढ़ देथौं। माननीय सभापति महोदय, मैं मानसिक रोग वाला हमेशा प्रश्न लगाता हूं लेकिन अब इसकी जरूरत ज्यादा है। बहुत लोग उधर हताश होंगे।

श्री कुलदीप जुनेजा :- आप बार-बार प्रश्न क्यों लगाते हो?

सभापति महोदय :- जुनेजा जी बैठिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- उधर हताश, निराश लोग बहुत हैं। मानसिक इलाज की जरूरत है। लिस्ट में देरी हो रही है, ढाई साल निकल चुके हैं।

श्री अमरजीत भगत :- देखिये जब कोई सरकार से हटता है न तो आदमी मानसिक रूप से विकृत हो ही जाता है। उसका असर साफ-साफ दिखाई पड़ रहा है।

श्री अजय चन्द्राकर :- मोहन मरकाम जी लाख छिपायें, वह मानसिक रूप से अवसाद ग्रस्त बेचारे खुद हैं, मैं उनके साथ हूं। जो उनको मिलना चाहिए, वह नहीं मिला। पूर्व मुख्यमंत्री के लड़के माननीय

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अरूण वोरा जी हैं। माननीय सभापति महोदय, हम दो साल से बोल रहे हैं फ्लेगशिप की योजना नरवा, गरूववा, घुरवा, बाड़ी है। आप थोड़ा सा धन्यवाद दे देते कि आप अभिसरण (convergence) से बनाते हैं, आप convergence कौन-कौन सी स्कीम से करते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यहां बैठे हुए मंत्री जी से जरूर जानना चाहूंगा कि उसमें convergence कौन-कौन सी स्कीम से होता है, तब निकलेगा भारत सरकार का योगदान कितना है। ऐसे नहीं निकलेगा।

माननीय सभापति महोदय, कैम्पा का प्रश्न आया था। एक मंडल के एक वन परिक्षेत्र में पहाड़ी क्षेत्र में 17 नरवा का निर्माण किया गया है। हम लोग मैदानी क्षेत्र में हैं, हम तो आज तक हमारी विधानसभा में एक नरवा को नहीं देखे हैं। हमारी विधानसभा का पूरे बजट में कुछ नहीं है, अपनी विधानसभा के बारे में बोलना बेकार है। पांच-पांच करोड़ की दो-तीन सड़के हैं। हम एक भी नाला नहीं देखे हैं। कैम्पा से बनायें चाहे कहीं से बनायें, बड़ा-बड़ा नाम लेते हैं कि हम जी.पी.एस., सेटेलाईट सिस्टम से बनायेंगे और वह भोसकेगा नहीं। सी.एस.साहब छत्तीसगढ़ी शब्द है। भोसकना यानि बैठ जाना, गिर जाना। कोई नाला बनायेगा, वह भोसकेगा नहीं। वह जो तीन ठो भसका है, वह ऐसा ही है, उतना चलता है। कांग्रेस की सरकार है, वह बहुत छोटा विषय है, उतना चलेगा।

माननीय सभापति महोदय, गोबर-धन योजना, अब गोधन न्याय योजना के बाद गोबर-धन योजना आती है। 400 करोड़ रुपये का प्रावधान गोबर-धन योजना में क्यों है? एकात मंत्री जी को बताना चाहिए कि गोबर धन योजना क्या है और उसमें स्वच्छता के द्वितीय, तृतीय चरण के लिए 400 करोड़ रुपये की जरूरत क्यों है? तब पता चलेगा कि केन्द्र सरकार की भूमिका क्या है? माननीय सभापति महोदय, मैंने अभिलेखागार के बारे में कहा। इसमें भी 2021-22 के बजट में अभिलेखागार है। आपको अभिलेखागार का बंटवारा लेना है। दो तरह से बंटवारा लीजिए। पहले भोपाल जाईये।

श्री अमरजीत भगत :- क्या 15 साल तक घास छील रहे थे? आपने 15 साल तक क्यों नहीं लिया? हम उसको कर रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं नहीं किया, मैं स्वीकार कर लिया। आप क्या रहे हो, आपकी डिमांड मांग में बोलेंगे। दो साल का बजट आ गया है, पिछले बार भी अभिलेखागार था, इस बार भी अभिलेखागार है।

माननीय सभापति महोदय, श्री राम वन गमन पथ के बारे में बोला। रीजनल साइंस सेंटर को जब डॉ. रमन सिंह जी ने बनवाया, दृष्टिकोण क्या होता है। सड्डू में जो जमीन दी गई है वह साईंस सेंटर के लायक दी गई है। 1 करोड़ 80 लाख में एक खेप बनाने से काम नहीं चलता। अहमदाबाद या कलकत्ता की तरह हमको अत्याधुनिक साईंस सेंटर बनाना था, उस अंदाज से उसके लिए जगह दी गई है। दृष्टिकोण यह होता है। पहले रीजनल फिर उसका उन्नयन।

श्री बृहस्पत सिंह :- उसको बनाने के लिए आप लोग कितना दिये थे?

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, मैं कुछ आंकडें पढ़ देता हूं। 30-11-2020 की स्थिति में 33 हजार, अब वह 36 हजार है। डॉ साहब ने उसको बोल दिया है। किसानों के बिजली के आंकडें 36 हजार से ऊपर हो गये, इस बार बजट 100 करोड़ है। क्योंकि किसानों को सिर्फ 2500 रुपये चाहिए और 2500 रुपये को मैं परिभाषित करने के लिए तैयार हूं कि उसको कितना पड़ा । अक्टूबर आखिरी में लुवाई शुरू हो गई थी, लू के सीधे ले जाते थे, लुए, ढुलाए, 4000 रूपये एकड़ मेरे ईलाके में हुआ । बोरा में भरकर देने का फिर ब्यारा बनाये फिर उसको रखे । वह जो आपके 2500 का आंकड़ा है न, अब काम नहीं करेगा । ग्रामीण जान गये कि 01 दिसंबर से 2 महीने जब धान रखे, उसकी सूक्ती और जोड़ लो 2500 काम नहीं करना है, 4000 रूपये एकड़ मींझ के, भरकर देने में ठेका था, जो पहले नहीं देते थे । एक लाख से ऊपर अस्थायी कनेक्शन हैं । उसमें तो एंट्री है, जाओ और एंट्री दो । अब इस साल डेढ़ सौ करोड़ रूपया बजट है । डॉ. साहब ने उसका उल्लेख कर दिया, मैं नहीं बोलूंगा तो मैं आपको धन्यवाद दे देता हूं । आप सन् 1980 से लड़ रहे हैं, आप दीर्घायु रहें, आप शतजीवी हों लेकिन आपकी पीढ़ी सौ प्रतिशत नहीं देख सकती क्योंकि आप यदि उत्तर को देखेंगे तो सन् 2017-18, 18-19 तक कोई लक्ष्य नहीं होता था, लक्ष्य कब घोषित हुआ सन् 19-20 से, 20-21 से 10 हजार होगा, इस साल 15 हजार होगा । उसके पहले यह था कि जो किसान आयेगा उसको हम बिजली देंगे, बिजली का खंभा देंगे । कैबिनेट में बैठते हो, फर्जी किसान मत बनो, हाथ उठाने वाले किसान मत बनो ।

सहकारिता मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) :- उसमें उसकी पूर्ति करेंगे ।

श्री शिवरतन शर्मा :- शत-प्रतिशत को देने की बात हो रही है । (व्यवधान)

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- जो भी उसमें आएगा ।

श्री अजय चंद्राकर :- 36 हजार किसान और इस साल और बढ़ जायेंगे।

श्री शिवरतन शर्मा :- 1 लाख 1,123 लोगों का पंप कनेक्शन अस्थायी चल रहा है । (व्यवधान)

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- जो लक्ष्य रहता है कि कम से कम हो, उसमें उससे भी अधिक कर सकते हैं, उसमें जितने किसान आयेंगे उन सबका होगा ।

श्री शिवरतन शर्मा :- आप शत-प्रतिशत लोगों को देने की घोषणा करो ।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- क्या आपने आज के उत्तर में नहीं सुना, आज बोले कि जितना आया था सबको पूरा कर दिये, आगे जो भी आयेगा उसको करेंगे । आप लोग बीच-बीच पर ध्यान नहीं देते हैं ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, इसमें है कि 3 मेडिकल कॉलेज खोले जायेंगे । यह केंद्र प्रवर्तित योजना है, यह लिखा है । वर्ष 2020-21 के लिये मान्यता नहीं मिली है, यदि राजा साहब होते तो मैं उनको बताता कि कॉलेज कैसे खुलता है, अंबिकापुर का मेडिकल कॉलेज खुलवाने उनको ले गया था । कैसे खुला उसको बताता कि इकबाल होना चाहिए, इच्छाशक्ति होनी चाहिए कि

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अंबिकापुर में, जगदलपुर में या रायगढ़ में कैसे खुला ? कागज में मेडिकल कॉलेज, ग्रांट का पैसा देने के लिये उनके पास पैसा नहीं है ।

सभापति महोदय :- 30 मिनट हो गये हैं ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, बस 2 मिनट में समाप्त कर देता हूं । देखिये, मैं प्रश्न का उत्तर पढ़ रहा हूं, पिछले सत्र का जो दो दिन पहले समाप्त हुआ है । जी हां, कोविड-19 एवं आवंटन की कमी के कारण कुल 4 लाख 91,502 आवास के लक्ष्य में कटौती की गई है, यह लिखा है । प्रश्न का उत्तर है अब इससे ऊपर और क्या लिखा है उसको पढ़ देता हूं । वर्ष 2020-21 में 1 लाख 57 हजार आवास स्वीकृत किये गये, उसके लिये राशि 800 करोड़ रूपये राज्यांश की जरूरत होगी, वर्ष 2020-21 के बजट में उसके लिये 400 करोड़ रूपये का प्रावधान है । आपके लिये गरीबी एक नारा है । आप समझ रहे हैं न, संपूर्ण स्वच्छता ।

श्री अमरजीत भगत :- आप जिस ढंग से बात कर रहे हैं न, आप वन वे ट्रेक में हैं । आपको अपनी जो जिम्मेदारी है उसके बारे में आपको एहसास ही नहीं है, अगर भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ का पैसा रोका तो क्या आप लोगों ने एक-बार भी दिल्ली जाकर बात की ।

श्री नारायण चंदेल :- श्री अमरजीत जी, दिन भर टोका-टोकी में इधर कागज चिपक जा रहा है । थोड़ा सा ध्यान रखिए । (हंसी)

श्री अमरजीत भगत :- नहीं, अगर प्राप्ति होगा तो खर्चा करने में कोई दिक्कत नहीं है। कोविड पीरियड में इसमें कमी आयी है, यह तो पूरे देश में सभी राज्य सरकारों ने कटौती की है, खुद प्रधानमंत्री जी ने सांसदों की निधि काट दी । सभी को छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहिए कि विधायक निधि नहीं काटे, किसी के भी तन्ख्वाह में कटौती नहीं की, आप कहां की बात करते हैं । केंद्र सरकार ने सबका पैसा रोक दिया ।

श्री बृहस्पत सिंह :- बढ़ी हुई राशि लेने से आज श्री चंद्राकर जी वापस करने की घोषणा करने वाले हैं ।

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- जबकि ये लोग कोरोना में दिल्ली में दान दिये थे।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, तहसील बनाये, हम जनता के लिये बोलते हैं । तहसील बनाना विषय नहीं है ।

समय :
3:00 बजे

हमने भी बहुत से कलेक्टोरेट बनाए, डॉ. रमन सिंह जी ने जो प्रशासन का विक्रन्द्रीकरण किया, जितने सब डिविजन बनाए, जितनी तहसीलें बनाईं वे इन तहसीलों के सामने कुछ नहीं हैं । सवाल है प्रशासन से दूर करना, प्रशासनिक शैली विकसित करना । आपकी प्रशासनिक शैली क्या है, मैं हमेशा

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

बोलता हूं कि इधर बैठे अफसर लोग हिंदुस्तान की सर्वोच्च प्रतिभाएं हैं । जो सीनियर लोग हैं वे या तो बाहर हैं या खाली बैठे हैं । जूनियर लोग अच्छा काम करते हैं या नहीं करते हैं, उसके बारे में टिप्पणी नहीं करता ।

श्री अमरजीत भगत :- कल हम लोगों ने इसी सदन में आपका भाषण सुना । आपने किस तरह से अधिकारियों को पागल कहा था । कल इसी सदन में हम लोगों ने आपकी बात सुनी थी ।

श्री अजय चन्द्राकर :- एक्सटॉर्शन, प्रशासन परेशान है । प्रशासन कैसा है ? नेता जी बोल रहे थे कि छत्तीसगढ़ में एक आदमी को ज़िंदा रहने के लिए घूमना पड़ रहा है । प्रशासन का निचले स्तर से लेकर ऊपर स्तर का आदमी परेशान है । कांग्रेस का एक नेता थाने में घुसता है और देता है । दो दिन तक सोचते हैं कि एफ.आई.आर. करें या न करें, सीसीटीवी में दिख रहा है । आप कांग्रेस के हैं, उनका मनोबल कैसे आएगा ? इसलिए वसूली से मुक्त हो, ठेका पद्धति से मुक्त हो और लालफीताशाही कम हो, यह प्रशासन होना चाहिए ।

माननीय सभापति जी, घोटुल पर एल्विन जी ने बहुत किताबें लिखीं, वे महात्मा गांधी जी के दत्तक पुत्र कहे जाते हैं । वह एक स्वाभाविक क्रिया है, मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि आप घोटुल के चक्कर में मत पड़ो । वह एक स्वाभाविक क्रिया है । उसको होने दीजिए, घटने दीजिए । घटने के जो कारण हैं, यदि जंगल कट रहे हैं, यदि वहां तक शहरीकरण जा रहा है तो इन चीजों को रोकने की जरूरत है, उन परम्पराओं को सहेजने की जरूरत है ।

सभापति महोदय :- कृपया समाप्त करें ।

श्री अजय चन्द्राकर :- जी । आपने मुझे तीन-चार बार समाप्त करने को कहा इसलिए मैं आखिरी बात कह देता हूं । बजट पारदर्शी नहीं है, बजट सिर्फ और सिर्फ दुर्ग संभाग का बजट है, इस बजट में क्षेत्रीय असंतुलन है और पहली बार ऐसी बात हुई है कि यह बजट राजनीतिक बजट दिखता है । राजनीतिक बजट इसलिए दिखता है कि दूसरे जनप्रतिनिधियों की भावनाओं का सम्मान यदि नहीं करेंगे तो आपकी यह नीयत छत्तीसगढ़ में असंतुलित विकास को पैदा करेगी । छत्तीसगढ़ में असंतुलन को पैदा करेगी । आपके पास राशि है या नहीं है, लेकिन भौगोलिक दृष्टि से राजनीतिक दृष्टि से यह क्षेत्रीय असंतुलन वाला बजट है, इसे राज्य का बजट नहीं कहा जा सकता। कानूनी तौर पर भले ही हम कह सकते हैं कि हम बजट पारित कर रहे हैं फिर विनियोग पारित होगा, वह भी एक संवैधानिक दायित्व होगा लेकिन मैं तो अपने निर्वाचन क्षेत्र के बारे में बात नहीं करूंगा लेकिन अभी दो-चार लोगों का निर्वाचन क्षेत्र देखा । उसके लिए पी.डब्ल्यू.डी. मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद् देता हूं कि उन्होंने सबको एक-एक, दो-दो करोड़ रूपए का काम दे दिया है । मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना की 200 करोड़ रूपए की अलग पुस्तक छपी है । मैंने पहली बार 200 करोड़ की अलग पुस्तिका छपी है । उससे बड़े-बड़े काम हो गए लेकिन वह नहीं छपा । मैं यह चाहता हूं कि जो बात रमन सिंह जी ने कही कि जो प्राथमिकता

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

में सिंचाई परियोजनाएं हैं, जो प्राथमिकता की शिक्षा के कार्य हैं, स्वास्थ्य में प्राथमिकता की जरूरत है । आप केवल स्वास्थ्य का एक, डेढ़ परसेंट बजट बढ़ाते हैं और बाकी सबमें बजट काटते हैं । एक जो मेरी इच्छा है उसको जानते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं । यह छत्तीसगढ़ आय-व्यय संक्षेप में है । इसमें मैंने टैग लगा रखा है कहां से पैसा आता है और कहां व्यय होता है । इसमें प्रतिशत में प्रशासनिक सेवाएं 8 प्रतिशत, ब्याज संग्रहण और ऋण परिशोधन में 8 परसेंट खर्च होता है और 10 परसेंट अन्य । यह अन्य क्या है भाई । यह अन्य खर्च क्या होता है, इसे सदस्य क्यों नहीं जान सकते, सदन क्यों नहीं जान सकता कि यह अन्य खर्च क्या होता है । सामाजिक सेवाओं में ही चिकित्सा, कला, खेलकूद, संस्कृति, शिक्षा, स्वास्थ्य में 8 परसेंट, जल आपूर्ति और सफाई में 1 परसेंट, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, पोषाहार में 4 परसेंट, आवास और शहरी विकास में 4 परसेंट, इसमें भी 2 अन्य । यह 2 अन्य क्या है ? 2 अन्य को सदन क्यों नहीं जान सकता ? इसमें इतनी पारदर्शिता क्यों नहीं होनी चाहिए कि यह अन्य क्या है, यह बताया जाए । इसीलिए मैं कहता हूं यह कटमनी, पॉकिटमनी का बजट है और यह बात कहते हुए राजनीतिक रूप से असंतुलित, भौगोलिक रूप से असंतुलित बजट है, मैं इसका विरोध करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं । जय हिन्द, जय छत्तीसगढ़ ।

सभापति महोदय :- बजट पर सामान्य चर्चा हेतु 23 सदस्यों के नाम शेष हैं। मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया संक्षेप में अपनी बात रखें। श्री संतराम नेताम जी।

श्री संतराम नेताम (केशकाल) :- माननीय सभापति महोदय, हमारे विपक्ष के साथी बजट का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। मैं हमारे विपक्ष के साथियों के लिए दो लाइन कविता कहना चाहता हूं और फिर अपनी बात की शुरूआत करूंगा। कई जलजले देखे हैं हमने 15 साल के इनके कार्यकाल में, कई जलजले देखें है हमने 15 साल के भाजपा के कार्यकाल में और कब से बैठे थे कम हम, माननीय मुख्यमंत्री जी के अच्छे बजट के इंतजार में। (मेजों की थपथपाहट) मैं अभी पूर्व मुख्यमंजी जी को सुन रहा था। वे 3 साल के बजट का तुलनात्मक भाषण दे रहे थे। उन्होंने अपने भाषण में यह भी कहा कि ऐसा बजट है कि आने वाले समय में अधिकारियों और कर्मचारियों की वेतन कटौती हो जायेगी। सभापति महोदय, मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं। पार्लियामेंट में हमारे एक साथी गये। वे हमारे साथ विधायक हुआ करते थे। उन्होंने अपनी पीड़ा बतायी कि हमारी जो निधि है, उसे काट दिया गया है। हमें निधि बंद कर दिये हैं। अब हम क्षेत्र का दौरा कैसे करेंगे ? स्वाभाविक बात है जब हम क्षेत्र में जायेंगे तो लोगों की मांग रहती है। उनकी मूलभूत जरूरत की चीज है चाहे रंगमंच हो, पुल है, पुलिया है, ऐसे विषम परिस्थितियों में वे अपने क्षेत्र का दौरा नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी बात, हमारे सांसदों को भी और हम विधायकों को भी जब हम गांव का दौरा करते हैं तो हमारी माता-बहन आरती लेते हैं। वे थाली लेकर निकलती हैं तो जेब में पैसा नहीं होता है। ऐसा कंडीशन आ गया है। पुल मांग रहे हैं, रंग-मंच मांग रहे हैं। सड़क मांग रहे हैं। हम कैसे जवाब देंगे? लेकिन उनके लिए एक लाइन भी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

नहीं बोला। सभापति महोदय, हम पिछली बार विधायक थे। मात्र 1 करोड़ रूपये का हमारा विधायक निधि था। हमारे मुख्यमंत्री जी ने विधायकों की चिंता करते हुए, क्षेत्र के विकास की चिंता करते हुए उन्होंने एक करोड़ से सीधा-सीधा दो करोड़ कर दिया है। इसलिए हमारे माननीय सदस्य बृहस्पत सिंह जी ने कहा कि अगर बढ़ा राशि को माननीय अजय चन्द्राकर जी वापस करने की घोषणा क्यों नहीं करते? सभापति महोदय, 4 लाख पूर्व कार्यकाल में जनसंपर्क निधि में देते थे। आज हम लोगों को 10 लाख रूपया मिल रहा है। हमारा 400 पाराटोला गांव पड़ता है। हम जब जाते हैं तो लोग वहां पर अपनी-अपनी डिमांड रखते हैं। कोई बाजा के लिए, कोई और सामग्री के लिए, कोई खेल सामग्री के लिए, कोई और भी चीज के लिए हम दे नहीं पा रहे थे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि बिना डिमांड किये, बिना हम विधायकों के कहे बगैर उन्होंने सीधे-सीधे 4 लाख से 10 लाख रूपया कर दिया। यह हमारी सरकार और मुख्यमंत्री की सोच है। ऐसा बजट उनके द्वारा लाया गया है कि पूरे प्रदेश की जनता के लिए हमारे बस्तर के लोगों के लिए मैं इसे बहुत बड़ा अच्छा बजट समझता हूं। जैसे गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का वे सपना लेकर आये हैं, उसके रूपांतर हम चल रहे हैं। निश्चित तौर पर हमारे यहां जो काम हो रहा है। गोधन न्याय योजना का हमारे बहुत से साथी मजाक उड़ाते हैं। गोबर की खरीदी हो रही है। अभी हमारे दो-तीन भाषण में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी को जब मैं सुन रहा था तो उन्होंने मोटर साइकिल का उल्लेख किया। मोटर साइकिल खरीदना क्या बुरा है? यह निश्चित तौर पर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरे विधान सभा में बड़ेराजपुर ब्लॉक के ग्राम लिहागांव में गोठान चल रहा है। वहां पर एक बच्चे से मैंने पूछा तो वह बोला कि मैं पढ़ता हूं और मैं वहां का निरीक्षण करने गया तो उन्होंने बताया कि मैं प्रत्येक दिन 2 क्विंटल गोबर बेचता हूं और आप समझ सकते हैं कि गोबर बेचकर अगर कोई आय पैदा कर रहा है, अगर अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रहा है, अपनी पढ़ाई का, शिक्षा का जो फीस पटा रहा है, मोटर साइकिल ले रहे हैं। मैं एक पुराने दिन की याद दिलाना चाहता हूं। आप भी किसान घर के बेटे हैं। हमारे यहां जब धान काटते थे तो हमारे माता-पिता लोग जब खेत में जाते थे और हमारे और भाई बहन लोग जाते थे तो धान में जो छूटता था, उसे शिला बोलते थे। मुझे अच्छी तरह याद है । हम लोग जब शिला बिनने के लिए जाते थे और धान को उठाने के लिए जाते थे और एक-दो किलो या आधा किलो धान बेचने के लिए दुकान चले जाते थे, वहां चॉकलेट लेते थे, उस समय पीपरमेंट बोलते थे, वह आपको याद होगा । लेकिन अभी बहुत दिनों का अंतराल हो गया था, बच्चे वह धान का सिला उठाने नहीं जा पा रहे हैं । अभी बच्चे दो-तीन किलो गोबर लेजाकर बेच रहे हैं । छत्तीसगढ़ के बहुत सी दुकानों में आजकल दुकानदार सामान बेचना छोड़ गोबर खरीद रहे हैं । यह इतनी अच्छी योजना है । यह प्रदेश के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए उदाहरण है । बच्चे, हमारे भाई-बहिन इसका लाभ उठा रहे हैं । भारतीय जनता पार्टी गाय के नाम पर राजनीति करती है और जब गोबर की बात आती है तो सदन में विरोध करते हैं । यह माननीय मुख्यमंत्री जी की बड़ी सोच है, एक बड़ा

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

उदाहरण है । आने वाले समय में गोधन न्याय योजना पूरे देश में एक उदाहरण बनेगा । लोग इस योजना को पसंद कर रहे हैं। दूसरे प्रदेश में भी इसकी तारीफ कर रहे हैं ।

सभापति महोदय, मैं बस्तर प्राधिकरण और सरगुजा प्राधिकरण की बात करूंगा। पिछली बार जब हम विधायक हुआ करते थे तो हम बस्तर प्राधिकरण की बैठक में हिस्सा लेने के लिए रायपुर आते थे । मेरी जानकारी में एक बार भी बस्तर में प्राधिकरण की बैठक नहीं हुई । मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, उनकी सोच को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने घोषणा की कि मैं प्राधिकरण का अध्यक्ष नहीं रहूंगा और वहां के वरिष्ठ विधायकों को इसलिए जिम्मेदारी दी गई है कि बस्तर और सरगुजा में वहां के विधायक तय करेंगे कि सड़क कैसे बनेगा, पुल कैसे बनेगा, वहां पर पेयजल और स्वास्थ्य की व्यवस्था कैसे होगी, यह वहां का विधायक तय करेगा । मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम लोग जगदलपुर में बैठक करते हैं तो वहां हम लोगों से राय मांगी जाती है, विधान सभा से प्रस्ताव मांगा जाता है कि इस पैसे को कैसे खर्च किया जाये । वहां से चर्चा करने के बाद जो जरूरतमंद है, उसको पहले पूरा करते हैं । ये माननीय मुख्यमंत्री जी को सोच है और वे अपने अधिकार को छोड़कर हम जैसे वरिष्ठ विधायक, जो अभी हमारे अध्यक्ष हैं, उनको यह जिम्मेदारी दी गई है । पिछले कार्यकाल में पैसों का बंदरबांट होता था । पिछले कार्यकाल में प्राधिकरण के पैसे का बंदरबांट होता था, पक्षपातपूर्ण कार्यवाही होती थी । आज हमारे विधायकगण निष्पक्ष होकर, वहां के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठकर चाहे वह पंचायत के स्तर का हो, चाहे जिला पंचायत के स्तर के प्रतिनिधि हो, उसका केसे उपयोग करना है, उसके लिए उस पैसे को बांटते हैं । यह हमारे मुख्यमंत्री जी की सोच है ।

सभापति महोदय, मैं खनिज न्यास निधि की बात करूंगा । खनिज न्यास निधि पहले जिला कलेक्टर के पास हुआ करता था । जिला कलेक्टर के द्वारा इतनी गड़बड़ियां की जाती थीं, उसका बंदरबांट होता था । आपको मालूम होगा कि सुकमा में एक पुल भी बनाया गया था । यह खनिज न्यास निधि वहां के स्थानीय, वहां के क्षेत्र के लोगों के विकास के लिए बनाया जाता है, उसका दुरूपयोग हो रहा था । पिछली बार वहां नीलकंठ टेकाम कलेक्टर थे, वे पैसे का बंदरबांट किये हैं । पुल और पुलिया में लिखवा दिए हैं, छायाचित्र बना दिया है । जबकि वह पैसा पुल और पुलिया, पेयजल और स्वास्थ्य के लिए मानव जीवन में खर्च होना चाहिए । इस प्रकार से कलेक्टर उसका दुरूपयोग करते थे । मैंने उसको टोका, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था । उस पैसे का बंदरबांट किया गया । आज हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी एक बड़ी सोच लेकर वहां के प्रभारी मंत्री को को इसका अध्यक्ष बनाया गया है, वहां के विधायकों को सदस्य बनाया गया है । इससे ज्यादा एक कदम बढ़कर और बताना चाहता हूं कि जनपद और जिला के सदस्यों को वहां का सदस्य बनाया जाता है । जब बैठक होती है तो कलेक्टर तय करता है, कलेक्टर पूछता है, कलेक्टर सबसे राय लेता है कि इस पैसे को हम कहां खर्च करें । खनिज न्यास निधि के पैसे का उपयोग हमारे बस्तर, सरगुजा और पूरे प्रदेश के विकास में हो रहा है ।

सभापति महोदय, डॉ. खूबचंद बघेल वाली जो योजना है, आप सोच सकते हैं । इससे पहले जो योजना थी, उसे मैं भूल रहा हूं । मुख्यमंत्री विशेष सहायता कोष योजना थी, यह छोटी-मोटी घटना नहीं है । उसमें 20 लाख रूपया लोगों को दे रहे हैं। जब गरीब परिवार का कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है, जब किसान बीमार पड़ता है तो उसके पास ईलाज के लिए पैसे नहीं होते हैं । वह चिन्ता और फिक्र में पड़ जाता है। आज हमारे मुख्यमंत्री जी की अच्छी सोच, 20 लाख बिल्कुल सरलीकरण, पहले तो सी.एम.ओ. और कलेक्टर का साईन होता था, आज वह भी बंद कर दिया। आप वहां पर डायरेक्ट बिल बनाओ और चिकित्सक का दस्तखत होगा, ये सब होने के बाद पेमेंट हो रहा है। आज लोग ईलाज करा रहे हैं। यह सरकार की एक बड़ी योजना है। इस प्रकार की योजना, इस प्रकार के बजट का विरोध हमारे विपक्ष के साथी लोग कर रहे हैं। सभापति महोदय, घोषणा की बात कर रहे थे। मैं बताना चाहता हूं, मैं पिछले 15 साल से यह सुन रहा हूं और पिछले 5 साल मैं इस सदन में था। इन्होंने कहा था कि हम जर्सी गाय देंगे।

सभापति महोदय :- कृपया संक्षिप्त करें।

श्री संतराम नेताम :- आदिवासियों के प्रत्येक परिवार को जर्सी गाय देंगे। मैं आज विपक्ष के साथियों से पूछना चाहता हूं जो विरोध करना चाहते हैं, आज वह जर्सी गाय कहां है, आदिवासी परिवार के कितने लोगों को आपने जर्सी गाय दिया ? बेरोजगार को रोजगार देने की बात बोल रहे थे। सभापति महोदय, हम लोग थोड़ा नये सदस्य में आते हैं, थोड़ा समय चाहिए। आपके रहते कभी-कभी बोलने का मौका मिल जाता है। मैं बेराजगारों की बात कह रहा था। पिछले बार बस्तर के लोग बेरोजगारी के अभाव में दूसरे प्रदेश में जा रहे हैं। मैंने पिछली बार भी इस बात को सदन में कहा था। रोजगार देने की भावना होना चाहिए। सरकार को प्रदेश की जनता, क्षेत्र की जनता बस्तर और सरगुजा के युवाओं के बारे में सोचना चाहिए। उनको कैसे रोजगार मिले, हम उनको कैसे बाहर जाने से रोकें, कैसे पलायन करने से रोकें, हम बेरोजगारों को कैसे रोजगार दें ? अभी माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा पुलिस में 2800 लोगों की भर्ती करना, 500 व्याख्याता का पद भर रहे हैं, इस प्रकार से उनकी योजना है। सदन में दोनों पक्ष की चिंता होना चाहिए तो वह बेरोजगारों की चिंता होना चाहिए। नौकरी के अभाव में हमारे कई साथी बाहर जा रहे हैं, इसको रोकने की आवश्यकता है। इनके द्वारा लोहांडीगुड़ा में टाटा की उद्योग स्थापित करने की बात हुई थी। वहां के किसान, क्षेत्रवासी बस्तर के लोग उस जमीन को इसलिए दिये कि वहां पर एक उद्योग स्थापित हो। वहां पर हमारे बच्चों को रोजगार, नौकरी मिले, ताकि अपने घर का रहन-सहन अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकें। सभापति जी, आप जानते हैं कि बस्तर में बहुत गरीब लोग हैं, ऐसे बहुत से किसान भाई लोग हैं, हमारे क्षेत्र की ऐसी जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, वहां धान और मक्का का उत्पादन तो बहुत कम होता है लेकिन ऐसे उद्योग लगाकर आप बेरोजगारों को रोजगार देंगे।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

समय :

03:17 बजे **(सभापति महोदय (श्री देवव्रत सिंह) पीठासीन हुए)**

आपकी सोच बढ़ेगी। मैं आपको निश्चित तौर पर कहना चाहता हूं। इन्होंने लोहांडीगुड़ा की जमीन को इसलिए दिया था कि रोजगार देंगे, लेकिन दस साल होने के बाद भी हमारे बस्तर के लोहांडीगुड़ा के बेरोजगार, वहां के किसानों को रोजगार नहीं दे रहे थे, यह सरकार की सोच, विपक्ष की सोच है, आज बजट का विरोध करते हैं। अच्छा बजट आया है। इस विषम परिस्थिति में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोरोनाकाल में भी अपना दायित्व संभाला। लोगों को रोजगार देने का काम, गौठानों में काम, जो प्रवासी मजदूर आ रहे थे, उनके रूकने, खाने, पीने यहां तक चप्पल देने का काम भी उन्होंने किया है। दूसरे प्रदेश के लोग भी यह कहने लगे कि छत्तीसगढ़ की सरकार बहुत अच्छी है, जब हम वहां से लौटे, साधन से आये तो रूकने, खाने, पीने, चप्पल, कपड़ा, दिया। जब हम रेलवे स्टेशन में, बस स्टाप में मिले तो वे कहने लगे कि हमने ऐसी व्यवस्था दूसरे प्रदेशों में नहीं देखा है। पिछली बार उन्होंने 670 करोड़ रूपये की व्यवस्था की थी। मैं नगरनार की बात करूं। नगरनार को इसलिए दिये थे, हम बस्तरवासियों को बड़ा दुख होता है, हम बस्तरवासियों के जनप्रतिनिधि बनकर आते हैं, हम जवाब नहीं दे पाते, आप सदन में जाकर क्या करते हो ? वहां के लोग हमको कई प्रकार की बातें सुनाते हैं। आखिर बस्तर को बेचना चाहते हो। जब आप वहां पर प्लांट, उद्योग लगाये हैं तो उसकी निजीकरण नहीं होना चाहिए। बस्तर की जनता और हमारे बेरोजगार लोग विपक्ष की आवाज को सुनते हैं, विपक्ष की सोच को देखते हैं, पिछले 15 साल आप सरकार में रहे, आखिर क्या किये ? 15 साल में केवल बेरोजगारों को ठगने का काम, बेरोजगारों को एक ठेका के नाम से शिक्षा देने का काम, ऐसी लूट मचाई थी। इसलिए जनता देख रही थी, हमने तो आवाज लगाई कि आप 2100 रूपये धान का समर्थन मूल्य दो, 300 रूपये बोनस दो, जब हम यहां पर बैठते थे और चिल्ला-चिल्लाकर आवाज लगाते थे, प्रश्न, ध्यानाकर्षण, शून्यकाल के माध्यम से जब हम आवाज उठाते थे, लेकिन हमारी बात को नहीं सुनते थे। हमारी जनता ने धैर्य रखा और इनका 15 साल का हिसाब-किताब कर दिए। सभापति महोदय, आज आप देख रहे हैं कि ये किस स्थिति में आ चुके हैं। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि इनका विरोध करना काम है, जनता के लिए आवाज उठाने का काम है, प्रदेश को कैसे विकास की ओर ले जाये, इसके लिए विरोध करना चाहिए। लेकिन ऐसा भी होना चाहिए यदि विकास होता है तो उसका समर्थन भी करना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं जब कोरोना काल में अपने क्षेत्र गया, हमारी सरकार 35 किलो चावल दे रही थी। ऐसा हुआ कि हमारी सरकार ने कोरोना काल में 70 और 95 किलो तक नि:शुल्क चावल दिया। मैं जब उनके पास गया तो बताया गया कि प्रदेश में ऐसी सरकार होनी चाहिए जो जनता

का विपत्ति में साथ दे। सभापति महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि जब लॉकडाऊन चल रहा था तो पुलिस लोगों को बाहर निकलने से रोकते थे, पुलिस वाले डंडा चलाते थे। इसलिए कि आप बाहर मत निकलो नहीं तो आप कोरोना में समा जाओगे।

सभापति महोदय :- संतराम जी, संक्षेप करिये।

श्री संतराम नेताम :- मैं बहुत संक्षेप कर रहा हूं। ऐसी विषम परिस्थितियों में भी अगर हमारे प्रदेश की जनता को उभारने का काम कर रहे हैं, उनको विकास की दिशा में ले जाने का काम कर रहे हैं तो उसका विरोध नहीं होना चाहिए। मैं मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के बारे में कहना चाहता हूं। पैसा बहुत अनाप-शनाप खर्च होता है। जब हमारे मुख्यमंत्री जी बस्तर, दंतेवाड़ा गये थे तो उस समय 41 या 42 प्रतिशत कुपोषण की मात्रा थी। आज खनिज न्यास निधि से उनको गरम भोजन देने से तो वहां कुपोषण लोगों की संख्या कम हो रही है। हम सुपोषण की ओर जा रहे हैं। हम बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। सरकार की सोच है कि हम मानव जीवन को कैसे अच्छा बनाये, आने वाले पीढ़ी को कैसे अच्छे ढंग से रखें।

माननीय सभापति महोदय, "किसानों की न्याय योजना " राजीव गांधी किसान न्याय योजना एक बहुत बड़ी योजना है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस वर्ष 20 लाख 53 हजार किसानों ने 92 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की है। जो छत्तीसगढ़ के इतिहास में सर्वाधिक है। वन मान्यताधारी 32 हजार 23 कृषकों से भी 10 लाख 70 हजार क्विंटल धान की खरीदी की गई है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना हेतु वर्ष 2021-22 के बजट में 5 हजार 703 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। माननीय सभापति महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि जब केन्द्र सरकार ने बोनस देने से मना किया तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने इसी सदन में घोषणा की, मुझे अच्छी तरह से याद है, उन्होने कहा कि हमने किसानों से वादा किया है, किसानों के साथ अन्याय नहीं होगा, हम किसानों को न्याय दिलायेंगे। इसलिए अंतर की राशि देने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना चलाई गई है। सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कर्ज माफी और राजीव गांधी किसान न्याय योजना से किसान सम्पन्न हुए हैं। मैं यह बात भी कहना चाहता हूं कि मैं गांव के करीब 5 हजार घरों में गया हूं, मैं 19 दिन में 19 गांव के 5 हजार लोगों के घरों में गया तब यह बात निकलकर सामने आई कि किसानों के लिए कोई हितैषी है, अगर किसानों के बारे में कोई सोचती है तो केवल और केवल मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार सोचती है।

सभापति महोदय :- कृपया, समाप्त करेंगे।

श्री संतराम नेताम :- माननीय सभापति महोदय, मैं दो लाईन के बाद अपनी बात समाप्त करता हूं। इस सरकार ने किसानों के घाव में मरहम लगाने का काम किया है। यदि धान और मक्का का समर्थन मूल्य मिल जाये, इसका बोनस मिल जाये तो किसान सम्पन्न हो जायेंगे। सभापति महोदय, आप जानते हैं कि आज 80 प्रतिशत लोग किसान हैं और बस्तर तथा सरगुजा में भी लोग खेती करते

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

हैं। अगर इस राजीव गांधी किसान न्याय योजना से राशि दे रहे हैं तो क्या बुरा है ? इस साल बस्तर में, मेरे यहां कोण्डागांव में कोई अव्यवस्था नहीं हुई है। प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा अच्छी व्यवस्था की गई थी। यह बात भी सही है कि बारदाना की कमी से तकलीफ हुई थी। पिछली बार मेरे विधानसभा क्षेत्र में विपक्ष के द्वारा सोची-समझी चाल के तहत लाठी चार्ज करवाया गया था। जानबूझकर किसानों को भड़काया गया। यह अच्छी पालिसी नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी किसान न्याय योजना के तहत राशि दे रहे हैं, मैं चाहता हूं कि इसी प्रकार से हर वर्ष 2500 रूपया धान का कीमत मिलना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, मैं यह भी जानता हूं कि आप भी किसान घर से हैं। अगर किसान को उसके धान का कोई अच्छा कीमत देगा, तो यह सरकार देगी। आप जानते हैं कि अब व्यापारियों के पास 40-45 किलो नहीं बेचते हैं, सीधा-सीधा 2500 रूपया धान का कीमत मिलती है तो लेम्प्स में बेचते हैं। ये सरकार की सोच और भावना है। ये प्रदेश की सरकार की इच्छा प्रदेश की जनता को मजबूत करने और रोजगार की व्यवस्था को मजबूत करने की, किसानों को मजबूत करने की है। यह हमारी सरकार की सोच से लाया गया एक अच्छा बजट है। मैं इसका समर्थन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री नारायण चंदेल (जांजगीर-चांपा) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत 2021-22 के आय-व्ययक का विरोध करते हैं और विरोध इसलिए है कि यह जो बजट है इस बजट में कहने के लिए कुछ नहीं है। दीया तो है लेकिन तेल नहीं है। इस बजट में योजनाओं का नाम बहुत दिया गया है लेकिन उसके लिए किसी प्रकार की राशि का आवंटन नहीं किया गया है। किसी में 100 रूपये, किसी में 150 रूपये तो किसी में 200 रूपये किया गया है। दुर्भाग्यजनक यह है कि ऋण बढ़ रहा है और राजस्व घट रहा है। ये बजट की विसंगति है और इसलिए इस बजट का हम विरोध करते हैं। आज छत्तीसगढ़ प्रदेश जब छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ जब तीन प्रदेश उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ बने तो छत्तीसगढ़ बहुत तेजी से विकास करने वाले राज्यों की श्रेणी में आ गया था लेकिन हम यदि कुल मिलाकर बजट को देखें और पढ़ें तो यह जो बजट है, जिसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में रखा है उस बजट का आकार छोटा हो गया। दूसरे अन्य प्रदेशों में बजट का आकार बढ़ रहा है यहां सिमट रहा है और इसलिए सिमट रहा है कि इन सवा दो साल में हम 36 हजार करोड़ के कर्ज में लद गये हैं। कुल मिलाकर हम देखें तो 80 हजार करोड़ रूपये की हमारे ऊपर देनदारी है। हम कैसे छत्तीसगढ़ को आगे ले जायेंगे? हम कैसे यहां गांव, गरीब और किसान का विकास करेंगे, हम कैसे यहां अपनी मूलभूत सुविधाओं को जुटायेंगे? चाहे आज गांव में सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, स्कूल हो, अस्पताल हो हम यहां के बुनियादी ढांचे को कैसे दुरूस्त करेंगे। दुर्भाग्य है कि आज छत्तीसगढ़ 21 साल का नौजवान हो गया है और उस समय जिस मंशा को लेकर छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया गया था, छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माताओं ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि 21 साल का नौजवान छत्तीसगढ़ कर्ज से लद जायेगा, कर्ज से कराहेगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज जो हमारी सरकार की

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

नीति और नीयत और इस सरकार की सोच ठीक नहीं है। इस सरकार की दिशा और दशा दोनों खराब है। सरकार के पास कोई विजन नहीं है कि कैसे हम छत्तीसगढ़ का उन्नत छत्तीसगढ़ बनाये। कैसे इस विकासशील छत्तीसगढ़ को विकसित छततीसगढ़ के रूप में डेव्हलप करें ये सरकार की योजना होनी चाहिए। इसलिए आज गांव की क्या हालत है? गांव के लोग पलायन करने को मजबूर हैं। मैं जिस जिले जांजगीर-चांपा से आता हूं, मेरे बगल में बलौदाबाजार जिला है। अभी कोविड-19 के समय कोरोना काल में जब पलायन करने वाले हमारे मजदूर भाई बहन आये तो 1 लाख 15 हजार मजदूर सिर्फ जांजगीर चांपा जिले से पलायन किए थे जो वापस आये। ये सरकार का आंकड़ा है। 1 लाख 20 हजार मजदूर बलौदा बाजार जिले से वापस आये। तो आज हम गांव को विकसित नहीं करेंगे, गांव में हम स्वरोजगार को बढ़ावा नहीं देंगे, हम ग्राम में ग्रामोद्योग को बढ़ावा नहीं देंगे, हम छोटे-छोटे कुटीर उद्योग को बढ़ावा नहीं देंगे तो इस बजट में कहीं पर ग्रामोद्योग, कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने का कहीं पर कोई उल्लेख नहीं है। उसके लिए राशि का कोई प्रावधान नहीं है। जिस क्षेत्र से मैं आता हूं वहां पर सर्वाधिक बुनकर रहते हैं जो हाथ से मेहनत करके, बुनाई करके कपड़ा बुनते हैं। उनका बुनी हुई साड़ी, उनका बुना हुआ कोसे का कपड़ा विदेशों में बिकता है। आज उन बुनकरों के सामने में रोजी रोटी का गंभीर संकट पैदा हो गया है। उन बुनकरों को सहुलियत देने के लिए, उनका कर्ज माफ करने के लिए इस बजट में कहीं पर किसी पृष्ठ में कोई प्रावधान नहीं है कोई उल्लेख नहीं है। पिछले एक साल से उन बुनकरों को बुनाई के लिए धागा नहीं मिल रहा है। इस बजट में क्या है इस बजट में कोई उल्लेखनीय चीज का उल्लेख नहीं है। यह बजट सिर्फ आंकड़ों का मायाजाल है। इसकी राशि को हम उसमें कर दिये और इसमें कर दिये और इतना बढ़ा दिये। कर्ज से लदा हुआ छत्तीसगढ़ है इस बजट में हम कैसे विकास की बात करें?

माननीय सभापति महोदय, यहां बहुत बड़ी बात किसानों की हो रही थी। हमारे छत्तीसगढ़ के किसानों के राष्ट्रीयकृत बैंक में जिन किसानों ने कर्ज लिया था, उसका केवल 40 प्रतिशत कर्ज माफ हुआ है। अभी भी वह 60 प्रतिशत कर्ज पटाने के लिए बाध्य है। सरकार के इस बजट में उसका कोई उल्लेख नहीं है कि हम राष्ट्रीयकृत बैंकों का कर्ज माफ करेंगे। किसी पृष्ठ, किसी पैरा में किसी राशि का उल्लेख नहीं है। आप बोलते हैं कि हम खेती को बढ़ावा देंगे। हम खेती को उन्नत करेंगे। इस प्रदेश में हम कैसे सिंचाई का रकबा बढ़ायेंगे ? हम कितने नये जलाशय, डेम, एनीकट बनायेंगे ? इस बजट में उसका कहीं पर कोई उल्लेख नहीं है। कैसे सिंचाई का रकबा बढ़ेगा ?छत्तीसगढ़ कैसे उन्नत होगा ? किसान कैसे खुशहाल होंगे, हम फसलचक्र में कैसे परिवर्तन करेंगे ?और जब तक हमारी खेती, किसान समृद्ध नहीं होगा, गांव समृद्ध नहीं होगा हम छत्तीसगढ़ के विकास की कल्पना नहीं कर सकते। आज छत्तीसगढ़ की सारी अर्थव्यवस्था खेती, किसान पर निर्भर है। और इसलिए जिस समय फसल अच्छी होती है रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, भिलाई के बाजार में रौनक होती है जिस समय अकाल, दुकाल पड़ता है अतिवृष्टि होती है तो हम देखते हैं कि बाजार में विरानी छाती है। हमारी सारी अर्थव्यवस्था फसल,

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

किसान पर आधारित है तो इसलिए छत्तीसगढ़ में सिंचाई का रकबा कैसे बढ़ायें ?इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी जिस समय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, उस समय उन्होंने कहा था कि दो साल को जो बकाया बोनस है वह हम किसानों को देंगे। इस बजट में कहीं पर कोई उल्लेख नहीं है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहते हैं कि जब इस बजट की चर्चा में अंत में उनका उत्तर आये तो इस बात की घोषणा करें कि किसानों का जो 2 साल का बकाया बोनस है, वह दिया जाये। बजट बिल्कुल असंतुलित है। सुदूर क्षेत्रों के लिए कहीं पर कोई विकास की राशि का उल्लेख नहीं है। आज हम नये सड़क का निर्माण करेंगे। वास्तव में जो सड़क हैं वह विकास का द्योतक है। हम नये सड़क के निर्माण की बात तो छोड़ दें, सड़क के रख-रखाव के लिए, पेच वर्क के लिए राशि का उल्लेख नहीं है। जो सड़क जीर्ण-शीर्ण, जर्जर हो गई है, चलने लायक नहीं है उसके लिए हम रखरखाव करेंगे। आज पूरे प्रदेश की बात बता रहा हूँ। मैं एक महीने पहले अभी बलरामपुर गया था । आज बलरामपुर चले जाईये, वह अण्डमान निकोबार है। आपके क्षेत्र सरगुजा में 40 से 50 किलोमीटर सड़क उखड़ी हुई है।

श्री बृहस्पत सिंह :- सर, वह एन.एच. की सड़क है पैसा दिलवा दीजिए। कई बार से हम लोग मांग कर रहे हैं। अभी तक नहीं मिल पाया है। उस सड़क को एन.एच. 343 बोलते हैं।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय सभापति महोदय,तो यह स्थिति है। आप नये सड़क का निर्माण कैसे करेंगे ? आज आपने मुख्यमंत्री सड़क योजना की बात कही। अभी भी हजारों की संख्या में इस छत्तीसगढ़ में जो सुदूर क्षेत्र हैंजो वनवासी, आदिवासी क्षेत्र हैं पिछड़ा वर्ग के क्षेत्र हैं वहां पर आज भी सड़क नाम की कोई चीज नहीं है। वहां पर बारहमासी सड़क नहीं है। जो छोटे-छोटे पुल-पुलिया हैं, बरसात के दिनों में 4-5 महीने के लिए अनेक गांव टापू बन जाते हैं। कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो आज भी इस छत्तीसगढ़ प्रदेश में दुर्भाग्य है कि उसको चार पाई में ढोकर ब्लॉक लेवल के अस्पताल तक लाया जाता है। हम छत्तीसगढ़ को बहुत समृद्ध छत्तीसगढ़ कहते हैं। छत्तीसगढ़ में सारे संसाधन हैं । उस संसाधन का हम कैसे सदुपयोग करें, यह सरकार की नीति, नियत के ऊपर निर्भर है। हमारी प्लानिंग क्या है, हमारी कार्ययोजना क्या है, इसलिए आज छत्तीसगढ़ पीछे जा रहा है और छत्तीसगढ़ की पहचान कर्ज में दबा हुआ प्रदेश की बन गई है। आज हम दिल्ली में जायें या किसी अन्य प्रदेश में जायें, हमारी पहचान कर्ज लेने वाले प्रदेश के रूप में बन रही है, कर्ज से लदा हुआ छत्तीसगढ़ के रूप में पहचान बन रही है। यह दुर्भाग्य है। माननीय सभापति महोदय, मैं उस दिन अभिभाषण में बिजली की समस्या के बारे में बोल रहा था। आज भी सुदुर गावों में लो-वोल्टेज की समस्या है। आज किसानों को 6-8 घंटे बिजली नहीं मिलती है। यह हमारी बुनियादी चीजें हैं। इन बुनियादी चीजों को पहली प्राथमिकता के आधार पर बजट में शामिल करके दूर करने का प्रयास करना चाहिए। अगर छत्तीसगढ़ का विकास करना है तो वास्तव में यहां के पानी, यहां की जवानी को रोकना पड़ेगा। उसको सही दिशा में मोड़ना

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

पड़ेगा। हम कैसे जल का संरक्षण करें, हम कैसे एक-एक बूंद पानी का सदुपयोग करें। हम कैसे हमारे जो बेरोजगार नौजवान हैं जो आज अर्जी लिए सड़कों पर घूम रहे हैं, सुशिक्षित नौजवान हैं, हम उनके हाथ में कैसे रोजगार थमायें। यह सरकार की नीति होनी चाहिए। अगर यह नीति होगी तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ विकास के रास्ते पर तेजी से जायेगा। अगर छत्तीसगढ़ को विकास के रास्ते पर ले जाना है तो यहां के जल, जंगल, जमीन को बचाना होगा। जब हम यहां के जल, जंगल और जमीन को बचायेंगे तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ विकास के रास्ते पर जायेगा। लेकिन उसके लिए इस सरकार की नीति ठीक होनी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, अभी हमने कोरोनाकाल में देखा, अभी बहुत सी बातें हमारे सदस्य बोल रहे थे। जब कोविड प्रारंभ हुआ, उस समय छत्तीसगढ़ में उसका असर नहीं था। जब 3-5 महीने बाद कोविड का संक्रमण फैला तो छत्तीसगढ़ सरकार की चिकित्सा व्यवस्था की सारी पोल खुल गई। हम 3-4 महीने में अपने संसाधन को नहीं जुटा पाये जो हमें आवश्यक रूप से तैयारी करनी थी। उस कारण छत्तीसगढ़ कोरोना की चपेट में आया।

सभापति महोदय :- कृपया समाप्त करेंगे। डॉ. लक्ष्मी ध्रुव।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय सभापति महोदय, बहुत सी चीजें थीं, विभागवार जब चर्चा होगी, तब हम लोग कहेंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह पिछले 5 जनवरी को जांजगीर में गये थे और उन्होंने मेडिकल कॉलेज की घोषणा की थी। इस बजट में जांजगीर में मेडिकल कॉलेज खोलने का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। जब वह उत्तर देंगे, क्योकि यह उन्हीं घोषणा है, 5 जनवरी मैं तिथि बता रहा हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय भी थे, माननीय प्रभारी मंत्री टी.एस.सिंहदेव जी भी थे। जांजगीर में मेडिकल कॉलेज खुल जाये, वह अपने उत्तर में उसकी घोषणा कर दें उसके लिए मैं उनको धन्यवाद दूंगा। इस बजट का मैं विरोध करता हूं। माननीय सभापति महोदय, आपने समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव (सिहावा) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोसे के थैले में बजट लेकर आये और उसको प्रस्तुत किया। उसमें पूर्ण रूप से "गढ़बो नवा छत्तीसगढ़" की झलक दिखाई दे रही थी। उन्होंने 2021 के बजट को height के रूप में प्रस्तुत किया और कोरोना संकट से उबारकर बजट को विकास के मार्ग पर ले जाने के लिए संकल्पित थे। सुराजी ग्राम योजना, राजीव गांधी न्याय योजना हो, गोधन न्याय योजना, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना के साथ छत्तीसगढ़ ब्रांड के रूप में राज्य एवं राज्य के बाहर सी-मार्ट स्टोर की स्थापना पर बल दिया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूं, धन्यवाद देती हूं कि इस कोरोना संकट से उबारकर छत्तीसगढ़ के विकास को आगे बढ़ाया है । राजकोषीय फिसलन को भी नियंत्रित करने का प्रयास किया गया है, राजकोषीय घाटा, जी.डी.पी. 6.52 प्रतिशत होना अनुमानित था जो कि बजट प्रस्ताव से दोगुना है । वर्ष 2020-21

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

में 4.56 प्रतिशत पर नियंत्रित करने का संकल्प लिया, इसके लिये भी वे बधाई के पात्र हैं । प्रस्तावित बजट में समग्र विकास की बात कही गई है । चाहे किसानों की बात हो, चाहे श्रमिकों की बात हो, चाहे वनवासियों की बात हो, चाहे महिलाओं और बच्चों की बात हो, चाहे पशुपालकों की बात हो, चाहे स्थानीय कर्मकारों की बात हो । सबके लिये उन्होंने समग्र विकास के लिये बजट रखा है । वे निश्चित रूप से जमीन से सोचते हैं और जमीन के पिछड़े वर्ग के लोगों के विकास के बारे में सोचते हैं । किसानों की स्थिति 15 सालों में क्या थी ? उसे सब लोग जानते हैं । आज किसान बॉर्डर में हैं और हमारे किसान अभी भी अपने अस्तित्व को बचाये रखने के लिये संघर्षशील थे, उनको आगे बढ़ाने के लिये जो कदम बढ़ाया है, वह प्रशंसनीय है। वर्तमान में 2 लाख 53 हजार किसानों का 52 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा है और वन अधिकार मान्यता के तहत् 10 लाख 70 हजार क्विंटल धान खरीदा गया है । वर्ष 2021-22 के लिये 5703 करोड़ का प्रावधान किया गया है और किसानों को आगे बढ़ाने के लिये विभिन्न सारी योजनाएं चाहे चिराग योजना हो, चाहे फसल बीमा योजना हो, चाहे कृषक समग्र विकास योजना हो, चाहे शाकम्बरी योजना हो चाहे उद्योगों की हो । माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहती हूं कि छत्तीगसढ़ में किसानों की संख्या लगभग 80 प्रतिशत के आसपास है, जब तक हम किसानों को आगे नहीं बढ़ायेंगे, जब तक किसानों को आत्मनिर्भर, स्वावलंबी नहीं बनायेंगे, मजबूत नहीं बनायेंगे तब तक छत्तीसगढ़ की जनता बहुत समृद्ध है, संपन्न है ऐसा सोचना व्यर्थ है इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको आगे बढ़ाने के लिये, आत्मनिर्भर बनाने के लिये ध्यान दिया है ।

माननीय सभापति महोदय, यदि श्रमिकों की बात कहें तो श्रमिकों की दिनचर्या की रोजी-रोटी चाहिए । छोटी-छोटी बातों पर बहुत दिक्कतें उठानी पड़ती हैं, या तो उनको समझ में नहीं आता है या वे कर नहीं पाते हैं इसलिए श्रमिक हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है ताकि इसमें असंगठित मजदूर, ठेका, सफाई-कामगार, घरेलू कामकाजी महिलाएं इसका लाभ उठा सकें इसके लिए 21 करोड़ का प्रावधान रखा गया है, यह निश्चित ही बहुत अच्छा कदम है और इसका मैं समर्थन करती हूं । हमारे वनवासी भाईयों के विकास के लिये भी कदम उठाया है क्योंकि जंगल के दुर्गम क्षेत्रों में रहते हैं और वे अपने वन को वन भी नहीं कह सकते थे तो इसके लिए उन्होंने व्यक्तिगत पट्टा और सामुदायिक पट्टे का वितरण किया, केवल बात ही नहीं की बल्कि उनको दिया है और उसका विकास करने के लिये कदम उठाये हैं । 24, 827 नये वन अधिकार पत्र सहित अब तक 4 लाख 36,619 व्यक्तिगत अधिकार पत्र वितरित किये गये हैं, यह बहुत ही सराहनीय है । लघु उपज में 54 लघु उपज का समर्थन मूल्य देने की बात कही गई है और साथ ही तेंदूपत्ता को उन्होंने 4000 किया है निश्चित तौर से उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान की है, यह सुरक्षा मिलने से वे अपना विकास कर सकेंगे, अपने बच्चों को पढ़ा सकेंगे और आगे उनको कहां जाना है यह सोचने की क्षमता पा सकेंगे, मैं इस कदम का बहुत-बहुत समर्थन करती हूं।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

माननीय सभापति महोदय, माताओं और बच्चों के लिये भी बजट में प्रावधान हैं । यदि माताएं सुरक्षित नहीं होंगी, यदि हमारे बच्चे स्वस्थ नहीं होंगे तो हम सुपोषित छत्तीसगढ़ नहीं देख सकते इसलिये कुपोषण से उबारने के लिये सुपोषण की ओर ले जाने का प्रयास किया गया है और इसमें भी बजट दिया गया है और अब तक 26.33 प्रतिशत कुपोषण को दूर करने का सराहनीय कदम उठाया है और कौशल्या मातृत्व योजना के तहत् 47 करोड़ का प्रावधान रखा गया है और विशेष पोषण आहार के तहत् 732 करोड़ का प्रावधान रखा गया है । निश्चित तौर से इन सुविधाओं से महिलाओं के स्वास्थ्य और बच्चों का विकास होगा और वे स्वस्थ रहेंगे। उसी तरह से मीडिया पत्रकार साथी हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हैं । चौथा स्तंभ भी निर्भीकता के साथ अपना काम कर सकें इसके लिए पत्रकारों को आकस्मिक दुर्घटना पर दो लाख से बढ़ाकर 5 लाख की सहायता दी जाएगी, यह एक सराहनीय कदम है । उसी तरह शहरों के आधुनिकीकरण के लिए भी कदम उठाए गए हैं । शहरी स्लम योजना के माध्यम से स्वच्छता दीदियों को आगे बढ़ाने का काम किया गया है । मुख्यमंत्री मितान योजना और नगरीय क्षेत्रों में सुशासन के लिए प्रयास किया गया है । शहरी निर्धन परिवारों के लिए मोर जमीन मोर मकान के तहत आवास देने का काम किया है वह सराहनीय है क्योंकि शहरों में आवास और पानी की सख्त जरूरत है । मुख्यमंत्री जी ने आधुनिक प्रौद्योगिकी के लिए भी कार्य किया है, कला संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए काम किया है। शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया है इसके साथ ही साथ उन्होंने हर क्षेत्र को लिया है ताकि छत्तीसगढ़ का समग्र विकास हो सके । छत्तीसगढ़ एक आत्मनिर्भर राज्य बन सके, ऐसी कल्पना की गई है । आपने बोलने का मौका दिया, धन्यवाद् ।

श्री सौरभ सिंह (अकलतरा) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लाए गए आम बजट पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । सभापति महोदय, साल भर हम राजनीति करते रहे, साल भर हम कोई भी स्टेटमेंट देते रहे लेकिन जब बजट आता है तो आंकड़े झूठ नहीं बोलते, वे सारी चीजों का आईना है । वे आंकड़े बताते हैं कि हम किस तरफ चल रहे हैं और प्रदेश किस तरफ जा रहा है । सभापति महोदय, यह जो बजट आया है यह कोरोनाकाल की एक मिस्ड ऑपरचुनिटी है । इकोनॉमिक्स में एक बात स्पष्ट है कि क्राइसेस से एक नई चीज का जन्म होता है। हमने यहां इस क्राइसेस का कोई फायदा नहीं लिया । नीरस बजट था, बजट की ग्रोथ पीछे हट रही है, जी.डी.पी. की ग्रोथ पीछे हट रही है, पर केपिटा इंकम की ग्रोथ पीछे हट रही है और राजस्व कलेक्शन पीछे हट रहा है । राजस्व कलेक्शन पीछे हटने के कारण हमारे छत्तीसगढ़ के इकोनॉमी का साइज़ पीछे आ रहा है और जब इकोनॉमी का साइज पीछे होगा तो समृद्धि नहीं आ सकती । इकोनॉमी का साइज आगे बढ़ना चाहिए और इसके बाद ही समृद्धि आएगी ।

सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने भाषण में सारी केन्द्र सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं का जिक्र किया है और उनका बोलना बिल्कुल सही था । यहां आने वाला 60 परसेंट पैसा केन्द्र

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सरकार का है, सरकार के राजस्व में 60 प्रतिशत केन्द्र सरकार का है । बड़े भाई के पैसे पर छोटा भाई चल रहा है । सारी फ्लैगशिप योजनाओं का जिक्र बजट भाषण में था । सभापति जी, आर्थिक सर्वेक्षण में पेज नम्बर 81 में स्पष्ट लिखा है कि इस साल रेवेन्यू डेफिसिट कम हुआ है, रेवेन्यू डेफिसिट कम हुआ है उसका कारण स्पष्ट है कि सेंट्रल पूल से जो हमारा शेयर मिलता है वह सेंट्रल पूल के शेयर में 32.65 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । वृद्धि के कारण 6 हजार करोड़ एक्स्ट्रा आया है । 6 हजार करोड़ एक्स्ट्रा आने के अनुमान से हमारा रेवेन्यू डेफिसिट कम हुआ है । तो पैसा तो केन्द्र सरकार दे रही है फिर ये बातें क्यों हो रही हैं कि हमें 15600 करोड़ का चूना लग गया । 16.6 परसेंट एक्स्ट्रा पैसा केन्द्र सरकार ने सेंट्रल शेयर से दिया है । तो फिर आप यह क्यों बोल रहे हो कि 15600 करोड़ का चूना लग गया । मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के भाषण में अपेक्षा करता हूं कि हम राजनीतिक चार्ज लगा रहे हैं तो चार्ज पूरे आंकड़ों के साथ होना चाहिए । कहां का कितना पैसा नहीं मिला, किस मद का कितना पैसा हमको नहीं मिला, ये बातें बिल्कुल स्पष्ट आना चाहिए । आप योजनाएं बना रहे हैं, अवश्य बनाइए लेकिन आप केन्द्र सरकार से पूछकर योजनाएं नहीं बना रहे हैं, केन्द्र सरकार आपके शेयर का पूरा पैसा दे रही है । अगर आप किसी योजना का क्रियान्वयन नहीं कर पा रहे हैं तो आप केन्द्र सरकार के ऊपर ब्लेम लगा देते हैं । सभापति जी, यह तो वही बात हुई कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा । आप नाचिए ना, आप आंगन को क्यों दोष दे रहे हैं । सभापति जी, आर्थिक सर्वेक्षण के पेज नम्बर 82 में गैर कर राजस्व, केन्द्र सरकार से प्राप्त सहायक अनुदान, वर्ष 2018-19 में 12500 करोड़, वर्ष 2019-20 में 21600 करोड़ और वर्ष 2020-21 में 30787 करोड़ । यह ग्रोथ आप 3 साल में देखिए। ऑलमोस्ट थ्री टाइम्स। तो केन्द्र सरकार पैसा दे रहा है और आपका पैसा, आपका जो ग्रोथ था, वह 38 परसेंट से आपका शेयर 30 परसेंट में आ गया तो आपका रेवेन्यू कलेक्शन होगा ही नहीं। आप अपना रेवेन्यू कलेक्शन नहीं कर रहे हैं। केन्द्र सरकार का पैसा आपके पास आ रहा है। वह तो आ रहा है। केन्द्र सरकार अपनी नीतियां कर रही हैं। राज्य सरकार अपने रेवेन्यू कलेक्शन के लिए क्या कार्य कर रही है? जब राज्य सरकार अपना रेवेन्यू बढ़ायेगी और जब केन्द्र सरकार का रेवेन्यू आयेगा तो दोनों रेवेन्यू को जोड़कर इस प्रदेश का वैकल्पिक विकास होगा। आप अपना रेवेन्यू नहीं बढ़ा रहे हैं। आप रेवेन्यू बढ़ाने पर कहीं पर कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, इकॉनामिक्स की एक थ्योरी है। आई.सी.ओ.आर. (incremental capital output ratio) कहते हैं। हम कितना पैसा इकानॉमी में लगायेंगे तो हमें कितने ग्रोथ का आउटपुट मिलेगा। छत्तीसगढ़ सरकार में हम पहले पैसा कम लगाते थे तो केपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा करते थे और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम करते थे। तो हमारा आई.सी.ओ.आर. अच्छा था। कम पैसा लगाकर हमारा छोटा बजट होता था और हमारी ग्रोथ ज्यादा होती थी। अब हमारे बजट का साइज तो बढ़ गया। हमें ज्यादा पैसा लगाना पड़ रहा है और ग्रोथ स्लो आ रही है। यह इकानॉमी के लिए अलार्मिंग सिग्नल है और विश्वभर के जितने भी अर्थशास्त्री हैं, किसी बजट के आंकलन के लिए इस पैरामीटर को मानते हैं।

माननीय सभापति महोदय, हम आज बात कर रहे थे और सब लोगों ने आज debt की बात की। कर्जा बढ़ रहा है। कर्जा बढ़ रहा है और अगर आप कर्जा लेकर केपिटल एक्सपेंडिचर में खर्चा कर रहे हैं तो उसमें रेट ऑफ रिटर्न आ रहा है। कुछ पैसा आयेगा । इकानॉमी में कुछ ग्रोथ आयेगी। आज हमने 42 हजार करोड़ 26 महीने में कर्जा लिया और पुराना मिलाकर करीब-करीब 80 हजार करोड़ हो गया। यह भी अंतर्राष्ट्रीय इकानॉमिक्स का बजट मैनेजमेंट का सिद्धांत है। जो कर्जा लिया जाता है साइज मैटर नहीं करता। pace मैटर करता है। स्पीड कितनी है? आप 26 महीने में 42000 करोड़ का कर्जा ले लिये। आप धीरे-धीरे लीजिए। वह अलार्मिंग सिग्नल है। वह छत्तीसगढ़ के भविष्य के लिए अलार्मिंग सिग्नल है और दूसरा अलार्मिंग सिग्नल मैं बता रहा हूं। जो आप कर्जा ले रहे हैं, वह आपके जी.डी.पी. ग्रोथ से ज्यादा कर्जा है। आपकी जितनी जी.डी.पी. ग्रोथ नहीं है, आप जितना इकानॉमी में पैसा जोड़ नहीं रहे हैं, आप 4 हजार करोड़ जोड़ रहे हैं, 5 हजार करोड़, 6 हजार करोड़ आपका बजट 1 लाख 5 हजार करोड़ पर टिका हुआ है और आप कर्जा लेते जा रहे हैं। कर्जा लेते जा रहे हैं। यह भी गलत है। यह भी इकानॉमी अलार्मिंग सिग्नल है कि आप रेट ऑफ ग्रोथ से ज्यादा आपकी रेट ऑफ debt है। डेट कलेक्शन की रेट और ज्यादा हो रही है। यह भी एक अलार्मिंग सिग्नल है। उसके साथ-साथ आज जब हम कर्जा ले रहे हैं, वर्ष 2018-2019 में 3652 करोड़ रूपये का हम सिर्फ ब्याज दे रहे हैं। आज वर्ष 2020-21 में हम 5840 करोड़ का सिर्फ ब्याज दे रहे हैं, जो हमारे राजस्व आय का 8 प्रतिशत है। यह सेक्रेटरी साहब के अभिवादन में है। सेक्रेटरी साहब का जो पत्र है, उसमें है। अगर हम रेवेन्यू का सिर्फ 8 प्रतिशत ब्याज दे रहे हैं और प्लस लोन का जो अदायगी है, वह तो 16-17 हजार करोड़ है। तो सारा पैसा तो उसी में जा रहा है। यह इस साल का जो अनुमान है तो इस तरह से अगर ब्याज की जंपिंग हुई तो वह आठ, साढ़े आठ हजार करोड़ का अनुमान है और वह आने वाले समय में 10 हजार करोड़ तक जायेगा। माननीय सभापति महोदय, हम किस तरफ जा रहे हैं। हम तो debt ट्रेप की तरफ जा रहे हैं और यह इस इकानॉमी के लिए थर्ड अलार्मिंग सिग्नल है कि हम debt ट्रेप के लिए मूव कर रहे हैं। debt ट्रेप माने एक क्लासिक सिस्टम है इकानॉमी का कि ब्याज पटाने के लिए हमें कर्जा लेना पड़ रहा है। यह हम क्लासिक सिस्टम की तरफ जा रहे हैं। ब्याज पटाने के लिए हम debt ट्रेप के लिए कर्जा ले रहे हैं। तो हम कहां जा रहे हैं? किस परिस्थिति की ओर जा रहे हैं? इन सारी चीजों के पीछे एक जड़ है। हम हमारा रेवेन्यू कलेक्शन नहीं बढ़ा पा रहे हैं और हम क्यों नहीं हमारा रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ा पा रहे हैं, उसके पीछे दो चीजें हैं। एक माफिया राज और दूसरा crony capitalism. हम उन्हीं लोगों को ठेका दे रहे हैं। हम उन्हीं लोगों को सप्लाई का काम दे रहे हैं, हम उन्हीं लोगों को अनुकृत कर रहे हैं, जो शासन और सत्ता के साथ जुड़े हुए हैं और अगर माफिया राज आयेगा तो सबसे पहले अगर कहीं मार मारता है तो राजस्व की क्षति करता है। अवैध रेत खदान चल रही हैं। भाई रजनीश जी यहां बैठे हैं। अगर अवैध रेत खदानें चल चल रही हैं, जितना उसका मापदण्ड है, उस मापदण्ड से ज्यादा अगर वह रेत निकालकर

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

बेच रहे हैं तो कहीं न कहीं हमारे राजस्व की क्षति कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, हमारा मुख्य राजस्व खनिज जी.एस.टी., लिकर, लैण्ड रेवेन्यू, वाटर और वैट से आता है । जी.एस.टी. से 14 हजार करोड़ रूपए के आसपास राजस्व आता है । अगर हम स्टेट जी.एस.टी. और सेन्ट्रल जी.एस.टी. को मान लें तो 14 हजार करोड़ रूपए आता है । मैं यह जानना चाहता हूं कि प्रदेश में कितने इनपुट के प्रकरण हैं । मैंने एक प्रश्न लगाया था, उस प्रश्न के जवाब में आया कि करीब-करीब 700 प्रकरण हैं, जो सिर्फ इनपुट चोरी की शिकायतें हुई हैं, जी.एस.टी. में इनपुट चोरी की, मैनेजमेंट की शिकायतें हुई हैं, जिसका निराकरण नहीं किया गया है । यह तो पकड़ा गए । कितने लाख लोग हैं, जो पकड़े नहीं गए, जिसके खिलाफ शिकायतें नहीं हुई हैं। तो जी.एस.टी. मैनेजमेंट की बहुत बड़ी आवश्यकता है । इसके साथ जी.एस.टी. की चोरी । एक इनपुट और इसके साथ जी.एस.टी. की चोरी । मैंने इस सदन में इसको कई बार बोला है और फिर से इस बात को बोल रहा हूं । पंचायत स्तर में 14वें वित्त में और अभी तो 15वां वित्त आ गया, 15वें वित्त के पैसों में चेक कट रहे हैं, उसमें कहीं पर भी जी.एस.टी. का प्रावधान नहीं है । यह एक जगह जी.एस.टी. चोरी की गई और अगर हम जगह-जगह जी.एस.टी. चोरी की समीक्षा करें तो कितना मिलेगा ।

सभापति महोदय, खनिज की बात है । हमारा राजस्व कहां से आ रहा है । 2018-19 में खनिज से हमारा जो रेवेन्यू आ रहा था, वह 6110 करोड़ था । 2019-20 में 6195 करोड़ था । 1.5 प्रतिशत का ग्रोथ था । हम भारत के खनिज का 15 प्रतिशत उत्पादन यहां करते हैं और हमारी ग्रोथ 1.5 प्रतिशत है । यहीं पर माफिया है। अगर कोयला, लोहा, रेत का माफिया आएगा तो माफिया सबसे पहले राजस्व की क्षति करता है और राजस्व की क्षति करके जनता का पैसा कुछ चिह्नांकित लोगों के हाथ में चला जाता है, जो इस बजट में आना चाहिए । इस साल सिर्फ खनिज राजस्व में -24 प्रतिशत का ग्रोथ हुआ है, जो हम नहीं ला पा रहे हैं । क्यों नहीं ला पा रहे हैं ? सरकार को इसको सोचने की जरूरत है । भारत का लगभग 100 प्रतिशत टिन छत्तीसगढ़ में है । ढाई साल में कोई प्लानिंग नहीं हुई कि टिन के लिए क्या माईनिंग की जाये ? बॉक्साइड के लिए कोई नई माईन्स नहीं आई । मैंने प्रश्न लगाया था कि देवभोग के डीवियर्स के डॉयमंड माईनिंग का क्या हुआ ? बी. विजय कुमार का, भरत शाह का, उस माईन्स का क्या हुआ ? वह माईन्स कहां पर है, क्यों माईनिंग नहीं कर रहे हैं ? केन्द्र सरकार ने गोल्ड ब्लॉक का एलोकेशन किया, गोल्ड ब्लॉक का ऑक्शन हुआ, पर यहां गोल्ड ब्लॉक की माईनिंग क्यों नहीं हुई ? यहां से माईनिंग का राजस्व आता है । नये जो कोल ब्लॉक हैं, केन्द्रीय मंत्री यहां पर आये, बैठे, मुख्यमंत्री जी से चर्चा हुई, दो कोल ब्लॉक को हटाया गया, दो कोल ब्लॉक को जोड़ने का आश्वासन दिया गया, नये कोल ब्लॉक हैं, पर नये कोल ब्लॉक को क्यों नहीं किया गया ?

सभापति महोदय :- सौरभ जी, कृपया समाप्त करेंगे ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री सौरभ सिंह :- माननीय सभापति महोदय, अंत में मैं एक बात कहूंगा, दो मिनट का समय चाहूंगा । आप कर्ज की बात कर रहे हैं । यहां पर इस सदन में बहुत राजनीति होती है कि किसने क्या बेच दिया और किसने क्यों बेच दिया ? अगर मोनेटाईजेशन की बात करें, प्राईवेटाईजेशन की बात करें । डिस-इंवेस्टमेंट, मोनेटाईजेशन, प्राईवेटाईजेशन तीनों अलग-अलग चीजें हैं और केन्द्र सरकार तीनों चीजों में काम कर रही है । आप तो शासकीय जमीन बेच रहे हैं । इस प्रदेश में कभी ऐसा नहीं हुआ कि शासकीय जमीन बिकेगी । आने वाले 20-30 साल में एक भी शासकीय जमीन नहीं बचेगी, उसके लिए आप बात कर रहे हैं कि हम शासकीय जमीन बेच रहे हैं । अगर केन्द्र सरकार एल.आई.सी. का आई.पी.ओ. ला रही है तो इसी सदन में अशासकीय संकल्प आता है कि हम केन्द्र सरकार के आई.पी.ओ. के बारे में, एल.आई.सी. के आई.पी.ओ. के बारे में चर्चा करेंगे । केन्द्र सरकार अपनी नीति कर रही है और जो पैसा लगा है, वह भारत की जनता का पैसा लगा है । इसी कालांतर में भारत की जनता का पैसा लगा है, उस भारत की जनता के पैसे का डिस-इंवेस्टमेंट प्राईवेटाईजेशन और मोनेटाईजेशन हो रहा है, उस पर क्या राजनीति हो रही है । आप तो शासकीय जमीन बेच रहे हैं । आप शासकीय जमीन बेचकर केन्द्र सरकार के ऊपर ऊंगली उठा रहे हैं । यह नहीं होना चाहिए । केन्द्र सरकार अपना Debt कम करने के लिए, fiscal Deficit फिजिकल डेफिट कम करने के लिए यह योजना बना रही है। सभापति महोदय, आपने बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद ।

डॉ. विनय जायसवाल (मनेन्द्रगढ़) :- सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । जब किसी भी बजट की बात होती है तो आंकड़ों के बारे में बड़ी-बड़ी बात की जाती है । मैं बजट के समर्थन में बहुत ज्यादा आंकड़ों की बात नहीं करूंगा, मैं नीयत की बात करूंगा ।जब सरकार बजट पेश करती है तो सरकार की नीयत क्या है, यह उस बजट में झलकती है ।

समय :
04:00 बजे

आज माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी अपना उद्बोधन दे रहे थे तो उन्होंने एक शब्द कहा, गैर विकासात्मक कार्य। गैर विकासात्मक कार्य में सरकार ज्यादा खर्च कर रही है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि गैर विकासात्मक कार्य क्या है ? गैर विकासात्मक कार्य जहां अभी जनसंख्या आने में आपके राईट साईड में जितने भी विशेषज्ञ बैठे हुए हैं, ये बताएं कि नया रायपुर में जो अरबों खरबों का बजट बर्बाद करके उसको बसाने का काम किया गया, उसमें आकंठ भ्रष्टाचार का काम किया गया, आखिर में वहां पर जनता कब बसेगी, आखिर वहां population कब आयेगा ? ये गैर विकासात्मक कार्य है, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। आपने मेडिकल कॉलेज से लेकर जयस्तंभ चौक तक फूटपाथ का निर्माण कर दिया, आखिर उस फूटपाथ का औचित्य क्या है ? ये गैर विकासात्मक कार्य है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के कार्यकाल में आपको पता है कि रेलवे स्टेशन की तरफ जो जाने वाली ओवरब्रिज बनी हुई है, उसमें किस गुणवत्ता का काम हुआ है और वह किस तरह से बना है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये गैर विकासात्मक कार्य है। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह यह बताना चाहेंगे कि क्या अगर किसान के ऊपर पांच हजार करोड़ से ज्यादा, अगर ये न्याय की बात करते हैं तो क्या गैर विकासात्मक कार्य है ? अगर हम छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय जैसी नवाचार योजना का लाभ लाते हैं और लोगों की आय को बढ़ाने का काम करते हैं तो क्या ये गैर विकासात्मक कार्य है ? ये नियत है, यह नियत की बात है। आप विपक्ष में बैठे हैं, आप बजट की बुराई कर सकते हैं। लेकिन कहीं न कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता इस बजट में दिखी है, खास करके अगर हम पिछले एक साल की बात करें तो ने केवल हमारा प्रदेश और हमारा देश, बल्कि पूरा विश्व जो है, वह कोरोना के चपेट में था। पूरे देश दुनिया और प्रदेश की जो आर्थिक गतिविधियां थी, वह बंद थी, लगभग एक साल बंद की स्थिति में थी। इसके बाद बजट में जो थोड़ा सा संकुचन हुआ है, उसमें हमारे विपक्ष के वक्ताओं ने अपना जो वक्तव्य रखा है। वह गैर जिम्मेदाराना ढंग से रखा है। मैं आपको यह बोलना चाहूंगा। जब हम किसी बजट की बात करते हैं तो जो उस राज्य में रहने वाले लोग हैं, होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात हमारे मुख्यमंत्री जी ने की और जिस HEIGHT बजट की बात की, उसको माननीय रमन सिंह जी ने बौनसाईज करके उसको बौना बताने की कोशिश की, उसके बारे में भी मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा। जब बजट प्रस्तुत होता है, तो उस राज्य में रहने वाला युवा जो बेरोजगार है, वह जानता चाहता है, वह पूछना चाहता है कि आखिर में मेरे लिये इस बजट में क्या है ? आज बस्तर टाइगर्स के नाम से 7 जिलों में 2800 युवाओं की भर्ती करने का काम इस बजट में किया गया है। जब बजट प्रस्तुत किया जाता है तो उसकी संवेदनशीलता भी देखी जाती है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो झलियामारी में किस तरह से आदिवासी बालिकाओं के आश्रम में उनके साथ अत्याचार हुआ, यह बताने की जरूरत नहीं है। आज मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता है कि कन्या छात्रावास और आश्रम में रह रही हमारी बच्चियों के लिए 2200 महिला होमगार्ड की भर्ती की व्यवस्था इस बजट में है। मैं यह बताना चाहता हूं, मैं बार-बार आपको यह स्मरण कराना चाहता हूं कि बजट में नियत होना चाहिए, नियत में खोट नहीं होना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, मैंने बेरोजगारी की बात की। अगर यहां का किसान पूछता है कि मेरे लिये क्या है ? माननीय सभापति महोदय, जब पहला बजट भाषण हुआ था, उसमें डॉ. रमन सिंह का पुराना भाषण का रिकार्ड निकलवाकर देख लीजिये, आप उनके भाषण को सुन भी सकते हैं, मुझे अभी भी इस बात का स्मरण है कि जब हमने 10 हजार करोड़ रूपया किसानों का कर्ज माफ किया और 2500 रूपये धान के समर्थन मूल्य की घोषणा की तो पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह जी ने इसी सदन में अपने वक्तव्य में कहा था कि कहां से वित्तीय प्रबंधन होगा, आप इतना रकम दे रहे हैं, आप इतनी ज्यादा राशि देने की घोषणा कर दिए कि आने वाले समय में यह टाय-टाय

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

फिस्स हो जायेगा। लेकिन आज तीसरे बजट में भी 5 हजार करोड़ से ज्यादा की राशि का प्रावधान राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए इस बजट में किया गया है। मैं आज विपक्ष के साथियों से पूछना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार ने किसानों को बोनस देने के लिए जब प्रतिबंध लगाया है, जब केन्द्र सरकार ने एम.एस.पी. के ऊपर प्रतिबंध लगाया है, उसके बारे में आपका क्या कहना है ? उसके बारे में केन्द्र सरकार की क्या नीयत है, इस बात को भी आप लोगों को अपने उद्बोधन में बताना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, 2016 में केन्द्र की सरकार ने घोषणा की थी कि 2022 में किसानों की आय, किसानों की इन्कम को दोगुना कर देंगे। अभी रिपोर्ट है कि 2016 से 2020 तक 4 वर्षों में किसानों के आय में मात्र 15 से 20 प्रतिशत वृद्धि हुई है। माननीय सभापति महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या शेष 2 साल में 80 प्रतिशत की वृद्धि किसानों को मिलेगा ? कभी नहीं मिलेगा। जिस तरह से ये आकड़ें बता रहे हैं, आप 10 प्रतिशत और वृद्धि मान लीजिये, आपने कहा था कि सन् 2016 से 2022 तक किसानों की इंकम को दोगुना करेंगे। लेकिन आप किसानों को 30 प्रतिशत से ज्यादा वृद्धि नहीं दे पायेंगे। लेकिन माननीय सभापति महोदय, इन दो सालों में माननीय भूपेश बघेल की सरकार ने, हमारी सरकार ने छत्तीसगढ़ में किसानों की इन्कम में 30 प्रतिशत वृद्धि करने का काम किया है।

सभापति महोदय :- जायसवाल जी, कृपया समाप्त करेंगे।

डॉ. विनय जायसवाल :- जी, मैं दो मिनट में खत्म करूंगा। कल डिबेट में यह बात आ रही थी कि यह सरकार छत्तीसगढ़ियां की बात करती है, छत्तीसगढ़ियों की बात करती है तो यह आत्मानंद इंग्लिश मिडियम स्कूल क्यों खोल रही है। कल डिबट में यह बात आ रही थी। माननीय सभापति महोदय, इसमें शर्म आना चाहिए। अगर हम छत्तीसगढ़ के गरीब बच्चों को, छत्तीसगढ़ के किसान के बच्चों को, छत्तीसगढ़ के मजदूर के बच्चों को डी.व्ही.ए. और डी.पी.एस. की तरह उत्कृष्ट इंग्लिश मिडियम स्कूलों की तरह शिक्षा देना चाहते हैं, हमारे छत्तीसगढ़ के जो नौनिहाल हैं, कल अच्छा पढ़कर, अच्छी-अच्छी जगह में जाकर जॉब करे और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करें तो इसमें कौन से बुराई है ? 151 इंग्लिश मिडियम स्कूल की जो घोषणा है, यह निश्चित रूप से अपने आप में अभिनव पहल है। माननीय सभापति महोदय, अधोसरंचना की बात हो या प्रशासन की बात हो या स्वास्थ्य की बात हो या बदलाव की बात हो, जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह बजट प्रस्तुत किया है, निश्चित रूप से हमारे विपक्ष के साथी भी कहीं न कहीं इसकी मन ही मन भूरी-भूरी प्रशंसा कर रहे होंगे कि कोरोना काल में इतना अच्छा बजट कैसे प्रस्तुत हो सकता है। आप खुलकर इस बात को बोलिये, हम आपका समर्थन करेंगे। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री रजनीश कुमार सिंह (बेलतरा) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कल जो बजट प्रस्तुत किया गया है, मैं उस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। आम तौर पर जब देश का

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

बजट पेश होता है तो उसका सकारात्मक पहलू देखने के लिए शेयर मार्केट निफ्टी को एक सूचकांक माना जाता है। यदि देश के बड़े वर्ग के लोगों के लिए बजट पेश है, तो वह शेयर मार्केट हो या निफ्टी हो, बहुत बूम करता है, जो हमने पिछले बजट में देखा है और लगातार देख रहे हैं। यदि छत्तीसगढ़ में शेयर मार्केट होता तो कल जो बजट पेश हुआ, तो आज वह शेयर मार्केट धड़ाम हो चुका होता। माननीय विनय जायसवाल जी बहुत तारीफ कर रहे थे कि बजट बहुत अच्छा है। माननीय सभापति महोदय, इनका जो बजट 1 लाख करोड़ रूपये का पेश हुआ है, जिसमें इनको ऋण भी चुकता करना है और पूंजीगत व्यय लगातार कम होता जा रहा है और कोई भी लोक कल्याणकारी राज्य के लिए पूंजीगत व्यय यदि कम होता है तो निश्चित रूप से विकास की सारी योजनाएं प्रभावित होती हैं, लोगों के जीवन यापन में उसका असर पड़ता है और उसका असर ये दिख रहा है कि 20 साल में छत्तीसगढ़ में पहली बार प्रति व्यक्ति आय में पहली कटौती हो रही है अन्यथा पिछले 20 साल से लगातार प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही थी। ये वर्ष 2019-2020 में 12928 करोड़ रूपये कर्ज लिये और उसमें से सिर्फ 8685 करोड़ रूपये पटाये। वर्ष 2020-2021 में 22069 करोड़ रूपये का कर्ज लिये और 4841 करोड़ ही पटाये। पिछले का 18 हजार करोड़ बाकी है। वर्ष 2021-2022 में इनका 18776 करोड़ रूपये का ऋण लेना अनुमानित है और 53076 करोड़ कर्ज पटाना बाकी है। तीन वर्ष में ये लगभग 53 हजार करोड़ का कर्ज ले चुके होंगे। एक तरफ ऋण बढ़ रहा है और राजस्व घाटा कम हो रहा है। जो राजस्व प्राप्ति है वह कम हो रही है। इस बार गैर राजस्व कर में 038 प्रतिशत की कमी हुई है और राज्य के कर में 1.55 प्रतिशत की कमी आई है। हमारी देनदारी लगातार बढ़ रही है। अगले वित्त वर्ष के आते-आते 80 हजार करोड़ से ऊपर की हमारी देनदारी हो जाये रहेगी इसलिए सरकार के बजट में निश्चित रूप से हमको जो निराशा झलक रही है इसका आने वाले समय में नकारात्मक पहलू दिख रहा है। बार-बार आती है कि केंद्र से क्या मिला। केंद्र से हमको जो राजस्व प्राप्तियां हुई हैं, वह 37298 करोड़ हैं जबकि राज्य की अपनी खुद की जो राजस्व प्राप्ति है वह 31045 करोड़ रूपये की है। तो आप इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि केंद्र सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार को पूरी तरह से सहयोग कर रही है।

श्री रामकुमार यादव :- भैय्या, ओ थारी और लोटा ल पिटवाये रहेव तेहू ल बतावव।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- बताथों-बताथों। ओला छत्तीसगढ़ीच में बताथों। दूसरी बात राज्य सरकार और केंद्र सरकार की तुलना करें, केंद्र सरकार ने इस कोरोना संक्रमण काल में जो कि पूरे भारत में था, विश्व में था, छत्तीसगढ़ में भी था लगभग 5 लाख करोड़ की पूंजीगत व्यय में बढ़ोत्तरी की है जो कुल बजट का 16 प्रतिशत है। जबकि राज्य सरकार ने जो बजट पेश किया है उसमें वह वृद्धि बहुत कम है। इसलिए केंद्र सरकार से बार बार तुलना करना छोड़कर राज्य को चाहिए कि हम अपना काम और जो बड़े-बड़े वायदे किए हैं उस काम को करें। 35 हजार पंप कनेक्शन की बात आई है, किसानों को पंप कनेक्शन के लिए क्यू में लगना पड़ा है। ऐसी क्या स्थिति बनी और हर योजना में सरकार को

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

मैचिंग ग्रांट का पैसा देने में दिक्कत हो रही है और यह बता रहा है कि हम सिर्फ धान-धान की बात कर रहे हैं और वह भी नहीं मिला है। रामकुमार जी, धान का पैसा अभी तक नहीं मिला है और हम 2500-2500 रूपये कर रहे हैं और पिछले साल का बजट प्रावधान ले गये थे, एक बार दे दिये रह थे।

श्री रामकुमार यादव :- मिलगेहे भईया।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- नहीं, कहां मिलेहे।

श्री सौरभ सिंह :- एक किश्त बचे हे। ओ पार्टी के हस ओला जल्दी करवा दे।

श्री रामकुमार यादव :- दूसरा हरेली तिहार और तीसरा देवाली में मिल जाही।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- सभापति महोदय, और राजस्व में जो लगातार कमी हो रही है। इस बात हमने शराब बिक्री में 5500 करोड़ का राजस्व प्राप्त किया है। इसमें 20 प्रतिशत ओव्हर रेट जो सेस हो रहा है यदि इसको हम बचत कर लें तो लगभग एक हजार करोड़ रूपये हमको सिर्फ शराब से अतिरिक्त मिल सकता है।   अभी रेत की बात आई है।

श्री मोहन मरकाम :- आपको शराब का रेट कैसे पता? अब आप लोग कहीं लाईन तो नहीं लगे थे।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- अब आप ही लोग बताते रहते हैं ना तो पता लग जाता है। माननीय मंत्री जी हमको रेट बताते रहते हैं। इसी प्रकार रेत का जो अवैध उत्खनन हो रहा है, कहने के लिए 10 करोड़ रूपये इन्कम है लेकिन इसका जिस तरह से दोहन हो रहा है कि आने वाले समय में सिर्फ बिलासपुर ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ की कोई नदी नहीं बचेगी। यह बहुत संवेदनशील मुद्दा है। हम देखते रहते हैं कि अंबिकापुर से यू.पी. तक जाता है और कहां-कहां नहीं जाता। 40 हजार, 50 हजार, 70 हजार में जाता है। एक दिन ऐसा आयेगा कि छत्तीसगढ़ को अपने घर बनाने के लिए उसी दर पर लेना पड़ेगा। इसलिए रेत का जो अवैध उत्खनन हो रहा है रेत का जो अवैध काम चल रहा है इसमें राजस्व के साथ-साथ छत्तीसगढ़ के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है, यह संवेदनशील मुद्दा है इसलिए इसको ध्यान देना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, यहां बार-बार विषय आता है कि कोविड आने के कारण हमको छत्तीसगढ़ में राजस्व की कम प्राप्ति हुई। अभी तक यह नहीं बताया गया है कि 25 मार्च के बाद जितने दिन लॉकडाऊन रहा, जो हमारी राजस्व प्राप्तियों के 4-5 प्रमुख संसाधन है, चाहे खनिज हो, चाहे रजिस्ट्री हो चाहे अन्य हो, लेकिन इसमें यह नहीं बताया गया है कि किसमें-किसमें कितना कम हुआ और ऐसा भी नहीं है कि यह कोविड के कारण हम जब पीक में थे तो यहां पर बड़े-बड़े हॉस्पिटल बन गये, बड़ी-बड़ी मेडिकल फेसलिटिज दी गई, कुछ वेंटिलेटर बन गये, कुछ आई.सी.यू. बेड बन गये। इसका मतलब यह नहीं है कि पूरा पैसा चला गया। पिछले बजट का चाहे जल संसाधन का काम हो, पी.डब्ल्यू.डी. का काम हो, आर.ई.एस. का काम हो, पूंजीगत व्यय के जितने भी काम रहे हों, किसी में

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

कोई काम अभी तक नहीं दिख रहा है। जबकि इस साल का हमारा दूसरा बजट पेश हो चुका है। माननीय मंत्री जी, नगरीय निकायों की स्थिति बहुत खराब है। नगरीय निकाय में बिलासपुर को बहुत बड़ा वृहद क्षेत्र बना दिया गया है।

नगरीय प्रशासन मंत्री(डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- माननीय सभापति महोदय, इनके पुराने मंत्री जी ने नगरीय निकाय को तो गड़बड़ करने का काम किया है। इनका पूरा खोदापुर बना दिया। वह क्या करेंगे ? उससे उबर नहीं पा रहे हैं।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- माननीय मंत्री जी, नहीं।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय सभापति महोदय, इनके विधान सभा क्षेत्र में सिवरेज लाईन बिलासपुर शहर में थी।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- माननीय सभापति महोदय,शैलेश पाण्डे जी सब बोलते हैं लेकिन बिलासपुर के बारे में नहीं बोलते हैं और उस दिन बशीर बद्र और इकबाल का शेर सुना रहे थे।

श्री शिवरतन शर्मा :- क्या है माननीय नगरीय निकाय मंत्री जी।

श्री शैलेश पाण्डे :- आप एक शेर और सुनिए।

श्री शिवरतन शर्मा :- सही मायने में महात्मा गांधी को अपना आदर्श मानकर चलने वाले हैं। इनके विभाग में सिर्फ और सिर्फ महात्मा गांधी की चलती है और वहां बिना महात्मा गांधी के कोई काम ही नहीं है।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- हां चलिए, आप एक शेर सुनाईये।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय सभापति महोदय, गांधी जी के बिना कुछु नइ चले।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय सभापति महोदय,हमन तो मानत हन कि गांधी जी के बिना कुछु नइ चले।

श्री शिवरतन शर्मा :- आपके यहां गांधी जी के बिना कुछ नहीं होता

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- मैं वही तो बोल रहा हूँ।

श्री शिवरतन शर्मा :- नहीं। गांधी जी के बिना आपके विभाग में कुछ होता ही नहीं है। हम तो स्वीकार कर रहे हैं।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय सभापति महोदय,हमन तो मानत हन कि गांधी जी के बिना कुछु नइ चले।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- आप इस विभाग को अच्छी तरीके से जानते हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- सही मायने में गांधी के अनुयायी तो आप ही हैं।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय आप लोग अनुयायी हैं।

श्री नारायण चंदेल :- उधर गांधी है और इधर बांधी है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सभापति महोदय :- कृपया टोका-टाकी न करें।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- लेकिन वह चले नइ।

श्री अमरजीत भगत :- अगर गोड़से वाले गांधी को मानने लगे तो बहुत बड़ा परिवर्तन है।

श्री शिवरतन शर्मा :- गोड़से का मंदिर बनाने वाला व्यक्ति कांग्रेस प्रवेश कर चुका है। मैंने उस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी को जानकारी दिया था।

सभापति महोदय :- माननीय रजनीश जी, अपनी बात जारी रखिए।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- जी। माननीय सभापति महोदय, मैं बोल रहा था कि इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कोई भी बात नहीं कही गई है जैसे कि हमारे वरिष्ठ सदस्य, वक्ता माननीय चन्द्राकर जी ने कहा कि यह सिफ एक जिले का बजट है और पिछले 3 सालों से देख रहे हैं। एक हाई स्कूल का उन्नयन नहीं हो पा रहा है हायर सेकेण्डरी स्कूल का उन्नयन नहीं हो रहा है पिछले 3 सालों से ढूंढ रहे हैं।

श्री अमरजीत भगत:- माननीय रजनीश जी, कम से कम बिलासपुर वाले तो मत बोलिए। आप लोगों के लिए हवाई जहाज दे दिया है।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- वहां हवाई जहाज लाने में आपका कोई योगदान नहीं है।

श्री अमरजीत भगत:- हमारे किये बिना वहां पर एयरपोर्ट बन गया क्या ?

श्री रजनीश कुमार सिंह :- आप फोटो छपवा लीजिए।

श्री अमरजीत भगत:- वहां एयरपोर्ट हमने ही बनवाया है।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- नहीं। उसमें आप 27 करोड़ दिये हैं उसको आप वापस ले लेंगे। वह आपको मिलेगा और केन्द्र सरकार ने उसको किया है। माननीय नरेन्द्र मोदी और हरदीप पुरी जी ने इसका सौभाग्य बिलासपुर वालों को दिया है।

श्री सौरभ सिंह :- वह जो एयरपोर्ट है वह एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इण्डिया का एयरपोर्ट है। यह छत्तीसगढ़ वाले इस बात को जान रहे हैं माननीय शैलेश पाण्डे जी भी जान रहे हैं। आप लोग फोटो छपवाईये और खुश रहिए, यह अच्छी बात है।

सभापति महोदय :- रजनीश जी, कृपया संक्षेप में अपनी बात कहिए।

श्री अमरजीत भगत:- आप लोग पूरी जानकारी लेकर आया करें। राज्य सरकार बनाती है। उसमें राज्य सरकार अंशदान, जमीन देती है तब जाकर एयरपोर्ट बनता है। आप आसमान में चलायेंगे क्या ?

श्री रजनीश कुमार सिंह :- तो फिर आप लोग अपना उड़वा क्यों नहीं लिये?

संसदीय सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्री से संबद्ध(डॉ. रश्मि आशिष सिंह) :- हम लोग तो कुछ नहीं बोल पाते हैं। चाउर वाले बाबा बन गये थे तब भी कुछ नहीं बोल पाये।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) :- माननीय अमरजीत भईया, आप सुनिए। आप दो मिनट सुनिए।

श्री नारायण चंदेल :- काय बोलना ?

श्री उमेश पटेल:- चंदेल भईया बोल रहे थे और बोलते-बोलते का बोल दिस जानत हस। लाईट ला दिया मा दिखाथन। माननीय रजनीश भाई आप समझ रहे हो। वह कहां से सीख रहे हैं, वह आप देख लीजिए।

सभापति महोदय :- माननीय रजनीश जी, आप अपनी बात समाप्त करिये।

श्री सौरभ सिंह :- उस सदन तो हम मान लिये थे कि .. ?

श्री उमेश पटेल:- उनको ट्रेनिंग कहां से हो रही है, यह मैं बता रहा हूँ।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- माननीय सभापति महोदय, मैं आखिरी में कहना चाहता हूँ। आप दो-तीन बार बोल चुके हैं। मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। कि मेरे पास शेर तो माननीय शैलेश पाण्डे जी के लिए है। आप चाह रहे हैं कि हम तो डूबेंगे सनम, लेकिन इधर वाले यह नहीं करेंगे। वही सबसे ज्यादा बहुत उसके पक्ष में थे कि बिलासपुर नगर निगम का विस्तार कर लिया जाये। और विस्तार हो गया तो शायद बिलासपुर नगर निगम एक ऐसा नगर निगम होगा जिसमें 5 विधान सभा है। इतना बड़ा क्षेत्र आ गया है कि एक पंचायत लिंगियाडीह है, उसी के अंतर्गत आता है। वह पंचायत साल में कम से कम 5 करोड़ का काम करता थी, अभी बिलासपुर नगर निगम को दो साल में 7 करोड़ रुपये मिला है।

श्री शैलेश पांडे :- आदरणीय रजनीश भैया, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिलासपुर को 20 करोड़ रुपये दिये, उसमें 9 करोड़ रुपये केवल आपकी विधानसभा में हम लोगों ने दिये हैं और डेढ़ करोड़ रुपये कल बिलासपुर विधानसभा में दिये हैं। यह हमने किया है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो माननीय मंत्री जी का बजट उठाकर देख लीजिए, आपको 10 करोड़ रुपये मिला है। आपको इतनी प्राथमिकता दी है, आपको हमारी सरकार की तारीफ करनी चाहिए।

सभापति महोदय :- चलिये, रजनीश जी, आप समाप्त करिये।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- माननीय सभापति महोदय, माननीय शैलेश जी बोल रहे हैं कि 9 करोड़ रुपये हैं, धन्यवाद दे दीजिए। मैं धन्यवाद दे देता हूं। लेकिन..।

श्री मोहन मरकाम :- लेकिन क्यों कह रहे हैं।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- मरकाम जी सुन लीजिए, यह दो पंचायतों में 9 करोड़ रुपये आता है जिसको यह लोग निगम में शामिल कर लिये हैं। मंगला और लिंगियाडीह, माननीय विधायक जी के क्षेत्र को बिलासपुर पूरा छोड़ दे रहा हूं। पिछले दो साल से 7 करोड़ रुपये मिले हैं उसी में बोल रहे हैं कि आप लोग धन्यवाद दीजिए। महाराज जी, 100 करोड़ रुपये रहता था और 20 करोड़ रुपये की जो घोषणा हुई है, अगले साल मार्च-अप्रैल 2022 तक आयेगा।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री शैलेश पांडे :- 100 करोड़ रुपये सेठ जी की जेब में जाता था, वह जाकर गुडाखू की फैक्टरी में लग जाता था।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- माननीय सभापति महोदय, इस बजट में ऐसा कुछ नहीं है।

श्री मोहन मरकाम :- हमारी सरकार से डमरूधर पुजारी जी कितने खुश हैं, वह प्रश्न ही नहीं पूछते।

श्री सौरभ सिंह :- पुजारी जी से धोखा हो गया, उसको आप क्यों कह रहे हैं। संतराम जी के बोलने के बाद आप लोगों ने ऐसा माहौल बना दिया कि मैं संतुष्ट हूं और पुजारी जी ने भी बाद मे बोल दिया कि मैं संतुष्ट हूं।

सभापति महोदय :- कृपया समाप्त करें।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- माननीय सभापति महोदय, यह बजट बिल्कुल नकारात्मक है, दिशाहीन है, विकास से दूर जाने वाले बजट है, इस बजट का विरोध करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने बोलने का अवसर दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री प्रकाश शक्राजीत नायक (रायगढ़) :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत बजट भाषण के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। पिछला एक वर्ष कोरोना काल में गुजरा है उसके बावजूद भी लगभग 97 लाख 145 करोड़ का बजट माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रस्तुत किया है। इस बजट में उन्होंने छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए, गावों के लिए विशेष ध्यान रखा है। छत्तीसगढ़ की आत्मा गावों में बसती है। छत्तीसगढ़ का मुख्य व्यवसाय कृषि है। किसान पिछले 15 साल से परेशान थे। किसानों को पिछले 15 सालों में लगातार असत्य वादे मिले। किसानों के लिए कई बार घोषणा हुई, कभी 270 रुपये बोनस, कभी 300 रुपये बोनस, कभी धान की 2100 रुपये कीमत देने की घोषणा हुई, लेकिन किसानों को पिछले 15 सालों में जो मिलना था, वह नहीं मिला। 15 सालों में 14 हजार से अधिक किसानों ने आत्महत्या भी की। इस बार के बजट में जब हमारी सरकार आई, सरकार आने के तुरंत बाद हमारी सरकार ने 17 लाख से अधिक किसानों का 9 हजार से ज्यादा कृषि ऋण माफ किया। हमने जो घोषणा पत्र में वादा किया था कि किसानों को धान की कीमत 2500 रुपये देंगे, उसको हमने दिया। प्रदेश में 2017-18 में 56 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई थी। वर्ष 2018-19 में 56 लाख से बढ़कर 80 लाख मीट्रिक टन, 2019-20 में 83 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई और इस साल छत्तीसगढ़ के इतिहास में सबसे ज्यादा 92 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस बजट में गावों, किसानों के लिए विशेष ध्यान रखा है, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। हमने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि हम वन अधिकार पट्टा देंगे और उनका भी धान हम खरीदेंगे, हम लोगों ने वन अधिकार पट्टाधारी किसानों से 10 लाख 7 हजार मीट्रिक टन धान की खरीदी की है और मुझे याद है कि पिछली सरकार ने बिजली बिल,

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

किसानों के जो पंप होते हैं, उसके बिजली बिल को माफ करने की घोषणा की थी, वायदा किया था लेकिन उस वायदे से मुकरते हुए उन्होंने 6 हजार यूनिट में सीमित कर दिया था लेकिन अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने बजट में कृषि पंपों के नि:शुल्क विद्युत के लिये 2500 करोड़ का प्रावधान रखा है । इसके लिये मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं । यही नहीं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो पंप का विद्युतीकरण होना है उसके लिये भी 150 करोड़ रूपये का बजट रखा है और किसानों को शून्य ब्याज में ऋण के लिये 59 सौ करोड़ का प्रावधान रखा है इसके लिये भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं ।

माननीय सभापति महोदय, मैं किसान हूं । मैंने बजट में एक नवाचार देखा, मैं भी किसान हूं और गांव में खेती करता हूं । जब हम लोग गांव में खेत में जाते हैं तो कच्चा रास्ता होता है और हम लोग वहां बरसात में जा नहीं पाते हैं । मुख्यमंत्री जी ने कृषि मुख्यमंत्री धरसा योजना के लिये जो 10 करोड़ की जो छोटी सी शुरूआत की है यह एक नवाचार है और किसानों में इसका बहुत हर्ष है और आगे जाकर यह बहुत लाभदायक योजना होगी और किसान इससे खुश रहेंगे । पहले हम लोग सुनते थे कि गाय हा गरू होगे हे लेकिन जब से हमारी सरकार आयी है और जब से गौधन न्याय योजना शुरू हुई है तो गाय हरू हो गे है, लक्ष्मी हो गे है अऊ आज गाय ला घर में बांधत हें, ओकर गोबर ला उठात हें अऊ गाय के गोबर ला बेचत हें अऊ मेरे विधानसभा क्षेत्र का एक किसान श्री तरूण दास गोबर बेचकर 3 महीने में 92 हजार रूपये उसको मिला है और उसने पहली बार अपनी जिंदगी में चूंकि उसके पास झोपड़ी है, उसके पास कभी इतना पैसा नहीं था कि वह साईकिल खरीद पाता लेकिन यह गौधन न्याय योजना है जिसके कारण उन्होंने एक मोटरसाईकिल खरीदा है और साथ ही साथ अपने बच्चों के लिये मोबाईल भी खरीदा है, यह हमारी गौधन न्याय योजना है । (मेजों की थपथपाहट)

माननीय सभापति महोदय, हमारे बजट में चूंकि मैंने शुरू में ही कहा कि गांव, किसान और मजदूरों के लिये यह बजट है और हमारे प्रदेश में कई नदियां बहती हैं, हमारे प्रदेश में मछुआरों की संख्या भी बहुत ज्यादा है । मैंने पहली बार देखा कि मछुआरों के लिये भी इस बजट में प्रावधान रखा गया है और 2 लाख से अधिक हमारे मछुआरे भाईयों को इसमें रोजगार मिलेगा । इस कोरोना काल में आप सबने देखा है कि पूरे देश की इस दीपावली में बाजार वीरान थे लेकिन यह छत्तीसगढ़ राज्य ही है जहां राजीव गांधी किसान न्याय योजना और गौवर्धन न्याय योजना के कारण पिछली दीपावली में हमारे छत्तीसगढ़ के बाजार आबाद रहे और हमारे गांव के लोगों ने बहुत ज्यादा खरीदी की, हमारे गांव के लोगों ने मोटरसाईकिल भी खरीदे और किसानों ने ट्रेक्टर भी खरीदा, गहने भी खरीदे और इस कोरोना काल में भी हमारे छत्तीसगढ़ के पूरे बाजार आबाद रहे । इसके लिये भी मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं ।

समय :

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

4:29 बजे **(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए)**

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बजट में उन्होंने गांव का ध्यान रखा, मजदूरों का ध्यान रखा इसके लिये मैं धन्यवाद देता हूं । मैं शिक्षा की बात करूंगा, हमर छत्तीसगढ़ प्रदेश में पहली बार गरीबों के लिये अंग्रेजी स्कूल खोले गये । स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल । 52 स्कूल खोले गये, जब इसकी शुरूआत हुई, हमने देखा है कि हमारे गरीब परिवार के पालकों ने वहां पर लाईन लगायी थी कि हमारे बच्चों का वहां पर एडमिशन हो और जब हमारे स्कूल चालू हुए, कोरोना काल के कारण बहुत दिन स्कूल चल नहीं पाये और जब स्कूल चालू हुए और मोबाईल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से जब वहां शिक्षा चालू हुई तो पालक इतने खुश हुए और आज छत्तीसगढ़ के हर ब्लॉक में हर बड़ी जगह में अंग्रेजी माध्यम स्कूल की मांग हो रही है । मैं धन्यवाद् दूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को जिन्होंने इस बजट में 119 नए अंग्रेजी माध्यम की स्कूलों का प्रावधान किया है । अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए नवा रायपुर में राष्ट्रीय स्तर के बोर्डिंग स्कूल की स्थापना की है, यह तो मील का पत्थर साबित होगा । कांकेर में उन्होंने बी.एड. कॉलेज की स्थापना की । इसके साथ ही साथ 7 नवीन महाविद्यालय और 3 कन्या महाविद्यालय को भी इस बजट में स्थान दिया है इसके लिए भी धन्यवाद् देता हूं । अध्यक्ष महोदय, हमने पिछली बार देखा था लोग आउटसोर्सिंग करते थे । इस बार बस्तर के युवाओं के लिए एक विशेष बस्तर टाइगर बल बनाया गया है जिसमें बस्तर के 2800 स्थानीय युवाओं की भर्ती की जाएगी, इसके साथ ही साथ 2200 महिला होमगार्ड की भर्ती के लिए इस बजट में स्थान है, इसके लिए भी मैं धन्यवाद् देता हूं । अध्यक्ष महोदय, जब हम छोटे थे तो हम भोपाल जाते थे, उस समय हमें भारत भवन घुमाया जाता था और भारत भवन देखकर हम हर्षित होते थे, मुख्यमंत्री जी ने इस बजट में भारत भवन का बजट में स्थान रखा वह तो बड़ी चीज है और सबसे बड़ी चीज हमने बचपन में सुना था कि भगवान राम छत्तीसगढ़ से गुजरे थे और शबरी माता ने उन्हें चख, चखकर बेर खिलाई थी । हम तो जानते भी नहीं थे कि यहां से राम भगवान गुजरे हैं केवल इतना ही जानते थे कि छत्तीसगढ़ में बेर खिलाया गया था । मुख्यमंत्री जी ने राम वन गमन पथ के लिए प्रावधान रखा है, इसके लिए धन्यवाद् । अध्यक्ष महोदय, सी-मार्ट की स्थापना की गई है । छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ के व्यंजन, छत्तीसगढ़ की कला, शिल्प, यहां के वनोपज के लिए सी-मार्ट की स्थापना का प्रावधान है ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, समाप्त कीजिए, बहुत लम्बा हो गया है ।

श्री प्रकाश शक्राजीत नायक :- अध्यक्ष महोदय, हम लोग तो घानी का तेल भूल गए थे । उसको भी स्थान दिया है । हम लोग पहले हमारे दादा-दारी के साथ जाते थे तो एक चरखा हुआ करता था, बैल उसे चारों ओर घुमाया करता था । उससे जो तेल निकलता था उसकी खुशबू, वह आज भी मुझे याद है । आज छत्तीसगढ़ की संस्कृति को सी-मार्ट के माध्यम से प्रचारित प्रसारित करने का प्रयास किया गया है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, देवव्रत जी ।

श्री प्रकाश शक्राजीत नायक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, दो मिनट । मैं तीन दिन से बोलने का प्रयास कर रहा हूं मुझे मौका मिल नहीं रहा था । आज मिला है तो सिर्फ दो मिनट दे दीजिए । अब हमें फिर से वह तेल खाने को मिलेगा । अध्यक्ष महोदय, आज हम जो दाल खाते हैं, वह दाल छिली हुई आती है । हमें गांव में जो दाल मिलती है वह दलकर निकलती है । इस सी-मार्ट के माध्यम से मिलने वाली दाल, ग्रामीण महिलाओं द्वारा दलकर निकली हुई दाल होगी । सी-मार्ट के माध्यम से ओरीजनल दाल खाने को मिलेगी । इसके लिए भी मैं धन्यवाद् देता हूं । मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इसलिए भी धन्यवाद् देता हूं कि उन्होंने हमारी मांग पर 11 नई तहसीलों का गठन किया है । सरिया और छाल को तहसील बनाने की घोषणा की इसके लिए धन्यवाद् देता हूं । आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए धन्यवाद्।

श्री देवव्रत सिंह (खैरागढ़) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आय-व्ययक प्रस्तुत किया है उसमें बहुत सारी बातें हैं । मैं HIGHT की बात से प्रारंभ करूंगा । मैं समझता हूं कि इस विपरीत परिस्थिति में हमारी सरकार का नारा HIGHT है तो मुझे विश्वास है कि यदि छत्तीसगढ़ की जनता ने इस बात को माना है कि भूपेश बघेल जो कहते हैं वह करके दिखाएंगे तो मुझे लगता है कि हाईट की परिकल्पना अगर साकार हो गई तो छत्तीसगढ़ पूरे देश में अकेला राज्य होगा जो आर्थिक मंदी और लगातार गिरती हुई अर्थव्यवस्था के बीच अपने आप को संभाल कर रखेगा । बजट के प्रस्तुतिकरण को लोग कई तरह से सोचते हैं। बहुत सारे देशों में, विदेशों में बजट एक सामान्य सी आय-व्यय की चर्चा होती है, लेकिन मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में जिन विपरीत परिस्थितियों में सरकार ने अपने दो साल के कार्यकाल में इस बजट को जो प्रस्तुत किया है, उसमें एक बड़ा संघर्ष दिखता है और मुझे लगता है कि विपरीत परिस्थितियां न केवल जी.एस.टी. न मिलना, न केवल राज्य में जो हमारा प्रमुख किसान है, उस पर हमारा पूरा बजट को ट्रांसफर करना, कोरोना की महामारी, इन सब चीजों के बाद भी यदि आज छत्तीसगढ़ खड़ा है और अन्य लोगों के लिए समावेशी विकास के मॉडल के रूप में यदि खड़ा है तो मुझे लगता है कि शायद मुख्यमंत्री जी इसके लिए न केवल बधाई के पात्र हैं, बल्कि एक मजबूत राजनैतिक इच्छा शक्ति उन्होंने दिखाई है और विपरीत परिस्थियों में मुझे लगता है कि अन्य राज्यों के मुकाबले जो एक राजनैतिक इच्छा शक्ति दिखाई है, वह बहुत मायने रखती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने पर पूरा देश विचार कर रहा है। भारत सरकार का जो बजट आया, वह 4.5 निगेटिव ग्रोथ लेकर आया और जी.डी.पी. के सुधरने की कोई बात नहीं होती है और बजट के प्रस्तुतिकरण में दो बातें हैं कि हम देखें कि बजट के जो सामान्य आंकड़े हैं, वह अपनी जगह हैं। निगेटिव जी.डी.पी. ग्रोथ दिखाते हैं, लेकिन यदि राज्य के अंदर में किसान संतुष्ट है, राज्य के अंदर में अगर कैश फ्लो है, राज्य के अंदर में जो हमारे संसाधन है, उस संसाधन को जो लोग आगे बढ़ाने का

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

काम करते हैं, चाहे हमारा पशु पालक है, चाहे हमारा किसान है, चाहे हमारा छोटा व्यापारी है, चाहे हमारा सब्जी और फल उत्पादन करने वाला व्यक्ति है, ये सारे लोग हमारे बूस्टर्स हैं और माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी भी अर्थव्यवस्था में जब गिरावट आती है तो प्रायमरी सेक्टर को जब हम मजबूत करेंगे तभी जाकर हमारी अर्थव्यवस्था खड़ी होगी। माननीय भूपेश बघेल जी ने वही किया और बड़ा सार्थक रूप से किया। आज छत्तीसगढ़ में हमारे जो किसान हैं, आप सोचिए, यदि राजीव गांधी किसान न्याय योजना नहीं मिलता तो क्या स्थितियां होतीं। यदि गोधन योजना चालू नहीं होती तो पैसे का percolation, कैश का percolation नीचे कैसे जाता। आज बाजारों में जो थोड़ी बहुत खुशी दिखती है और जो उत्साह बाजारों में है, इस कारण है कि शासन ने ऐसी योजना बनायी कि जिसमें गरीब और अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति के जेब में पैसा गया। मुझे लगता है कि हमारे सामने बहुत सारी प्रायरिटीज हैं कि हम बड़ी-बड़ी बिल्डिंग बनायें। हम राजधानी को और सुंदर बना दें। बड़ी-बड़ी चीजें करें, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे समय में जब हम संक्रमणकाल में हैं तो ये जो निर्णय शासन का हुआ, ये जो दो क्रांतिकारी योजनाएं हुईं, इससे न केवल हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत खड़ी हुई है, बल्कि यह रोल मॉडल के रूप में और जगह स्थापित होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जी.डी.पी. सकल घरेलू उत्पाद के बारे में चर्चा होती है। अगर जी.डी.पी. का कैल्कुलेशन छत्तीसगढ़ के बेस में करे कि जो अंतिम छोर पर सबसे गरीब व्यक्ति खड़ा है, उसके जीवन में क्या परिवर्तन आयेगा? तो जी.डी.पी. का सही कैल्कुलेशन आयेगा। ठीक है अर्थशास्त्री लोगों ने जी.डी.पी. के कैल्कुलेशन के लिए पैरामीटर्स बना रखे हैं, लेकिन उस पैरामीटर में छत्तीसगढ़ कहीं रहता नहीं। अगर आपको जी.डी.पी. की ग्रोथ देखनी है कि कैसे किसान के जीवन में परिवर्तन आया, उसकी प्रतिव्यक्ति आय में परिवर्तन आया तो आपको छत्तीसगढ़ में मौलिक रूप में देखना चाहिए। मैं समझता हूं कि आज जो छत्तीसगढ़ में कैश का सर्क्यूलेशन है, जिस प्रकार से छोटे प्लॉट्स में जमीन खरीदी हुई, जिस प्रकार से लोगों ने मोटरसाइकिल व ट्रैक्टर्स वगैरह खरीदे, जिस प्रकार से ज्वेलरी का मार्केट उठा तो मुझे लगता है कि शायद अगर हम बजट पर चर्चा करते हैं, प्रदेश की आर्थिक हालात पर चर्चा करते हैं तो यह भूपेश बघेल जी का इकबाल है कि जो सोच वे लेकर चले थे, उस सोच को उन्होंने जमीन पर लागू कर दिया। मैं बहुत से साथियों की बात सुन रहा था कि राज्य ने कर्ज लेकर कर्ज की सीमा को बढ़ा दिया है। 36 हजार करोड़ के कर्ज की बात है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जितने भी विकसित देश हैं, वे लोग विकास के किसी भी मॉडल को लागू करने के लिए बड़े से बड़ा कर्ज लेकर ही विकास करते हैं। आप देखिए, जितनी बड़ी सड़कें बनीं, जो नाबार्ड के माध्यम से बनीं। एन.एच.ए.आई. के माध्यम से बनीं, उन सबमें एशियन डेव्हलपमेंट बैंक नाबार्ड का कर्ज ही था । यदि हमारी सरकार या किसानों को उनकी ऋण की अदायगी के लिए, किसानों को उनकी धान की कीमत देने के लिए ऋण लेती है तो यह तो हमारी प्रायरिटी है । मुझे लगता है कि कर्ज लेकर विकास करने की परिपाटी तो पूरे विश्व की रही है । मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार इसलिए भी व्यक्त करना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

में इन परिस्थितियों में जो धान खरीदी इस वर्ष हुई, मैं सन् 2000 से खुद धान बेचने का काम करता हूं । हम लोग परिवार में लगभग ढाई से तीन हजार क्विंटल धान अलग-अलग बेचते हैं, पर जितनी समेकित प्रणाली इस बार धान खरीदी में थी, जितनी सिस्टमेटिक धान खरीदी हुई, मुझे लगता है कि ऐसा कभी नहीं हुआ। शायद हमारी यह प्रायरिटी थी कि हम धान खरीदी को सुनिश्चित करें और अच्छे से करें । इसीलिए मैं कहता हूं कि जब धान खरीदी सही तरीके से हुई तो मार्केट में पैसा आया और अगर आज किसान खुशहाल है तो लगता है कि उसका पैसा सही समय पर मिल जाता है । मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से कोरोना काल में राजस्व की प्राप्तियां बहुत कम हुई और भविष्य में भी हमारी पूंजीगत मद का इंवेस्टमेंट है, वह कम रहेगा, पर इस राज्य में ऐसी बहुत सारी संभावना है, जहां हम अपने खर्च में कटौती करके आगे जा सकते हैं और प्रदेश में जिस प्रकार की जलवायु, जिस प्रकार का वातावरण है, मुझे लगता है कि यदि हम इस लाईन पर डेव्हलपमेंट करें कि कोल्ड चैन बनाएं या कोल्ड स्टोरेज बनाएं तो छत्तीसगढ़ अकेला राज्य ऐसा है, जहां 7 से 8 महीने तक सब्जी और फल का उत्पादन जलवायु और आर्द्रता के कारण होता है । मुझे लगता है कि यदि इस क्षेत्र में हम आगे काम करें तो जो फलों और सब्जियों में हमारा वैल्यू एडीशन होने वाला है, वह इस राज्य को एक नई पहचान देगा ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश में बिजली के उत्पादन में नई ऊंचाइयों को प्राप्त हो सकता है । यदि नई कोयला खदानें प्रारंभ हों, नये प्लांट लगें तो जो बिजली उत्पादन हमारे राज्य में होगा तो हम उसको निर्यात करके राशि कमा सकते हैं । हम लोग छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ी समस्या देखते हैं कि जो सी.एस.पी.डी.सी.एल. में ट्रांसमिशन लॉसेस हैं, उसके कारण हमारी बहुत सारी बिजली अपव्यय होती है । उसको रोकने का प्रयास सी.एस.पी.डी.सी.एल. के माध्यम से होना चाहिए । सौर ऊर्जा एक बड़ा शक्ति का केन्द्र है । छत्तीसगढ़ में उसके लिए बहुत अच्छी संभावनाएं हैं। मैं मुख्यमंत्री जी को अपनी तरफ से धन्यवाद देना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक बड़ी योजना की स्वीकृति उन्होंने बजट में दी । लगभग 50 वर्षों से उस योजना की मांग थी । एक त्रिशूल नाला है, उसमें इतना पानी होता है कि मई-जून में वहां पर पानी बहता रहता है, लेकिन दुर्भाग्य से वह पूरा पानी मध्यप्रदेश में बालाघाट जिले में जाया करता था । माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय रविन्द्र चौबे जी ने एक लिंक योजना बनाई है । लिंक योजना के बजट में उसको स्वीकृत की है । इसमें त्रिशूल नाले के पूरे पानी को सूरही जलाशय में डाला जाएगा, जिससे राजनांदगांव और दुर्ग जिले को मध्यप्रदेश में जाने वाला पानी मिलेगा ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा, मैंने पहले भी कहा है कि राजस्व प्राप्ति को बढ़ाने के लिए निश्चित रूप से जो हमारी डायमंड माईनिंग का काम है, उसको भी किया जाना चाहिए और मेरी विधान सभा क्षेत्र से लगा हुआ बालाघाट जिले का जो जंगल है,

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

जहां कमलनाथ जी की सरकार ने गोल्ड माईनिंग का काम प्रारंभ किया है, अभी वहां पर गोल्ड माईनिंग का काम चल रहा है और हमारे अपनी विधान सभा क्षेत्र में भी गोल्ड माईनिंग की बहुत सारी संभावनाएं हैं । लोग प्राय: चोरी करके वहां पर सोने की कण निकालते हैं । गोल्ड माईनिंग हमारी विधान सभा क्षेत्र में भी प्रारंभ होनी चाहिए । अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष महोदय :- बहुत-बहुत धन्यवाद । माननीय सदस्यों के लिए स्वलपाहार की व्यवस्था लाबी स्थित कक्ष में एवं पत्रकारों के लिए प्रथम तल पर की गई है । कृपया सुविधानुसार स्वलपाहार ग्रहण करें ।

श्रीमती इंदू बंजारे (पामगढ़) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में बोलने के लिए खड़ी हुई हूं ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ सरकार कहती है कि हम प्रदेश में अच्छी शिक्षा लाएंगे, लेकिन मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूं कि प्रदेश में कई ऐसी जगह है, जहां पर स्कूल भवन बहुत ही जर्जर हो चुकी है और कई ऐसे स्कूल हैं, जहां पर भवन का निर्माण ही नहीं हुआ है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करती हूं कि मेरे पामगढ़ क्षेत्र में बहुत से ऐसे स्कूल हैं, जो भवनविहीन हैं और बहुत से ऐसे स्कूल हैं जो पूरी तरह जर्जर हो चुकी है, मैं इसको नये भवन निर्माण करने की मांग करती हूं। साथ ही मेरे पामगढ़ क्षेत्र में बहुत से ग्राम पंचायतों में हाईस्कूल है, जिसे हायर सेकेण्डरी में उन्नयन करने की अत्यंत आवश्यकता है, मैं इसकी भी मांग करती हूं। अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य के क्षेत्र में पामगढ़ क्षेत्र में एक ही सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र है जिसमें पूरे क्षेत्र के लोग ईलाज के लिये आते हैं लेकिन भवन जर्जर हो जाने के कारण वह सिर्फ प्रिफर सेंटर बनकर रह गया है जिससे लोगों को स्वास्थ्य की सुविधा नहीं मिल पा रही है, जिससे उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, चूंकि मेरा क्षेत्र मजूदर और किसान बाहुल्य है, उनमें इतनी क्षमता नहीं है कि वे प्राईवेट हास्पिटलों में जाकर लाखों रूपये खर्च करके अपनी स्वास्थ्य का ईलाज करा सकें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगी कि पामगढ़ में जो सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र है वह बहुत जर्जर है, इसकी मांग माननीय मुख्यमंत्री जी से करती हूं। जांजगीर जिला के मुख्यालय से पामगढ़ होते हुए जो बलौदाबाजार डोटोपार मार्ग बना है, उसमें बीच में डोंगोकोरोदोर ससहा रोड है, वह रोड निर्माण जो हुआ है, वह अधूरा है चूंकि वहां पर किसानों की जमीन प्रभावित है, उनको मुआवजा नहीं मिला है जिसके कारण रोड अधूरा है जिससे आवागमन में काफी दिक्कतें होती हैं, वहां पर लोगों का एक्सीडेंट अनेक प्रकार की हादसाएं होती रहती हैं। किसानों को जल्द ही मुआवजा वितरण कराकर उस मार्ग को बनाने की मैं मांग करती है। मैं पामगढ़ क्षेत्र में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिये और बेरोजगार भाईयों को रोजगार दिलाने के लिये माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करती हूं कि वे अपना ठोस कदम उठाये। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, धन्यवाद।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा (धरसींवा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बजट पेश किया है वह अभूतपूर्व और ऐतिहासिक है। कोरोनाकाल के इस विषम परिस्थिति में भी जहां पूरी दुनिया विषम परिस्थिति से जूझ रही हैं, वहां इस स्तर का बजट प्रस्तुत करना ऐतिहासिक है। जहां गरीब किसान, गरीब मजदूर, महिला, सुरक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सभी के हित को ध्यान में रखकर जनहितैशी बजट पेश किया गया है। यह बजट हमारी सरकार का स्लोगन "गढ़बो नवा छत्तीसगढ़" को साकार करते हुए दिख रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट में शामिल सभी योजनाएं छत्तीसगढ़वासियों को उन्नति एवं प्रगति की ओर अग्रसर करती हैं। मैं इस बजट का हृदय से स्वागत करती हूं। हमारी सरकार एक संवेदनशील सरकार है जो किसानों, महिलाओं, युवाओं, शिक्षा एवं स्वास्थ्य, मजदूरों के लिये, सभी वर्ग को ध्यान में रखकर यह बजट बनाया गया है जो कि सही मायनों में यही लाभकारी हितकारी बजट है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरकार के तीसरे बजट में फिर से एक बार गांवों और किसानों पर ध्यान दिया है। हमारी सरकार किसान, गरीब मजदूर सरकार है। हमारी सरकार किसानों के लिये चिंतित रही हैं, किसान हितैशी बजट पेश कर माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह संकेत दिया है कि किसानों के लिये वह कितने सजग और संवेदनशील है। आज पूरे देश में जो अन्नदाताओं के हालात हैं, वह किसी से छिपी नहीं है। आज पूरे देश में किसान बदहाल और बेबश हालत में गुजर रहा हैं, वहीं हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश के अन्नदाताओं का स्तर सुधारने के लिये 2500 रूपये धान का समर्थन मूल्य देकर उनकी मेहनत को जो सम्मान दिया है, वह एक किसान का पुत्र ही कर सकता है, न कोई व्यापारी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं एवं बेटियों की सुरक्षा के लिये संवेदनशील है। वह इस बजट में दिख रहा है, कन्या छात्रावास आश्रम में हो रही छात्राओं के लिये 2200 महिला होमगार्ड भर्ती करने जा रही है, जिससे महिला सुरक्षा के साथ-साथ प्रदेश की बेटियों को रोजगार भी मिलेगा। हमारी सरकार ने बजट में दूसरी बेटी के जन्म पर माता को 5 हजार रूपये आर्थिक सहायता देने का प्रावधान रखा है, यह बहुत ही सराहनीय है। सही मायने में बेटियों का सम्मान हो रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे देश में छत्तीसगढ़ ऐसा प्रदेश बन गया है, जहां मछली पालन को खेती का दर्जा दिया गया है। यह बहुत ही सराहनीय है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को ऐसा लाभकारी एवं हितकारी बजट पेश करने के लिए हृदय से धन्यवाद देती हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू (धमतरी) :- माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं शासन द्वारा प्रस्तुत बजट के विरोध में बोलने के लिए खड़ी हुई हूं। विरोध इसलिए है क्योंकि बजट में केवल और केवल शब्द है और धरातल पूरा खाली है। सरकार कहती है कि हमने यह किया, ऐसा किया, वैसा किया। सरकार ने एक बहुत बड़ा काम कर्ज लेने का किया है। यह सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि सरकार ने कर्ज लेने का काम किया है। मैं इस विषय में सरकार को यह कहना चाहती हूं कि

"असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो,
क्या कमी रह गई है, देखो, सुधार करो।
जब तक सफल न हो, नींद-चैन का त्याग करो,
संघर्षों का मैदान है, छोड़ मत भागों तुम,
कुछ किये बिना किसी की जय-जयकार नहीं होती
और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।"

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए आप यह प्रयास कीजिये कि अगला बजट लोगों के हित में हो।

डॉ.(श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- हमारी सरकार ने कर्ज लिया है या आपकी सरकार ने कर्ज लिया था ?

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मैं नहीं कह रही है, यह बजट कह रहा है कि आपने इस बात को स्वीकार किया कि प्रदेश में जी.एस.डी.पी. दर में लगातार कमी आई है, इसमें 1.77 प्रतिशत की कमी आई है। जी.एस. डी.पी. दर में कमी आना, यह सरकार के लिए श्रेय का विषय नहीं है, इसमें सरकार को खुश नहीं होना चाहिए बल्कि इसमें सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए कि प्रदेश के जी.एस.डी.पी. दर में क्यों कमी आई है ? कमी इसलिए आई है क्योंकि आपने एक भी उद्योगों की स्थापना नहीं करवाई है। यदि उद्योगों की स्थापना होती तो सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जी.डी.पी. दर में कमी नहीं आती। यदि जी.एस.डी.पी. दर में कमी आई है तो लोगों के प्रति व्यक्ति आय में कमी आई है। आपने खुद स्वीकार किया है कि 0.14 प्रतिशत प्रति व्यक्ति आय में कमी आई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सरकार केवल शब्दों के मायाजाल से चलती है। केवल किताबों तक और केवल यहीं तक सीमित रह गई है। अभी सरकार के लिए सोचने का विषय है। सरकार कहती है कि हम लोगों के आय में वृद्धि कर रहे हैं। यदि आप उद्योगों की स्थापना करते तो लोगों का प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ता और लोग स्वतन्त्र होकर बाजार में खर्च करते। आपने यहां पर स्वयं स्वीकार किया है कि 5.28 प्रतिशत उद्योगों के निर्माण में कमी आई है। साथ ही साथ इसमें विशेष यह है कि एस.टी. और एस.सी. वर्ग के लिए कोई भी नई योजना इस बजट में नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, यदि सरकार से कुछ कहा जाता है, यदि हम जनप्रतिनिधि कुछ कहते हैं, जनता कुछ कहती है तो सरकार केवल और केवल एक राग अलापती है कि कोरोना वैश्विक महामारी चली जिसके कारण प्रदेश की आर्थिक स्थिति खराब हुई। जब आपकी आर्थिक स्थिति खराब थी, आप आर्थिक बदहाली से गुजर रहे थे तो आपको 11 तहसीलों को बनाने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि इसमें भी खर्च करना है, इसमें भी पैसे देने हैं। इसलिए आपको प्रदेश की चिंता पहले करनी थी। आपको यहां के हर वर्ग की चिंता करनी थी। आपका बजट, कहीं भी समावेशी बजट नहीं है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार ने कहा कि हम युवाओं को बेरोजगारों भत्ता देंगे। उन्होंने इस बात को बहुत स्पष्ट किया इसीलिए आज ये सत्ता में आये। लेकिन आप बजट को उठाकर देख लीजिये कहीं पर भी बेरोजगार युवाओं के लिए बजट में अलग से प्रावधान नहीं है। इन्होंने हमारी मातृशक्ति, जिसे छत्तीसगढ़ महतारी अर्थात् मां शब्द पहले, यानि यहां पर महिलाओं की महत्ता बढ़ती है। लेकिन आपने इन्हीं महिलाओं के साथ छल किया है। आपने महिलाओं से कहा है कि महिला समूहों का कर्ज माफ करेंगे। लेकिन आप बजट को उठाकर देख लीजिये किसी भी महिला समूह के लिए कर्ज माफी हेतु अलग से कहीं पर भी प्रावधान नहीं है। यदि आपने महिलाओं से वादा किया है, युवाओं से वादा किया है तो आपको उस वादे को पूरा करना चाहिए। क्योंकि आप बार-बार कर्ज ले रहे हैं। यदि आप महिलाओं और युवाओं को ध्यान में रखते तो आप थोड़ा सा कर्ज और ले सकते थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब माननीय मुख्यमंत्री जी का भाषण चल रहा था..।

श्री रामकुमार यादव :- बहिनी..।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- भाई साहब, आप चुप रहिये। आपको मौका मिलेगा तो आप बोल लीजियेगा।

श्री रामकुमार यादव :- मोदी जी हा दो करोड़ लागन ला देहू कहे रहिस हे। उहू ला सुरता कर ना।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जब यहां माननीय मुख्यमंत्री जी सरकार का बजट प्रस्तुत कर रहे थे, तब हम सब उसे बहुत ध्यान से सुन रहे थे, उन्होंने जिस शब्द का बहुत बेबाकी से प्रयोग किया कि छत्तीसगढ़ का हम हाईट पर ले जा रहे हैं। बहुत अच्छा शब्द है ये पुस्तकों में, सुनने में हमें बहुत अच्छा लगता है लेकिन जिस शब्द का इन्होंने प्रयोग किया H- Holistic development जिसे कि हम समग्र विकास कहते हैं इसमें किसान, श्रमिक, वनवासी, माताओं और बुजुर्गों का विकास ये इनकी अवधारणा है। प्रदेश के विकास में बुजुर्गों का विकास ये इनकी अवधारणा है। यदि इसमें हम युवा जो कि हमारी आने वाली पीढ़ी है यदि एक शब्द युवा जोड़कर यदि युवाओं के स्किल का भरपूर उपयोग ये सरकार करती तो यह प्रदेश कहां से कहां होता लेकिन आपने हमारे प्रमुख वर्ग युवा जिसे कि हमें छोड़कर नहीं चलना चाहिए जिसे कि हमें लेकर चलना चाहिए ऐसे युवा जो कि हमारे प्रदेश के भविष्य का निर्धारण करते हैं ऐसे युवाओं को आपने छोड़ दिया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, E- Education। गुणवत्तापूर्वक शिक्षा और शिक्षा के लिए हर वर्ग की जाति एवं समुदाय को अवसर देना। अभी पिछले दो सालों में शिक्षा की दुर्गति हुई है। सरकार ने शिक्षा की ओर कहीं पर भी ध्यान नहीं दिया। यदि हम बच्चों को शिक्षा देते हैं तो संस्कार रूपी शिक्षा देना हमारा प्रथम फर्ज है। लेकिन कहीं भी सरकार ने इस बात का ऐलान नहीं किया कि इसमें कुछ ऐसे नये विषयों को जोड़ दिया जाए जिससे हम हमारे बच्चों को शिक्षा के साथ-साथ संस्कार भी हमारी इस पीढ़ी को दे सकें। छत्तीसगढ़ की संस्कृति और उसकी परंपरा के विषय में हमारी नई पीढ़ी के बच्चों को हम

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

बता सकें। जब भी बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं तो बहुत ही सुंदर और साफ सुथरे वातावरण में बच्चों को शिक्षा ग्रहण करानी चाहिए लेकिन यहां पर ऐसी स्थिति बनी है कि प्रदेश में अनेक ऐसे स्कूल हैं जो डिसमेंटल होने की स्थिति में हैं लेकिन सरकार का ईफ्रास्ट्रक्चर की ओर जरा भी ध्यान नहीं है। जहां पर पर I शब्द का उपयोग infrastructure अर्थात अधोसंरचना के लिए किया जाता है, सरकार कहती है कि हमने सड़कों का निर्माण, जनसुविधा का विस्तार करना ये उन्होंने अपनी प्राथमिकता में रखा है लेकिन अभी दो से ढ़ाई सालों में सरकार ने अपने नये निर्माण कार्यों की एक ईंट किसी भी विधानसभा में नहीं रखी है। जहां पर G शब्द का प्रयोग होता है governance अर्थात प्रशासन। प्रशासन को संवेदनशील, सशक्त और जवाबदेह बनाना। मुझे दुख के साथ यहां पर कहना पड़ रहा है कि यहां पर मुख्यमंत्री जी हाईट शब्द का प्रयोग किए और जहां पर वह कहते हैं कि वह प्रशासन को जवाबदार बनाना चाहते हैं, मुझे यह बताते हुए बहुत दुख होता है कि एक दिन समाचार पत्र में भी आया था और हम सब विधायकों को यह पीड़ा भी है कि हम प्रशासन को जितने भी पत्र लिखते हैं एक भी पत्र का जवाब हम विधायकों को नहीं मिलता। यह मैं पूरे दावे के साथ, प्रमुखता से इस बात को इस सदन में बोल रही हूं।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- रंजना, मोला जतका पत्र लिखे हो तेखर जवाब दे हों। मोर पत्र के जवाब मिले हे कि नहीं?

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- यदि धोखे से भी यदि किसी एक पत्र का जवाब मिल जाता है तो एक भी कार्यवाही नहीं होती है। और शासन का प्रशासन में कितना लगाम है यह शासन जानता है। यदि सरकार H अर्थात Health की बात करती है जहां पर स्वास्थ्य केंद्रों का उन्नयन, आधुनिक सुविधाओं के विकास की बात है। जहां पर सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करती है मैं पूरे देश में बहुत दूर नहीं जाना चाहती। मेरे ही विधानसभा क्षेत्र में वर्षों से जिला अस्पताल है जहां पर 100 बिस्तर अस्पताल है और वहां पर आसपास के जिले के मरीज भी आते हैं और वहां पर 200 बिस्तर से भी अधिक काम होता है और यह अनेक सुविधाओं से लैस यह सरकारी अस्पताल है। यदि सरकार बड़ी बड़ी बात करती है तो मेरा आग्रह है कि धरातल पर काम हो रहा है या नहीं हो रहा है यह सरकार को देखने की आवश्यकता है। जहां पर T अर्थात Transformation की बात अर्थात बदलाव की बात सरकार करती है, जहां पर संस्कृति को पहचान देना, तीजा, गौरी-गौरा और ऐसे गोवर्धन पूजा जैसी बात यदि सरकार करती है। हम सब व्यक्ति चाहते हैं कि हमारी संस्कृति और हमारी परंपरा आगे बढ़े।

श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े :- आप तीजा मानती हो कि नहीं मानती हो।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- यदि आप प्रति व्यक्ति आय को बढ़ायेंगे, जब तक प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ेगी, सरकार कुछ नहीं कर सकती। आपको यदि अपने त्यौहार मनाने हैं तो जब तक व्यक्ति के हाथ में पैसा नहीं रहेगा, आप कोई भी त्यौहार चाहकर भी नहीं मना सकते। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि आप केवल बजट पेश करने तक सीमित न रहें और आपने जो बजट पेश किया है वह

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

धरातल पर कितना उतर रहा है, इस बात की जानकारी की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए धन्यवाद।

<u>सदन को सूचना</u>

अध्यक्ष महोदय :- एक घण्टे की समय वृद्धि की आवश्यकता है। मैं समझता हूँ कि सदन सहमत है? माननीय प्रमोद कुमार शर्मा।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई)

श्री प्रमोद कुमार शर्मा (बलौदाबाजार) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद्। मैं वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट भाषण में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, उन्हें धन्यवाद् देता हूँ कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में सुहेला ग्राम को एक पूर्ण तहसील का दर्जा दिये, इसके लिए मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से यह दो साल की सरकार छत्तीसगढ़िया की सरकार है। यहां छत्तीसगढ़ के लोगों का स्वाभिमान जागा है, उनको एहसास हुआ है कि यह सरकार छत्तीसगढ़ियों की सरकार है। पहले छत्तीसगढ़ी बोली को बोलने में लज्जा होती थी, वह आज छत्तीसगढ़ के लोग गर्व महसूस कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के लोगों में यह भावना आयी है, इनका स्वाभिमान जागा है कि यह छत्तीसगढ़ी की सरकार, हमारी सरकार है और हमारे छत्तीसगढ़ के तीज त्यौहार और जो परम्परा, संस्कृति का छत्तीसगढ़ नहीं पूरे हिन्दुस्तान में मान-सम्मान बढ़ा है। निश्चित रूप से माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार किसानों के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। इसके साथ में मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आप किसानों के लिए बहुत अच्छा धान खरीदी के लिए नया केन्द्र खोले हैं। आप ऐसा प्रयास कर रहे हैं तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा काम है, लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी और शासन को अपने क्षेत्र की एक समस्या से अवगत कराना चाहूंगा कि अभी पिछले महीने बरसात के समय 29 तारीख को पानी गिरने के कारण कुछ किसानों को टोकन मिलने के बाद भी उनका धान नहीं खरीदा जा रहा है। वहां कलेक्टर साहब आगे तक के फाईल बढ़ा दिये हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय खाद्य मंत्री जी बैठे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि उन 100-200 किसानों की कोई गलती नहीं है। अगर ऊपर वाले की मेहरबानी से पानी गिर जाए तो उन किसानों की क्या गलती है? आप बड़ा दिल करते हुए, उन किसानों का धान खरीदने के लिए पहल करें। मैं आप सबसे सादर निवेदन करता हूँ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से माननीय भूपेश बघेल जी की सोच अच्छी है।यह पूरे छत्तीसगढ़ में नहीं, पूरे हिन्दुस्तान में इसकी सराहना हो रही है। गौधन न्याय योजना निश्चित रूप से

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

छत्तीसगढ़ में ही नहीं, पूरे हिन्दुस्तान के लिए एक मिसाल होना चाहिए। एक ऐसी सोच जो छत्तीसगढ़ के लोगों को सीधे सरकार से जोड़ सके और गोबर खरीदी की जो सोच, बहुत अच्छी सोच की शुरूआत की है तो इसके लिए पूरे हृदय से इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि इस सरकार में ऐसी सोच है मतलब यह सीधे छत्तसगढ़ियों की सरकार है। इसके लिए मैं अपने समस्त क्षेत्रवासियों की तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद् दूंगा कि कभी छत्तीसगढ़ के लोग यह कल्पना भी नहीं किये थे कि कभी छत्तीसगढ़ में गोबर खरीदी का काम चालू होगा। आज इस उदाहरण को लेकर, अगर पूरे हिन्दुस्तान में इसको लागू करें तो जो लोग गौ सुरक्षा की बातें करते हैं तो उनके प्रति भी गौमाता के लिए असली सेवा, असली श्रद्धा यही होगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे बलौदा बाजार विधान सभा क्षेत्र में करीब 18 हजार श्रमिक कार्यरत हैं। माननीय श्रम मंत्री जी भी बैठे हुए हैं मैं आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि इस बजट में उन श्रमिकों के लिए किसी भी प्रकार का प्रावधान नहीं रखा गया है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि बलौदा बाजार जिले में एक ईआईसी हॉस्पिटल, श्रमिकों के हॉस्पिटल के लिए खोला जाए ताकि 18 हजार श्रमिक जो काम करते हैं उनकी सुविधा के लिए एक केन्द्र हो सके।

माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे ही मेरे विधान सभा क्षेत्र में 2-3 सड़कों की स्थिति बहुत ही खराब है। मैं यह कहना चाहूंगा कि अगर बलौदा बाजार विधान सभा क्षेत्र में 6-6 बड़े-बड़े सीमेंट प्लांट हैं तो सबसे ज्यादा राजस्व का स्त्रोत वहां से प्राप्त होता है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि थोड़ी सी दया दृष्टि जिस हिसाब से क्षेत्र है तो उस क्षेत्र में आप लोगों की दयादृष्टि बनी रहे।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये। धन्यवाद्।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आखिरी में स्वास्थ्य विभाग के संबंध में कहना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- विभागवार चर्चा में अपनी बात कह दीजिएगा।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

अध्यक्ष महोदय :- श्री शैलेश पाण्डे जी, आप 10 मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री शैलेश पाण्डे (बिलासपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूँ।

श्री अजय चन्द्राकर :- यदि आपका कागज गुम गया हो तो आप मोहन मरकाम जी से ले लीजिए।

श्री शैलेश पाण्डे :- मैं पहले से कागज ले लिया हूँ।

श्री अजय चन्द्राकर :- यदि कागज गुम गया होगा तो आप इनसे ले लीजिए। अभी वह चलती फिरती लायब्रेरी हैं, वह पुराने गुरूजी हैं।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री मोहन मरकाम :- चन्द्राकर जी, हमारी सरकार की नीतियों का फायदा देखिये, शर्मा जी, पुजारी जी भी तारीफ कर रहे हैं। प्रश्न भी नहीं पूछ रहे हैं। आप सोच सकते हैं कितना असर पड़ रहा है।

श्री अजय चन्द्राकर :- गुरूदेव, आप अपनी सरकार की कहां बात कर रहे थे, आप तो दिल्ली, उत्तर प्रदेश, अरूणांचल प्रदेश की तरफ थे। आप नार्थ-ईस्ट गये थे।

अध्यक्ष महोदय :- आपको मेल की संज्ञा दी है, सीटी बजाईये और शुरू हो जाईये।

श्री शैलेश पांडे (बिलासपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बिलासपुर में एक कार्यकर्ता है, उसने माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए एक कविता भेजी है, मैं चाहता हूं कि उसको आपके समक्ष सुना दूं।

अध्यक्ष महोदय :- वह कविता आपकी है या किसी कार्यकर्ता की है?

श्री शैलेश पांडे :- कार्यकर्ता की है।

अध्यक्ष महोदय :- कोई कवयित्री की है या कवि की है? (हंसी)

श्री शैलेश पांडे :- माननीय अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं, पहले आप बताईये।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके सवाल का जवाब नहीं दिया है।

अध्यक्ष महोदय :- जवाब आयेगा। उसके बगैर आप पढ़ नहीं सकते। आप यहां बताईये।

श्री शैलेश पांडे :- यह कविता विनय नाम के एक लड़के की है।

अध्यक्ष महोदय :- अच्छा।

श्री शैलेश पांडे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कविता इस प्रकार है :-

उन गढ्ढों को भरना बाकी है,
उन अंधेरों को हरना बाकी है,
भरेंगे वह सब गढढे,
उन्हीं पर राह बनायेंगे,
भरेंगे वह सब अंधेरें,
वहीं पर दीपक जलायेंगे।
माननीय मुख्यमंत्री जी,
साथ है आपका, भरोसा है, आपका
प्यार है आपका, आशीष है आपका
लेकिन छत्तीसगढ़ महतारी का आशीर्वाद
थामकर एक दूसरे का साथ, चलेंगे साथ।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- भूपेश है तो भरोसा है।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- ओतिस समझ में आईस कि नई आईस।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री सौरभ सिंह :- पांडे जी आप मुख्यमंत्री जी की खुलकर तारीफ करिये, राजा साहब नहीं हैं।

श्री शैलेश पांडे :- उसने आपके लिए भी कुछ भेजा है। आपको भी सुना देता हूं।

भगवान का सौदा करते हैं, वह इंसान की कीमत क्या जानें,

जो धान की कीमत दे न सके, वह जान की कीमत क्या जानें। (मेजों की थपथपाहट)

माननीय अध्यक्ष महोदय,

प्रजासुखे सुखं राज्ञ: प्रजानां तु हिते हितम्

नात्मप्रियं हितं राज्ञ: प्रजानां तु प्रियं हितम्

माननीय अध्यक्ष महोदय, अर्थात प्रजातंत्र में जो मुखिया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- पंडित जी, जब लिखकर लाये हो तो यह बता दो कि कौन बोला था, कहां बोला था ?

श्री शैलेश पांडे :- इसको हम बोले हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- चलिये, जो बोले हैं, कहां बोले हैं, आपको बताना चाहिए।

श्री अमरजीत भगत :- कम किम करोति।

श्री अजय चन्द्राकर :- सच-सच बताओ, उसको कौन बोला था और कहां बोला था ?

श्री शैलेश पांडे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रजातंत्र में प्रजा के सुख में ही मुखिया का सुख निहित है। जब प्रजा सुखी अनुभव करे, तभी मुखिया को संतोष करना चाहिए। जिस प्रदेश की जनता गरीब हो, पिछ़ड़ी हो, जिसमें अधिकतम व्यवसाय खेती हो, वनवासी हों, जिस प्रदेश में, बच्चों की पढ़ाई, दो वक्त घर चलाना, पेट की भूख, कुपोषण, एनीमिया, आवागमन चुनौती हो, उस प्रदेश की ऐसी योजनायें हों जिससे जनता को सीधा लाभ पहुंचाया जा सके। जिससे उनका जीवन स्तर बेहतर हो सके और उनके घर में सुख शांति हो। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब प्रदेश की कमान संभाली तब उन्होंने लाखों किसानों का कर्ज दो घंटे में अदा कर दिया। यह हमारी सरकार का वादा था, यह हमारी सरकार की सोच थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, मैं उसके समर्थन में यह कहना चाहता हूं कि उन्होंने अपने दृष्टिकोण में किसान, ग्रामीण व्यक्ति को ध्यान में रखा है। जो अंतिम व्यक्ति है, जो इस छत्तीसगढ़ की पहचान है, उस व्यक्ति का ध्यान रखा है। उन्होंने समग्र विकास की बात की है। मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने जो कल 97 हजार करोड़ रुपये के आसपास का बजट पेश किया है, उसमें 83 हजार करोड़ रुपये का राजस्व है और 13 हजार 800 करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय है। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि हमारे विपक्ष के साथियों ने बहुत सारी बातें कहीं हैं कि राजस्व व्यय बहुत ज्यादा है, पूंजीगत व्यय बहुत कम है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले एक साल बाजार खुला कहां रहा ? पिछले एक साल में कोरोना के काल में कहां पर धंधा हुआ ? कौन नौकरी करने गया ? कहां पर व्यक्ति

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

दो वक्त की रोटी कमा पाया ? नहीं कमा पाया तो कहां से राजस्व आयेगा, क्या आसमान से राजस्व टपकेगा ? ऐसी कोई योजना नहीं होती है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले एक साल में सबसे बड़ी चुनौती थी कि आदमी के पास खाने के लिये पैसा नहीं था, उसके पास रोजगार नहीं था । हजारों लोगों के रोजगार छीन रहे थे और उनको दो वक्त की रोटी देनी थी ऐसे में हमारी सरकार ने काम किया, ऐसे में हमारी सरकार ने संतुलन बनाया, ऐसे में लोगों के लिये सबसे बड़ी चीज थी कि उनका जीवन बच सके । आज इस कोरोना काल में लगभग 2 से 3 हजार लोग हमारे बीच में नहीं हैं, भगवान न करे लेकिन कहीं एकाध लाख लोग उस कोरोना की चपेट में आ जाते और वे काल के गाल में समा जाते तब हम क्या करते ? हम नाली बना सकते हैं, हम पुलिया बना सकते हैं, हम सड़क बना सकते हैं लेकिन हम आदमी को जिंदा नहीं कर सकते हैं । हमारी सरकार की यह प्राथमिकता थी कि सबसे पहले उनकी जान की रक्षा करो, सबसे पहले पूरे छत्तीगसढ़ में सबकी रक्षा करो । लगभग 2 करोड़ 80 लाख के आसपास की आबादी है, लगभग पौने 3 करोड़ लोगों की रक्षा करना हमारा सबसे पहला कर्तव्य था । हमारे विपक्ष के साथी यह बोलते हैं कि आपका बजट जो है वह अच्छा नहीं है, गंदहीन है, स्वादहीन है, पता नहीं क्या-क्या बोला जाता है । हमारे इस प्रदेश के लिये ऐसा बोला गया । मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप आज से 7 साल पहले की बात याद करिए कि पूरे देश में गुजरात मॉडल की चर्चा हो रही थी, गुजरात मॉडल ऐसा है, गुजरात मॉडल वैसा है, गुजरात मॉडल की बात कर रहे थे । मैं विपक्ष के साथियों से पूछना चाहता हूं कि क्या 7 सालों में किसी ने गुजरात मॉडल का नाम लिया ? माननीय नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने उसके बाद से लेकर आज 7 साल हो रहे हैं, क्या किसी ने गुजरात मॉडल की बात की ? नहीं की, क्यों नहीं की क्योंकि वह कुर्सी में पहुंचने का केवल एक रास्ता था । माननीय डॉ. रमन सिंह उसका पूरा-पूरा अनुसरण कर रहे थे ।

श्री शिवरतन शर्मा :- क्या है श्री पाण्डे जी, आप गुजरात मॉडल को छोड़कर स्तुतिगान करो, आज राजा साहब नहीं हैं । आप बिल्कुल फ्रीहैण्ड पूरा जितना सतुतिगान कर सकते हो, कर लो । शायद आपका सी.आर. सुधर जाए । जहां पर हैं वहां से थोड़ा ऊपर आ जाएं ।

अध्यक्ष महोदय :- पाण्डे जी, आपका समय निर्धारित है । आप निर्धारित समय में समाप्त करने की कोशिश कीजिए । इनके बहकावे में मत आईए ।

श्री शैलेष पाण्डे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जल्दी समाप्त करने की कोशिश करूंगा, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं । डॉ. रमन सिंह जी के लिये, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिये महल बनाओ, पुलिया बनाओ, सड़क बनाओ, अधोसंरचना बनाओ यह सब बनाओ, यह सब उनकी प्राथमिकता है । आदमी को बनाओ इनकी प्राथमिकता में है ही नहीं । क्या ह्यूमन डवलपमेंट केपेसिटी बिल्डिंग काम नहीं है ? अगर हमारी सरकार हर व्यक्ति को सक्षम बना रही है, अगर हमारी सरकार किसान की जेब में

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

पैसा डाल रही है, अगर हमारी सरकार उनका ऋण माफ कर रही है, हमारी सरकार कुपोषित लोगों को पोषित कर रही है, अगर हमारी सरकार बहुत सारे सिंचाई के ऋण माफ कर रही है, हमारी सरकार बहुत सारे काम ग्रामीण व्यक्ति के लिये, गौपालकों के लिये, किसानों और मजदूरों के लिये कर रही है तो क्या यह केपेसिटी बिल्डिंग नहीं है ? आपको केवल इंफ्रास्ट्रक्चर से मतलब है । इंफ्रास्ट्रक्चर हर सरकार की अपनी प्राथमिकता होती है । जब इनका समय था तब इनके समय इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर आगे बढ़ाया । हमारी सरकार के समय जब किसान मर रहे थे यहां पर 27 हजार बेटियां गायब थीं, यहां पर महिलाएं सुरक्षित नहीं थीं, कुपोषित थीं, एनीमिया से मर रही थीं और हमारे प्रदेश में स्थिति खराब थी तब हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश की बागडोर संभाली । मैं आपको बताना चाहता हूं कि केंद्र सरकार ने अपने बजट में 23 परसेंट की कटौती की और केंद्र सरकार के वित्त मंत्री ने संसद में इस बात को एलानिया बोला कि हम देश के संस्थानों को जरूरत पड़ेगी तो बेचेंगे यह आज तक के इतिहास में किसी ने नहीं कहा। मात्र 1 लाख 7 हजार करोड़ रूपये का राजस्व उन संस्थानों को बेचने से मिलेगा उसकी पूर्ति के लिये सारा केंद्र सरकार इन सबको बेचने में लगा हुआ है । आप ही बताईए कि एक-तरफ तो आप यह बोलते हैं कि पूंजीगत व्यय नहीं कर रहे हैं, आप बोलते हैं जीडीपी कम हो रहा है, इनका दिमाग केवल उसी भ्रष्टाचार में घुसा रहता है कि पूंजी लगायेंगे, सड़क-नाली बनायेंगे, इससे भ्रष्टाचार होगा । इनको आदमी से, छत्तीसगढ़ के लोगों से, छत्तीसगढ़ की जनता से कोई मोह नहीं है । अगर हमारी सरकार काम कर रही है, किसानों पर ध्यान दे रही है, अगर मजदूरों पर और ग्रामीण आदमियों पर ध्यान दे रही है तो इसमें कोई गलत काम नहीं कर रही है। आपकी प्राथमिकता हो सकती थी कि आप पूंजीगत व्यय करते, हमारी प्राथमिकता है । हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी पूंजीगत व्यय के लिए 13 हजार करोड़ का प्रावधान रखा है । अध्यक्ष महोदय, ये लोग यहां पर अलग बात करते हैं और केन्द्र सरकार के पास जाकर अलग बात करते हैं । इनका चेहरा अलग है और इनकी चाल अलग है । मैं आपको आंकड़े बताना चाहता हूं केन्द्रीय करों में जो राज्य का हिस्सा है उसमें 2014-15 में 1 हजार 81 करोड़ का अंतर है । आना चाहिए था 9 हजार 500 करोड़, मिला कितना 8 हजार 300 करोड़। मैं आपको बताना चाहता हूं 2017-18 में 113 करोड़ कम आया । 2018-19 में 816 करोड़ कम आया, जब इनकी सरकार थी । जब हमारी सरकार आई तब पहले 5808 करोड़ का टैक्स इन्होंने नहीं दिया । दूसरी बार 8400 करोड़ का टैक्स नहीं दिया । अध्यक्ष महोदय, ये 15 हजार करोड़ रूपए हमारा अधिकार था । माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम भीख नहीं मांग रहे हैं, यह हमारा अधिकार था । यहां की जनता के खून पसीने की कमाई थी, जिसको आपने नहीं दिया । अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के विकास के लिए, अधोसंरचना के विकास के लिए 15 हजार करोड़ बहुत होते हैं । यह पैसा नहीं आया उसके बावजूद भी 13 हजार 800 करोड़ का हमने पूंजीगत व्यय रखा। इनकी सरकार की प्राथमिकता पूरे समय पूंजी है, पूंजी लगाओ, पूंजी लगाओ । गड्ढे खोदो, पूंजी लगाओ फिर गड्ढे खोदो फिर पाताललोक में पहुंचा दो ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

ये सब इनकी सरकार की प्राथमिकता है, हमारी सरकार की नहीं है । इनकी सरकार के समय इनमें घमंड था, ये लाठी से मारते थे, डंडे से मारते थे, जेल में डालते थे, जनता से तो बात ही नहीं करते थे । आदरणीय सुनिये आप, बशीर बद्र जी की शायरी है आपके लिए - घरों में नाम थे, नाम के साथ ओहदे थे । बहुत तलाश किया पर कोई आदमी न दिखा । यह सच्चाई कि आज प्रदेश में जो स्थिति आपकी है, आपकी पार्टी की है वह इसीलिए है क्योंकि आपने 15 साल तक छत्तीसगढ़ में जो काम किया है । वह छत्तीसगढ़ की जनता को पसंद नहीं आया है । माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बजट लाया है, उसके लिए मैं सबसे पहले उन्हें बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने सबसे पहले 67 लाख परिवारों के लिए खाद्यान्न की व्यवस्था की । अध्यक्ष महोदय, ये लोग एक व्यक्ति को 7 किलो चावल देते थे । ये देखिए ये इनका 2014-15 का बजट है । मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब इनकी सरकार थी जब इनका तीसरा राउंड आया तो इनकी प्राथमिकता समृद्ध किसान, भूख और कुपोषण से मुक्ति मिले, छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति अच्छी हो, सशक्त नारी हो, क्या इनमें से एक भी काम हुआ । एक भी काम नहीं हुआ । ये सारे काम ऐसे के ऐसे 15 साल पड़े रहे । जब हमारी सरकार आई तो ये सारी चुनौतियां हमारे सामने आई और इन चुनौतियों का ही हमने सामना किया और उसको लेकर हमने अपना बजट बनाया ।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद् ।

श्री शैलेश पाण्डे :- बहुत सारा बाकी है अभी तो ।

अध्यक्ष महोदय :- बहुत अच्छा भाषण दिया आपने ।

श्री शैलेश पाण्डे :- ठीक है ।

श्री रामकुमार यादव (चन्द्रपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं माननीय मख्यमंत्री जी के 2021-22 के बजट पेश करे हे ओखर समर्थन मा खड़े हौं । मैं छत्तीसगढ़ के धन्यवाद दिहौ 2 करोड़ 80 लाख जनता ला, जेन अइसन मुख्यमंत्री बनाइस । मैं बजट मा समर्थन दे बर खड़े हौं । जइसे ए बजट पेश करिस तो मैं दिया बाती लेकर खोजत रेहेव बजट ला के एमा का का हावय । मैं देखत रेहेव कि मोर छत्तीसगढ़ के वो गरीब आदमी जेमन रोज कमाथे, रोज खाथे तेकर लिए का व्यवस्था करे गे हे । मैं बजट में ये खोजत रहेव कि अइसे गरीब आदमी जेमन रोज किसानी करथे अउ धरती के सीना चीरकर उपजाथे ओखर बर का व्यवस्था बनाए गे हे । वो बस्तर सरगुजा मा रहने वाला, गरीब आदिवासी समाज जेमन जंगल मा जाकर लकड़ी ला तोड़के, तेंदूपत्ता ला तोड़के जीवन यादप करथे वो गरीब के लिए का व्यवस्था बनाए गे हे । वो नवजवान साथी जब छत्तीसगढ़ अलग होइस तो ओमन सोचे रिहिस के भोजपुरी फिलिम होथे, बम्बई मा फिलिम बनथे । अपन प्रदेश छत्तीसगढ़ मा भी फिलिम बनतिस ता हमुमन श्री देवी, मिथुन चक्रवर्ती जैसे हीरो बनतेन । अइसे करके सपना देखे रिहिस हे ओखर का व्यवस्था बनाए गे हे ।

श्री रामकुमार यादव :- अभी फिलिम बनथे। बहुत सुपरहिट बनथे। अमिताभ बच्चन तक ला फेल कर देथे ओहा । सुने होहू। अमिताभ बच्चन ले बड़े सुपर स्टार बनगेहे हमर भूपेश बघेल जी हा।

श्री नारायण चंदेल :- यादव जी तो खुद ही चलता फिरता फिलिम हे। (हंसी)

श्री रामकुमार यादव :- बड़का दाउ, थोड़ कन बइठ न थोड़ा।

श्री शिवरतन शर्मा :- यादव जी, एक बार छत्तीसगढ़ विधानसभा सदस्य मन नाटक करत रहन। पंपाबुर के राजा, ओखर एक कलाकार हमर मिश्री भैय्या रहिसे हमर संसदीय कार्य मंत्री जी। अउ एक कलाकार धर्मजीत जी रहिसे और रिहर्सल के दौरान अइसे होइसे कि राजनीतिक दिशा ही बदल गे। ए फिलिम बनही तो राजनीतिक दिशा झन बदल जाये।

श्री रामकुमार यादव :- महाराज, सुन लेवव थोकन। सुने के भी क्षमता रखहिओ। छत्तीसगढ़ हा अलग होइस, तो ओमा बहुत सारा भावना छिपे रहिसे, जो पुरखा मन यहां पर अलग करिन, ओमन सोच के करिन कि हमरो बोली आगे बढ़तीस। काबर कि छत्तीसगढ़ के कहावत हे। हमर चंदेल भैय्या जी, कोस कोस में पानी बदले, अउ 15 कोस में बानी। एहा छत्तीसगढ़ के हे। एक कोस ले दूसर कोस में जाहौ तो पानी के स्वाद बदल जाथे। अउ 15 कोस ले ऊपर जाहौ तो खाल्हे राज उपर राज आ जाथे। आज ऐ बोली के 15 साल में इहां पर कोई सम्मान नहीं होइस, लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी ला धन्यवाद दिहव। हमन छत्तीसगढ़ के मन पड़दा होये हन तो हमर ददा मन सिखोए हे, बेटा एहा बासी हे, एहा भाजी हे, एहा गेड़ी हे, एहा भंवरा हे, ए हमला सिखोये रहिसे। आज 15 साल तक आप मन ओला तोप देहो। धन्यवाद, दिहौ मेहा मुख्यमंत्री जी ला, जेला छत्तीसगढ़ कहाथ होही, छत्तीसगढ़ के आज मोर भाषण ला मोला एला बोलथव ओला सुनही अउ कही कि सही बात में आज 15 साल में आज छत्तीसगढ़ ला मुख्यमंत्री मिलेहे, ओहा भूपेश बघेल जी के तौर पर मिले हे। अइसे आज पूरा प्रदेश कहात होही। (मेजों की थपथपाहट) मैं अउ कहना चाहथव। आज ए छत्तीसगढ़ में कई प्रकार के कहथे कोई आदमी। मेहा कोरोनाकाल में देखेहों। कोरोनाकाल में आज हमर छत्तीसगढ़ के आदमी मन कोनो जम्मू-काश्मीर, दिल्ली में जाकर के टंगाये रहिसे। महू ओ गरीब घर के लइका हो, जे जम्मू-काश्मीर में जाके बूता करे रहो। आज ओ गरीब आदमी मन ला, ओ महिला मन ला 7 हजार परिवार लगभग 60 लाख से ऊपर महिला मन ला आज गौठान में काम करेके अवसर प्राप्त होए हे। आज 9 करोड़ से ऊपर ज्यादा गोबर के दू रूपये किलो मिलेहे। मे ए कहना चाहथौ पूरा सदन के माध्यम से पूरा प्रदेश मन हा मोर बात ला सुनत होही, ओहा देखही कोई चैनल में चलही त। आज 9 करोड़ रूपया काकर जेब में गिसे। ओहा अंतिम छोर के गरीब व्यक्ति जेमन दू रूपया के घलू सारीडॉन गोली लेबर ओमर तरसथे, तिही मन के जेब में गिसे। आज आप मन एक छत्तीसगढ़ी में एक कहावत हे। भरे ला भरे जूछा ला ढरकाए हे। हम बिल्कुल कहथन कि राजधानी रायपुर के भी और इहां ले बड़े महल बना देवौ। रायपुर ला बनावौ। दुर्ग ला बनावौ, लेकिन अंतिम छोर के व्यक्ति ओखरो ये छत्तीसगढ़ निर्माण में खुशी के लिए हाथ होना चाहिए। आज ओ

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

छत्तीसगढ़ के व्यक्ति आज जाके देखौ ओखरो जेब में पइसा हे। कोन ओ गरीब आदमी। ओ महिला मोर दाई आज बड़े बड़े घर के उद्योगपति के घरवाली मन, ओखर बहनी मन, बेटी मन तो रोज बड़े-बड़े सेंट लगाथे। नाना प्रकार के साबुन चुपरथे, लेकिन मोर बेटी, मोर बहनी दाई मन जेमन अंतिम छोर में रहने वाला हे, काला कहिथे साबुन, रेक्सोना, काला डेटाल साबुन लाइफबॉय बोलथे, तेला कभू देखे नहीं रहिसे, लेकिन धन्यवाद देहौं मुख्यमंत्री जी ला जे आज गोबर योजना निकाल कर के गोधन योजना निकाले हे, आज ओमन के जेब में पइसा गेहे। तहूं मन आज बड़का बड़का तेल ला चुपर के ओमन अपन आप ला गौरवान्वित महसूस करथे। तेखर लिए मेहा धन्यवाद देना चाहथौं। (मेजों की थपथपाहट) और चन्द्राकर जी आप बहुत ज्ञानी हव। हमन देखथन। हम कम पढ़े लिखे हन। हम कम पढ़े लिख हन, लेकिन आप बहुत ज्ञानी व्यक्ति हो, आप ला मेहा नमस्कार करथौ अउ भगवान आप मन ला अउ बहुत बड़े सद्बुद्धि देवे, ज्ञान देवे, अउ आप बहुत बड़े बनौं। (हंसी) लेकिन में देखे हो एक ठोक कहावत हे जइसने घर ला ओहा तमतमा के निकलथे कि मेहा आज विरोध करिहौ मेहा विरोध करिहौ। आप तो सिर्फ विरोध हच करेला आथौ। सब पूरा प्रदेश के मन देखथे। आप ही मन कहथौ कर्जा माफी, कर्जा माफी करके, 15 साल ले तो भारी बड़े मंत्री रहव, मेहा जानथव। तुम्हर भारी चलय। ओ समय काबर नहीं कहौं कि छत्तीसगढ़ के कर्जा माफी करबो करके। 15 साल में 1 लाख, 2 लाख 01 करोड़ छोड़ो, 4 नग अगर माफ कर दे होहू ये 15 साल के तो छत्तीसगढ़ के पूरा जनता तुम्हर जय जयकार कर देतिसे। एक रूपया आज कर्जा माफी नहीं करे हव। आज किसान के कर्जा माफी होवथे त आपला तकलीफ होवथे । छत्तीसगढ़ के सरकार हे, भूपेश बघेल जी अउ मोर जांजगीर जिला के आन-बान-शान जेकर आशीर्वाद से रामकुमार बोलथे, मोर चरणदास महंत जी के सरकार हे । ज्यादा समय नहीं लंव, काबर कि मोर बबा ह भेरी-भेरी देखथे । अउ ओकरे संरक्षण में बोले हव । हमर जांजगीर वाला बड़का दाऊ चंदेल जी, तोला प्रणाम हे, तूहर भाचा ला समझावव, वह अब्बड़ टोका-टाकी करत रहिथे । अध्यक्ष महोदय, आप मन मोला बोले के मौका देव, एकर ले जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़ ।

श्री गुलाब कमरो (भरतपुर-सोनहट) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट के समर्थन में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं ।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- अध्यक्ष महोदय, हरेक झन ला जोहार देखथे, लेकिन कुछ तो आशीर्वाद देवव अउ उहू कोती जोहार देखथे, सब तरफ तो जोहार देखथे, लेकिन कोनो आशीर्वाद देवत नहीं हव ।

श्री नारायण चंदेल :- नहीं, ओला पूरा-पूरा आशीर्वाद हे अउ असली में ऊपर ले [XX][7] देखिस हे न, तव ओ ह मढ़ईस हे ।

[XX][7] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार विलोपित.

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने आपके लिए शब्द उपयोग किया है, वह असंसदीय है । विलोपित करना या नहीं करना आपके ऊपर है, पर वह आपके लिए असंसदीय बोले हैं । आप इनको प्रताड़ित करिए ।

अध्यक्ष महोदय :- उसको विलोपित कर दीजिए ।

श्री गुलाब कमरो :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा क्योंकि जिस समय पूरे देश में कोरोना का संकट है, वह आज भी चल रहा है । हम लोगों में डर था कि जिस तरह से देश की सरकार में माननीय मोदी जी ने सांसदों के वेतन-भत्तों में कटौती कर दी, कहीं हम लोगों के वेतन-भत्तों में भी कटौती न हो, इसलिए मन ही मन, अंदर ही अंदर में डर था, लेकिन इस सदन में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने कोई कटौती नहीं की । अभी मैं पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय रमन सिंह जी की बातों को सुन रहा था, वे कह रहे थे कि वर्तमान सरकार ने कुछ नहीं किया, पर मैं इस सदन को, सभी साथियों को बताना चाहूंगा कि जब इनकी सरकार थी तो आदरणीय रमन सिंह जी कोरिया जिले को गोद लिये थे । 15 साल गोद लेने के बाद कोई काम नहीं किया । जब से माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार बनी है और अध्यक्ष महोदय हमारे क्षेत्र के आदर्श हैं, हमारे लीडर हैं, उनका हमेशा आशीर्वाद रहता है । इन दो सालों की सरकार में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा । इस सदन में मुझे कहने में कोई लज्जा नहीं है कि मुख्यमंत्री हो तो ऐसा । हमारे विधान सभा अध्यक्ष और हमारे नेता हो तो ऐसा । इसलिए उन्होंने अपने जन्मदिन में घोषणा की थी कि कटघोरी में सब स्टेशन होगा । तीन महीना हुआ नहीं कि उसकी स्वीकृति मिल गई । अभी जब वे जिले के दौरे में गए थे तो उन्होंने आपकी अगुवाई में, आपकी उपस्थिति में, आपके आशीर्वाद से नागपुर में कॉलेज की घोषणा की थी, जिसे घोषणा किये तीन महीना भी नहीं हुआ और वह पूरा हो गया । इस प्रकार से हमारा कार्यकाल है । रमन सिंह जी की सरकार ने केल्हारी में तहसील की घोषणा की थी, पर नहीं हुआ । उन्होंने केल्हारी में पुल की घोषणा की थी, पर वह पूरा नहीं हुआ। केल्हारी में अस्पताल की घोषणा की, पर पूरा नहीं हुआ । लेकिन माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने, दो साल की सरकार ने सारे कार्यों को पूरा किया इसलिए मेरा नारा है कि मुख्यमंत्री हो तो भूपेश बघेल जैसा हो । इसलिए आपने लगातार किसानों की चिन्ता की है । किसानों की, ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत हो, इसके लिए हमने धान का समर्थन मूल्य शुरू किया, कर्ज माफी हुआ । इसके अलावा राजीव न्याय योजना की शुरूआत हमने की है, जिसकी अंतिम किश्त देना अभी शेष है, पर वह जल्दी मिल जाएगा ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही पूरे देश में पहली बार ऐसा हुआ है, जिसमें धान की बम्फर खरीदी हुई है, जिसमें 32 हजार किसान ऐसे हैं, जो वन अधिकार पट्टा वाले हैं । साथ ही हमारे आदर्श, सबसे जानकार सम्माननीय चन्द्राकर जी एक दिन ट्विटर में बोले थे कि इनको राष्ट्रीय चिह्न

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

लगाना चाहिए । वे हंसी-मजाक कर रहे थे, पर पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों की आर्थिक इंकम 80 करोड़ हुई है । जब आर्थिक इंकम होगी तो किसानों के जीवन में बदलाव आएगा । जब आर्थिक इनकम होगा तो उनके घर की शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, उनके गांवों के क्षेत्र का विकास होगा तब जाकर हमारा छत्तीसगढ़ सुनहरा हो पायेगा। इसके साथ ही हमारे ग्रामीण अंचलों में विकास होगा। अभी उदाहरण दे रहे थे कि हमारे गांवों में सड़क नहीं है, पुल नहीं है, अधोसंरचना के लिये कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। आप उसको एक बार पढ़िये, आप दो साल की सरकार की उपलब्धियों को देखिये, हमारा जो क्षेत्र है, वह मध्यप्रदेश की सीमा से लगा हुआ है, भगवान श्री राम का आगमन हरचोगा में आया था, हरचोगा के बाद से कोटाकल होते हुए रामगढ़ की ओर निकले हैं। 15 साल की सरकार ने कभी भी चिंता नहीं की, लेकिन अध्यक्ष महोदय, आपके आशीर्वाद से 30 किलोमीटर की सड़क बहुत जल्दी शुरू हो रही है। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में जहां बिजली नहीं है, जो पार्क के क्षेत्र में आते हैं, इसलिए मैं माननीय पी.एच.ई. मंत्री जी को भी धन्यवाद दूंगा कि आपके आशीर्वाद से आपने जो एक प्लान जल ज्योति मिशन बनाया है। आपने हर घर को कनेक्शन देने का काम किया है। हमारी सरकार ने घर-घर लक्ष्य रखा है। अध्यक्ष महोदय, माननीय खाद्य मंत्री जी ने किसानों की चिंता की है, अभी आदरणीय देवव्रत सिंह जी कह रहे थे, इस बार इतनी सिस्टम से धान खरीदी हुई है, कहीं भी कोई शिकायत नहीं मिली है। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक ही कारण है। हमने छोटे-छोटे धान खरीदी केन्द्र बनाया। हमने सोसायटी को बढ़ाया। इसलिए लोगों की भीड़ नहीं हुई, वहां पर लोगों का जमावड़ा नहीं हुआ जिसके कारण किसान अपना धान आराम से बेच सके हैं। हमारी सरकार की योजना इस प्रकार से चल रही है। आपने देखा होगा कि 15 साल की सरकार ने कोई चिंता नहीं की। यहां पर हमारे हायर सेकेण्डरी स्कूल है, सरकारी कार्यालय है, वहां तक सड़क नहीं थी। हमारी सरकार ने सुगम सड़क के माध्यम से वहां तक सड़क की स्वीकृति दी है। जब किसानों की बात होती है तो मुझे बड़ी खुशी होती है, हमारी सरकार किसानों की चिंता करती है। अब धरसा योजना लेकर आ गयी है। जहां बरसात में खेत के रास्ते में कीचड़ हो जाती है, वहां पर सड़क नहीं है, उनके लिये भी छत्तीसगढ़ की सरकार ने चिंता की है। अध्यक्ष महोदय, बोलना तो काफी कुछ चाह रहा था, क्योंकि आप हमारे अध्यक्ष हैं। रमन सिंह जी कोरिया जिले को गोद लिये थे, कुछ नहीं हुआ लेकिन आपके आशीर्वाद से 44 नये ग्राम पंचायत की सौगात मिली है, पंचायत भवन 9 करोड़ की लागत से बन गया है। यह छत्तीसगढ़ की माननीय भूपेश बघेल जी की संवेदनशील सरकार है। चाहे वह शिक्षा का हो, प्रदेश में 119 इंग्लिश मीडियम स्कूल खुला है। क्योंकि हम लोग विधायक दल की बैठक में चिंता करते थे, हम लोगों ने कहा था कि चाहे बड़े-बड़े अधिकारी के बच्चे हों, चाहे नेता के बच्चे हों, प्राईवेट स्कूल में पढ़ते हैं लेकिन हमारे गरीब बच्चे जिनके पास इनकम नहीं होती है, वे उतनी फीस देकर नहीं पढ़ पाते हैं, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 119 इंग्लिश मीडियम स्कूल की स्थापना की है जिसमें से

तीन स्कूल मुझे भी मिली है। मैं इस बजट का समर्थन करता हूं। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। धन्यवाद।

श्री देवेन्द्र यादव (भिलाई नगर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद।

समय :
05:33 बजे **(सभापति महोदय (श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह) पीठासीन हुए)**

सभापति महोदय, कल माननीय मुख्यमंत्री जी बजट भाषण पेश कर रहे थे और बजट भाषण सुनकर हमें यह महसूस हो रहा था कि यह छत्तीसगढ़ है और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। छत्तीसगढ़ की जनता की विकास के लिये कुछ योजना लेकर आये हैं। पूर्व की सरकार भी बजट पेश करती थी, हम याद करते हैं, पिछले वर्षों में जब बजट पेश होता था, वह बजट बनते ही उसकी मूल भावना क्या रहती थी? उसकी मूल भावना रहती थी कि उसमें कमीशन कहां से आयेगा ? बजट के माध्यम से कितनी कमाई होगी, कितना जेब में आयेगा ? उस आधार पर बजट का आबंटन नहीं बंदरबाट किया जाता था। आज यह बदलाव माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सबको देखने को मिल रहा है। जहां ईमारतों पर नहीं...।

श्री शिवरतन शर्मा :- यादव जी, हमारी सरकार ने किसी पेड़ पर तो चस्पा करने का काम नहीं किया जो काम आपने किया।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय सभापति महोदय, इस सरकार का ध्यान इमारतों पर नहीं, इबारतों पर है। हमारी संस्कृति, धरोहर, पुरखों ने जिस छत्तीसगढ़ की परिकल्पना की थी, हम उस सही दिशा में निर्माण करने के लिए काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के शिल्पकार का पलायन करने की स्थिति पिछले वर्षों तक थी। मजदूर पलायन कर रहे थे, किसान यहां 4 महीने खेती करता था इसके बाद दूसरे राज्यों में जाकर ईटा भट्टा में काम करते थे। माननीय मुख्यमंत्री जी के भाषण में, उनके बजट में तेलघानी, चर्म शिल्पकार, लौह शिल्पकार, रजतकार इन सभी लोगों पर ध्यान दिया गया है। माननीय सभापति महोदय, ये वे लोग हैं, जो कहीं न कहीं इस बात पर सोच-विचार में थे कि इनका जो पैतृक कार्य है, पारिवारिक कार्य है, अब इस दौर में उसकी आवश्यकता खत्म हो गई है, जरूरत खत्म हो गई है। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को आभार करूंगा कि जिन्होंने कोसा के कारीगर, हमारे तेलघानी साथी, चर्म शिल्पकार, लोहार, कुम्हार इन्हीं से ही तो छत्तीसगढ़ बसता है और उन्होंने छत्तीसगढ़ के इन सब लोगों पर ध्यान दिया।

माननीय सभापति महोदय, हमारे देश की जो हालत है, वह हमारे विपक्ष के साथी भी देखते हैं और हम सब भी देखते हैं। पिछले सौ दिनों से किसान अपने खेत, जमीन और अपनी फसल के लिए

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

आंदोलन में खड़े हैं, वहां दिल्ली में बैठे हुए हैं। इनके कानों में जूं तक नहीं रेंगती। ये किसान की फसल और खेत को भी बेचना चाहते हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- यादव जी, भिलाई में ठेकेदार लोग कितने दिनों तक बैठे थे ?

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय सभापति महोदय, क्योंकि विपक्ष को सार्थक चर्चा नहीं करना है, विरोध करना है। तो मैं इनको जवाब दे देता हूं। जो लोग सौ दिन बैठे थे, वे लोग आपके कार्यकाल के भुगतान के लिए प्रताड़ित होकर बैठे थे। वह 2016-17 का भुगतान था।

श्री शिवरतन शर्मा :- किन परिस्थितियों पर पेड़ पर नोटिस चस्पा करना पड़ा ? आप सदन को यह भी बता दो।

श्री देवेन्द्र यादव :- उस पेड के पास चबूतरा भी हमने बनवाया।

श्री शिवरतन शर्मा :- नहीं-नहीं, चस्पा।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय सभापति महोदय, यह जो भारत सरकार चल रही है, मुझे लगता है कि वह बेचूंजीवी सरकार है। जो मिले, उसको बेच दो। ये सेल बेच देना चाहते हैं, ये बी.एस.एन.एल. बेच देना चाहते हैं, ये एच.ए.एल. बेच देना चाहते हैं, ये भेल बेच देना चाहते हैं, ये रेल बेच देना चाहते हैं, ये एयरपोर्ट, एयरवेज, सब कुछ बेच देना चाहते हैं। यह सरकार इस मानसिकता की है। एक तरफ हमारे प्रदेश की सरकार है, जिसके मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी छाती ठोंककर कहते हैं कि अगर केन्द्र सरकार नगरनार स्टील प्लांट बेचेगी तो छत्तीसगढ़ की सरकार उसको खरीदेगी।

श्री अजय चन्द्राकर :- यादव जी, एक मिनट सुनो। जिस दिन नगरनार को खरीदेंगे बोले, उस दिन हम लोग छाती ठोकते देखे नहीं हैं। ये छाती कहां ठोके, पहले यह बताओ ?

श्री शिवरतन शर्मा :- यह प्रस्ताव तो हम लोगों का था, जिसको स्वीकार किया गया था। यह प्रस्ताव तो हमने रखा था कि सरकार खरीदे।

श्री अजय चन्द्राकर :- कहां छाती ठोके, पहले यह बताओ ? हम लोग तो छाती ठोकते देखे ही नहीं है। आप सीनियर मिनिस्टर बैठे हो।

सभापति महोदय :- माननीय सदस्य को अपनी बात रखने दें।

श्री देवेन्द्र यादव :- सभापति महोदय, मैं अपने भाषण में सभी सम्माननीय सदस्यों को जवाब दूंगा। इस देश की सरकार इस तरीके से चल रही है। आज हमारे प्रदेश की सरकार स्व. चंदू लाल चन्द्राकर मेडिकल कॉलेज को शासकीयकरण करने का कार्य कर रही है ताकि जो मेडिकल के बच्चें हैं, उनको मदद हो सके। एक तरफ ये देश की सरकार है, धान, मक्का, गेहूं, गन्ना जैसी महत्वपूर्ण फसलों पर एम.एस.पी. खत्म करने का षड़यंत्र कर रही है और दूसरी तरफ हमारे मुखिया हैं, हमारे जो 52 वनोपज हैं, उनको समर्थन मूल्य पर खरीदने जा रही है। ये आलू, प्याज जैसे फसलों के भण्डारण को फ्री हैण्ड करने जा रही है ताकि लूट मच जाये। यहां छत्तीसगढ़ में कोदो, कुटकी, रागी जैसे फसलों को भी

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

न्यूनतम समर्थन मूल्य में लाने की तैयारी कर रही है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं कि देश में बेरोजगार दर-दर भटक रहे थे, मजदूर पलायन कर रहे थे, तो छत्तीसगढ़ में मनरेगा के माध्यम से यहां के मजदूरों को रोजगार देने का काम किया है। माननीय सभापति महोदय, गांधी जी ने कहा था कि पहले ये आप पर हंसेंगे, फिर आपसे लड़ेंगे, लेकिन अंत में जीत आपकी होगी। गोधन न्याय योजना आई तो यही सम्मानित सदस्य क्या-क्या बातें करते थे यह आपको याद है। आज इनकी ही केंद्र सरकार गोधन न्याय योजना की तारीफ करती है और पूरे प्रदेश की सरकारें इसको लागू करने के लिए आगे बढ़कर याद कर रही हैं और हमारे प्रतिनिधिमंडल को बुला रही हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- क्या है, गांधी जी ने जो कहा था वह बात कहां कही थी मालूम है? चंपारण आंदोलन बिहार में। सुने कि नहीं सुने। लेकिन भाषण एक तो देख देखकर बोल रहे हो वह अच्छा नहीं है। दूसरा यदि देख-देखकर बोलना है तो उससे अच्छा है कि उसको टेबल कर दो। तीसरी बात- मुख्यमंत्री जी छाती कहां पर ठोंके ये जरूर बताना।

श्री शिवरतन शर्मा :- गांधी जी ने जो कहा था उसको वास्तव में पूरे देश में क्रियान्वित करने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए, उस काम में नरेंद्र मोदी जी लगे हुए हैं।

श्री देवेन्द्र यादव :- आपके नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं मैं उसी पर आ रहा हूं, आप सुनियेगा और उसका जवाब दीजिएगा।

श्री अजय चंद्राकर :- देखकर मत बोलो ना।

श्री देवेन्द्र यादव :- मैं आपको देखकर बोलता हूं। मैं आसंदी से इजाजत लेते हुए माननीय सदस्य की ओर देखकर अपनी बातों को कहूंगा। इनकी सरकार, इनके पूर्व मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमारी केंद्र की सरकार 60 लाख मीट्रिक टन धान लेगी। इसके बाद कितना हुआ? 24 लाख मीट्रिक टन। इस पर आपको कुछ नहीं कहना है? इस पर यदि आपके जवाब आयें तो हम मानें कि आप छत्तीसगढ़ की जनता के समर्थन में बात करते हैं, छत्तीसगढ़ के हित में बात करते हैं लेकिन आप केवल राजनीति करना चाहते हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- देवेंद्र जी, अगर छत्तीसगढ़ के 40 लाख किसानों को आप राजीव गांधी न्याय योजना का लाभ देंगे तो हम आपके साथ खड़े होंगे।

श्री देवेन्द्र यादव :- आप राजनीति कर रहे हैं, कुंठा और ईर्ष्या से ग्रसित हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि आप छत्तीसगढ़ के हित में बात करना चाहते हैं तो एक प्रतिनिधिमंडल ले जाईये और जाकर बोलिए कि आप हमारे छत्तीसगढ़ के किसानों का धान खरीदिये। माननीय सभापति महोदय, राजीव गांधी किसान न्याय योजना से इनको तकलीफ है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री पुन्नूलाल मोहले :- थोड़किन छत्तीसगढ़ी में भी बोलव।

श्री देवेन्द्र यादव :- उसमें भी बोलूंगा। जब-जब जैसी परिस्थिति आयेगी, वैसा बोलूंगा। आपसे तो मैं सीखता हूं, आप तो हम सबके गुरूदेव हो। पीछे की पाठशाला आप ही ने सिखाई है। मैं गुरूदेव को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ता हूं। मुझे लगता है कि ये केवल बेचूजीवी नहीं हैं कुंठितजीवी भी हैं और इनके लिए अभी तक कोई वैक्सीन भी नहीं आई है। यदि ट्रायल करना हो तो यहां पर ट्रायल करने के लिए लोग उपस्थित हैं।

सभापति महोदय, कल मैं डॉक्टर साहब का ट्वीट पढ़ रहा था। उन्होंने लिखा कि यह छत्तीसगढ़ का बजट है, ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं और कांग्रेसियों की टावरी हो रही है। मुझे उनका ट्वीट पढ़कर बड़ा दुख हुआ कि ये क्या बात लिख रहे हैं। फिर मुझे समझ में आया कि तकलीफ कहां है। पहले जो बजट बनता था वह ससुर, दामाद, बेटे के लिए बजट बनता था, अब यह युवाओं, किसानों और छत्तीसगढ़ के आम लोगों के लिए बजट बना है इसलिए इनको तकलीफ हो रही है। ये राम भगवान की बात करते हैं। राम के नाम पर राजनीति करते हैं। मैं अपने विपक्ष के साथियों से यह पूछना चाहता हूं कि रामराज्य होता क्या है उसकी परिकल्पना को भी समझना जरूरी है। भगवान श्रीराम ने अपने भाई भरत से कहा था कि हम लोग हमारी प्रजा से जो कर लेते हैं वह इस तरीके से लें जैसे सूरज नदियों, तालाबों से पानी लेता है और जब वह वर्षा के रूप में बरसात करता है तो उससे विकास होता है और वह पानी खेत, खलिहान, घरों से लेकर वापस नदी, नालों और तालाबों में जाता है। इस तरीके से करना चाहिए। लेकिन यह इनकी सरकार है, इनको लज्जा आनी चाहिए कि आज देश के अंदर क्या स्थिति है? आज 28 दिनों में, पिछले एक महीने में 16 बार पेट्रोल, डीजल के दाम में वृद्धि हुई है। अब इनके पूर्व मुख्यमंत्री, इनके सम्मानीत सदस्य और ये सारे लोग कोई सायकल नहीं चला रहे हैं। पहले यह सायकल में निकल जाते थे कि पेट्रोल-डीजल का दाम बढ़ गया, हम सायकल चलायेंगे। अब इनको सायकल की याद नहीं आ रही है। यह इनका दोहरा चरित्र है। आप देखिए एक दिसम्बर, 2020 को 594 रूपये में सिलेण्डर मिलता था, आज तीन महीने में सिलेण्डर का दाम 890 रूपये हो गया है।इस पर यह कुछ भी नहीं बोलेंगे।

श्री शिवरतन शर्मा :- आप इसकी तुलना वर्ष 2004 से करिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय सभापति महोदय, इस पर यह कुछ भी नहीं बोलेंगे। इन्होंने तो इस देश में लोगों को स्थिति यह कर दी की अब सब्सीडी नहीं, खाना-पीना भी छोड़ना पड़ेगा। मैंने इस पूरे बजट को ध्यानपूर्वक पढ़ा और एक तरफ हमने यह महसूस किया कि इस युवावस्था में विकास के नये आयाम कैसे होते हैं? उसको हमने समझा कि डवलपमेंट केवल इंफ्रास्ट्रक्चर पर नहीं होता, चीजों को बसाने पर होता है। एक तरफ इनकी केन्द्र की सरकार है जिसके राज में प्रजा दु:खारी और ये पूंजीवाद के नरक अधिकारी, बने हुए हैं। दूसरी तरफ माननीय भूपेश बघेल जी की कांग्रेस की सरकार है जो अपनी

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

पूरी मेहनत लगन से पिछले 15 सालों के गड्ढ़ों को पाट भी रही है, समाजवाद की ओर बढ़ भी रही है और आर्थिक और लोकतांत्रिक समानता को बढ़ाने का प्रयास कर रही है। मैं इस बजट का समर्थन करते हुए, अपनी वाणी को विराम देता हूँ।

माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

सभापति महोदय :- श्रीमती ममता चन्द्राकर। सभा की कार्यवाही बुधवार दिनांक 03 मार्च, 2021 को 11.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित।

(सायं 5 बजकर 47 मिनट पर विधान सभा बुधवार, दिनांक 03 मार्च, 2021 (फाल्गुन 12, शक् संवत् 1942) के पूर्वाहन 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

चन्द्र शेखर गंगराड़े

रायपुर(छ.ग.) **प्रमुख सचिव**

दिनांक 02 मार्च, 2021 **छत्तीसगढ़ विधान सभा**

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं